



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रतिष्ठित से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

1) नई दिल्ली, शनिवार जनवरी 1, 1983/पौष 11, 1904
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 1983/PAUSA 11, 1904

इस भाग में बिना पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate page is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
tory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India
(other than the Ministry of Defence)

योजना मंत्रालय
(सांख्यिकी विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

1.—इस विभाग के दिनांक 1 दिसम्बर, अधिसूचना संख्या एम-12011/4/82-भा. सां. के क्रम संख्या तीन में डा. बी.पी. अधिकारी के स्थान पर फिसर जे.के. घोष का नाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेश के रूप में रखा जाए।

[संख्या एम-12011/4/82-भा.सां.सं.]

महेन्द्र नाथ, उप-सचिव

MINISTRY OF PLANNING
(Department of Statistics)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 1.—In this Department's Notification No. M-12011/42-ISI dated 1st December, 1982 against Sl. No. 3 of para the name of Prof. J. K. Ghosh is substituted for Dr. P. Adhikari as representative of ISI on the Committee.

[No. M-12011/4/82-ISI]
MAHENDRA NATH, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982

(आय-कर)

कां०जा० 2.—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961) 1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री शिव बाल योगी महाराज ट्रस्ट, बंगलूर को 'निर्धारण वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के अन्नगत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं० 4976/कां० सं० 197/125/81-अ०क(एI)]

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

New Delhi, the 23rd November, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 2.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of the sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shri Shiva Balayogi Maharaj Trust, Bangalore" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1984-85.

[No. 4976/F. No. 197/125/81-IT(A)]

आय-कर

(INCOME-TAX)

का० आ० 3 -- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री महादेवी बिर्ला मेमोरियल चैरिटी ट्रस्ट को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचना करती है।

[सं 4982/का० सं० 197/171/80-आ०क० (ए1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 3.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Mahadevi Birla Memorial Charity Trust" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4982 F. No. 197/171/80-IT(AI)]

आय-कर

का० आ० 4 -- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'क्रिश्चियन इन्स्टीट्यूट फॉर दि स्टडी ऑफ रिलीजन एण्ड सोसाइटी' को निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचना करती है।

[सं 4984/का० सं० 197/123/79-आ०क० (ए1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 4.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Christian Institute for the study of Religion and Society" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1980-81 to 1982-83.

[No. 4984/F. No. 197/123/79-IT(AI)]

आयकर

का० आ० 5 -- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'सेवा निधि ट्रस्ट' को निर्धारण वर्ष 1981-82 और 1982-83 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं 4987/का० सं० 197/81/80-आ०क० (ए1)]

(INCOME-TAX)

S.O. 5.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Seva Nidhi Trust' for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1981-82 and 1982-83.

[No. 4987 F. No. 197/81/80-IT(AI)]

आय-कर

का० आ० 6 -- केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 की उपधारा (23-ग) के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'श्री चित्तापुर मठ' को निर्धारण वर्ष 1980-81 से 1983-84 तक के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिए उक्त धारा के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है।

[सं 4988/का० सं० 197/12/81/आ०क० (ए1)]

मिलाप जैन, धवर सचिव

S.O. 6.—In exercise of the powers conferred by clause (v) of sub-section (23C) of the section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 'Shri Chitrapur Math' for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1980-81 to 1983-84.

[No. 4988 F. No. 197/12]

MILAP JAIN,

केन्द्रीय प्रत्यक्षकर बोर्ड

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

आयकर

का० आ० 7 -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्ववर्ती अधिसूचना सं० 4501 तारीख 3-3-82 को आंशिक रूप से उपरान्त करने हुए निम्नलिखित संशोधन करता है। क्रम सं० 23ड० के सामने स्तम्भ 1, 2 और 3 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी :-

आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
23ड० पश्चिमी बंगाल	कलकत्ता	1 जिला I (1), कलकत्ता 2 जिला III (3) कलकत्ता 3 जिला हावड़ा, कलकत्ता 4 विशेष सर्वेक्षण सकल कलकत्ता 5 विशेष सर्वेक्षण सकल कलकत्ता 6 कम्पनी जिला 6, कलकत्ता

यह अधिसूचना 19-4-1982 में प्रभावी होगी।

[सं 4576 (का० सं० 18, 82)]

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 17th April, 1982

(INCOME-TAX)

S.O. 7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in partial modification of the previous Notification No. 4501 dated 3-3-82 the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments. The existing entries under Column 1, 2, 3 against SI No. 23E, shall be substituted by the following entries:—

Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3
23E West Bengal-VI	Calcutta	1. Distt. II (1), Calcutta. 2. Distt. III (3), Calcutta. 3. Distt. Howrah, Calcutta. 4. Spl. Survey Cir. Calcutta. 5. Spl. Survey Cir. Calcutta. 6. Companies Distt. Calcutta.

This notification shall take effect from 19-4-1982.

[No. 4576 /F.No.187/14-82IT(A)]

(अ.य.क.)

आय-कर

कां.आ. 8.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) या प्रदान की गयी क प्रती करना हुआ और पूर्ववर्ती अधिसूचना सं. 4391 तारीख 21-12-1981 का आंशिक रूप से उद्घाटन करने हुए निम्नलिखित संशोधन करने हैं। क्रम सं. 10 और 10A के समाने स्तम्भ 1, 2 और 3 के नीचे की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:—

आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3
10 गुजरात-I	अहमदाबाद	कम्पनी सिकिल, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 और 15 अहमदाबाद
10A गुजरात-II	अहमदाबाद	कम्पनी सिकिल, 3, 10, 11, 12, 13 और 14 अहमदाबाद सिकिल 1, 2 और 3 अहमदाबाद। इ. डी. क्रम-आई टी सिकिल, अहमदाबाद। हिम्मत नगर सिकिल। मोदासा सिकिल। पालनपुर सिकिल।

यह आदेश 19 अप्रैल, 1982 में प्रभाव हुआ।

[सं. 4577 फा. सं. 187/14/82-आई टी (ए. आई.)]

(INCOME—TAX)

S.O. 8.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of the previous Notification No. 4394 dated 24-12-1981 the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments. The existing entries under Col. 1, 2 and 3 against Sl. No. 10 & 10A shall be replaced by the following:—

Commissioner of Income-tax	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3
10 Gujarat-I	Ahmedabad	Companies Circles I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XIV & XV, Ahmedabad
10A Gujarat-II	Ahmedabad	Companies Circles III, X, XI, XII, XIII & XVI Ahmedabad. Circle-I, II & III, Ahmedabad. ED-cum-IT Circle, Ahmedabad. Himmatnagar Circle. Modasa Circle. Palanpur Circle.

This order shall take effect from 19th April, 1982.

[No. 4577/F. No/87/14/82-IT (A)]

कां.आ. 9.—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इस बाबत सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को आंशिक रूप से उपातर्गित करने हुए निदेश देता है कि इससे उपर्युक्त अधिसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित आय-कर आयुक्त अपनी अधिकारिता का प्रयोग, ऐसे क्षेत्रों में व्यक्तियों के वर्गों या आय या आय के वर्गों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों की वकन करेगा जो उक्त अधिसूची के स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट आय-कर सिकिलों/वार्डों या जिलों में समाविष्ट है।

परन्तु यह कि आय-कर आयुक्त ऐसे व्यक्तियों या मामलों की वाकन भी कृत्य करेगा जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उसके अधीनस्थ किसी आय-कर प्राधिकारी को समनुदेशित किए गए हैं या किए जाएंगे।

परन्तु यह और कि आयुक्त ऐसे व्यक्तियों या मामलों की वाकन कृत्य नहीं करेगा जो उसकी अधिकारिता के बाहर किसी आय-कर प्राधिकारी को समनुदेशित किए गए हैं या किए जाएंगे।

क्रम सं.	आय-कर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3	4
8	दिल्ली-1	नई दिल्ली	1 कपनी सिकिल-2, नई दिल्ली। 2 कपनी सिकिल 7 नई दिल्ली। 3 कपनी सिकिल 10 नई दिल्ली। 4 कपनी सिकिल 14, नई दिल्ली। 5 कपनी सिकिल 15, नई दिल्ली। 6 कपनी सिकिल, 19, नई दिल्ली। 7 विशेष सिकिल 15, नई दिल्ली। 8. विदेश शाखा, नई दिल्ली। 9 विशेष सिकिल 3, नई दिल्ली।
8क	दिल्ली 2	नई दिल्ली	1 कपनी सिकिल 1, नई दिल्ली। 2 कपनी सिकिल 4, नई दिल्ली। 3 कपनी सिकिल 5, नई दिल्ली। 4 कपनी सिकिल 6, नई दिल्ली। 5 कपनी सिकिल 8, नई दिल्ली। 6 कपनी सिकिल, 9, नई दिल्ली। 7 कपनी सिकिल 11, नई दिल्ली। 8 कपनी सिकिल 17, नई दिल्ली। 9 कपनी सिकिल 18, 21, 25, नई दिल्ली। 10 कपनी सिकिल, 24, नई दिल्ली। 11 जिला 6 (13), नई दिल्ली।
8	दिल्ली 3	नई दिल्ली	1 जिला 5 (8) का छोड़कर जिला 5, नई दिल्ली के सभी वार्ड। 2 जिला 8, नई दिल्ली के सभी वार्ड। 3 अतिरिक्त सर्वेक्षण सिकिल, 4, नई दिल्ली। 4 कपनी सिकिल 3, नई दिल्ली। 5 कपनी सिकिल, 12, नई दिल्ली। 6 कपनी सिकिल 13, नई दिल्ली।

1	2	3	4	1	2	3	4
			7. कंपनी सफिल 16, नई दिल्ली 8 कंपनी सफिल 20, नई दिल्ली 9 कंपनी सफिल 23, नई दिल्ली 10 सम्पदा शुल्क तथा आय-कर सफिल, नई दिल्ली। 11 अनिश्चित सम्पदा शुल्क तथा आय-कर सफिल नई दिल्ली।				6 जिला 11, नई दिल्ली के सभी बाई। 7 विशेष सफिल 14, नई दिल्ली। 8 विशेष सफिल-6 (अतिरिक्त) और विशेष सफिल-16 नई दिल्ली, जो उन सभी व्यक्तियों के मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए हैं जिनके संबंध में आर्थिक सुरक्षा अधिनियम (नक्सरी क्लियरिंग) और विदेशी मुद्रा में नूतनाट के लिए (और/या विदेशी मुद्रा सुरक्षण और तत्परी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन निराधारण क्लियरिंग) और जो आयकर आयुक्त (अन्वेषण) नई दिल्ली को छोड़कर दिल्ली स्थित सभी आयकर आयुक्तों की अधिकाधिकता के अधीन है। 9 जिला 5(s), नई दिल्ली।
8ग दिल्ली 4,	नई दिल्ली		1 जिला-3-क, नई दिल्ली के सभी बाई। 2 जिला-3-ख, नई दिल्ली के सभी बाई। 3 जिला-3-ग, नई दिल्ली के सभी बाई। 4 निष्कांत सफिल, नई दिल्ली। 5 सर्वेक्षण सफिल, 3, नई दिल्ली। 6 परिवहन सफिल, नई दिल्ली जो सभी व्यक्तियों के (जिनके अस्तगत यथास्थिति ऐसी फर्मों या कंपनियों के या उनके भागीदारों या उनके निवेशकों के जो आयकर आयुक्त, दिल्ली 1, 2 3, 4 5, 7, 8 और नक्सरी या युक्त (अन्वेषण) दिल्ली, नई दिल्ली की अधिकारिता को अधीन सफिल परिवहन प्रचालकों का कार-बार या बुनि करने हैं। मामले भी हैं संबंध में कार्यवाही करते हैं।				
8ग दिल्ली-5,	नई दिल्ली		1 जिला 2, नई दिल्ली के सभी बाई। 2 जिला 4, नई दिल्ली के सभी बाई। 3. जिला 7, नई दिल्ली के सभी बाई। 4. परिवार सफिल, नई दिल्ली।	8घ दिल्ली-8,	नई दिल्ली		1 जिला 10, नई दिल्ली के सभी बाई। 2 सम्पदा सफिल 4, नई दिल्ली 3 डेकेदार सफिल नई दिल्ली, जो सभी व्यक्तियों के, (जिनके अस्तगत यथास्थिति फर्मों या कंपनियों के, उनके भागीदारों या निवेशकों के मामले भी हैं (जो आयकर आयुक्त दिल्ली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आयकर आयुक्त (अन्वेषण) दिल्ली, नई दिल्ली की अधिकारिता के अधीन किसी कार्य को करने के लिए वास्तविक उर्जाधिनियम और डेकेदार या कारबार या बुनि करने हैं (जिनके अस्तगत कोई कार्य करने के लिए अनिर्णय फ. प्रदाय करता भी हैं) संबंध में कार्यवाही करता है। 4 कंपनी सफिल, 22, नई दिल्ली 5 विशेष सफिल 6 और 10, नई दिल्ली। 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट सफिल, नई दिल्ली जो सभी व्यक्तियों के (जिनके अस्तगत फर्मों और उनके भागीदारों के मामले हैं) जो आयुक्त दिल्ली-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आय-कर आयुक्त
8घ दिल्ली 6,	नई दिल्ली		1 वेरन सफिल, नई दिल्ली। 2 प्राइवेट वेरन सफिल, नई दिल्ली। 3 टी डी एस सफिल, नई दिल्ली। 4 न्याय सफिल, नई दिल्ली। 5 अलिप्त निधि सफिल नई दिल्ली				
8घ दिल्ली 7,	नई दिल्ली		1. जिला 1, नई दिल्ली के सभी बाई। 2 जिला 3, नई दिल्ली के सभी बाई। 3 जिला 3 (19) से (23) और जिला 3(27), नई दिल्ली। 4 जिला 6 (13) नई दिल्ली को छोड़कर जिला 6, नई दिल्ली के सभी बाई। 5. जिला 9 नई दिल्ली के सभी बाई।				

(अन्वेषण) दिल्ली, नई दिल्ली की अधिकारिता के अधिन चार्टर्ड प्रकाउंटेंटों वा बार-बार वा बुलि करते हैं, संबंध में कार्यवाही करता है।

7 विधि व्यवसायी मकिल नई दिल्ली जो सभी व्यक्तियों के, (जिनके अन्तर्गत कर्मों, उनके भागीदारों के मामले भी हैं) जो आयकर आयुक्त दिल्ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आयकर आयुक्त (अन्वेषण) दिल्ली, नई दिल्ली, की अधिकारिता के अधीन विधि व्यवसायों वा जिसके अन्तर्गत सासि-सिटर और अधिवक्ता भी है कारबार वा बुलि करते हैं, संबंध में कार्यवाही करता है।

8 चिकित्सक मकिल, नई दिल्ली जो सभी व्यक्तियों के (जिनके अन्तर्गत कर्मों और उसके भागीदारों के के मामले भी हैं) जो आयकर आयुक्त दिल्ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आयकर आयुक्त अन्वेषण दिल्ली, नई दिल्ली की अधिकारिता के अधीन एसापेबिक, होम्सोपेयिक यूनि, अ.युर्वेदिक वा चिकित्सा की कोई अन्य पद्धति के चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सक चिकित्सक और रोगविज्ञानी का कार-बार वा बुलि करते हैं, संबंध में कार्यवाही करता है।

(अन्वेषण) दिल्ली नई दिल्ली ; ऐसे सभी नए मामलों के संबंध में कार्रवाई करते वाले सर्वेक्षण/वार्ड/सालिज जहाँ विवरणियां प्रथम बार 1-5-1980 को या उसके पश्चात् फाइल की जाती है या ऐसे मामले जिनके संबंध में सभी तक निवारण नहीं किया गया है और जहां आयकर अधिनियम की धारा 139 (2) या 148 के अन्तर्गत सूचना 1-7-1980 को या उसके पश्चात् जारी

की जाती है और जो कपनों मकिलों, डेकेदार मकिलों, परिवहन मकिलों, बेतन मकिलों प्राइवेट बेतन म मकिलों, टो.बी.एम. मकिलों न्याय मकिलों चार्टर्ड एकाउंटेंट मकिलों चिकित्सक मकिलों, रिजि अद्वैतारी मकिलों और प्रतिशय मकिलों, नई दिल्ली को छाड़कर आयकर, आयुक्त दिल्ली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आयकर आयुक्त (अन्वेषण) दिल्ली, नई दिल्ली की अन्तर्गत अधिकारिता के है।

यह अधिसूचना 19 अप्रैल, 1982 का प्रसारी होगी।

[सं. 4578/का.सं. 187/14/82-आई टा (न आई)]

S.O. 9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of all previous modifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto shall exercise jurisdiction in respect of such areas or of such persons or clauses of persons or of such incomes or classes of incomes or of such cases or classes of cases as are comprised in the Income-tax Circles, Wards or Districts referred to in the Column (4) of the said Schedule.

Provided that a Commissioner of Income-tax shall also perform his functions in respect of such persons or of such case as have been or may be assigned by the Central Board of Direct Taxes to any Income-tax Authority Subordinate to him

Provided further that a Commissioner shall not perform his functions in respect of such persons or such cases as have been or may be assigned to any Income tax Authority outside his jurisdiction.

SCHEDULE

S. No.	Commissioner Headquarters	Jurisdiction
1	2	3
8.	Delhi-I	New Delhi
		1. Companies Circle-II, New Delhi.
		2. Companies Circle-VII, New Delhi.
		3. Companies Circle-X, New Delhi.
		4. Companies Circle-XIV, New Delhi.
		5. Companies Circle-XV, New Delhi.

1	2	3	4	1	2	3	4
			6. Companies Circle-XIX, New Delhi.				5. Survey Circle-III, New Delhi.
			7. Special Circle-XV, New Delhi.				6. Transport Circle, Delhi dealing with the cases of all persons (including the cases of firms or companies the partners or as the case may be, the Directors thereof carrying on business or profession as Road Transport Operators under the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII & Commissioner of Income-tax, (Inv.), Delhi, New Delhi.
			8. Foreign Section, New Delhi.				
			9. Special Circle-III, New Delhi.				
8A Delhi-II	New Delhi	1. Companies Circle-I, New Delhi.		8D Delhi-V	New Delhi	1. All Wards in Distt. II, New Delhi.	
		2. Companies Cir. IV, New Delhi.				2. All Wards in Distt. IV, New Delhi.	
		3. Companies Cir. V, New Delhi.				3. All Wards in Distt. VII, New Delhi.	
		4. Companies Cir. VI, New Delhi.				4. Refund Circle, New Delhi.	
		5. Companies Cir. VIII, New Delhi.					
		6. Companies Cir. IX, New Delhi.		8E Delhi-VI	New Delhi	1. Salary Circles, New Delhi.	
		7. Companies Cir. XI, New Delhi.				2. Pvt. Salary. Circles, New Delhi.	
		8. Companies Cir. XVII, New Delhi.				3. T.D.S. Circles, New Delhi.	
		9. Companies Cir. XVIII, XXI, XXV, New Delhi.				4. Trust Circles, New Delhi.	
		10. Companies Cir. XXIV, New Delhi.				5. Provident Fund Circle, New Delhi.	
		11. Distt. VII(13), New Delhi.		8F Delhi-VII	New Delhi	1. All Wards in Distt. I, New Delhi.	
8B Delhi-III	New Delhi	1. All Wards in Distt. V, New Delhi except Distt. V(8).				2. All Wards in Distt. III-D, N. Delhi.	
		2. All Wards in Distt. VIII, New Delhi.				3. Distt. III (19) to (23) & Distt. III (27), New Delhi.	
		3. Addl. Survey Cir. IV, New Delhi.				4. All Wards in Distt. VI, New Delhi except Distt. VI (13), New Delhi.	
		4. Companies Cir. III, New Delhi.				5. All Wards in Distt. IX, New Delhi.	
		5. Companies Cir. XII, New Delhi.				6. All Wards in Distt. XI, New Delhi.	
		6. Companies Cir. XIII, New Delhi.				7. Spl. Cir. XIV, New Delhi.	
		7. Companies Cir. XV, New Delhi.				8. Special Circle-VI (Addl.) and Special Circle-XVI, New Delhi for dealing with the cases of all persons in respect of whom an	
		8. Companies Cir. XX, New Delhi.					
		9. Companies Cir. XXIII, New Delhi.					
		10. Estate Duty-cum-I.T. Circle, New Delhi.					
		11. Addl. Estate Duty-cum-I.T. Circle, New Delhi.					
8C Delhi-IV	New Delhi	1. All Wards in District-III-A, New Delhi.					
		2. All Wards in District-III-B, New Delhi.					
		3. All Wards in District-III-C, New Delhi.					
		4. Evacuee Circles, New Delhi.					

1	2	3	4	1	2	3	4
			order of detention has been made under the Maintenance of Internal Security Act (for smuggling activities) and foreign Exchange racketeering) and/or Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and which are under the jurisdiction of all Commissioners of Income-tax at Delhi excluding the Commissioner of Income-tax (Central), New Delhi.				of Commissioners of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV V, VI, VII, VIII and Commissioners of Income-tax (Inv.), Delhi, New Delhi.
		9.	Distt. V(8), New Delhi.			7.	Lawyer's Circle, New Delhi dealing with the cases of all persons (including in the case of firms partners thereof) carrying on business or profession as Lawyers (including solicitors and advocates) under the jurisdiction of Commissioners of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioner of Income-tax (Inv.), Delhi, New Delhi.
8G	Delhi-VIII	New Delhi.	1. All Wards in Distt. X, New Delhi. 2. Survey Circle-IV, New Delhi. 3. Contractors Circles, Delhi dealing with the cases of all persons (including the cases of firm or companies, the partners of as the case may be, the directors thereof) carrying on business or profession as Architects, Engineers and Contractors for carrying out any work (including supply of labour for carrying out any work under the jurisdiction of Commissioners of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioner of Income-tax (Inv.), Delhi, New Delhi. 4. Companies Cir. XXII New Delhi. 5. Spl. Cir. VI & X, New Delhi. 6. Chartered Accountant's Circles, New Delhi, dealing with the cases of all persons (including in the cases of firm partners, thereof carrying on business or profession as Chartered Accountants under the Jurisdiction			8.	Doctors Circles, New Delhi, dealing with the cases of all persons (including in the cases of firms, partners thereof) carrying on business or profession as Medical Practitioners of Allopathic, Homeopathic, Unani, Ayurvedic or any other system of medicine) Radiologists and Pathologists under the jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioner of Income-tax (Inv.), Delhi, New Delhi.
				8H (Inv.) Delhi.	New Delhi.		Survey Wards/Circles dealing with all new cases where returns are filed for the first time on or after 1-5-1980 or cases which have not neither to been assessed and where notice u/sec. 139(2) or 148 of Income-tax Act, 1961 is to be issued on or after 1-7-1980 pertaining to the territorial jurisdiction of Commissioner of Income-tax, Delhi-I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII and Commissioner of Income-tax (Inv.) Delhi, New Delhi except cases relating to

1	2	3	4	1	2	3	4
			Companies Circles, Contractor Circles, Transport Circles, Salary Circles, Private Salary Circles, T.D.S Circles, Trust Circles, Chartered Accountants Circles, Doctors Circles, Lawyers Circles and Refund Circles, New Delhi	21घ	तमिलनाडु-5	मद्रास	1 नगर सिकिल- VI, मद्रास 2 विल्लुपुरम सिकिल 3 पाडिचेरी सिकिल 4 कुड्डलोर सिकिल 5 नागपट्टनम सिकिल 6 थजावूर सिकिल । 7 कांचीपुरम सिकिल । 8 वेलोर सिकिल । 9 तावगम सिकिल ।

This notification takes effect from 19th April, 1982.

[No 4578/F No 187/14/82-IT (AI)]

कां०आ० 10-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इस बाबत सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक रूप से उद्घाटन करने हुए निदेश देती है कि इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित आयकर आयुक्त अपनी अधिकारिता का प्रयोग, ऐसे क्षेत्र या व्यक्तियों के वर्गों या आय या आय के वर्गों या ऐसे मामलों या मामलों के वर्गों की बाबत करेगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में निर्दिष्ट आयकर सिकिलों, वाडों या जिलों में समाविष्ट हैं ।

परन्तु यह कि आयकर आयुक्त ऐसे व्यक्तियों या मामलों की बाबत भी कृत्य करेगा जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उनके अधीनस्थ किसी आयकर प्राधिकारी का समनुदेशित किए गए हैं या किए जाएं ।

परन्तु यह और कि आयुक्त ऐसे व्यक्तियों या मामलों की बाबत कृत्य नहीं करेगा जो उसकी अधिकारिता के बाहर किसी आयकर प्राधिकारी को समनुदेशित किए गए हैं या किए जाएं ।

अनुसूची

क्रम सं०	आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3	4
21	तमिलनाडु 1	मद्रास	1 नगर सिकिल-I मद्रास 1 2 विदेश अनुभाग, मद्रास
21क	तमिलनाडु-2	मद्रास	1 कंपनी सिकिल-I मद्रास 2 कंपनी सिकिल-II, मद्रास 3 नगर सिकिल III, मद्रास 4 नगर सिकिल-IV, मद्रास
21ख	तमिलनाडु 3	मद्रास	1 इडी तथा आई टी सिकिल, मद्रास 2 इडी तथा आई टी सिकिल, थजावूर 3 कंपनी सिकिल III, मद्रास 4 नगर सिकिल II, मद्रास 5 नगर सिकिल-VII, मद्रास 6 हुडी सिकिल, मद्रास I
21ग	तमिलनाडु 4	मद्रास	1 वेतन सिकिल-I, मद्रास 2 वेतन सिकिल II, मद्रास 3 प्रतिशय सिकिल, मद्रास 4 नगर सिकिल-V मद्रास 5 फिन्म सिकिल, मद्रास

21घ	मदुरै	मदुरै	1 कंपनी सिकिल, तिरुचिरापल्ली 2 नगर सिकिल I, तिरुचिरापल्ली । 3 नगर सिकिल II, तिरुचिरापल्ली । 4 कन्नूर सिकिल 5 पुडुकोट्टाई सिकिल 6 कराइकुडी सिकिल 7 कंपनी सिकिल मदुराई 8 मदुरै सिकिल 9 विशेष सिकिल मदुरै 10 डिडीगुल सिकिल । 11 निरुनेलवेली सिकिल । 12 तुतीकोरिन सिकिल । 13 विरुथुनगर सिकिल । 14 नागरकोइल सिकिल । 15 संपदाशुल्क तथा आयकर सिकिल ।
-----	-------	-------	---

21च	कोडंबतूर	कोडंबतूर	1 कंपनी सिकिल-I, कोडंबतूर । 2 कंपनी सिकिल-II, कोडंबतूर 3 कंपनी सिकिल III, कोडंबतूर 4 कंपनी सिकिल IV, कोडंबतूर 5 कंपनी सिकिल V, कोडंबतूर 6 नगर सिकिल I, कोडंबतूर 7 नगर सिकिल II, कोडंबतूर 8 नगर सिकिल III, कोडंबतूर 9 वेतन सिकिल, कोडंबतूर 10 उटारुमड सिकिल । 11 पोलाची सिकिल 12 तिरुप्पुर सिकिल 13 इरोडे सिकिल 14 कृष्णगिरि सिकिल । 15 कंपनी सिकिल, मलेम । 16 सिकिल, मलेम । 17 सिकिल-II मलेम । 18 संपदा शुल्क तथा आयकर सिकिल, कोडंबतूर ।
21छ	(अन्वेषण)	मद्रास	1 विशेष सर्वेक्षण सिकिल, मद्रास । 2 विशेष सर्वेक्षण सिकिल, मदुरै ।

1	2	3	4	1	2	3	4
		3 विशेष सर्वेक्षण सर्किल, कोडंबपुर ।		21C	Tamil Nadu- IV	Madras	1. Salary Circle-I, Madras. 2. Salary Circle-II, Madras. 3. Refund Circle. Madras. 4. City Circle-V, Madras. 5. Film Circle, Madras.
		4 विशेष सर्वेक्षण सर्किल I, II, और III मद्रास ।					
		5 विशेष सर्वेक्षण सर्किल कोडंबपुर ।		21D	Tamil Nadu-V	Madras	1. City Circle-VI, Madras. 2. Villupuram Circle. 3. Pondicherry Circle. 4. Cuddalore Circle. 5. Nagapattinam Circle. 6. Thanjavur Circle. 7. Kancheepuram Circle. 8. Vellore Circle. 9. Tambaram Circle.
		सह प्रसिद्धता 19-4-82 से प्रभावी होगी ।					
		[सं० 4579/फा० सं० 187/14/82-आई०टी (ए आई)]					
		बी०बी० श्रीनिवासन, सचिव					

(INCOME-TAX)

S.O. 10.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and in partial modification of all previous modifications in this regard, the Central Board of Direct Taxes hereby directs that the Commissioner of Income-tax mentioned in Column (2) of the Schedule annexed hereto shall exercise jurisdiction in respect of such areas or of such persons or classes of persons or of such incomes or classes of incomes or of such cases or classes of cases as are comprised in the Income-tax Circles, Wards or Districts referred to in the column (4) of the said Schedule:

Provided that a Commissioner of Income-tax shall also perform his functions in respect of such persons or of such cases as have been or may be assigned by the Central Board of Direct Taxes to any Income tax Authority subordinate to him;

Provided further that a Commissioner shall not perform his functions in respect of such persons or of such cases as have been or may be assigned to any Income-tax Authority outside his jurisdiction.

SCHEDULE

S. No.	Commissioner Head- of Income-tax quarters	Jurisdiction	
1	2	3	4
21	Tamil Nadu-I Madras	1. City Circle-I, Madras. 2. Foreign Section, Madras.	
21A	Tamil Nadu-II Madras	1. Company Circle-I, Madras. 2. Company Circle-II, Madras. 3. City Circle-III, Madras. 4. City Circle-IV, Madras.	
21B	Tamil Nadu-III Madras	1. ED-cum-IT Circle, Madras. 2. ED-cum-IT Circle, Thanjavur. 3. Company Circle-III, Madras. 4. City Circle-II, Madras. 5. City Circle-VII, Madras. 6. Hundi Circle, Madras.	
21E	Madurai	Madurai	1. Com. Cir., Tiruchirappalli. 2. City Cir. I, Tiruchirappalli. 3. City Cir. II, Tiruchirappalli. 4. Karur Circle. 5. Pudukottai Circle. 6. Karaikudi Circle. 7. Company Circle, Madurai. 8. Madurai Circle. 9. Spl. Cir. Madurai. 10. Dindigul Circle. 11. Tirunelveli Circle. 12. Tuticorin Circle. 13. Virudhunagar Circle. 14. Nagercoil Circle. 15. ED-cum-IT Circle, Madurai.
21F	Coimbatore	Coimbatore	1. Com Cir. I, Coimbatore. 2. Com. Cir. II, Coimbatore. 3. Com. Cir. III, Coimbatore. 4. Com. Cir. IV, Coimbatore. 5. Com. Cir. V, Coimbatore. 6. City Cir. I, Coimbatore. 7. City Cir. II, Coimbatore. 8. City Cir. III, Coimbatore. 9. Salary Circle, Coimbatore. 10. Ootacamund Circle. 11. Pollachi Circle. 12. Tiruppur Circle. 13. Erode Circle. 14. Krishnagiri Circle. 15. Com. Cir., Salem. 16. Circle I, Salem. 17. Circle II, Salem. 18. ED cum IT Cir., Coimbatore. 19. Coimbatore.

1	2	3	4
21G (Investigation) Madras		1. Spl. Survey Cir., Madras. 2. Spl. Survey Cir., Madurai. 3. Spl. Survey Cir., Coimbatore. 4. Spl. Inv. Circles, I, II & III, Madras. 5. Spl. Inv. Circle, Coimbatore	

This notification shall come into force from 19-4-1982.
[No. 4579/F. No. 187/14/82 IT (A)]

V.B. SRINIVASAN, Secy

आर्थिक कार्य विभाग

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1982

क्र०आ० 12- बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबन्ध, एवं वर्ग की श्रौर श्राने की अवधि के लिए श्रानि 29 दिसम्बर, 1983 तक, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, मंगलूर पर उम सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक इनका संबंध, कुंदगोल, जिला-धरवाड़, कर्नाटक से इसके द्वारा 810, 811 और 812 म्यूनिसिपल सख्याओं वाली दुकान तथा टिन के भंडारा सहित दो भूमिगत मकान की अवल सम्पत्ति की धारिता से है।

[संख्या 16/32/82-व० श्राने-11]

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1982

आयकर

क्र०आ० 11- प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 121 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपनी अधिसूचना सं० 4579 तारीख 17-4-82 का निम्नलिखित संशोधन करता है।

कम सं०-21ग और 21घ के सामने स्तभ 4 के नीचे निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी।

क्रम सं०	आयकर आयुक्त	मुख्यालय	अधिकारिता
1	2	3	4
21घ	समिलनाहु-IV	मद्रास	6 कंपनी सर्किल IV मद्रास
21घ	समिलनाहु- V	मद्रास	10 कुंबकोनम सर्किल I

यह आदेश 19-4-1982 से प्रभावी होगा।
[सं० 4592/क्र०सं० 187/14/82-आई टी (ए आई)]
मिलाप जैन, अवर सचिव

New Delhi, the 29th April, 1982

(INCOME-TAX)

S.O.11.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 121 of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to its Notification No. 4579 dated 17-4-82.

The following entries shall be added under Col. 4 against Sl. No. 21 C and 21D.

Sl. No.	Commissioner of Income-tax	Head quarters	Jurisdiction
21C	Tamil Nadu IV	Madras	6, Comp. Circle IV, Madras.
21D	Tamil Nadu V	Madras	10, Kumbakonam Circle.

This order shall take effect from 19-4-1982.

[No. 4592/F. No. 187/14/82 IT (A)]
MILAP JAIN, Under Sec.

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 12.—In exercise of the powers conferred by section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of section 9 of the said Act shall not apply to the Karnataka Bank Ltd., Mangalore, for a further period of one year i.e. upto the 29th December, 1983 in respect of the immovable property of a two storeyed house including shop and tin godowns bearing municipal Nos. 810, 811 and 812 held by it at Kundgol, Dharwar District, Karnataka.

[No. 15/32/82-B.O III]

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1982

क्र० आ० 13.—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्वारा घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (I) और (II) के उपबन्ध 28 जून, 1983 तक की अवधि के लिए केनरा बैंक पर उम सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहाँ तक ये उपबन्ध इसके अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के केरल इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल कन्सल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड, के निदेशक होने पर इसलिए पावदी लगाते हैं कि वह, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अन्तर्गत पंजीकृत एक कंपनी है और (ख) उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के उपबन्ध 28 जून, 1983 तक की अवधि के लिए केनरा बैंक पर उम सीमा तक लागू नहीं होंगे, जहाँ तक ये उपबन्ध उक्त बैंक के केरल इंडस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल कन्सल्टेंसी आर्गनाइजेशन लिमिटेड की शेयर धारिता पर पावदी लगाते हैं।

[संख्या 15/28/82-बी० श्राने II I]

एन० डी० अन्ना, अवर सचिव

S.O. 13.—In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that (a) the provisions of sub-clauses (i) and (ii) of clause (c) of sub-section (1) of section 10 of the said Act shall not apply to Canara Bank for a period upto 28th June, 1983 in so far as the said provisions prohibit its Chairman and Managing Director from being the Director of the Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd., being a company registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and that (b) the provisions of sub-section (3) of section 19 of the said Act shall not apply to Canara Bank for a period upto the 28th June, 1982 in so far as the said provisions prohibit it from holding shares in the Kerala Industrial and Technical Consultancy Organisation Ltd.

[No. 15/28/82-B.O.II]
N. D. BATRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1982

क्र० आ० 14—बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 56 के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और भारत के दिनांक 4 अगस्त, 1979 के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) नई दिल्ली की दिनांक 19 जुलाई, 1979 को सा० आ० सं० 2639 के अधीन प्रकाशित अधिसूचना सं० 8(22) 79—ए० सी० के क्रम में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर एतद्द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 18 और 34 के उपबंध, किसी सहकारी बैंक पर, 20 जुलाई, 1985 तक की और अवधि के लिए वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में इस प्रकार के बैंक द्वारा लिए गए ऋणों अथवा अधिमों के संबंध में उत्पन्न दायित्वों के सदर्भ में सहकारी बैंक द्वारा नकदी प्रारक्षितियों तथा परिसंपत्तियों की प्रतिशतता बनाए रखना आवश्यक है।

वर्तते कि, धारा 18 के अधीन नकद प्रारक्षित की गणना करने वाले उपर्युक्त बैंक द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप धारा (2क) के खण्ड (क) के अधीन रखी गई परिसंपत्तियों की गणना करने में अन्य सभी मांग और समय देयताओं के संबंध में, निगम से लिए गए ऋण के असंवितरित भाग और निगम से लिए गए उधार के संबंध में निगम को प्रेषित न की गई वसूलियों को छाड़ दिया जाएगा।

[संख्या 8-32/82-ए० सी०]
राम बेरा, अवसर सचिव

New Delhi, 10th December, 1982

S.O. 14—In exercise of the powers conferred by Section 53 read with Section 56 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) (hereinafter referred to as the said Act) and in continuation of the title in the Government of India,

Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi under No. 8/(22)/79-AC dated the 19th July, 1979 published at S.O. No. 2639 of the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (ii) dated 4 August 1979, the Central Government, on the recommendation of the Reserve Bank of India, hereby declares that the provisions of sections 18 and 24 of the said Act shall not, for a further period upto 20 July 1985 apply to a co-operative bank insofar as they require the co-operative bank to maintain the percentage of cash reserve and assets respectively mentioned therein in respect of liabilities arising out of the loans or advances availed of by such bank from National Co-operative Development Corporation established by Government of India under the National Co-operative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962):

Provided that in computing the cash reserve under Section 18 and the assets which the said bank maintained under clause (a) of sub-section (2A) of Section 24 respectively of the said Act, in respect of all other demand and time liabilities, the undistributed portion of the loan availed of from the Corporation and the unremitted recoveries to the Corporation on account of the borrowing from the Corporation shall be excluded.

[No. 8-32/82-AC]
RAAM BEHRA, Under Secy.

(आयकर विभाग)

(आयकर आयुक्त का कार्यालय)

कोचीन, 4 दिसम्बर, 1982

क्र० आ० 15.—केन्द्रीय सरकार की राय में धनकर अधिनियम, 1957 की धारा 42-क के अधीन निर्धारितियों का नाम और अन्य विविधियों को प्रकाशित किया जाना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है। अतः आयकर आयुक्त, कोचीन प्रभार में वित्तीय वर्ष 1981-82 में 10 लाख रुपये से अधिक शुद्ध धन पर धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के अधीन कर निर्धारित किये गये निम्नलिखित व्यक्तियों ('ए' से सूचित किया है) और हिन्दू अवैमक्त कुटुंबों ('एच. यू. एफ' से सूचित किया है) के नाम और अन्य विविधियाँ जैसे (1) निर्धारण वर्ष (2) निर्वाचित धन (3) निर्धारित धन (4) कर देय और (5) कर प्रदत्त (सभी रकम रुपये में) एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं।

1. श्री एम० ए० अजित प्रसाद जैन, मनीयूर एस्टेट, कम्पेटीटा 'ए'

(1) 1977-78 (2) 1214000 (3) 1568700
(4) 29315 (5) 29315

(1) 1978-79 (2) 1124800 (3) 1648000
(4) 31451 (5) 31451

(1) 1979-80 (2) 1041500 (3) 1585600
(4) 29214 (5) 29214

(1) 1980-81 (2) पुनरीक्षण/रिट प्यूल नहीं किया है (3) 2000000 (4) 43750
(5) नहीं

2. श्री बर्टन रैट, कुट्टनेलूर 'ए'

(1) 1980-81 (2) 1079500 (3) 1079500
(4) 16135 (5) 16135

3. श्री के० ए० एनियाकुट्टी त्रिषूर 'ऐ'
(1) 1980-81 (2) 1269000 (3) 1337200
(4) 23866 (5) 23866
4. श्री ए० पी० जोर्ज, इरिजालकुडा 'ऐ'
(1) 1981-82 (2) 1195690 (3) 1156800
(4) 18454 (5) 18454
5. श्री ए० बी० गोपालकृष्ण वेणाय, न्यू गुण वेणाय
ग्रान्ट को द्वारा, एरणाकुलम, 'ऐ'
(1) 1977-78 (2) 1059568 (3) 1677800
(4) 32473 (5) 32473
6. श्रीमति ग्लाडिस एस० कोडर, 'ऐ'
(1) 1979-80 (2) 1717000 (3) 1680400
(4) 25941 (5) 26192
(1) 1980-81 (2) 1793400 (3) 1784900
(4) 33298 (5) 32070 और
(1) 1981-82 (2) 2101545 (3) 2094200
(4) 32452 (5) 41690
7. श्री जोस ग्रन्टेणी तुनेवत्, चालकुडी 'ऐ'
(1) 1979-80 (2) 2025000 (3) 2073400
(4) 46320 (5) 46320
8. श्री के० एफ० जोस, त्रिषूर 'ऐ'
(1) 1979-80 (2) 1090000 (3) 1421200
(4) 24280 (5) 24280 और
(1) 1980-81 (2) 1535200 (3) 1720100
(4) 39755 (5) 39755
9. श्री ए० के० कादरकुट्टी, पल्लिकृष्ण बंगसी,
टेल्लिचवेरी 'ऐ'
(1) 1977-78 (2) 1216700 (3) 1239700
(4) 19743 (5) 19743
10. श्रीमति मरियाम्मा कुर्यन, कालरी एस्टेट, मेप्पाडी.
'ऐ'
(1) 1979-89 (2) 937414 (3) 1053200
(4) 14625 (5) 14454
11. 1 श्री सी० पी० माणी, चालिगेरी हाऊस, त्रिषूर
'ऐ'
(1) 1981-82 (2) 1055500 (3) 1055500
(4) 15415 (5) 15415
12. स्वर्गीय श्री के० पी० मोयदीनकुट्टी, के० पी०
एम० कुंजहम्मद के अधिष्ठित उत्तराधिकारी, मन्नारकाट 'ऐ'
(1) 1978-79 (2) 310500 (3) 1198300
(4) 18707 (5) 1291
13. श्री सी० एम० मुहम्मद कासीम, मरुण मंजिल,
चालकुडी, 'ऐ'
(1) 1981-82 (2) 1004100 (3) 1008900
(4) 14107 (5) 14017
14. श्री के० बी० मोहम्मद, अब्दीर तहीरा मंजिल,
करुवनूर 'ऐ'
(1) 1981-82 (2) 1415800 (3) 1415800
(4) 26223 (5) 26223
15. श्री ए० एम० नारायण वेणाय, मैसर्स न्यू गुण
वेणाय ग्रान्ट को, एरणाकुलम 'ऐ'
(1) 1977-78 (2) 687817 (3) 1127440
(4) 16935 (5) 16935
16. श्री एस० एस० नारायणन, एरणाकुलम 'ऐ'
(1) 1981-82 (2) 1407769 (3) 1402800
(4) 25834 (5) 25834
17. श्री नीलिकन्डी कुंजहम्मद हाजी, कलपेट्टा 'ऐ'
(1) 1977-78 (2) 478065 (3) 1567200
(4) 28750 (5) 7500
18. श्री उम्मत पी० कोशी, अलक्साड्रा, एस्टेट, बी०
डिविजन, पडगिरी, 'ऐ'
(1) 1979-80 (2) 1277400 (3) 1217800
(4) 33873 (5) 33873 और
(1) 1980-81 (2) 1023200 (3) 1465800
(4) 25395 (5) 253951
19. श्रीमति एन० टी० सरोजिनी अम्मा, चेलूर विल्ला,
काक्कनाड, 'ऐ'
(1) 1979-80 (2) 783803 (3) 1105606
(4) 16390 (5) 6604
20. श्री एम० मुबैर, हाजी, मारी कुन्नु, कालिकट
'ऐ'
(1) 1981-82 (2) 901800 (3) 1036600
(4) 14665 (5) 11588
21. श्री ए० एम० सुरेश शेणाय, न्यू गुण शेणाय
ग्रान्ट को द्वारा, एरणाकुलम 'ऐ'
(1) 1977-78 (2) 777167 (3) 1248300
(4) 19958 (5) 19958
22. श्रीमति आर स्वर्णम नारायणन, प्रीति, चिट्टूर
रोड, एरणाकुलम 'ऐ'
(1) 1981-82 (2) 1453300 (3) 1387400,
(4) 25372 (5) 25372

23. श्री लोमस पी० काशी, ए०, डिबिजन, पड़गिरि नेल्लियांपती, 'ते'	(1) 1971-72 (2) 500000 (3) 2466700 (4) 78465 (5) —
(1) 1979-80 (3) 1799900 (3) 1810500 (4) 37117 (5) 37117 और	(1) 1972-73 (2) 500000 (3) 1877800 (4) 66244 (5) —
(1) 1980-81 (2) 1513100 (3) 1536700 (4) 27535 (5) 27535	(1) 1973-74 (2) 500000 (3) 1877800 (4) 66244 (5) —
24. श्री ए० एल० वासुदेव शेणाय, न्यू गुण शेणाय ग्रान्ट को, द्वारा. एरणाकुलम 'एच० यू० एफ०'	(1) 1974-75 (2) 500000 (3) 1877800 (4) 66244 (5) —
(1) 1980-81 (2) 700454 (3) 1003200 (4) 23910 (5) 23910	(1) 1975-76 (2) 500000 (3) 1882400 (4) 98184 (5) —
25. श्री बेणुगोपाल बर्मा राजा, कुल्लेनगोड, 'एच. यू. एफ'	(1) 1961-62 (2) 226538 (3) 1585200 (4) 196 (5) —
(1) 1962-63 (2) 501033 (3) 1606900 (4) 1896 (5) —	(1) 1976-77 (2) 500000 (3) 1882400 (4) 98184 (5) — और
(1) 1963-64 (2) पुनरीक्षण रिट फायल नहीं किया है (3) 1707100 (4) 2100 (5) —	(1) 1977-78 (2) 500000 (3) 1934000 (4) 50560 (5) —
(1) 1964-65 (2) पुनरीक्षण रिट फायल नहीं किया है (3) 1702200 (4) 2460 (5) —	26. श्री एम० जे० विजय पद्मन, विजय मंदिरम, कलपेट्टा, 'ते'
(1) 1965-66 (2) 500000 (3) 1679900 (4) 4972 (5) —	(1) 1976-77 (2) 247600 (3) 1469200 (4) 38764 (5) 8000 और
(1) 1966-67 (2) 500000 (3) 1679900 (4) 22098 (5) —	(1) 1977-78 (2) 8334 (3) 1620700 (4) 26974 (5) —
(1) 1967-68 (2) 500000 (3) 1679900 (4) 220 98 (5) —	
(1) 1968-69 (2) 500000 (3) 1 679900 (4) 22098 (5) —	
(1) 1969-70 (2) 500000 (3) 1676600 (4) 25755 (5) —	
(1) 1970-71 (2) 500000 (3) 3425700 (4) 81961 (5) —	

[सी० सं० 212/82-83 आर०]

जी० आर० पटवर्धन

आयकर आयुक्त

(Income-tax Department)

Office of Commissioner of Income-Tax

Cochin, the 4th December 1982

S.O. 15.—Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to publish under section 42A of the Wealth-tax Act, 1957 the names and other particulars relating to the following individuals (indicated by 'I') and Hindu Undivided Family (indicated by 'H.U.F.') who have been assessed under the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) on net wealth exceeding Rs. 10 lakhs, in the Charge of the Commissioner of Income-tax, Cochin, during the financial year 1981-82, such particulars like (i) Assessment year, (ii) Wealth returned, (iii) Wealth assessed, (iv) Tax payable, (v) Tax paid (all amount in rupees) are hereby published:

1. Sri M.A. Ajit Prasad Jain, Maniyur Estate, Kalpetta 'I'

(i) 1977-78	(ii) 1214000	(iii) 1568700	(iv) 29315	(v) 29315
(i) 1978-79	(ii) 1124800	(iii) 1648000	(iv) 31451	(v) 31451
(i) 1979-80	(ii) 1041500	(iii) 185600	(iv) 29214	(v) 29214 &
(i) 1980-81	(ii) R/W not filed	(iii) 2000000	(iv) 43750	(v) Nil.

2. Sri Bartan Wright, Kuttinelloor 'I'				
(i) 1980-81	(ii) 1079500	(iii) 1079500	(iv) 16135	(v) 16135
3. Sri K.A. Elakutty, Trichur. 'I'				
(i) 1980-81	(ii) 1269000	(iii) 1337200	(iv) 23865	(v) 23866
4. Sri A.P. George, Irinjalakuda. 'I'				
(i) 1981-82	(ii) 1195690	£(iii) 1156300	(iv) 13454	(v) 13454
5. Sri A.V. Gopalakrishna Shenoy, C/o. New Guna Shenoy & Co., Ernakulam. 'I'				
(i) 1977-78	(ii) 1059568	(iii) 1677800	(iv) 32473	(v) 32473
6. Mrs. Gladys S. Koder. 'I'				
(i) 1979-80	(ii) 1717000	£(iii) 1680400	(iv) 25941	(v) 26192
(i) 1980-81	(ii) 1793400	(iii) 1784900	(iv) 33298	(v) 32070 &
(i) 1981-82	(ii) 2101545	£(iii) 2094200	(iv) 43452	(v) 41690
7. Sri Jose Antony Thulevath, Chalakudy. 'I'				
(i) 1979-80	(ii) 2025000	(iii) 2073400	(iv) 46320	(v) 46320
8. Sri K.F. Jose, Trichur. 'I'				
(i) 1979-80	(ii) 1090000	(iii) 1421200	(iv) 24280	(v) 24280 &
(i) 1980-81	(ii) 1535200	(iii) 1720100	(iv) 39755	(v) 39755
9. Sri A.K. Kaderkutty, Pallicon Bungalow, Tellicherry. 'I'				
(i) 1977-78	(ii) 1216700	(iii) 1239700	(iv) 19743	(v) 19743
10. Mrs. Mariamma-Kuriën, Coleric Estate, Mepoadi. 'I'				
(i) 1978-79	(ii) 937414	(iii) 1053200	(iv) 14625	(v) 14454
11. Sri C. P. Maney, Chalissery House, Trichur. 'I'				
(i) 1981-82	(ii) 1055500	(iii) 1055500	(iv) 15415	(v) 15415
12. Late, Sri K. P. Moideenkutty, by L/HK. P.M. Kunjahamed, Mannarghat. 'I'				
(i) 1978-79	(ii) 310500	(iii) 1198300	(iv) 18707	(v) 1291
13. Sri C.M. Mohamed Kassim, Maroon Manzil, Chalakudy. 'I'				
(i) 1981-82	(ii) 1004100	(iii) 1008900	(iv) 14017	(v) 14017
14. Sri K.V. Mohamed Zakir Thahira Manzil, Karuvannur. 'I'				
(i) 1981-82	(ii) 1415800	(iii) 1415800	(iv) 26223	(v) 26223
15. Sri A. S. Narayana Shenoy, M/s New Guna Shenoy & Co., Ernakulam. 'I'				
(i) 1977-78	(ii) 687817	(iii) 1127440	(iv) 16925	(v) 16935
16. Shri S. S. Nayayanan, Ernakulam. 'I'				
(i) 1981-82	(ii) 1407769	(iii) 1402800	(iv) 25834	(v) 25834
17. Sri Neelikandi Kunhamed Hari Kalpetta. 'I'				
(i) 1977-78	(ii) 478065	(iii) 1567200	(iv) 28750	£(v) 7500
18. Sri Oommen P. Koshy, Alexandra Estate, B. Division, Padagiri. 'I'				
(i) 1979-80	(ii) 1277400	(iii) 1217800	(iv) 33873	(v) 33873 &
(i) 1980-81	(ii) 1023200	(iii) 1465800	(iv) 25395	(v) 25395
19. Smt. N. T. Sarojini Amma, Cheloor Villa, Kakkanad. 'I'				
(i) 1979-80	(ii) 783803	(iii) 1105605	(iv) 16390	(v) 6604
20. Sri M. Subair Haji, Marikunnu, Calicut. 'I'				
(i) 1981-82	(ii) 901800	(iii) 1036600	(iv) 14665	(v) 11588
21. Sri A. S. Suresh Shenoy, C/o. New Guna Shenoy & Co., Ernakulam 'I'				
(i) 1977-78	(ii) 777167	(iii) 1248300	(iv) 19958	(v) 19958

22. Smt. R. Swarnam Narayanan, Preethi, Chittoor Road, Ernakulam. 'I'

(i) 1981-82 (ii) 1451300 (iii) 1387400 (iv) 25372 (v) 25372

23. Sri Thomas P. Koshy, A. Division, Padagiri, Nelliampathy, 'I'

(i) 1979-80 (ii) 1799900 (iii) 1810500 (iv) 37117 (v) 37117 &
(ii) 1980-81 (ii) 1513100 (iii) 1536700 (iv) 27535 (v) 27535

24. Sri A. L. Vasudeva Shenoy, C/o. New Guna Shenoy & Co., Ernakulam 'HUF'

1980-81 (ii) 700454 (iii) 1003200 (iv) 23910 (v) 23910

25. Sri Venugopala Varma Raja, Kollengode, 'HUF'

(i) 1961-62	(ii) 226538	(iii) 1585200	(iv) 196	(v) —
(i) 1962-63	(ii) 501033	(iii) 1606900	(iv) 1896	(v) —
(i) 1963-64	(ii) R/W not filed	(iii) 1707100	(iv) 2107	(v) —
(i) 1964-65	(ii) R/W not filed	(iii) 1702200	(iv) 2460	(v) —
(i) 1965-66	(ii) 500000	(iii) 1679900	(iv) 4972	(v) —
(i) 1966-67	(ii) 500000	(iii) 1679900	(iv) 22098	(v) —
(i) 1967-68	(ii) 500000	(iii) 1679900	(iv) 22098	(v) —
(i) 1968-69	(ii) 500000	(iii) 1679900	(iv) 22098	(v) —
(i) 1969-70	(ii) 500000	(iii) 1679900	(iv) 25755	(v) —
(i) 1970-71	(ii) 500000	(iii) 3425700	(iv) 81961	(v) —
(i) 1971-72	(ii) 500000	(iii) 2466700	(iv) 78465	(v) —
(i) 1972-73	(ii) 500000	(iii) 1877800	(iv) 66244	(v) —
(i) 1973-74	(ii) 500000	(iii) 1877800	(iv) 66244	(v) —
(i) 1974-75	(ii) 500000	(iii) 1877800	(iv) 66244	(v) —
(i) 1975-76	(ii) 500000	(iii) 1882400	(iv) 98184	(v) —
(i) 1976-77	(ii) 500000	(iii) 1882400	(iv) 98184	(v) —
(i) 1977-78	(ii) 500000	(iii) 1934000	(iv) 50560	(v) —

26. Sri M. J. Vijaya Padman, Vijayamandiram Kulpetta, 'I'

(i) 1976-77 (ii) 247600 (iii) 1469200 (iv) 38764 (v) 8000 &
(i) 1977-78 (ii) 8334 (iii) 1620700 (iv) 26974 (v) —

Ernakulam, Cochin-16.

[C. No. 212/82-83/R]

G. R. PATWARDHAN,
Commissioner of Income Tax, Cochin

4.12.82

Dated : ————

13.9.904

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

भाषण

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1982

कां०भा० 16.—यतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के भेदन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नों के क्रय, भण्डारकरण, संवर्धन, परिवहन, वितरण तथा विक्रय के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जोकि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य हैं।

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के भेदन तथा लेखा कार्यालयों में कार्य कर रहे और उपरिवर्जित कृत्यों के पालन में लगे निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियों ने केन्द्रीय सरकार के तारीख 16 अप्रैल, 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उसमें विनिर्दिष्ट तारीख के अन्तर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी न बनने के अपने आग्रह को उक्त अधिनियम की धारा 12 ए के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है।

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्न-

लिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के सामने दी गई तारीख से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है :

क्रम सं०	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	केंद्रीय सरकार के अधीन स्थायी पद	स्थानान्तरण के समय केन्द्रीय सरकार के अधीन पद	भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण की तारीख
----------	----------------------------	----------------------------------	---	--

1	2	3	4	5
1.	श्री ए०पी० मलिक	तकनीकी अधिकारी	सहायक निदेशक (तकनीकी)	30-12-70
2.	श्री एन०एन० मुखर्जी	तकनीकी सहायक	तकनीकी अधिकारी	1-3-69
3.	श्री माया राम सुपुल श्री शंकर दत्त	—	वाचमैन	1-3-69

[सं० 52/1/82-एफ०सी०-III]

प्रार०के०सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1982

S.O. 16 —Whereas the Central Government has ceased to perform the function of purchase, storage, movement, transport, distribution and sale of foodgrains done by the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food which under Section 13 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) are the functions of the Food Corporation of India.

And whereas the following officers and employees serving in the Department of Food, the Regional Directorates of Food, the Procurement Directorates and the Pay & Accounts Offices of the Department of Food and engaged in the performance of the functions mentioned above have not, in response to the circular of the Central Govt. dated the 16th April, 1971 intimated, within the date specified therein, their intention of not becoming employees of the Food Corporation of India, as required by the proviso to Section 12 A of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 12 A of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) as amended upto date, the Central Government hereby transfers the following employees to the Food Corporation of India with effect from the date mentioned against each of them :—

Sl. No.	Name of the Officer/employees	Permanent post held under the Central Govt.	Post held under the Central Govt. at the time of transfer	Date of transfer to FCI
1	2	3	4	5
1.	Shri A. P. Malik	Technical Officer	Asstt. Dir. (Tech.)	30-12-70
2.	Sh. N.N. Mukherjee	Technical Asstt.	Tech. Officer	1-3-69
3.	Sh. Maya Ram S/o Shri Sitanker Dutt	—	Watchman	1-3-69

[No. 52/1/82-FC-III]
R.K. SINGH, Dy. Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982

का०आ० 17—केंद्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण से निम्नलिखित दूरदर्शन केंद्रों को जिनके कर्मचारियों के हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है:—

1. दूरदर्शन रिले केंद्र, बंगलूर,
2. दूरदर्शन केंद्र, जयपुर,
3. दूरदर्शन केंद्र, कानपुर,
4. दूरदर्शन केंद्र, नागपुर,
5. दूरदर्शन केंद्र, बम्बई।

[सं० ई-11011/5/82-हिन्दी]
इन्दु भूषण कर्ण, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 17—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following Doordarshan Kendras, the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Doordarshan Relay Centre, Bangalore.
2. Doordarshan Kendra, Jaipur.
3. Doordarshan Kendra, Kanpur.
4. Doordarshan Kendra, Nagpur.
5. Doordarshan Kendra, Bombay.

[No. E-11011/5/82-Hindi]
I. B. KARN, Under Secy.

श्रम तथा पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० भा० 18.—विना ट्रेड विंग्स लिमिटेड, 30, के० दुबाश मार्ग फोर्ट, बम्बई-23, (महाराष्ट्र/5064), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उप-धारा (2A) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निषेध सद्बन्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं;

एतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, मेसार्सों का भ्रष्टरण, निरीक्षण प्रसारों का संवाय आदि की है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी नक़ल बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पक्ष है, उसका स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुरस्कृत करेगा और उसकी बाइन स वयस्क प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम अधीन होगा, तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिभूत के रूप में दोनों रकमों के अन्तर की बराबर रकम का संवाय करेगा।

1085 GI/82 3

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सके, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को स्वयंभूत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वृत्ति में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को भी यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होती, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके वृत्तिकार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक वृत्ति में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के साथ-साथ निम्न के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/380/82-पी०एन-2]

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

New Delhi, 6th December, 1982

S.O. 18.—Whereas Messrs Trade Wings Limited, 30, K. Dubash Marg, Fort, Bombay-23, (MH/5064) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Link Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, &c.

accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall make prompt payment of the sum assured to the nominee/ heirs entitled for it and in any case within 7 days of receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(380)/82-P.F. II]

कॉ. का. 19--मेम्बरों में से किसी एक को मृत्यु के कारण होने वाले, केंद्रीय गवर्नर, डॉ. एनी बेन्टन रीड, एम.एस. 100015 (महाराष्ट्र/ 11/89) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी श्रमिक निधि और प्रकीर्ण उपग्रह अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के तहत छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

श्रीर केंद्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिनियम या प्रविष्टि का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निधि की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधि सहित बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुमति है।

अतः केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय अनुकूल में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपधाराओं के प्रयोग से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक प्राधिकार मानव्य निधि अनुसूची, महाराष्ट्र का ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केंद्रीय सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास का समाप्ति के 15 दिन के भीतर उदाहरण करेगा जो केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम में प्रशासन में, जिसके अनन्त लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संचय, लेखाओं का संतुलन, निरीक्षण प्रभारों का संचय आदि की है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य भाषा का अनुवाद, स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी श्रमिक निधि का वह उक्त अधिनियम के तहत छूट प्राप्त किसी स्थापना की श्रमिक निधि का पट्टे ही सदस्य है, उक्त स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम दर्ज करेगा और उक्त श्रमिक निधि प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निधि को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपग्रह फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपग्रह फायदों में संशोधन रूप से छूट दी जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपग्रह फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमति हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी स्टाफ के हानि हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस स्कीम से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के घटकर के बराबर रकम का भुगतान करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम में उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रदीर्घ क भविष्य विधि आयुक्त, महा 1972 के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक सचिव, प्रादेश आयुक्त, प्रादेश अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दुर्लक्षण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुना है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तरीके के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम तैयार करे, प्रीमियम का भुगतान करने में, असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है, तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के भुगतान में किए गए किसी व्यक्ति-कर्म की दशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम के प्रभुगत होती, बीमा फायदों के भुगतान का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का भुगतान तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के साथ ही के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस० 35014/272/82-टी०एफ०- II]

S.O. 19.—Whereas Messrs Centuary Spinning and Manufacturing Company Limited, Centuary Bhawan, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400025 (M.L./4269), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and Provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme, the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(272)/82-PF II]

क्रा० अ० 20.—मैसर्स अमर निर्माण वर्क्स, ग्वालिघेर (मध्य प्रदेश 1800), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त

अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिनियम या प्रोविडेंट फंड का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ने फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभोग्य हैं ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए और इससे उपायय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, मध्य प्रदेश की ऐसी विवरणियां भेजगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उन संशोधनों की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुका बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुरस्त दर्ज करेगा और उनकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधीन उपलब्ध फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभोग्य हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधीन सन्देश रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस वृत्ति में संवेद्य होती जब वह उक्त स्कीम के प्रधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का सदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदित के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, प्रपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों का अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना हुआ है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में समर्थ रहता है, और पालिसी का व्यवगत हो जाने दिया जाता है ता, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में उक्त स्थापन के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रधीन होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक ब्या में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014/289/82-पीएफ-11]

S.O. 20.—Whereas Messrs Amar Knitting Works, Gwalior (MP/1800) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is liable to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(289)/32-PF. II]

का०आ० 21- मैसर्स सीडल्स इण्डस्ट्रिज (इण्डिया) लिमिटेड, नोडल इण्डस्ट्रिज (कॉन्ट्रोल) 643743 (नॉनगिरोज) (नॉनलनाडु/551), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपकरण अधिनियम, 1952 (1952 का 19), (जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हा गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पुराने अधिनियम या प्रीमियम या संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उक्त फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुभूत हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाययत अनुमति में विनिश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुमति

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भा.उ.व्य. निधि आयुक्त, लखनऊ, को ऐसी विवरणियां भेजेंगी और ऐसे विवरण रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक ऐसी निरीक्षण प्रवृत्ति का प्रत्येक भाग की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खण्ड (ब) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासक या, जिसके अन्तर्गत योजनाओं का चलाया जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, गृहस्थों का अन्तर्गत, निरीक्षण प्रवृत्ति के सदाय सहायक हैं, होने वाले सभी व्यय का बहुत नियोजक द्वारा उचित जांचा जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा 111 अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचनापत्र पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त दिनों स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्वयंसे में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम गुरुरत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगत करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उक्त फायदों में अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु या इस स्कीम के अधीन सदस्य रहना उस समय से कम है, जो कर्मचारी का उक्त स्कीम में सदस्य होता है, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के अधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिफल के रूप में देना स्कीमों के अन्तर्गत के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भा.उ.व्य. निधि आयुक्त, लखनऊ के पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और जहां जहां संशोधन से कर्मचारियों के लिए परावृत्त प्रभाव पड़ेगा या संभावित हो सकेगा प्रादेशिक भा.उ.व्य. निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देना से पूर्ण कर्मचारियों को सन्तोषजनक स्वरूप करने का युक्तियुक्त प्रयत्न देगा।

9. यदि किन्हीं कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त स्कीम में बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन द्वारा प्रदायित है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी स्कीम से कम हो जाते हैं, तो यह छूट खत्म की जा सकती है।

10. यदि उक्त अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन स्कीम का प्रावधान है, तो बीमा निगम द्वारा प्रीमियम का संदाय करने अवकाश रहता है और कर्मचारियों की व्यवस्था हो जाने बिना उक्त छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय के लिए या किसी स्थापना की वशा में उन मूल जल्दियों के उत्तरदायित्वियों या विधिक कार्रवाई का या यह कुछ न की गई होती तो उस स्कीम के अंतर्गत हानि, नुकसान या क्षति के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी उत्तरदाय की मृत्यु होने पर उसकी हकदार मांग निर्दिष्टितो/विधिक कार्रवाई का बीमाकृत स्कीम का संदाय सहायता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत स्कीम प्राप्त होने के मांग किए के अंतर्गत सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/290/82-पीएफ II]

S.O. 21.—Whereas Messrs Needle Industries (India) Ltd., Needle Industries, Post Office Nilgiris-643243 (TN/354) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section, (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that

would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(290)/82-PF. II]

कॉ० आ० 22.—मैसर्स नाइल इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई प्लॉट, आर्ले मिन्का हाउसिंग, गौरीगंज ईस्ट, बम्बई-65 (महाराष्ट्र/18357) जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी प्रविध्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अन्तर्गत छूट दिए जाने के लिए याचना किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी, जिसमें पूर्णक अतिरिक्त या प्रीमियम का संदाय किया जाता है, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम में अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए कायदे उन कायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अन्तर्गत उठे अनुमति है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इससे उपाय अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्षों के अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रयोजन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक प्रविध्य निधि अधिनियम, महाराष्ट्र (बम्बई) की ऐसे दिशानिर्देशों में होगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसे सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, काल-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निराकरण प्रचारों का प्रत्यक्ष मास की म.प्र.पि के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रिय सरकार, उसका अधिनियम या धारा 17 की उपधारा (3A) के खण्ड (क) के अधीन समकालीन पर निविष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम को प्रभावित में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रमियम का, संदाय, लेखाओं का भ्रमण, निरीक्षण प्रचारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत निर्यातक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्य की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षा बर्त करेगा और उसकी बाबत आदेश्यक प्रतियोग भारतीय जीवन बीमा नियमों को संबल करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदों उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुशेष हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु या इस स्कीम के अधीन सदस्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उम्र तथा में सदस्य होता, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के तरावर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करेगा का व्यक्तिगत अवसर होगा।

9. यदि किसी कारणवश, रवाना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा नियमों को उस सामूहिक बीमा स्कीम के बिना स्थापन पहले अपना चुका है अर्थात् नहीं रहे जाते हैं, या इस स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट नहीं दी जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत मारीज के संभार, जो भारतीय जीवन बीमा नियमों के अन्तर्गत, प्रमियम का संदाय करने में असमर्थ रहता है, और पालिसी को अन्तर्गत हो जाने दिया जाता है तो छूट नहीं दी जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रमियम के संदाय में किन्हीं व्यक्तियों की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों की जो यदि यह, छूट नहीं गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के अन्तर्गत में नियोजक, उस स्कीम के समान आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके ज़रूरत नाम निर्देशितों/

विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा नियमों से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तत्त दिन के अन्तर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एन० 35014/325/82 पी०एफ०-2]

S.O. 22—Whereas Messrs Modern Bakeries (India) Limited, Bombay-Unit, Aarey Milk Colony Gortgaon East, Bombay-65 (MH/18357) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the payable under this scheme be less than the amount which would be payable had the employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(325)/82-PF. II]

का० आ० 23.—मैसर्स पीको इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड एलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 'ए० शिवसागर एस्टेट, डाक्टर अन्नी बेसन्त रोड, वर्ली, बम्बई-18 (महाराष्ट्र/9599) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिषेक या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे अपने उक्त फायदों से अधिमान्कूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहायक बीमा कीम, 1976 (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाययुक्त सूचनाओं में विनिश्चित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन का प्रदत्त किए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देते हैं।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, (1-7-82) को लेखी निवेदनियों से ज्ञेय और ऐसे लेखों रखे गए तथा उनके लिए ऐसे सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय विज्ञापित करे।

नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मान की समाप्ति के त्रि मासिक अवधि करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 7 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर करे।

सामूहिक बीमा स्थापन के प्रशासन में, जिसके प्राथमिक लेखाओं का, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, अन्तरण, निरीक्षण प्रभावों का संदाय आदि भी हैं, होने, व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए, तब उपसंशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में, उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रकाशित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उक्त फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्धि रकम उस रकम के कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृत्तिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चित अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असमर्थ रहता है, और फालिसों की व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कदार नाम निर्देशितियों विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तत्पश्चात् के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस 35014/321/82 पी० एफ-11]

S.O. 23.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals Limited, A. Shivasagar Estate Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18, (MH/9599) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution of payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the

Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Bombay, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and here any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employers under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(326)/S2-PF. II]

कां.प्र. 24—मैसर्स पीको इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने मॉडल रोड, मेजगाव, बम्बई-400010 (महाराष्ट्र/5101) (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) से कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिवास या प्रीमियम का संचालन (ग्रुप) बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निर्जप मंडल बीमा स्कीम 1978 (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा, (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और हमने उदाहरण अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के तहत उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आगत महापत्र को ऐसी विवरणियां भेजना और ऐसे लेखा रजिस्टर तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करना जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रवेश नाच की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाव करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17-की उपधारा (3क) के अंतर्गत (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संचालन, शिखारों का धारण, निरीक्षण प्रसारों का भंडारण आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उचित संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का बहुतांश की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सचिव-महोदय पर प्रेषित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहलू ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तविक भावपूर्ण प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संचालित करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जागेई का पता करेगा (जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन मंजूर रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में मंजूर होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशित को प्रतिशत के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का भुगतान करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किमा संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या उस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी सीमा से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को स्वयंसेवक हो जाने दिए जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिकर की दशा में, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशनियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशनियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तत्पश्चात् के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[नं० एम-35014/334/82-पी० एफ०-II]

S.O. 24.—Whereas Messrs Peico Electronics and Electricals Limited Nesbit Road, Mazgaon, Bombay-400010 (MH/5104) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(334)/82-PF, III]

कां० बा० 25—महेश एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड इण्टरनेशनल ट्रेडर्स डिवीजन, इम्प्लाइज को-ऑपरेटिव बैंकर्स सोसाइटी लिमिटेड, कॉम्प्यूटरी ईस्ट बम्बई-400001 (महाराष्ट्र/11705), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म-कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही,

भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निधेय सहवर्द्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें हमने पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभवेय है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभवेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है

अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/335/82-पी० एफ-II]

S.O. 25.—Whereas Messrs Mahindra & Mahindra Limited International Tractors Division, Employees' Co-operative Canteen Society Limited, Kandivli East, Bombay-40001 (MH/11705) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme

appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that, the benefits available under the Group Insurance Scheme are more valuable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(335)/82-PF.II]

क्रां० 26.—मैसर्स मधु मिलन स्पष्टेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, आगरा बम्बई रोड, देवास-455001 (मध्य प्रदेश/3387) (जिसे इस में इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखा

तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक साल की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रचारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कामें उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश्य रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सदस्य में नियोजक, उस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दिष्टियों/विविध शर्तों की विसंगति रकम का संशय तात्पर्य से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मुनिबित्त करेगा।

[संख्या: एस-35014/33C/82-पीएफ-II]

S.O. 26.—Whereas Messrs Madhu Milan Syntex (P) Limited, Agra Bombay Road, Dewas (MP/3287) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any contribution on payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(33C)/82-PF.II]

कां आ 27- सैमर्प जलत महकरी बैंक लिमिटेड, रायसे बिनिङ्ग, महारष्ट्र नगर, फार्म-116416 (रायसे/15467) (जिसे हमने हमको पश्चात् उक्त स्थापन कहा है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अतिदाय या प्रीमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिये ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप महबूब बीमा स्कीम 1976 (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुशेष हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायक अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सदस्य में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महारष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समान समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिनके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की अनुसूची की तालिका में उसकी मुख्य शर्तों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य-निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त एवं बरगो और उम्मीदवान आवश्यक प्राविश्य भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंप करेगा।

6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ा जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक प्रत्युत्पन्न हों, जो उक्त स्कीम के अधीन प्रत्युत्पन्न हैं।

7 सामूहिक बीमा स्कीम व किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी का मृत्यु इस स्कीम के अधीन सन्त्येय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्दिष्टता या प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा, और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनु-साधन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनि-युक्त अवसर देगा।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को जब सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नही रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी गति से कम हो जाते हैं, तो छूट छूट रह की जा सकती है।

10 यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के अन्तर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में धमकाने रहता है और पालिसी का व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिरिक्त की दशा में उस मृत सदस्य के नामनिर्दिष्टियों या विधिक वारिसों को जो यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के संघ में नियोजक, इस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दिष्टियों/विधिक वारिसों की बीमाहृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाहृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/337/8-बी०एफ०-11]

S.O. 27.—Whereas Messrs Janta Sahakari Bank Limited, Karale Building, Mahabir Nagar, Sangli-416416 (MH/15467) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities of inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(337)/82-PF. III]

का० भा० 28 -मोटर इण्डस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड, 75, एम० आर्डी. ई० गी० एस्टेट मिम्बर रोड, सतपुर नासिक-42300 (महाराष्ट्र, 1905), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभोग्य हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्राबुक्त, महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समसमय पर निदिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रश्नों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवद करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-धसय पर निदिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्वयण, निरीक्षण प्रश्नों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पत्र पर प्रकाशित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम शुरू करेगा और उसकी वास्तव प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवद करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपबन्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपबन्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपबन्ध फायदे उन फायदों के अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभोग्य हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी घात के होने हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन गन्तव्य रकम उस स्कीम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संवद होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिभार के रूप में दोनों स्कीमों के अन्तर्गत के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्राबुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्राबुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चयन अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की इस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पत्रों द्वारा अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी गति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में दिए गए किसी व्यक्तिगत की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन घाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[संख्या एस-35014(338)/82-पी०एफ०-II]

S.O. 28.—Whereas Messrs Motor Industries Company Limited, Nasik Division, 75, M.I.D.C. Estate, Satpur, Nasik (MH/12053), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(338)/82-PF. II]

क्र० आ० 29 - मैसर्स फेडर (इंडिया) लिमिटेड, 19/21, मनोहर दास स्ट्रीट, डाकघर बाक्स 1307, बम्बई-1 (महाराष्ट्र/14526), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 10) (जिसे इसमें

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उक्त स्थापन के अधीन रहने के लिए स्वीकृत किया है) के धारा 17 की उपधारा (2क) के अन्तर्गत छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समझाना हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिनियम या प्रविण्य का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश सहायक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) के अन्तर्गत उन्हें अनुकूल है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपलब्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत रहते हुए, उक्त स्थापन को तत्त बर्ष को अन्तर्गत के लिए उक्त स्कीम के अन्तर्गत उक्त स्थापन के प्रयोजन से छूट देने का फैसला है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र (बम्बई) को ऐसी विवरणियाँ भेजनी और ऐसे लेखा रकबों तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करनी, जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अन्तर्गत समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय प्रादिकृति है, होने वाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रकाशित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों को उक्त फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में सम्मिलित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अन्तर्गत अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अन्तर्गत नन्देय रकम उन रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में गंदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अन्तर्गत होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामानिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त यह राजपत्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किस संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुनिन्युक्त अवसर देगा।

9 यदि किन्तु कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम के उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अर्धन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अर्धन कर्मचारियों को प्राप्त होता है, तो फायदे किस रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द हो जा सकता है।

10 यदि किस कारणवश, नियोजक उस नियत तारखे के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रमियम का सदाय करने में अप्रकृत रहता है, और पालिसा को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द हो जा सकता है।

11 नियोजक द्वारा प्रमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिरिक्त का दशा में उन मृत सदस्यों के नागरिकनिधियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होता तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12 उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक, इस स्कीम के अर्धन आने वाले किम सदस्य के मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एम- 35014/348/82-पीएफ-II]

S.O. 29—Whereas Messrs Fenner (India) Limited 19/21, Marchand Street Post Office Box 1307 Bombay-1 (MH/14526) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable than the benefits admissible under the Life Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme including maintenance of accounts, submission of returns payment of insurance premia, transfer of a group's payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

1085 GI/82—5

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled

10 Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled

11 In case of default if any made by the employer in payment of premium etc the responsibility for payment of a sum assured to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heir within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S 35014(348) 82 PF II]

कां० आ० 30—मैसर्स फेनर इण्डिया लिमिटेड (शेड टू एन्प्लॉईड) जिला पूणे, डा० अर वलचन्दनगर-413114 (महाराष्ट्र राजा) (मह/91/4) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2A) के अधिन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का समधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रमियम का सदाय किए बिना हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अर्धन जीवन

बीमा के रूप में पायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारियों विशेष सहकारी बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अर्थात् उन्हें अनुमति है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (2क) द्वारा प्रयत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाययुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को उक्त शर्तों की अवधि के लिए उक्त स्कीम में सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राथमिक सविष्य विधि प्रावधान, महाराष्ट्र (बम्बई) का ऐवत विधायिका सेवेया और ऐसे सेवा सेवेया तथा निरोक्षण के लिए ऐव सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समयसमय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सहाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत से, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का उदा आवा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का संदाय, सेवाओं का अन्तर्गत, निरोक्षण प्रभावों का संदाय आदि की है, होने वाले सभी व्ययों का सदा नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों का बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी सविष्य विधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किया स्थापन की सविष्य विधि का पड़ते हैं। सहाय है, उनके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम पुराने बने करेगा और उक्त स्कीम के अन्तर्गत प्रीमियम भारतीय बैंक बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमति हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सहाय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस बात से संदेय हुआ, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्दिष्ट को प्रतिकर के रूप में बीमा रकमों के अन्तर्गत बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्राथमिक सविष्य विधि प्रावधान महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्राथमिक सविष्य विधि प्रावधान, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को उक्त दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुविशेष अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय बैंक बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना

अनुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रद्द का जा सकता है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय बैंक बीमा निगम नियत करे, प्राथमिक का संदाय करने में असफल रहता है, और पात्रों को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द का जा सकता है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययिक्त्य का वडा, ये उन मृत सदस्यों के नामनिर्दिष्टों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य का मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दिष्टियां/विधिक वारिसों का बीमाकृत रकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय बैंक बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के बाद दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/349/82-पी.एफ. II]

S.O. 30.—Whereas Messrs Walchandnagar Industries Limited, (Motor Transport), District Pune, Post Office Walchandnagar-413114, (Maharashtra State), (MH/9124), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended, alongwith a translation of the salient portions thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol

1. as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(349)/82-PF. II]

का० आ० 31---मैसर्स प्रीमियम पावर केबल्स लिमिटेड, नरेश हाऊस, 34-छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, बम्बई-39, (महाराष्ट्र/18099), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्राचीन उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार ने समाधान हो गया है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी, किसी पृथक भविष्य या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष सहवर्द्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूते हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (2क) द्वारा प्रस्ताव शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट बातों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापना को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रयोजन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र का ऐसा विवरणित योजना और रीति योजना रखेगा तथा निरक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास का समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का भंडार, सेवाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभावों का सदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का उक्त नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रतिलिपि, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या का भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उक्त नम दुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाधत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूते हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देश रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी की उस दशा में संवेद्य होना, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों की प्रतिकार के रूप में दोनों रकमों के दक्षत के दरावर रकम का संवाह करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का मुक्ति-युक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापना के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इन स्कीम के अधीन कर्मचारियों की प्राप्त होने वाले फायदे किसी राशि से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारखे के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का भंडार करने में सफल रहता है, और पात्रता की व्यवस्था हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उक्त मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों की

जा याद वह पट न दा गे हाता ता उता स्कान क अनात हाते, बामा फायदा क सदाय का उपलब्धताय नियाजक पर हाता ।

12 उक्त स्थापन क सवध मे नियाजक, इस स्कान के अधन आते बरा इता सदस्य क मृत्यु हान पर उसक हकदार नाम निदाशताया/विधायक बाराता का बनाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्यक दशा मे नारताय जावन बमा नियम से बनाकृत रकम प्राप्त हान के सात दिन के भतर सुनाश्चित करेगा ।

[सख्य एस- 35014/372/82-पाएफ-11]

31—Whereas Messrs Oriental Power Cables Limited, Narang Road, 14, Chhatrapati Shivaji Maharaj Marg, Bombay 39, (P.M. 10099), hereinafter referred to as the said establishment have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act),

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme),

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1 The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2 The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3 All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4 The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5 Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6 The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7 Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8 No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9 Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under the Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10 Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11 In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S 35014(372)/82-PF II]

का० आ० 32 -मैरात ट० के० स्टल द्वा रूज (पट्टे, लिमिटेड, एम० आई० ड० सी०, प्लॉट न० 7, ड 1 बॉय, चन्दाड पूना-19 (नहाराष्ट्र/15871), (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्थापन, कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रवण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 का उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

और केन्द्रीय सरकार का साक्षात् हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रमियम का सदाय किए बिना ही, भारतीय जवन बामा नियम की सामूहिक बमा स्कम के अधन जवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारी के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहवद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुजेय है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपबद्ध अनुसूच में निर्दिष्ट शर्तों के अधन रूटे हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष का अवधि के लिए उक्त स्कम के सभ उपबन्धों का प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1 उक्त स्थापन के सवन्ध मे नियाजक प्रादेशिक भविष्य निधि अथवा, मा० राज्य के से विवरणिया भेजेग और तेरे लेखा रखेगा तथा निरक्षण के लिए ऐस सुविधाएं प्रदान करेग जा केन्द्रिय सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2 नियोजक, ऐसे निरक्षण प्रभागों के प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रिय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन मे, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बमा प्रमियम का सदाय, लेखाओं का अन्तरण, निरक्षण प्रभागों का सदाय आदि भा है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा प्रभावित समूहिक बंसा स्कीम के निम्नलिखित प्रति, श्रीम जय कर्मा उक्त संघोषित किया जाये, तब उस संघोषित का प्रति तथा कर्मचारियों को बहुगुणा के भाषा में उनकी सुगम उतों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पत्र प्रस्तुत करेगा।

5. यदि कोई भी कर्मचार, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधिन छूट प्राप्त किसी स्थापन का भविष्य निधि का पहले है, स्वयं है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक समूहिक बंसा स्कीम के सदस्य के रूप में अपना नाम उक्त दर्ज करेगा और उक्त बाबा अवश्यक प्रमाण भारत में जन्म बंसा निगम को सौंप करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों का उक्त फायदे बढ़ाए जाने हैं तो, नियोजक समूहिक बंसा स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे में सुविधा के रूप में बूट का जन्म का व्यवस्था करेगा जिसे कि कर्मचारियों के लिए समूहिक बंसा स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध फायदे उन फायदे से अधिक माफ़ा है, जो उक्त स्कीम के अंतर्गत अनु-जय है।

7. समूहिक बंसा स्कीम में किसे बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी का मृत्यु पर इस स्कीम के अंतर्गत दाता स्कीम उस स्कीम से कम है, जो कर्मचारी को उस दाता में उक्त दाता, जब दाता स्कीम के अंतर्गत होता तो, नियोजक कर्मचारी के विभिन्न परिस्थितियों को प्रतिफल के रूप में दाता स्कीमों के अंतर्गत के बरकरार स्कीम का संवाद करेगा।

8. समूहिक बंसा स्कीम का उक्त स्कीमों में बाई रॉ संघोषित, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त समूह के पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा और जहां कि संघोषित से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के संभावना हो, बहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनु-मादन देने में पूर्व कर्मचारियों को अपना सुविधागत स्पष्ट करने का सुवि-मुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस समूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पड़ने अपना चुका है अंतर्गत नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे हितों से कम हो जाते हैं, या यह छूट रहे की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम भारतीय के अंतर्गत, जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जारी, प्रीमियम का संवाद करने में अपना रहता है, श्रीम पालिसी को व्यक्त हो जाये किता जाता है तो, छूट रहे की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम का संवाद में किसे समूहिक व्यक्ति का दशा में उन मृत सदस्यों के परिवारिकों या निरंतर वारिसों को जो यदि यह छूट न हो हानि जा उक्त स्कीम के अंतर्गत हानि, बंसा फायदे के संवाद का उत्तरदायित्व नियोजक पर होता।

12. उक्त स्थापन के संवाद में नियोजक, इस स्कीम के अंतर्गत जाने खरीदने, सदस्य का मृत्यु होने पर उक्त स्कीम का निधिगतियों/विधिक दायित्वों का बीमागत स्कीम का संवाद न्याय से श्रीम प्रत्येक दशा में भारतीय, जय बंसा निगम से बीमागत स्कीम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या 35014/373/82-प्रा.प.क.11]

S.O. 32—Whereas Messrs T. K. Steel Industries (Private) Limited, MIDC, Plot No. 7, D-1 Block, Chinchwad, Poona-19. (MII/15871) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premium, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employee, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of insurance benefits to the nominees or the legal heirs of

deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(373)/82-PF. II]

का० आ० 33.—वैसाय इण्डियन एलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड 1, मिडिल्टन स्ट्रीट, कलकत्ता-71, (पश्चिम बंगाल/5137) और उसकी 39-जी०टी०रोड, बेलूर मठ, हावड़ा, (पश्चिम बंगाल/185) पर स्थित कारखाना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट देने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का संतोधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् भविष्य या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा नियम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उत फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष सहस्रक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभोग हैं ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इनमें उपररक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट बातों के धर्मीय रहते हुए, उक्त स्थापन की तीन वर्ष की अवधि के लिए स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल की ऐसी विवरणियाँ भेजना और ऐसे लेखा रखेना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करना जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की सहायता के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके धनार्जन लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभावों का संवाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जावेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित-सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की जापान से उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रसारित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के धर्मीय छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बातों आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा नियम की संवाय करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के धर्मीय कर्मचारियों

को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के धर्मीय उपलब्ध फायदे उस स्वीकृति से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के धर्मीय अनुभोग है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उस स्कीम के अधीन संवाय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी का उस वक्ता में संवेद होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता था, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों की प्रतिकर के रूप में बाकी रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन ने कर्मचारियों के हित पर पक्षपात प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को सूचना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चित अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा विभाग की या सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुना है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इन स्कीम के धर्मीय कर्मचारियों का प्राप होने वाले फायदे किसी स्कीम से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उक्त नियम शीर्षक के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा विभाग नियम करें, प्रीमियम का संवाय करने का प्रयत्न करता है, और पश्चिम का संवाय हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रशासन की सहायता के लिए गए किसी व्ययार्जन की दशा में उन मूल सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों का जो यदि यह छूट न हो गई होती तो उक्त स्कीम के अधीन होते, बीमा फायदों के संवाय के उपबन्धों के अधीन रह जावेगा ।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक इन स्कीम के धर्मीय होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उक्त स्कीम के निर्देशितियों/विधिक वारिसों की संवाय रकम का संवाय व्यवस्था से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा विभाग से बाकी रकम प्राप्त होने के साथ दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[No. एन-35014/373/82-बी० एक-II]

S.O. 33.—Whereas Messrs Indian Aluminium Company Limited, 1, Midleton Street, Calcutta-71 (WB/RE-5137) and its Factory at 39, G. T. Road, Belur Math, Howrah, (WB/185) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the SCHEDULE annexed hereto the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heir entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

कॉ० भा० 34—मैमर्स सुशील फेडरलिटर्स, 33/ए, इण्डस्ट्रियल एस्टेट, गान्धिवपुर, कोलकाता-46:10:13, (मध्य प्रदेश/2055), जिसे इसमें उचित वर्गीकरण उचित स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रबंधन उपायधन अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उचित वर्गीकरण कहा गया है) को धारा 17 की उपधारा (2क) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है;

श्रीर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किर्मा पृथक् श्रमिक या प्रामाणिक का संघर्ष किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कार्य करते हुए और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उक्त फायदों से अधिक प्रमुख हैं जो कर्मचारी निधि राहत बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसमें उचित वर्गीकरण कहा गया है) के अधीन उन्हें प्रदानित है,

यह, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायधन अनुसूची में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के मातृ उपधर्मा के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राविधिक भविष्य निधि अनुसूचित मध्य प्रदेश को ऐसी निरीक्षण या भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रश्नों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के अन्दर सत्यापन करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत, उनके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, निरीक्षणों का प्रत्येक मास करना, बीमा प्रामाणिक का संवाह, निरीक्षण या अन्यथा, निरीक्षण प्रश्नों का सत्यापन आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत निरीक्षण द्वारा किया जायेगा।

4. निरीक्षण, केन्द्रीय सरकार द्वारा यदा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों के अन्तर्गत, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को अनुसूची की भाषा में उनकी मुख्य भाषा का अनुवाद स्थापन के मुख्यालय पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि बोर्ड ऐसा करने में, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अन्तर्गत छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम मुरत दर्ज करेगा और उसकी वास्तविक प्रामाणिक भारतीय जीवन बीमा निगम को सत्यापन करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों या उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उस फायदों से अधिक अनुसूचित हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुसूचित हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राकम उस राकम से कम है, जो कर्मचारी का उस वृत्ति में संदेय होती, अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशित को

प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी समोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त मंत्र प्रवेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संगठन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारियों, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पढ़ने अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असमर्थ रहता है, और पालिसी को व्यंग्यत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दो गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होती, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर मुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस० 35014/375/82-पी०एफ० II]

S.O. 34.—Whereas Messrs Sushil Fabricators, 33/A, Industrial Estate, Govindpura, Bhopal-462023, (MP/2055) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(375)/82-PF. III]

क० अ० २५-- मैसर्स सुशिल फैब्रिकेटर्स का० अ० काठकोट मैनफैक्चरिंग कार्पोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड, 17-18 पोखराउड्ड, इन्दौर-3 (मध्य प्रदेश-16491), (जिसे इसमें इसके पश्चात् ज्वलन रक्षागण धारा 8(1) के अंतर्गत भविष्य निधि और पक्षीय उपस्थापन समिति, 1952 (1952 का 10) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ज्वलन रक्षा अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए प्रावेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारियों, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष महबूब बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्राप्ता, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा के अधीन—उक्त के अधिनियम, मुद्रा, मुद्राएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार,

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्राप्ता, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुद्राएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रधारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत सेवाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, सेवाओं का प्रवर्तन, निरीक्षण प्रधारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पत्र पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित करेगा और उसकी बायत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों के अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारिख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययक्रम की दशा में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारिख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्ययक्रम की दशा में उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के तत्पश्चात् 15 दिन के भीतर निदिष्ट करेगा।

[संख्या एस-35014(338)/82-सी०एफ०-II]

S.O. 28.—Whereas Messrs Motor Industries Company Limited, Nasik Division, 75, M.I.D.C. Estate, Satpur, Nasik (MH/12053), (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India, in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium to within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(376)/82-PF. II]

का० शा० 36 वैयर्थ बोपडा इन्डियन सेल्स कारपोरेशन, बी०-66 नारायणा इण्डियन एरिया, फेस-7 नई दिल्ली-110028 (दिल्ली-2235), (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी पब्लिक निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का. 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पब्लिक प्रविधाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहायक बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हीं अनुज्ञेय हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इससे उपार्जित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रदर्शन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक पब्लिक निधि प्रायुक्त, नई दिल्ली को ऐसी विवरणियाँ भेजना और ऐसे लेखा रखा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करने का जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रभावों में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्वयण, निरीक्षण प्रभावों का संवाय आदि भी हैं; होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अनुसूचित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों को एक प्रति, और जब कभी उन्हें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन का प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी पब्लिक निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की पब्लिक निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम नुस्खे दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन गारंटी रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के पत्रिक वारिस/नामनिर्देशिता को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के तत्पर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक पब्लिक निधि प्रायुक्त, नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक पब्लिक निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृत्तिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त हुए फायदे 15वीं दिनांक से कम हो जाते हैं, तो वह छूट रह ही जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर या भारतीय जीवन बीमा निगम तत्पर करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्ययगत का ज्ञान दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रतिनिधिम के सदस्य ने किए गए किसी व्यक्तित्व की वशा में उन भुक्त भवनों के नाम निर्दिष्टियों या निधिगत धारियों का जो यदि यह छूट नहीं दी गई होती तो उक्त स्कीम के प्रयोग के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के सतत का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के तत्पश्चात् में नियोजक, इस स्कीम के अधीन प्राप्त होने वाली किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्दिष्टियों/निधिगत धारियों का नामांकित स्कीम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक वशा में भारतीय जनता बीमा निगम से नामांकित स्कीम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/378/82-पीएफ-II]

S.O. 36.—Whereas Messrs Chopra Electrical Sales Corporation, B-65 Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110023 (DLI/2235) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, along with a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme as soon as the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme is less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(378)/82-PF. II]

का० आ० 37—मैसर्स इण्डिया पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड, डाक बक्स नं० 3490 5 संज, वैजारी रोड बाजार-14 (फनडिक-3657), (जिसे हमने इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपकरण अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी नृषक अभिदाता या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की नाभूतिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में काफ़ी उका रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष सहस्र बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्षों की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, फनडिक (कर्मचारी) को सेवा विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संशोधन करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर विधिष्ठ करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत सेवाओं का रखा जाता, धिवरधियों का प्रस्तुत किया जाता बीमा प्रीमियम का संदाय, सेवाओं का प्रसारण, निरीक्षण प्रसारों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी सविध्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की सविध्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम दुरुस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में नमूदित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों में अधिक आनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होने हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संबंधित रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी का उस वृत्त में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता था, नियोजक कर्मचारी के विधिक धारि/नाम निर्देशित को प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक सविध्य निधि आयुक्त, कर्नाटक (बंगलूर) के पूर्व अनुमोदित के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक सविध्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी की व्यवगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रह की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम का संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की वृत्त में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक धारि/नामों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होती, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु पर होने वाले इकट्ठा नाम निर्देशितियों/

विधिक धारि/नामों का बीमाकृत रकम का संदाय उत्तरदा से और प्रत्येक वृत्त में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सत दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस 35014/379/82-पा०एफ०-11]

5.0. 37.—Whereas Messrs India Packaging Products (Private) Limited, Post Box No. 2480, 5th Mile, Bellary Road, Bangalore-24 (KIN/3657) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka (Bangalore) maintain, such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Karnataka (Bangalore) and where any amendment is likely to affect

adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain under their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(379)/82-PF. II]

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1982

कां० आ० 38.—मैसर्स खण्डेयवाल फेरो अलॉयज लिमिटेड, डाकघर-खण्डेयवाल नगर जिला, नागपुर-441402 (महाराष्ट्र/8658), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं, जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायुक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रभर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र, का ऐसी शिवरथिया भेजेगा और ऐसे सेवा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा या केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निराकरण प्रकारों का प्रत्येक मास की संपाति के 15 दिनों के भीतर सदाशु करेगा या केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के अन्तर्गत में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गत, निरीक्षण प्रकारों का सदाशु गारि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का सदस्य ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम का संदाशु करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्वेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को बतौर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाशु करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देना से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाशु करने में असफल रहता है, और पालिती को व्यवस्त हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम का संदाशु में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों की ओर यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाशु का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संदाशु तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के साथ हीन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/484/82-पी०एफ०-11]

New Delhi, the 9th December, 1982

S.O. 38.—Whereas Messrs Khandelwal Ferro Alloys Limited, P.O. Khandelwal Nagar, District Nagpur-441402 (M. 8658) (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under sub-section (2A) of section of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976, (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already opted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life

Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(284)/82-PF. II]

का० आ० 39 -मैसर्स 'एल्फर्टिन्स इमालाईज एन्ड कंस्ट्रक्शन्स लिमिटेड', 20/4, सुबुरा राड, फर्रुखवाड (हरियाणा) 8 (पञ्जाब/46/81), जिसे इसमें द्वाकें पञ्चायत उक्त स्थापन हुआ गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें द्वारकें पञ्चायत उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् नमिदाय या प्रीमियम का संभावित बिना हो, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रयोग के बिना बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे फायदे उन फायदों से अधिक अनुभूत हैं जो कर्मचारी विदेश मन्त्रालय बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें द्वारकें पञ्चायत उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है ;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और इस उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भाषण विधि प्रायुक्त पञ्जाब (हरियाणा) की ऐसी विवरणियां प्रेषण और ऐसे लेख रखे जायें निरीक्षण के लिए ऐसी पुविधार् प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय समय पर निरिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रसारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (35) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निरिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसमें प्रत्येक निर्यात का रखा जाता, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाता, बीमा प्रीमियम का रकम, जवाबों या प्रस्ताव, निरीक्षण प्रसारों का सदाय प्रादि भी है, द्वारकें वाले सदस्यों का बहुत निरीक्षण द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा पेशा अनुमानित नृहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उदयें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति हमें कर्मचारियों की अनुसूची में लाया में उसकी मुख्य शर्तों का अनुवाद स्थापन के सूचना-बोर्ड पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किया स्थापन की भविष्य निधि का फायदे हो सम्भव है, उसके स्थापन में निर्यात किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित रखे करेगा और उसकी बायत सावधान्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उल्लेख फायदे बढ़ा जाते हैं ता, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में संपूर्ण रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उल्लेख फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमति हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उक्त स्कीम के अधीन सदैव एकम उस स्कीम में कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता था, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्दिष्टता को प्रतिकर के रूप में दानों एकम के अंतर के बराबर एकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र बल्बई के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जावेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सके, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्रस्ताव वृत्ति-होण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त प्रस्ताव देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्वयं के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्वयं पक्ष अपनाना चाहते हैं, अथवा उसी स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति में कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निम्न तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम निश्चित करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पारिशों को व्ययगत हो जाने विमा जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्दिष्टियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्कीम के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्कदार नाम निर्दिष्टियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत एकम का संदाय तत्पश्चात् से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत एकम प्राप्त होने के तत्पश्चात् के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एन-35014/30/82-प्रीव फंड-II]

S.O. 39.—Whereas Messrs Escorts Employees Ancillaries Limited 20/4, Mathura Road, Faridabad (Haryana) (PN/4628) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto

the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab (Haryana), maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab (Haryana) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who, would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment

shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(302)/82-PF II]

का०आ० 40 - मैसर्स अमिनेज एण्ड प्लास्टिसिजर्स लिमिटेड, "डी" बिल्डिंग शिव सागर एस्टेट, डाक्टर अरुण बसन्त रोड, वर्ली, बम्बई-18 (महाराष्ट्र/14187) जिसे हमने इसमें पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) जिसे हमने इसमें पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए वे कायदे, उन कायदों में अधिकतम सुविधा है जो कर्मचारी निवेश सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 (जिसे हमने इसमें पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन लगे अनुज्ञेय है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए और हमने उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे देखा रहेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रचारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रचारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कमो कम में संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद; स्थापन के सूचना-रद्द पर प्रेषित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरक्षित दर्ज करेगा और उसकी वास्तविक आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध कायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध कायदे उन कायदों से अधिकतम सुविधा हो, जो उक्त स्कीम के अधीन उपलब्ध हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता, तो नियोजक कर्मचारी के विधवा वारिस/नामानिर्देशितों को प्रतिफल के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त महाराष्ट्र, के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना व्यक्तिगत स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उक्त सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तरीके के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को ब्यवगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधवा वारिसों को जो यदि यह, छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन होने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उनके हकदार नाम निर्देशितों विधवा वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के मात धिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/410/82-पी०एफ० II]

S.O. 40.—Whereas Messrs Aminees and Plasticizers Limited, "D" Building Shiv Sagar Estate, Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay-18 (MH/14187) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

3. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund, of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra (Bombay) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No S-35014(410)/82-PF. III]

कांसा 41 - मैमर्न डेरेलमेन्ट कन्सल्टेन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, 74-वीं, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-16, (पश्चिम बंगाल/13709), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और एकीकृत उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें 1085 GI/82-7

यके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है,

आर केन्द्रीय सरकार का तात्पर्य हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किन्तु पृथक अधिनियम या प्रत्यक्ष कानून द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के तहत जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निगम म्यूचुअल बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है,

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उल्लेख अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को नोट 7 की शर्तों के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रवर्तन में छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजित प्रादेशिक मानक अधिनियम द्वारा पश्चिम बंगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार समान समय पर निदिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का पत्रिका मास की मर्यादा के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खंड (क) के अधीन मर्यादित पर निदिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संचय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमति प्रदत्त सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्यकों को भाषा में उनकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारियों भविष्य निधि का था उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन को भविष्य निधि का पड़ने ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तव आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को सदातः करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संचय रकम उन रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संचय होनी, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिवत वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त पश्चिम बंगाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँकहीं संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकर प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन

बने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का यत्न करना आवश्यक होगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के जिन स्थापन पहले अपना चुका है, प्रवीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अर्हता कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उन निम्न तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करें प्रोविडेंट का मदद करने में प्रयत्न करता है और पालिसी को अयत्न हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रोविडेंट के संवत्स में किए गए किसी व्ययक्रम की दशा में उन मूल मददों के लाभार्थियों या अधिकारियों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत होने, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक इन स्कीम के अर्हता प्राप्त करने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्धारितियों, अधिकारियों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के साथ-साथ के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस-35014/416/82-पी०एफ०-II]

S.O. 41.—Whereas Messrs Development Consultants (Private) Limited, 24-B, Park Street, Calcutta-16 (WB/13709) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(416)/82-PF. II]

का० अ० 42.—मैसर्स डेवलपमेंट (इण्डिया) लिमिटेड, नं० 26, कमाण्डर-इन-चीफ रोड, मद्रास-600108 (नमिल नाडू/5394), जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी अधिकार विधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक प्रतिभाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष सहयोग बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत हैं;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएँ प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संवाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रभारी का सहाय्य आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का, बहुत नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रकाशित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी वास्तविक अवधिगत प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संबर्तन करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वृत्ति में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियम तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियम करे, प्रीमियम का संवाय करने में असमर्थ

रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिगत दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं० एस०-35014/418/82-पी० एफ०-11]

S.O. 42.—Whereas Messrs Ponds (India) Limited, No. 26, Commander-in-Chief Road, Madras-600108, (TN/5394) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act (10 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of salient features thereof, in the language the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enroll him as a member of the Group Insurance Scheme and necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits available under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Tamilnadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014(418)/82-PF. II]

का० आ० 43 - मेमर्स टो० टी० इन्स्टीट्यूट ऑफ़ ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, पोस्ट बाका नं० 51, बल्लभ रोड, (यूनिट टैन्टेक्स, तंजावुर) तंजावुर, (तमिलनाडु-6839) (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक् प्रीमियम या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में कायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये कायदे न कायदा से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सञ्चय बीमा स्कीम, 1976 (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें सुंभेय है;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (क) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपा-धनसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के नीचे छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि त तमिलनाडु को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा उन के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरोक्षण प्रभावों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 धारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरोक्षण प्रभावों का संदाय आदि भी हैं, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम मुरस्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदाय करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि का जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है, जो कर्मचारी को उस वक्ता में संदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त तमिलनाडु के पूर्ण अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो सता, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना वृत्तिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं ता वह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस निया तारीख के अंतर्गत, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी का व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गए किसी व्यतिश्रम की वक्ता में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर हाता।

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्काार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक वक्ता में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[संख्या एस०-35014/283/82-पी० एफ०-2]

S.O. 43.—Whereas Messrs T. I. Investments and Trades Private Limited P.B. No. 52, Vallam Road, (Unit Tante, Manjavar), Manjavar (IN/6839) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc shall be borne by the employers.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their points of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S. 35014(283)/82 PF. II]

कॉ० आ० 44 मैत्रे कोमट एगिटा विनिटेड, पेरुगुडा राम-96 (निम्न नं०/1905) पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी विधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे उपधारा (2क) के उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की इससे इसके पश्चात् अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किम् पृथक अधिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही भारतीय जीवन बीमा निगम की समूहिक बीमा स्कीम के अर्थात् जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी विशेष सहकारी बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हे अनुमति है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपरान्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के समान उपबन्धों के प्रयोजन से छूट देती है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्राथमिक विषय निधि अनुसूची (निर्माण) की ऐसी शिखरिका सेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुद्रिकाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निश्चित करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रवारा का प्रत्येक काम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निश्चित करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रकाशन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, शिखरिकाओं का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तर्गण, निरीक्षण प्रवारा का संदाय आदि की है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदन सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उसमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की सूची के साथ ही साथ उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पत्र पर प्रकाशन करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी विधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त की स्थापन की विधि का पढ़े हैं। समस्या है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम मुरतब करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संश्लेष करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बराबर जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जायेगी की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमति हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अर्थात् संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अर्थात् होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुनिश्चक अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिससे स्थापन पहले अपना कृपा है अर्थात् नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के अर्थात् कर्मचारियों का प्राप्त होने वाले फायदे किम्वं राशि से कम हो जाते है, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पाविसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है, तो, छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में, उन मूल सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को जो, यदि यह छूट न की गई होती तो उक्त स्कीम के अर्थात् होते, कोमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संवध में नियोजक, इस स्कीम के अर्थात् जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के साथ बित के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[नं० एस०-35014/287/82-पी०एफ०३]

S.O. 44.—Whereas Messrs Facit Asia Limited, Perungudi, Madras-96 (TN/4805) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Link Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employers.

4. The employer display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas the employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Tamil Nadu and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

का० आ० 45 - मैसर्स युनिट्रॉन लिमिटेड, 1-2, इण्डस्ट्रियल एरिया एन० आर० टी० फरीदाबाद (हरियाणा) (पंजाब/238), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, किसी पृथक अधिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहकर बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुभूत है ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसने उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा (चंडीगढ़) को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत् करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुभूत हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संवेद्य रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संवेद्य होती, अब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा (चंडीगढ़) के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्तिक्रम की वशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्पराता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

[सं० एस-35014/408/82-पी एफ-2]

S.O. 45.—Whereas Messrs Unitron Limited, 1-2, Industrial Area, N.I.T. Faridabad, (Haryana) (PN/238) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contributions or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana (Chandigarh), maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including Maintenance of accounts, sub-

mission of return, payment of insurance premium, transfer of assets, payment of taxation charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and as and when amended alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Haryana (Chandigarh) and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced to any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Life Insurance Corporation of India and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would, have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014 (408)/82-PF. III]

गौर केन्द्रिय सरकार का सम्बन्ध है कि उन स्थापन के अंतर्गत, निम्न सूचीबद्ध या प्रविश्य मामलों के अंतर्गत जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निवेश मंत्रालय बीमा स्कीम 1952 (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उठाने अनुमति है,

अतः केन्द्रिय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसके उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट बातों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देता है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक विविध विधि आयुक्त, हैदराबाद, को ऐसी विवरणियां भेजना और ऐसा लेखा रखना तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करनी जो केन्द्रिय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रारंभों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेंगे जो केन्द्रिय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 का उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रवर्तन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रारंभों का संदाय आदि है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रिय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुमुखी कोषों में उसकी सुझावों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी विविध विधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन का विविध विधि का पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजन किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेंगे और उसके बाद आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेंगे।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेंगे जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुमति है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती। जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वरिष्ठ/मनिफेस्टी की प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेंगे।

कां० सं० 46 ---मैसर्स इण्डियन उस्म एण्ड फार्मोस्युटिकल्स लिमिटेड, पोस्ट आफिस गालानगर/नजिफ, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश/3107), (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी विविध विधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे हमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, हैदराबाद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुचितयुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है छोड़न नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के छोड़न कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संवाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संवाय में किए गए किसी व्यक्तिकर की वशा में, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक कार्रियों को जो, यदि यह छूट न हो जाती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होती, बीमा काबजों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के छोड़न जाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हक्काार नामनिर्देशितियों/विधिक कार्रियों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक वशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा।

[सं०एस-35014/419/82-पी०एफ-2]

S.O. 46.—Whereas Messrs Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited, Post Office Balanagar Township, Hyderabad (AP) 3107) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme for a period of three years.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Hyderabad, maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

1085 GI/82—8.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heirs/nominees of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Hyderabad and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

[No. S-35014/419/82-PF.II]

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1982

New Delhi, the 8th December, 1982

का० प्रा० 47.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 2143, तारीख, 9 अगस्त, 1974 को अधिक्रान्त करते हुए, गुजरात राज्य के लिये एक क्षेत्रीय समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

अध्यय :

1. सचिव, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त
श्रम और रोजगार विभाग,
सचिवालय, गांधीनगर।

सदस्य :

2. उप सचिव,
श्रम और रोजगार विभाग,
सचिवालय, गांधीनगर।
3. वित्तीय सलाहकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
सचिवालय, गांधीनगर।
4. श्री रजनीकान्त आर० नागरी,
प्रबन्ध निदेशक,
नागरी मिल कं० लिमिटेड
अहमदाबाद।
5. श्री बी० बी० पटेल,
इंगरसोल रेन्ड इण्डिया,
जी० आई० डी० सी०,
नरोदा, अहमदाबाद।
6. श्री जयन्तीलाल एम० शाह,
गुजरात चेम्बर आफ कामर्स
एण्ड इण्डस्ट्रीज,
पी० बाक्स नं० 4045,
रणछोड़ लाल मार्ग,
अहमदाबाद।
7. श्री अरविन्द भाई डी० दावे,
अहमदाबाद मिल मजदूर युनि-
यन, खानपुर गेट के सामने,
अहमदाबाद।
8. श्री मंगलदास एस० पटेल,
जनरल सेक्रेटरी,
टैक्सटाईल लेबर युनियन,
नादियाड।
9. श्री समीर मनसूरी,
मंत्री,
केमिकल मजदूर सभा,
फतेपुरा,
याकूतपुरा के पास,
वादीदारा।

राज्य सरकार की सिफारिश
पर केन्द्रीय सरकार द्वारा
नियुक्ति दो व्यक्ति

राज्य में कर्मचारियों के
संगठन के परामर्श से केन्द्रीय
सरकार द्वारा नियुक्त कर्म-
चारियों के प्रतिनिधि।

S. O. 47.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. S.O. 2143, dated the 9th August, 1974, Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Gujarat consisting of the following persons, namely:

Chairman :

1. Secretary,
Labour and Employment
Department, Sachivalaya,
Gandhinagar

Appointed by the Central
Government

Members :

2. Deputy Secretary,
Labour and Employment
Department, Sachivalaya,
Gandhinagar
3. Financial Adviser,
Labour and Employment
Department, Sachivalaya,
Gandhinagar
4. Shri Rajnikant R. Nagari,
Managing Director,
Nagari Mill Co. Limited,
Ahmedabad.
5. Shri B.B. Patel,
Ingarol Rand India, GIDC,
Naroda, Ahmedabad.
6. Shri Jayantilal M. Shah,
Gujarat Chambers of Com-
merce and Industries, Post
Box No. 4045, Ranchhodlal
Marg, Ahmedabad
7. Shri Arvindbhai D. Dave,
Ahmedabad Mill Majdoor
Union, Opposite Khanpur
Gate, Ahmedabad.
8. Shri Mangaldas S. Patel,
General Secretary,
Textile Labour Union,
Nadiad.
9. Shri Samir Mansoori,
Mantri,
Chemical Majdoor Sabha
Fatepura,
Near Yakutpura,
Vadodara

Two persons appointed by the
Central Government on the
recommendation of the
State Government.

Three representatives of
employers appointed by
Central Government in
consultation with organi-
sations of employers in the
State.

[No.V-20012/(2)/78-PF-II]

का० प्रा० 48.—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 4 के उप-पैरा (1) के अनुसरण में और भारत सरकार के तत्कालीन श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० प्रा० 1052, तारीख 22 मार्च, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, बिहार राज्य के लिये एक क्षेत्रीय समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्—

अध्यय :

1. सचिव एवं आयुक्त,
बिहार सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
पटना।

केन्द्रीय सरकार द्वारा
नियुक्त।

सदस्य :

2. श्रम आयुक्त,
बिहार सरकार,
श्रम और रोजगार विभाग,
पटना । राज्य सरकार की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त दो व्यक्ति
3. संयुक्त सचिव,
बिहार सरकार,
श्रम और रोजगार,
पटना ।
4. श्री ओ० पी० अदुक्रिया,
महासचिव,
मैसर्स न्यू इण्डिया शुगर मिल्स
लिमिटेड,
डाकघर हमन पुर शुगर मिल्स,
(बिहार शुगर मिल्स एसोसिएशन)
जिला समस्तीपुर,
बिहार । राज्य में नियोजकों के संगठनों के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नियोजकों के तीन प्रतिनिधि ।
5. श्री सी० एस० सिंह,
वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी,
मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एंड
लोकोमोटिव कं० लि० (बिहार
इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन), एम-
31, श्री कृष्णनगर, पटना-800001.
6. श्री एस० सी० जैन,
महाप्रबन्धक, रोहतास इण्डस्ट्रीज
लिमिटेड,
अभय भवन, फासर रोड,
(बिहार चेम्बर आफ कामर्स),
पटना-800001
7. श्री जी० बी राघवन,
हिन्द मजदूर सभा,
माईका लेबर यूनियन,
डाकघर गिरिडीह,
जिला हजारीबाग, बिहार । राज्य में कर्मचारियों के संगठनों के परामर्श से नियुक्त कर्मचारियों के तीन प्रतिनिधि ।
8. श्री शंभू शरण सिंह,
महासचिव,
फटीलाईजर फैक्टरी वर्कर्स यूनियन,
(इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन, कांग्रेस,
एल-594, सहरपुरा, सिन्दरी
(धनबाद)
9. श्री राज किशोर प्रसाद मिह,
सचिव,
बिहार स्टेट कमेटी आफ आल इंडिया
ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 4, नारायण
मार्केट, लंगर टोली, पटना-800504.

[संख्या बी-20012/8/78-पी० एफ० 2]

ए०के० भट्टराई, अवसर सचिव

S.O. 48.—In pursuance of sub-paragraph (1) of paragraph 4 of the Employees' Provident Fund Scheme 1952 and in supersession of the notification of the Government of India in late Ministry of Labour No. S.O. 1052 dated the 22nd March, 1975, the Central Government hereby sets up a Regional Committee for the State of Bihar consisting the following persons:—

Chairman.

1. The Secretary and Commissioner to the Government of Bihar, Department of Labour and Employment, Patna. Appointed by the Central Government

Members :

2. Labour Commissioner, Government of Bihar, Patna. } Two persons appointed by the Central Government on the recommendation of the State Government.
3. The Joint Secretary to the Government of Bihar, Department of Labour and Employment, Patna. }
4. Shri O.P. Adukia, General Secretary, M/s. New India Sugar Mills Ltd., P.O. Hisanpur Sugar Mills, (Bihar Sugar Mills Association), District Samastipur, Bihar. } Three representatives of employers, appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employers in the State.
5. Shri C.S. Singh, Senior Executive Officer, M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., (Bihar Industries Association), M-31, Shri Krishna Nagar, Patna-800001.
6. Shri S.C. Jain, General Manager, Rohtas Industries Ltd., Abhay Bhawan, Fraser Road, (Bihar Chamber of Commerce) Patna-800001.
7. Shri G.V. Raghavan, Hind Mazdoor Sabha, Mica Labour Union, P.O. Giridih, District Hazaribagh, Bihar. } Three representatives of employees appointed by the Central Government in consultation with the organisation of employees in the State.
8. Shri Shambhu Saran Singh, General Secretary, Fertilizer Factory Workers' Union, (Indian National Trade Union Congress,) L-594, Saharpur, Sindri, (Dhanbad).
9. Shri Rajkishore Pd. Singh, Secretary, Bihar State Committee of All India Trade Union Congress, 4, Narain Market, Langertoli, Patna-800004.

[No. V. 20012/8/78-PF. III]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० आ० 49—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 34 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त इसके द्वारा, इस विभाग की दिनांक 6-12-82 की अधिसूचना नं० 1(19)/विशेष सैल 82 एम० एस० 11 द्वारा बन्दोबस्त आयुक्त के रूप में नियुक्त तमिलनाडु सरकार के राजस्व विभाग में सयुक्त सचिव (पुनर्वास) तथा उपसचिव (पुनर्वास) का प्रशासनिक तथा वित्तीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत तमिलनाडु सरकार को

हस्तांतरित मुआवजा पूल की समस्त अर्जित निष्कान्त सम्पत्तियों के निपटान के लिये तत्काल प्रभाव से उक्त अधिनियम के नियम 87, 88, 90 (1) (क) 90 (ख) 90 (11) 90 (12) और 101 के अधीन अपनी शक्तियाँ सौंपते हैं।

सं० 1(19)/वि(विवेचन)/82-ए. स. एस. 11ख
एस० के० बसु, मुख्य बन्दोबस्त आयुक्त

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 49.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 34 of the Displaced persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954 (44 of 1954), the Chief Settlement Commissioner hereby delegates to the Joint Secretary (Rehabilitation) and Deputy Secretary (Rehabilitation) as the case may be, in the Revenue Department, Government of Tamilnadu, appointed as Settlement Commissioner vide Notification No. 1(19)/Spl. Cell/82-SS. II(A) dated the 6th December, 1982, his powers under rule 87, 88, 90(1)(a), 90(1)(b), 90(11), 90(12) and 101 framed under the said Act for the purpose of disposal of all acquired evacuee properties forming part of compensation pool, transferred to the State Government of Tamil Nadu, under administrative and financial arrangements with immediate effect.

[No. 1(19)/Spl. Cell/82-SS. II(B)]

S. K. BASU, Chief Settlement Commissioner

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1982

का० आ० 50—केन्द्रीय सरकार ने यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (VI) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं० का आ० 2271 तारीख 7 जून, 1982 द्वारा दिल्ली मिल्क स्कीम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 जून, 1982 से छः मास की कालावधि के लिये उपयोगी सेवा घोषित किया था।

और केन्द्र सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त कालावधि को छः मास की ओर कालावधि के लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (द) के उपखण्ड (VI) के परन्तुक द्वारा शक्तियों का प्रयोग का प्रदत्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 23 दिसम्बर, 1982 से छः मास की ओर कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

एल के० नारायणन, अवर सचिव

[संख्या एस 11017/14/81-ए(ए)]

New Delhi, the 14th December, 1982

S.O. 50.—Whereas the Central Government having been satisfied that the public interest as required had, in pursuance of the provisions of sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), declared by the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2271 dated the 7th June, 1982, the Delhi Milk Scheme to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the 23rd June, 1982.

And whereas, the Central Government is of opinion that public interest requires the extension of the said period by a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a further period of six months from the 23rd December, 1982.

[No. S-11017(14)/81-D.I.(A)]

L. K. NARAYANAN, Under Secy.

New Delhi, the 1st December, 1982

S.O. 51.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Engineering Stores Depot, Panagar, and their workmen, which was received by the Central Government on the 24th November, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 36 of 1972

PARTIES :

Employers in relation to the Engineer Stores Depot,
Panagar

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice M. P. Singh, Presiding Officer.

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. K. K. Ganguly, Advocate.

On behalf of Workmen—Mr. D. L. Sen Gupta, Advocate, with Mr Nand Sreemani, Advocate.

STATE : West Bengal

AWARD

By Order No. L-14011/2/71-LRI dated 22nd May, 1972, the then Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, Government of India sent the following dispute to this Tribunal for adjudication :

“(1) Whether the action of the Officer Commanding, Engineer Stores Depot, Panagar in terminating the services of Sarvashri B. R. Ganguly, S. Roy and Kashi Prasad, IMEs with effect from the 15th November, 1971 is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?”

(2) Whether the action of the Officer Commanding, Panagar in transferring Sarvashri N. C. Chakraborty and A. K. Ghatak, Joint Secretary and Treasurer respectively of the Military Engineer Workers Union, Engineer Stores Depot, Panagar from Panagar is justified? If not, to what relief are the workmen entitled?”

2. This reference has come on remand under Order dated 15th July, 1977 passed by the Hon'ble High Court at Calcutta in a writ application No. 3567(W)/73 setting aside the award of Sri S. N. Bhagchi dated May 3, 1973 published in the Gazette of India dated June 2, 1973.

3. So far as the dispute No. (2) relating to the transfer of the Officers mentioned in the Schedule of reference is concerned, it has ceased to exist as stated by both the parties before this Tribunal and hence a 'no dispute' award is passed in respect of dispute No. (2).

4. As regards dispute No. (1) it appears that Messrs B. R. Ganguly, S. Koy and Kashi Prasad were drivers, Mechanical Equipment under the Defence Military Engineering Service at Panagarh on temporary basis, that is, they were civilians connected with the Defence department. They were rendered surplus in January, 1970. As they could not be absorbed elsewhere even after the lapse of more than one year, the Officer Commanding, Panagarh, was directed by the Chief Engineer, Eastern Command, Calcutta during July, 1971 that the surplus men will be asked to accept the lower post and if unwilling their services will be terminated as per provisions of the Special Army Order No. 415153. Accordingly, the three concerned drivers were asked to accept the lower post of DES which they did not accept. So their services were terminated after expiry of the notice period of one month on 15/19 November, 1971.

5. The case has been argued both on preliminary points as well as on merit. Two preliminary points have been raised by the management, (i) Whether the ESD, Panagarh of the Defence Service was an industry within the meaning of Section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947 and, (ii) whether the concerned three persons were subject to the Army Act, 1950 and as such excluded from the definition of "workman" in Section 2(s) of the Industrial Disputes Act.

6. Preliminary point 1—Whether industry.—The first question is whether the ESD, Panagarh was an industry under Section 2(j) of the Industrial Disputes Act. Mr. K. Ganguly, learned Advocate appearing for the management contended that Regal or Sovereign activity of the Government is excluded from Section 2(j) and such activity is not an industry. So far as this proposition of law is concerned, he is right. The Supreme Court in *State of Bombay v. Hospital Mazdoor Sabha*, AIR 1960 SC 610 at page 615-1960 1 LLJ 251 observed, "negatively stated the activities of the Government which can be properly described as regal or sovereign are outside the scope of Section 2(j). These are functions which a constitutional Government can and must undertake for governance and which no private citizen can undertake." The same view was taken in the *Corporation of City of Nagpur v. Its Employee*, AIR 1960 SC 675-1960-1 LLJ 523. It was laid down that the inalienable functions of the Government were outside the spell of industry. This view was accepted by the majority view in *Bangalore Water Supply & Sewerage v. A. Rajappa*, 1978 Lab. IC 467 1978 1 LLJ 349-AIR 1978 SC 548 and 969 wherein it was observed: ".....sovereign functions, strictly understood (alone) qualify for exemption, not the welfare activities or economic adventures undertaken by the Government or statutory bodies. Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially severable, then they can be considered to come within Sec. 2(j)". It is thus clear that if the Government departments discharge purely sovereign functions of the State in exercise of its inalienable functions its activities shall be outside the circle of industry but not the other governmental activities are excluded from Sec. 2(j). Such essential constitutional (inalienable) functions of the State are, like administration of justice, administration of laws and legislative powers. In the words of Lord Watson these activities are, "The primary and inalienable functions of a constitutional government" vide *Richard Coomber v. Justices of the Country* [(1883) 9 AC 61]. It is thus clear that whatever be the definition of "industry" it cannot include the regal or sovereign functions of the State. Lord Watson in the said case has described these functions as administration of justice, maintenance of order and repression of crime as amongst primary inalienable functions of a constitutional Government. It is to be noted that the definition of industry in the Industrial Disputes Act, 1947 is on the model of Australia and the Indian decisions on the

concept of industry are greatly indebted to the Australian judgments. In an Australian case *Issacs, J.*, in his dissenting judgment in *Federated State School Teachers' Association of Australia v. State of Victoria* (1928-29) 41 CLR (569) states thus at page 585.

"Regal functions are inescapable and inalienable. Such are the legislative power, the administration of laws the exercise of the judicial power. Non-regal functions may be assumed by means of the legislative power. But when they are assumed, the State acts simply as a huge corporation, with its legislation as the charter. Its action under the legislation, so far as it is not legal execution of the law, is merely analogous to that of a private company similarly 'authorised'."

From the above it is obvious that regard and sovereign functions of the State are outside the pale of industry as denied in Sec. 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947.

7. Mr. Sen Gupta, learned Advocate appearing for the Union, however, contends that the activity of the ESD in the present case was not regal or sovereign but it will come within the definition of "industry" as given in Sec. 2(j) of the Industrial Disputes Act. His argument is that the activities of the ESD will be covered by the expression "manufacture" used in that definition. His contention, I think, is sound. Section 2(j) runs as follows:

"(j) 'industry' means any business, trade, undertaking manufacture or calling of employers and includes any calling, service, employment, handicraft, or industrial occupation or avocation of workmen."

It follows from the above that for an activity to be called as 'industry' the employer must be engaged in any business, trade, undertaking, manufacture or calling. The term "industry" also includes any calling, service, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of the employees. Thus the definition of an industry is of wide import. In an Australian case *Jumbunna Coal Mines No Liability v. Victorian Coal Miners' Association*, 6 CLR 309 (370) (HCA) Issacs, J. speaking for the High Court of Appeal, picturesquely illustrated the terms used in the definition of 'industry' to mean a business (as merchant), a trade (as cutter), a manufacturer (as a flour miller) undertaking (as a Gas Company), a calling (as an Engineer or Service (as a carrier) or an employment (a general term like calling embraces some or the other and intended to extend avocations which might not be comprised with anything of the rest)....." From the above observation of Issacs, J. it is quite clear that the word "manufacture" has been explained by the example of a Flour Miller. In *New Grand High Class Bakery v. ESI Corp.*, 1976 Lab IC 1466. The making of bread in the bakery was held to be a manufacturing process. Manufacture, in my opinion, is a kind of productive activity in which the making of the articles or materials (obtained in large scale) is by physical labour or mechanical power. In Webster's, *New World Dictionary*, "manufacture" means the making of goods and articles by hand or specially by machinery obtained on a large scale with division of labour. The same meaning has been given in the concise Oxford Dictionary. A question, therefore, does arise whether the ESD, Panagarh manufactured any article in the sense stated above. WW-2 Balaram Ganguly, one of the three concerned employees, has stated in his evidence in-chief that nut, bolts, brackets, etc were manufactured for running repairs. There seems to be no denial of this fact. So the contention of Sri Sen Gupta has force. But, apart from it there are other materials to indicate that ESD was an industry. According to WW-2 the ESD had several sections. There was one section Bridging, Building, etc. There was another section of technical work. It was the store of electric motors, pumping sets, electric materials etc. There was also a workshop in which there was running repairing. There was another section, namely, Moulding section and a Blacksmithy section. The workshop activities were carried on in connection with carpentry also. There is nothing in the cross-examination of WW-2 to discredit him. WW-1, M. K. Mitra, the General Secretary of the MES Workers Union, ESD, Panagarh has deposed that maintenance of stores, repair of stores, and several shops were at Panagarh Depot. Various machines were kept for the purpose of repair and there were about 1000 workers both

industrial and non-industrial in 1971-72. Clerks, supervisory staff, store keeping personnel, fire fighting staff were non-industrial workers whereas all types of technicians and the mistries were included in industrial workmen. He has further stated that there was Works Department at Panagar unit constituted by the Officer Commanding, ESD Panagar according to the Industrial Disputes Act, 1947 and that the ESD was a factory registered under the Factories Act. There is no specific cross-examination by the management on these points. I rely on his evidence. MW-1 A. K. Mukherjee the Barrack Stores Officer has deposed that the ESD, Panagar was a store holding unit and used to cater for stores required for different military engineering services. Besides several operational type of stores such as, bridges, different types of Boards removable sets for military necessity were maintained. He also said that articles to be stored at the ESD, Panagar were purchased at the direction of the Army Headquarters and that for day-to-day work and other materials were purchased for packing purposes to be despatched to different centres and that the unserviceable articles were sold by Officer Commanding at Panagar through Government Auctioneer. Sri Ganguly drew my attention to the Written Statement of the Employer which states that ESD, Panagar is a defence establishment under the Ministry of Defence and that its functions relate primarily to holding and handling of stores required for defence purposes and that it was not a manufacturing or productive concern. It further states that the workload is based on the tonnage of the stores held and handled. He submitted that in the ESD there has never been any question of production bonus and that it is not a productivity unit. Learned Counsel points out that the unit is connected with the Defence Department and that the cars, lorries all belong to military unit and that the President cannot be conceived of running an industry. It is said that the President is the Supreme Commander of the Army, Navy and Air Force in exercise of sovereign functions. In short, his argument is that the ESD is a military department and is maintained under exercise of regal or sovereign functions of the Government. In my opinion, the activities of the ESD aforesaid can not be said to have been done in exercise of the sovereign functions of the State. They cannot be called primary and inalienable functions of the State. Sovereign functions cannot be destroyed. It is inseparable and inalienable from the conception of the State. In the present case admittedly the entire unit of the Defence Department, Panagar was closed and dismantled (perhaps in the year 1976) because it had no utility for the Government of India. I would like to point out here that admittedly the ESD was a defence establishment (vide the written statement of the management). If, so, it was an industry according to entry No. 8 of the First Schedule of the Industrial Disputes Act, 1947. Sri K. Ganguly referred to the case of Management, Station Canteen, Bangalore v. Presiding Officer, Labour Court, Bangalore & Ors., 1972 Lab. IC 776; Indian Naval Canteen Control Board v. Industrial Tribunal, Calicut, 1971 Lab. IC 1326 and the Supreme Court case of 1970 Lab. IC 1172 in the case of Safdar Jung Hospital, New Delhi v. Kuldip Singh Sethi for the purpose of explaining the meaning of industry. The last case of the Supreme Court was over-ruled by the latest Supreme Court decision in Bangalore Water Supply & Sewerage Board etc. v. A. Rajappa & Others, 1978 1 LLJ 349. The Mysore case aforesaid has relied on Safdar Jung case. After the latest pronouncement made by Hon'ble Supreme Court in the Sewerage Board case it is not necessary to discuss the case relied upon by Sri K. Ganguly. I am of opinion that the activities in question were analogous to 'business' and come within the purview of Sec 2(i) of the Industrial Disputes Act, 1947. I hold so accordingly. Thus the point raised by the management has no force.

8. Preliminary point 2—Whether subject to Army Act ?

The next question is whether the three concerned persons of the ESD, Panagar are subject to the Army Act, 1950 and as such excluded from Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947. Sri Ganguly for the management argues that these persons should be held to be subject to the Army Act in view of the provisions of Section 2(1)(i), 3(1)(a), (b) and (c) and Section 9 of the Army Act read with the two army orders of 1962 and 1972 and hence they were not workmen in 1971 or in 1972 and therefore no industrial

dispute existed which could be referred to this Tribunal for adjudication. It is pointed out that though the two army orders of 1962 and 1972 were withdrawn in the year 1979 by army order No. 1/75 of 1977 and probably these persons could now raise dispute but they were not competent to do so in 1971 or 1972 when the provisions of the two army orders of 1962 and 1972 were in force. He submits that the validity of the reference is to be judged by the law as it existed at the date when the reference was made in 1972. It will be better to quote the different sections of the Army Act to which reference has been made, Section 2(1)(i) reads as follows :

"2. Persons subject to this Act—(1) The following persons shall be subject to this Act wherever they may be, namely :

** ** ** **

(i) persons not otherwise subject to military law who, on active service, in camp, on the march or at any frontier post specified by the Central Government by notification in this behalf, are employed by, or are in the service of, or are followers of, or accompany any portion of, the regular Army."

Section 3 runs as below :

"(i) 'active service', as applied to a person subject to this Act, means the time during which such person—

- (a) is attached to, or forms part of, a force which is engaged in operations against an enemy, or
- (b) is engaged in military operations in, or is on the line of march to, a country or place wholly or partly occupied by an enemy, or
- (c) is attached to or forms part of a force which is in military occupation of a foreign country;"

Section 9 provides :

"Power to declare persons to be on active service—Notwithstanding anything contained in CI. (i) of Section 3, the Central Government may, by notification, declare that any person or class of persons subject to this Act shall, with reference to any area in which they may be serving or with reference to any provision of this Act or of any other law for the time being in force, be deemed to be on active service within the meaning of this Act."

Admittedly Section 3 of the Act does not apply to these three persons. These three persons were not on active service within the meaning of that section. Mr. Ganguly, however, strongly relies on Section 9 and contends that these persons shall be deemed to be on active service by virtue of the notification issued by the Central Government under that section and hence they shall be subject to the Army Act within the meaning of Section 2(1)(i). He says that all the three sections, namely, Section 2(1)(i), 3 and 9 have to be read harmoniously and if so read these three persons shall be deemed to be on active service by virtue of the provisions of the army orders of 1962 and 1972 read with Section 9 of the Army Act.

9. In my opinion the contention is not sound. Section 2(1) in clauses (a) to (i) of the Army Act enumerates the persons who are subject to the operation of the Act. According to sub-clause (i) of this section persons governed by the Act included persons not otherwise subject to military law who, on active service, in camp, on the march or at any frontier post specified by the Central Government by notification in this behalf are employed by, or in the service of, or are followers of, or accompanying any portion of, the regular army. In other words, this sub-clause includes the civilians of the defence service. If such civilians are on active service and employed by the regular army or if they are in camp and are in the service of the regular army or if they are on the march and are followers of the regular army or if they are serving at any frontier post and accompany any portion of the regular army they shall be subject to the Act. Section 9 applies only to persons who are already subject to the Army Act but not on active service as contemplated by Section 3. They are deemed to be on active service by virtue of notification of

the Central Government. Such notifications in the present case are Exhibits M-3 and M-4. The first notification in the present case, namely Ext. M-3 is the army order No. 517/62 published in the Defence Gazette Notification No. 6E dated 28th November, 1962. It declares all persons subject to the Army Act as on active service. It runs as below :—

“Government of India, Ministry of Defence Gazette Notification No. 6-E dated 28th November, 1962 is reproduced below :—

“In exercise of the powers conferred by section 9 of the Army Act, 1950 (46 of 1950) the Central Government hereby declares that all persons subject to that Act, who are not on active service under clause (i) of Section 3 thereof, shall wherever they may be serving, be deemed to be on active service within the meaning of that Act for the purpose of the said Act and of any other law for the time being in force.”

Exhibit M-4 is another army order No. 267/72 dated 10th June, 1972 and declares all persons who are subject to the Army Act as on active service. M-4 is “Government of India, Ministry of Defence Notification No. SRO dated 28th November, 1962. It is same as the Army Order of 1962.” Thus the two notifications were issued by the Central Government, Ministry of Defence in exercise of powers under Section 9 of the Army Act, 1950. It is clear that all these persons must be already subject to the Army Act but not on active service from before the notifications. This fact is clear from the wording of Section 9 under which only a person or class of persons subject to the Army Act can be declared to be on active service. This is also clear from the two army orders of 1962 and 1972 which has used similar words. Mr. Ganguly argued that all civilians in defence service were declared to be on active service by notification under Section 9 and so they came within the purview of Section 2(1)(i). In my opinion he is not right. It is only those civilians of the defence service who are already subject to Army Act who are declared to be on active service. I think that Section 9 does not at all relate to the civilians of the defence service unless they are already subject to the Army Act prior to the notification. Section 9 does not make any person subject to the Army Act but it only declares civilians to be on active service. I have already said that Exhibits M-3 and M-4 have used words from which it is clear that only persons subject to the operation of the Army Act but not on active service can be declared to be on active service by the Central Government by issuing notification under Section 9. The contention thus fails. It follows that the contention of the management that the three concerned employees from 28th November, 1962 were governed by the two successive notifications (Exhibits M-3 and M-4) and were subject to the Army Act, 1950 under Section 2(1)(i) read with Section 9 of the Act is not tenable for the simple reason that the notifications aforesaid dealt with only those persons who were already subject to the Army Act and not with other civilians connected with the defence service. So, the concerned persons were not excluded from the definition of workman by reason of the provision of Section 2(s)(i) of the Industrial Disputes Act which reads thus “.....but does not include any such person, who is subject to the Army Act, 1950, or the Air Force Act, 1950 or the Navy (Discipline) Act, 1934”. The management relied on *Sach Deo Sharma v. Union of India & Others*, AIR 1964-J & K, 21 Div., in which it was held that if the person is attached for the time being to or forms part of a force which is engaged in operation against an enemy, he is amenable to the Army Act. That was a case where a civilian officer attached to Works Engineer in Defence Service was declared to be on active service by notification under Sec 9 of the Army Act and was held to be amenable to the Army Act and could be tried by a Court of Enquiry set up under 177 of the Rules framed under the Army Act. It is clear that the officer in that case was attached to or formed part of a force. Such is not the case here. Moreover it seems that the J & K Bench in that case has not construed the expression “any person or class of persons subject to this Act” in Section 9 which clearly means that only such persons as are subject to the Act can be declared to be on active service. There being no interpretation of that expression in the said decision it cannot be of much assistance in the present

case in which the interpretation of the provision of Section 9 and of the two army orders is in question.

10. Counsel appearing for the management next relied on *Ous Kutlingal Achudan Nair and Others v. Union of India and Others*, AIR 1976 SC 1179. In that case it was held by the Honble Supreme Court that the employee of the Defence Establishment such as cooks, chowkidars, lascars, Barbars, Carpenters, Merchants, Bootmakers, Tailors, etc. who were in the Training establishments could not form trade unions as their fundamental right had been completely taken away by the Central Government. It would be noticed, however, that in that case those persons were in Training establishments and answered the description of members of armed forces. Further, it was their duty to follow or accompany the army personnel on active service, or in camp or on the march. It was in these circumstances that it was held that although they were non-combatant and were in some matters governed by the civil services regulations, yet they were integral to the armed forces. It was observed that though they answered the description of “members of the armed forces” within the contemplation of Article 33 of the Constitution of India and consequently by virtue of Section 21 of the Army Act, the Central Government was competent by notification to make rules curtailing their fundamental rights. That case therefore is not of any assistance to the management because in the present case it has not been shown that the three concerned motor drivers were on active service employed by the regular army or in camp in the services of the regular army or on the march following regular army or at the frontier post accompanying any portion of the regular army. There is no evidence on record to that effect.

11 Another point which is vitally connected with this question is whether the three concerned employees are workmen. They will not be workmen simply because they are not excluded from Sec. 2(1). They have to be brought under any of the four specified categories, namely, skilled or unskilled manual, technical, clerical or supervisory. In my opinion these persons will come under the category of skilled manual. They will therefore, be workmen. My conclusion, therefore, is that the three employees were workmen within the meaning of Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947.

12. In connection with the above two preliminary points a further point has been argued by Sri Sen Gupta for the workmen that the Industrial Disputes Act itself indicates that industry can be carried by or under the authority of the Central Government. He has referred to Section 2(a) of the Industrial Disputes Act, 1947 and also to some of the provisions of the Standing Orders issued by the Engineer-in-Chief, Army Headquarter, of the year 1971 printed in 1972. His contention is sound. Section 2(a) of the said act shows it. It is further clear from the entries in the First Schedule of the Act under which even the Indian Government Mints are industries. It will not be out of place to mention here that modern State is a Welfare State under the Constitution of India. Its activity is not confined only to safeguard the country from external aggression or internal disturbances. It builds Dam, construct railways, operates buses and trams, flies planes, digs canals, generates electricity, maintains fair price shops, runs schools and colleges and so on. It performs a lot of multifarious functions. There are several government undertakings and Government Corporations employing large number of workers. I do not see as to why Industrial Disputes Act will not apply to government activities except that which is undertaken in exercise of its sovereign functions. Item 92 of the aforesaid Standing Orders of 1971 permits a civilian subordinate to form trade unions under the provisions of the Trade Unions Act. Item 94 permits formation of Works Committee as provided in the Industrial Disputes Act, 1947 in the MES units; item 96 provides for Joint Consultative Committee for promoting harmonious relations and to secure greater measure of cooperation between the government and its employees in the matter of common concern. Under Item 99 all enactments on labour laws are applicable to the MES units except where they are specifically exempted from the application of certain provisions of the Act by competent authority. Reference may also be made to the case of *M/s. Hindustan Aeronautics Ltd. v. The Workmen and Ors.*, 1975

I ab IC 1218—AIR 1975 SC 1737 where the Barrackpore branch of the Bangalore Division of the Government Company was engaged in an industry of repairs of air crafts or the like at Barrackpore. This was admittedly an industry. Mr Ganguly appearing for the management argued that three concerned employees were full-fledged government servants and they were controlled by civil services regulations, defence service regulations for the MES 1968, Standing Orders issued by the Engineer in Chief, MES, Regulation Chapter X dealing with stores and by manual of Indian Military Law and so they were not competent to raise industrial dispute. I do not agree with this contention. In my opinion, even government servants of an industry run by or under the authority of government can raise industrial dispute. From the above discussion it is quite obvious that the ESD, Panagar was an industry, that the three concerned employees were workmen and that the Industrial Disputes Act, 1947 applied to them. I have also found that they were not subject to the operation of the Army Act, 1950.

13 Point 3—I will now touch the merits of the case. Admittedly the services of the three concerned employees S Roy B R Ganguly and Kashi Prasad were terminated under the provisions of Para 14 of SAO/S/53 with effect from 15 November, 1971 under the Order of Lt Col Engineer-Officer Commanding dated 16th October, 1971 on the ground that they did not accept the lower post of DES after they had been rendered surplus consequent upon reduction of workload. The orders terminating their services are Exhibits M-9(a), M-9(b) and M-9. Mr Ganguly submitted that the termination of their service being in accordance with the provisions of the special Army Order 4/H/53 cannot be held to be invalid. He pointed out that the conditions of service of these employees were determined by Army Headquarters at New Delhi, that the policy decisions were recorded by notifications and as such the validity cannot be challenged before this Tribunal. He further argued that the management acted in accordance with Statutory Army Order 4/H/53 para 14 and hence the termination order is valid. I do not agree. The management had no doubt right to terminate the service of the concerned employees but that right can be exercised only in accordance with law. The termination amounts to retrenchment and hence the Industrial Disputes Act is also applicable. Admittedly no retrenchment compensation was paid to any of them. The provisions of Section 25F therefore were not complied with. This will make the termination of service illegal and void. Mr Ganguly argued that the termination of service did not amount to retrenchment. In my opinion the argument is not correct. In the State Bank of India v M Sanderamoni 1976—1 LLJ 478 the Supreme Court observed "termination for any reason whatsoever are the key words. Whatever the reason every termination spells retrenchment. Termination embraces not merely the act of termination but the fact of termination however produced". In Santosh Gupta v State Bank, Patiala, 1980 II LLJ 72 the Supreme Court again held that retrenchment means termination of service for any reason whatsoever and it covers every kind of termination of service except those not expressly included in Section 25F or not expressly provided for by any other provision of the Act such as 25FF and 25FFF. The view taken in this case was upheld in I Robert D'Souza v Executive Engineer South Eastern Railway and Another 1982 I LLJ 330. I would therefore hold that the termination of service constituted retrenchment within the meaning of expression "retrenchment" in section 2(OO) of the Industrial Disputes Act 1947. It is true that this interpretation was given in 1976, 1980 and 1982 but the provisions of Section 2(OO) existed at the time of termination of service of these employees and there is no reason as to why correct interpretation should not be applied to those provision.

14 For the above reasons the orders contained in Exhibits M-9, M-9(a) and M-9(b) are set aside. So far as the back wages are concerned I think that the amount be the full back wages and hence I would direct the defence authority concerned under whom the Panagarh depot was working and some load of which after its closure has been taken by Kanakinara Depot (vide MW 1) to pay to the three concerned employees S Roy B R Ganguly and Kashi Prasad full back wages from the date of termination of service till date. They will be deemed to be in service and paid all consequential benefits that would have been available to them had they been in service. The management however

will be entitled, if it so likes, to terminate the services of these three employees in view of their non-acceptance of the lower post in accordance with law and after complying with the provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act 1947. It may also be mentioned that if any of the three workmen has reached the age of superannuation by this time, he will be paid upto that date only.

²This is my Award

Calcutta,

The 12th November, 1982

M P SINGH, Presiding Officer

[No L 14011(2)/71 LR]

S.O 52—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Employees' State Insurance Corporation and their workman, which was received by the Central Government on the 26th November, 1982.

BFFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO 1 AT BOMBAY

PRFSENT

Justice M D Kambl Esqr, Presiding Officer

Presiding Officer

Reference no CGIT-23 or 1981

PARTIES

Employers in relation to the Management of Employees' State Insurance Corporation.

AND

Their Workman

APPEARANCES

For the employer—Mr. H V Advocate

For the workman—Mr. V. R Datar, Advocate

INDUSTRY

Insurance

STATE

Maharashtra

Bombay the 30th October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No L-15012(1)/81-D II B dated 31st October, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the Employees' State Insurance Corporation and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below—

SCHEDULE

"Whether the management of ESIC is justified in terminating the services of Smt M P Kulkarni, LDC, with effect from 3-1-1980? If not, to what relief is the said worker entitled?"

2 The workman, Mrs M P Kulkarni was employed as a Lower Division Clerk in the employer-corporation. Her appointment was at Pune with effect from 16-3-1978, under the order of appointment dated 7-3-1978. The letter of the appointment states that she had been selected and was offered a purely temporary post of Lower Division Clerk. The appointment was to last to 31-5-1978 after which date unless

the tenure of appointed was extended her services were to stand terminated automatically without giving her any further notice. According to the workman, during her employment with the corporation a number of artificial breaks were given in the service, and finally her services were terminated with effect from 3-1-1980 A.M. In the statement of claim the workman has given the dates of the actual employment. The case as pleaded in the statement of claim by the workman is that the work she was doing was of regular nature and there was no justification on the part of the corporation to keep the workman as a temporary employee. There was no justification for the corporation to give breaks in the service of the workman. During her employment with the corporation there were no adverse reports against her from any of her superiors and despite this the corporation from time to time gave artificial breaks in her service. It was also pleaded that while terminating her services the corporation did not give any reasons for the same. Referring to the contention of the corporation that the workman had not successfully passed the test conducted by the corporation, the workman stated that at the time of her initial appointment she was not told that she was required to pass any selection test. It was alleged that no rules have been framed by the corporation requiring a candidate to pass a selection test. It was further stated that there are some other employees who are retained in the service of the corporation though they have not passed the selection test. There was therefore violation of Article 14 of the Constitution of India, as the Corporation is a state within the meaning of Article 12 of the Constitution of India. According to the workman, after the termination of her service the corporation has recruited fresh hands in Pune office where the workman was working. The corporation has therefore violated the right of the workman under Section 25-F of the Industrial Disputes Act. The workman submitted that the termination of her services amounts to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act and while terminating her services the corporation did not pay the retrenchment compensation and notice wages in accordance with the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act and therefore the termination of the services of the workman was illegal. The workman therefore prayed that the corporation be directed to reinstate the workman with continuity of service and back wages.

3. The employer-corporation by its written statement contended that it was a statutory body constituted under the provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 and that the corporation has several branch offices in the State of Maharashtra and one of the Sub-Regional Offices is at Pune. According to the corporation, the workman was employed as a Lower Division Clerk with effect from 16-3-1978 on a purely temporary and ad hoc basis. By the letter of appointment it was made clear that the appointment was to last upto 31-5-1978. The corporation appointed the workman on the same basis subsequently under various orders. Under these orders the services of the workman were liable to be terminable at any time without any notice and without assigning any reason thereof, the appointment being on purely temporary and ad-hoc basis. It was stated that the corporation in pursuance of the power vested in it under the said Act of 1948 has framed the Regulations governing the recruitment of their employees and that the said Regulations are called "Employees' State Insurance (Recruitment) Regulations, 1965". It was pointed out that Regulation 5 and Regulation 21(2)(f) deals with the eligibility for appointment of a candidate in the corporation and that no candidate to a post can be appointed on a permanent basis in contravention of the Employees' State Insurance Regulations. According to the corporation, for the purpose of eligibility for appointment the candidate must be within the prescribed age limit and that the candidate to a post must possess the prescribed educational qualifications and experience and that as provided under Regulation 21(2) the recruitment to a post of Lower Division Clerk has to be made only by open competitive examination and the candidate who qualifies in the written test can only be appointed as Lower Division Clerk. The letters of appointment issued to the workman made it clear that her services were liable to be terminated at any time without any notice and without assigning any reason. In view of this position, the workman has no lien on appointment. The workman appeared as many as four times for the open competitive examination, but she failed

in those examination. Had she qualified in the competitive examination her services would have continued. The outside candidate for the test is required to be sponsored by Employment Exchange only. But, as the workman had crossed 25 years of age the Employment Exchange did not sponsor her name.

4. It was further stated by the corporation that as per the policy of the corporation which is an All India Organisation, as and when the Lower Division Clerks are required, open competitive examinations are being held as per the Regulations of 1965 and the candidates who pass the open competitive examination are being provided regular employment depending upon the availability of vacant post. No person can be appointed on a regular basis in contravention of the provisions of the Recruitment Regulations of 1965. The corporation denied that there was no rule requiring any employee to pass the selection test as alleged. It was pointed out that the rule about the test is to be found in Regulation 21(2)(f) of the Regulations of 1965. It was alleged that the corporation could not make any permanent appointment in contravention of this Regulation.

5. The corporation denied that the termination of the services of the workman amounted to retrenchment within the meaning of Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. It was pleaded that the workman had no right to remain in service as per the corporation's Regulations and that all her appointments were purely temporary. Her services were terminated as per the terms of appointment as contained in the order of appointment. On these pleadings the corporation prayed that the reference be rejected.

6. Now, it is not in dispute that the services of the workman were terminated on 3-1-1980. It is also not in dispute that before this date of termination the workman had put in service for more than 240 days in the period of 12 months preceding 3-1-1980. By virtue of the provisions in Section 25-B of the Industrial Disputes Act, the workman therefore shall be deemed to be in continuous service for a period of one year. It is not in dispute that the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act were not complied with. The workman was not given one month's notice nor she was paid in lieu of notice, wages for the period of the notice. It is therefore contended for the workman that the order of the termination of her service was illegal and inoperative. As against this, it is contended very strenuously by the learned counsel Mr. Mehta, for the corporation that the services of the workman were temporary. The workman had not passed the qualifying test to enable her to continue in the service. The termination of the services of the workman therefore was perfectly justified. It was also contended that the termination of the services of the workman did not amount to retrenchment. Mr. Mehta placed reliance upon Regulation 21(2)(f) of the Employees' State Insurance (Recruitment) Regulations, 1965. It provides that recruitment to certain categories of posts, including the category of Lower Division Clerk shall be made by open competitive examination. Mr. Mehta further submitted that the workman was appointed on a purely temporary basis. He pointed out to the last letter of appointment dated 11-12-1979. That letter states that the appointment will last upto 29-2-1980 after which date, unless her tenure of appointment is extended, her services will stand terminated automatically without giving her any further notice. Now, the services of the workman were terminated by the letter of the Regional Director dated 21-1-1980, in which it is said that the workman may be deemed to have been relieved of her duty with effect from 3-1-1980 A.M. It may be conceded that the appointment of the workman was purely temporary and the corporation had a right to terminate her services as she had not passed the open competitive examination. However, if the termination amounted to retrenchment, the mandatory provisions laid down in Section 25-F of the Industrial Disputes Act will have to be complied with. The question therefore is whether the termination of the services of the workman amounts to retrenchment. Now, the expression "retrenchment" has been defined in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. It is provided there :—

"retrenchment" means the termination by the employer of the service of a workman for any reason whatsoever, otherwise than as a punishment inflicted by way of disciplinary action, but does not include,—

- (a) voluntary retirement of the workman; or
- (b) retirement of the workman on reaching the age of superannuation if the contract of employment between the employer and the workman concerned contains a stipulation in that behalf; or
- (c) termination of the service of a workman on the ground of continued ill-health;"

7. Reliance is placed on behalf of the workman on the decision of the Supreme Court in *State Bank of India v. N. Sundaramoney* (1976 I. L.L.J. 478). It was observed there that "termination for any reason whatsoever" were the key words in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act. Whatsoever the reason, every termination spells out retrenchment. A termination is where a term expires either by the active step of the master or the running out of the stipulated term. The Supreme Court observed that the termination embraces not merely the act of termination by the employer, but the fact of termination, however, produced. It was observed :—

"To write into the order of appointment the date of termination confers no moksha from Section 25-F(b) is inferable from the proviso to Section 25-F(1)."

The Supreme Court repelled the contention that automatic extinguishment of service by effluxion of time did not amount to retrenchment.

8. Now, it cannot be disputed that the workman had rendered continuous service for a period of one year within the meaning of Section 25-F read with Section 25-B of the Industrial Disputes Act. Now, the Supreme Court has in the case of *L. Robert D'Souza v. Executive Engineer, Southern Railway* (Indian Factories Journal and Factories Journal Reports, Vol. 60 p. 144) decided on February 16, 1982, observed :—

"Once the case does not fall in any of the excepted categories, the termination of service, even if it be according to automatic discharge from service under agreement, would none the less be "retrenchment" within the meaning of section 2(oo) of the Act."

It is further observed :—

"Even assuming that the workman whose service was terminated was a daily worker, once he has rendered continuous uninterrupted service for a period of one year or more within the meaning of section 25-F of the Act and his services are terminated for any reason whatsoever and the case did not fall within any of the excepted categories, notwithstanding that the rules governing his service would be attracted, they would have to be read subject to the provisions of the Act, and the termination would amount to "retrenchment"."

It was therefore necessary for the corporation comply with the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act as the termination of the services of the workman amounted to retrenchment. No one month's notice nor retrenchment compensation was paid to the workman. The termination of the services of the workman therefore would be ab initio void.

9. Mr. Mehta for the corporation submitted that the workman could not be retained in service as she did not pass the competitive examination as required by the Regulations framed by the corporation. Her termination was therefore, justified. He relied upon the decision of the Orissa High Court was a case of compulsory retirement in terms of and Village Industries Board (1981 II I.J.J. n. 411). It was held in that case that the termination being in terms of the Service Regulations, it did not amount to retrenchment

and that therefore there was no necessity for complying with the provisions of Section 25-F. In coming to that conclusion the Orissa High Court tried to take support from the decision of the Supreme Court in the case of *Hariprasad Shivshankar Shukla v. A. D. Divikar* (AIR 1959 S. C. 121). It may be mentioned that the case before the Orissa High Court was a case of compulsory retrenchment in terms of the Service Regulations. However, the Supreme Court has now in the decision of *Santosh Gupta v. State Bank of Patiala* (1980 L.I.C. p. 687—AIR 1980 S. C. 1219) observed :—

"The expression "termination of service for any reason whatsoever" in Section 2(oo) covers every kind of termination of service except those not expressly included in Section 25F or not expressly provided for by other provisions of the Act such as 25FF and 25FFF."

It was expressly held in this case :—

"Thus, the discharge of the workman on the ground she did not pass the test which would have enabled her to be confirmed was 'retrenchment' within the meaning of Section 2(oo) and, therefore, the requirement of Section 25F had to be complied with."

The earlier decision of the Supreme Court in the case of *Hariprasad Shivshankar Shukla v. A. D. Divikar* (AIR 1957 S. C. 121) was considered in this case. The decision of the Orissa High Court in the case of *Purna Chandra Giri v. Krissa Khadi and Village Industries Board* (supra) therefore will be of no avail to the employer-corporation.

10. The services of the workman were terminated on 3-1-1980. Despite the breaks in service the workman had admittedly worked for more than 240 days in the year preceding 3-1-1980. It is clear that the termination of the services of the workman amounted to retrenchment within the meaning of that expression in Section 2(oo) of the Industrial Disputes Act, since it did not fall within any of the excepted categories mentioned in Section 2(oo). It must, therefore be held that the termination of the services of the workman amounted to retrenchment and as there was no compliance with the provisions of Section 25-F of the Industrial Disputes Act, the retrenchment was bad and invalid.

11. A reference may be made in this connection to the decision of the Kerala High Court in the case of *Bhaskaran v. Sub-Divisional Officer* (1982 I.L.J. p. 248) where it is observed :—

"The provisions of Ss. of 25F, 25G and 25H have overriding effect. Anything inconsistent contained in any other "law", which necessarily includes the Service Rules, cannot be given effect to. They have simply to be ignored, if the establishment in question is an industry."

The above decision will support the view that if an employee does not pass a written test required for absorption in permanent service and the services of such an employee are sought to be terminated the employer is not exempted from the operations of Section 25-F of the Industrial Disputes Act merely because the passing of a written test is compulsory under the service rules or regulations. In view of this discussion, I hold that the retrenchment of the workman was improper, invalid and inoperative.

12. The next question is what relief should be given to the workman. A reference may usefully be made in this connection to the decision of the Supreme Court in the case of *Surendra Kumar v. Industrial Tribunal cum-Labour Court, New Delhi* (1980 L.I.C. 1292). In this case it was observed :—

"Plain common sense dictates that the removal of an order terminating the services of workmen must ordinarily lead to the reinstatement of the services of the workmen. It is as if the order has never been and so it must ordinarily lead to back wages

too. But there may be exceptional circumstances which make it impossible or wholly inequitable vis-a-vis the employer and workmen to direct reinstatement with full back wages. For instance, the industry might have closed down or might be in severe financial doldrums; the workmen concerned might have secured better or other employment elsewhere and so on. In such situations, there is a vestige of discretion left in the Court to make appropriate consequential orders."

In the above case the termination of the services of the workmen was in violation of the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act. The Labour Court refused to give the workmen the relief of reinstatement in service with full back wages, but instead directed the payment of compensation of six months' salary to each of the workmen in addition to the retrenchment compensation. The Labour Court in making this order was influenced by the fact that the termination of the services of the workmen was a consequence of their failure to pass the test prescribed for permanent absorption into the service of the Bank and their reinstatement would have the effect of equating them with the workmen who had qualified for permanent absorption by passing the test. The workmen-appellants claimed before the Supreme Court that they should be awarded the relief of reinstatement with full back wages. After having considered the earlier decisions of the Supreme Court cited before them their Lordships observed that in the case before them they were unable to see any special impediment in the way of awarding the relief of reinstatement. The Labour Court, as is pointed out above observed that the award of the relief of reinstatement with full back wages would put the workmen on a par with those who had qualified for permanent absorption by passing the prescribed test and that would create dis-satisfaction amongst the latter. Their Lordships of the Supreme Court disagreeing with the view of the Labour Court observed that the workmen could never be on par since reinstatement would not qualify them for permanent absorption and they would continue to be temporary, liable to be retrenched. The Supreme Court allowed the appeal of the workmen-appellants and they were directed to be reinstated with full back wages. However, the order of reinstatement was qualified with the following directives :—

"We, however, super-impose the condition that the salary on reinstatement of the workmen will be the salary which they were drawing when they were retrenched (subject of course to any revision of scales that might have been made in the meanwhile) and the period from the date of retrenchment to the date of reinstatement will not be taken into account for the purpose of reckoning seniority of the workmen among temporary employees. The respondent is free to deal with its employees, who are temporary according to the law."

13. I would therefore, in accordance with observations of the Supreme Court follow the same course viz., granting reinstatement to the workman with full back wages with the conditions super-imposed as was done by the Supreme Court.

14. Mr. Mehta, the learned counsel for the employer-corporation, submitted that in case this Tribunal took the view that the termination of the services of the workman was illegal and inoperative, to reinstatement should be ordered, instead the workman should be given compensation equivalent to a few months' pay and allowances. I must confess that I had accepted this submission in a similar case, being Reference No. CGIT-1 of 1980 where this corporation was the employer. The facts of that case were similar in as much as the services of the workman there were terminated as the workman had not passed the test. The services of the workman were so terminated without complying the provisions in Section 25-F of the Industrial Disputes Act. Instead of granting the relief of reinstatement I had ordered that the workman should be given compensation equivalent to six months' pay and allowances, if any. In making that order, I had relied upon certain observations of the Supreme Court in the case of Gujarat Steel Tubes Ltd. v. Its Mazdoor Sabha (1980 L.I.C. 1004). The decision of the Supreme Court in Surendra Kumar v. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi (supra) was not brought to my notice at that time. In view of what is observed by the Supreme Court in the case of Surendra Kumar v. Industrial Tribunal-cum-Labour Court, New Delhi (supra) where facts were identical I am of the view that the workman, Mrs. Kulkarni

should be reinstated with full back wages. The salary of the workman, however, on reinstatement will be the salary which she was drawing when she was retrenched from service (subject to any revision of scales that might have been made in the meanwhile) and the period from the date of retrenchment to the date of reinstatement will not be taken into account for the purpose of reckoning seniority of the workman among temporary employees.

15. In the result, I find that the management of E.S.I.C. is not justified in terminating the services of the workman, Mrs. M. P. Kulkarni, with effect from 3-1-1980. She would be entitled to the relief of reinstatement with full back wages with conditions as stipulated above.

16. My award accordingly. No order as to costs

M. D. KAMBLI, Presiding Officer
[No. L-15012(1)/81-D. II (B)]

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 53.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Railway and their workmen, which was received by the Central Government on 7-12-82.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, BOMBAY

PRESENT :

Shri M. A. Deshpande, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-2/31 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Central Railway.

AND
Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—Shri P. R. Pai, Advocate.

For the workmen—Shri V. B. Mahadeshwar, Convenor, Jt. Action Committee of Clerical Staff of C. Rly, Parel.

INDUSTRY : Railways.

STATE : Maharashtra.

Bombay, dated the 19th November, 1982

AWARD

By their order No. L-41011(13)/81-D.IIB dated 2-11-1981 the Central Government have referred the following two issues for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the demand of the workmen for filling up of the upgraded post of Office Superintendent at Parel Workshop on unitwise basis is justified? If so, to what relief are the workmen entitled?

Whether the action of the Central Railway in applying para 315 of the Indian Railway Establishment Manual for fixing the seniority of Chief Clerks for the purpose of filling up of the upgraded post of Office Supdts. is justified? If not to what relief are the concerned workmen entitled?"

2. The matter is being agitated by Joint Action Committee for Central Railway Clerical Staff Struggle and this Committee who has filed statement of claim in support of the claim. The record speaks that there are two unions working in the field namely Parel Workshop, Central Railway, by name National Railway Mazdoor Union and the Central Railway Mazdoor Sangh, who were served with notice of the present proceeding but none of them turned up with the result that the Action Committee has remained the sole agitator. The Railways however have not challenged the right of the said Committee to espouse the cause of the workmen and as such on reference, the matter has to be adjudicated. The silence observed by the two unions lead to the inference that they do not want to add anything to what is contended by the Action Committee and therefore did not feel it necessary to come forward.

3. The contention of the Committee as seen from the statement of claim Ex. 3/W is that initially the clerical cadre of the Central Railway Workshop Parel which is inclusive of Kurduwadi Workshop was combined with the clerical cadres of Chief Mechanical Engineer's Office, Matunga Workshop and Jhansi Workshop for the purpose of promotion to the selection post of Chief Clerk in the grade of Rs. 335-425

(AS)/Rs. 550-750(RS). However the recruitment to the lowest grade clerical post of Clerk in the scale of Rs. 110-180(AS)/260-400(RS) was all along being effected by each of the units separately, partly by direct recruitment through the Railway Service Commission, and appointments on compassionate grounds and partly by promotion from Class-IV. Similarly promotions to the next higher grade posts namely Senior Clerk/Time-keepers in the same scale of Rs. 130-300 (AS)/Rs. 330-560 (RS) and the Head Clerk/Time keeper in the scale of Rs. 210-380 (AS)/Rs. 425-700 (RS) were made on the basis of Unit-wise seniority. It is alleged that because of the creation and operation of comparatively more number of higher posts in the office of the Chief Mechanical Engineer, the Junior and Senior Clerks in the said office were able to secure promotions to the post of Head Clerk much more earlier than their counterpart serving in Parel Workshop despite having put in longer years service in the relevant grade posts than the former. The promotions to the selection post of Chief Clerk was also in the combined seniority of all separate units together, drawn on the basis of the date of the entry to the grade of Head Clerk, as a result of which, it is alleged, Head Clerks of the Chief Mechanical Engineer's office though comparatively junior became eligible and secured promotion to the post of Chief Clerk much more earlier than the senior clerical staff of the Parel Unit. This was in spite of the Central Railway letter No. 21800-RA/Spl. IV dated 26-12-1968 to decentralise ministerial cadres and effect promotions upto grade Rs. 335-425 (AS) on unit-wise basis. Similarly, the Railway Board's instructions in the letter No. PC-63/Pt. 4/4 dated 15-12-1967 to the effect that the clerical posts, based on the percentage of distribution of posts in the various grades, including grade Rs. 335-425 (AS) should be evenly distributed amongst all the units was also not given effect to in respect of Parel Clerical Unit. It is alleged that a number of clerical posts in the grade Rs. 335-425(AS) were actually operated in the Chief Mechanical Engineer's office and this was despite the Railway Board's mandatory order contained in the letter No. PC. III/74-PS-3/UPG/5 dated 14-2-1977. By the said letter the Ministry of Railways have expressed their desire to ensure that due share of higher grade posts sanctioned under the scheme in each category is allotted to various divisional/subordinate offices without any undue weightage being given to Headquarters offices.

4. Because of this great injustice there were joint representations, interviews and meetings with the concerned authorities when it was ultimately decided by the Central Railway Administration by their letter No. HPB/201/UPG, dated 23-6-1979 to decentralise and fill up the posts of Chief Clerks, grade Rs. 550-750 (RS) from among the eligible candidates of each seniority unit, this decision, it is alleged, made effective from 1-1-1979 and only eligible candidates from amongst the Parel Unit were considered and a panel of selected candidates was drawn and approved by the competent authority on 8-8-1979.

5. Later on, under the scheme of restructuring of the clerical cadres, four posts of Chief Clerks grade Rs. 550-750 (RS) from amongst the total posts of Chief Clerks within the cadre of Parel Workshop became due for upgradation to the post of Office Superintendent in the grade Rs. 700-900 (RS). It is alleged that this upgradation of the Chief Clerks to office Supdt. did not involve or envisage any change or additions to the duties and responsibilities attached to such upgraded posts. It is also a non-selection post to be filled in from amongst the Chief Clerks of Parel Unit in the order of their seniority. However instead of following the proper procedure, it is complained, the Central Railway Administration posted candidates from other Units thus depriving the eligible candidates of Parel Unit of their due chance of promotion.

6. Regarding point No. 2 it is contended that for the purpose of filling up the upgraded post of Office Supdt. in the grade Rs. 700-900 (RS) on the basis of the pooled seniority of all the four units the procedure laid down is to draw out a combined seniority list of all the Chief Clerks of the four units namely Parel Workshop, Matunga Workshop, Jhansi Workshop and Chief Mechanical Engineer's office, Bombay, as contemplated under para 314 of the Indian Railways Establishment Manual and then to effect the promotion to the post of office Supdt. It is alleged that the panel of the Chief Clerks of Parel Workshop was approved by the competent authority on 8-8-1979 while the panels for other three units were drawn and approved much time thereafter. It is alleged that in terms of para 314 of the Manual all the empanelled Chief Clerks of Parel Unit are eligible to have their seniority

fixed enblock over the Chief Clerks of all other concerned units thus entitling the senior-most Chief Clerks of Parel Unit to promotion to the four posts of Office Supdt. in their own Unit. However, the Central Administration erroneously regulated the seniority and promotion by mis-applying para. 315 of the Manual, thereby depriving the eligible Chief Clerks of Parel Workshop of the chance of promotion.

7. It is therefore prayed that the up graded post of Office Supdt. should be filled in by seniority on Unit-wise basis and that while fixing the seniority not para.315 but para.314 should be the governing paragraph and suitable declaration to be given accordingly.

8. By their written statement Ex. 2/M the Railways refuted these contentions. They admit that the clerical post upto and including grade Rs.550-750 (RS) have been decentralised and are being filled in by Unit-wise from amongst the staff of that Unit. It is however contended that the posts of grade Rs. 700-900 (RS) are centrally controlled at the Head-quarters level and filled in on pooled seniority in the various Units. Therefore the four posts of Parel Workshop, it is alleged, are filled/to be filled by senior-most suitable candidates on pooled seniority basis observing 40 points roster for employees belonging to reserved communities. It is alleged that the post of Office Superintendent is to be filled in by promotion from amongst the senior-most suitable candidates in the next lower grade and if that date of appointment is the same, the date of entry to the grade next below shall be the determining factor. It is therefore contended that the total length of service in the clerical cadre is not the criterion to determine the seniority. Lastly it is stated that the question of decentralising the posts of Office Supdt. is under consideration in consultation with the organisation of labour and till such time the promotion channel cannot be changed unilaterally by the Railways and so the reference should be dismissed.

9. On the above pleadings the following issues arise for consideration and my findings thereof are :—

ISSUES..

FINDINGS

- | | |
|--|--|
| 1. Whether the orders contained in the letters No. 21800-RA /Spl. IV dated 26-12-1968, PC-63/Pt.4, dated 15-12-1967 and letters PC. III/74- PS- 3/ UPG/5 dated 14-2-1977 have relevance and whether they govern the question of Unit-wise seniority? | Only relevant for proving the history. |
| 2. Whether the demand of employees for filling up the upgraded posts at Parel Workshop on unit-wise basis is Justified ? | Yes |
| 3. If yes what relief is possible? | As per award. |
| 4. Whether the Railways have wrongly applied paragraph 315 of the Indian Railway Establishment Manual and should have applied paragraph 314 ? | Yes |
| 5. If yes whether the seniority of Chief Clerks for the purpose of filling up of the upgraded posts of Office Superintendent has been rightly fixed ? | No |
| 6. If not to what relief the concerned employees are entitled? | Does not arise. |
| 7. What award? | As per award . |

REASONS

10. Both the parties decided not to adduce any oral evidence in the case but relied upon the documents and other material brought on record. At Ex. 5/W there is a Railway Board's letter dated 15-12-1967 wherein the injustice caused by the pooled seniority was considered and it was decided that the higher grade posts should be distributed between Headquarters and Divisions or Workshops or other subordinate offices, separately for each of the Units of promotion in grades for which promotion is unitwise and not all Railway-wise basis. Next comes the D.O. letter dated 18-7-1977 written by the Dy. Chief Mechanical Engineer Parel recommending that selection for the post of Chief Clerk and Personnel inspectors should not be held on pooled basis but on unit basis. We find a reflection thereof in the letter of the Chief Mechanical Engineer, Bombay V.T. Ex. 7/W dated 23-6-79 whereby the Railways decided to decentralise the post of Chief Clerk with effect from 1-1-1979 and to fill in the vacancies from amongst the eligible candidates of each seniority unit. It was directed to take immediate action to form panels for filling up the upgraded selection grade posts

of Chief Clerks in the grade of Rs. 550-750(RS) by the Units themselves. At Ex. 8/W there is a letter dated 15-7-1977 calling for the considered opinion of the Units regarding the avenue of promotion of clerical staff of Parel Workshop. At Ex. 9/W dated 10-8-1979 we find the names of employees-workmen—for filling the post of Chief Clerk/Time-keepers Grade 1 in the scale of Rs. 550-750 (RS) of Parel and Kuidwad Workshop.

11. We have already noticed that all along the demand of the Parel Workshop was to treat them as a separate unit for avenue of promotion and in this demand they got the support from the Dy. Mechanical Engineer, Parel as seen from the letter dated 31-10-1979 Ex. 10/W who found this demand as just and genuine. The same Officer by another letter Ex. 11/M dated 18-3-1980 suggested that seniority for promotion for the post of Office Superintendent in the scale Rs. 700-900 (RS) should have been based on the seniority of the Chief Clerk the grade immediately below, under paragraph 314 of the Indian Railways Establishment Manual. The Officer has pointed out that in the past the seniority for promotion to P.I. Scale Rs. 550-750 (RS) was based on the principle laid down in paragraph 314 of the Establishment Manual and the staff of Matunga workshop were treated as senior for promotion as P.I. and as they were placed on the panel in the scale Rs. 425-640 (RS) earlier than the staff of Parel and the same analogy should be applied.

12. As far back as in the 1967 by letter dated 15-12-67 the Railway Board had taken a decision that the higher grade posts should be distributed between Headquarters and Divisions or Workshops or other subordinate offices, separately for each of the Units of promotion in grades for which promotion is unit-wise and not all Railway-wise basis strictly according to the prescribed percentages. It was found that the centralised system caused injustice to the other officers like Parel Workshop etc. As a result of this letter by another letter dated 26-12-1968 Ex. 13/M it was decided that each departmental Headquarters would be an independent unit upto and inclusive of the grade Rs. 335-425 (AS) and the posts in the grade of Rs. 350-475 (AS) will be filled on the basis of pooled seniority of the staff in the grade of Rs. 335-425 (AS) of all Headquarters units. However on 23-6-1979 a directive was issued that the post of Chief Clerk in the grade of Rs. 550-750 should be decentralised with effect from 1-1-1979 and filled from among the eligible candidates of each seniority unit. Now from Ex. 16/M we come to know that in the year 1979 as well as in the year 1980 the number of clerical posts in the Parel Workshop remained the same at 375 and the only change was effected in the various grades being 9 posts of Office Superintendent with effect from 1-10-1980, in the scale of Rs. 700-900 (RS).

13. It was urged on behalf of the Railways that although there was decentralisation of the post of Chief Clerks, when the question of posting of Office Supdt. comes in, not the Unit-wise seniority but pooled seniority should be the criterion and it was suggested that till this issue is under consideration no unilateral action could be taken by the Railways. We have already seen that decentralisation was effected in order not to allow an unit to get advantage over other units because of various factors and ultimately even the posts of Chief Clerk from amongst whom upgraded posts of Office-wise were to be filled in were also decentralised on Unit-wise basis. Now once the principle that decentralisation is necessary stands accepted, there is no reason why this should not be extended further and it is made applicable to the post of office Supdt. especially when the contention of the Action Committee in para. 2(V) of Ex. 3/M to the effect that the upgradation of the posts from Chief Clerk to Office Supdt. did not involve or envisage any change or additions to the duties and responsibilities attached to such upgraded posts, is not refuted. It is also a non-selection post and therefore must be filled in on seniority basis. There is grant force in the contention of the Action Committee that if the pooled seniority is taken into account, candidates from other units are likely to gain advantage at the costs of Chief Clerks serving at the Unit at Parel and the former decentralisation being the result of removal of such injustice, the same rule will have to be followed in the case of Office Supdt. also. At last the Railways could not point out as to how the rules of pooled seniority of office Supdt. would be just particularly when upto the posting of Chief Clerks the same was discarded being causing injustice. I therefore answer issue No. 2 suitably namely that the demand for Unit-wise seniority is justified. Various circulars are referred

to for issue No. 1 but they have got no direct bearing except for tracing the history about decentralisation at various stages.

14. Even one of the officers has found the demand true and genuine and the Railways have also not rejected the demand but kept it under consideration. Having regard to this fact and further having regard to the circumstances discussed above rules of seniority of Unit-wise basis will have to be applied from date of reference atleast if not earlier and suitable promotional avenues will have to be given to the person concerned. Once point No. 1 is answered suitably really appearing point No. 2 would not arise at all. However, since there is a reference finding one way or other will have to be noted. The Rules regulating seniority of non-Gazetted Railway servants are to be found in Chapter III of the Railway Establishment Manual. Under the Para 314 which lays down seniority in selection posts, it has been laid down that seniority of two or more officiating railway servants selected at different selections for a particular selection post should be fixed with reference to the date of selection, that is to say, railway servants borne on an earlier panel shall be senior to those selected later even though the latter may be continuously officiating in the selection post as a local arrangement from a date prior to the date of promotion of the former or the latter may be substantively senior to the former. We have already seen that in his letter dated 18-3-1980 the Dy. Chief Mechanical Engineer Parel had drawn the attention of his superior that the seniority for the promotion at Parel in the grade Rs. 550-750 was based on the principle laid down in paragraph 314 of the Establishment Manual and it is further stated that the staff of the Matunga Workshop was treated as senior for promotion as P.I. as they are placed on the panel earlier than the staff of Parel. It is the contention of the workmen that in pursuance of the direction given in the letter dated 23-6-1979 the Parel workshop had formed a panel while other units had lagged behind.

15. The Railways are applying paragraph 315 but it is attracted only if the date of appointment to a grade is the same. After the panels were formed and when para. 314 is clear it would be the said paragraph and not paragraph 315 which would govern the seniority. If at all there is another paragraph applicable it would be paragraph 321 which determines the relative seniority of employees in an intermediate grade belonging to different seniority units appearing for selection/non-selection post in higher grade. Different seniority units are therefore considered separately at the same time if the inter-se seniority is to be fixed the said paragraph would be attracted. Therefore answer issue 4 suitably and hold that the seniority of the Chief Clerks on the basis of paragraph 315 is wrongly fixed and it should be under paragraph 314. However since point No. 1 is decided in favour of the Action Committee no relief need be granted on this account. Award accordingly.

No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer

[No. L-14011(13)/81-D. II (B)]

S. S. PRASHER, Desk Officer.

Dated : 25-11-82.

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 54.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Bhulanbarree Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhulanbarree, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the

Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 43 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bhulanbarree Colliery of M/s. Bharat Coking Coal Limited, Post Office Bhulanbarree, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri G. Prasad, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal

Dhanbad, the 6th December, 1982

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012/144/81-D.III(A) dated the 28th July, 1981 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

“Whether the demand of the workmen of Bhulanbararee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited at and Post Office Bhulanbararee, District Dhanbad, that Shri Rama Shankar Singh should be designated as a Munshi and paid in the scale of pay attached to that post is justified? If so, to what relief is the workman entitled?”

2. The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement dated 2-12-1982 has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer
[No. L-20012/144/81-D.III(A)]

Ref. No. GM-PER/XI/81/5643-45 Date 16-10-1981
MEMORANDUM OF SETTLEMENT UNDER RULE 58 OF INDUSTRIAL DISPUTE CENTRAL RULES, 1957
Representing the Management : Representing the Union:
Shri P.K. Roy, Dy. Personnel Manager Shri Ram Janam Singh, Branch Secretary, R.C.M.S. Bhulanbararee Branch.
Shri SRK Rao, Personnel Officer. Shri Rama Shankar Singh, OBR Bhulanbararee Colliery.

SHORT RECITAL OF THE CASE

An industrial dispute was raised before A.L.C. (C) Dhanbad in respect of Shri Rama Shankar Singh claiming the wages and category of Munshi. The dispute ended in failure and the Ministry of Labour referred the matter for adjudication under the following terms :—

“Whether the demand of the workman of Bhulanbararee Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited at the Post Office Bhulanbararee, District Dhanbad that Shri Rama Shankar Singh should be designated as a Munshi and paid in the scale of pay attached to that post is justified? If so to what relief is the workman entitled?”

The matter was referred to H.Q. and it was decided to settle the dispute between the parties on the following terms and conditions :—

1. That Shri Rama Shankar Singh, OBR was working as Munshi and be designated as Munshi as per Wage Band and be placed in Clerical Grade III with immediate effect.

2. That it was agreed between the parties that Shri Rama Shankar Singh shall not claim the wages of Munshi prior to the date of the settlement.

3. It was agreed between the parties that since dispute has been referred to the Industrial Tribunal for adjudication, the parties will file a joint compromise petition before the Hon'ble Tribunal when the case is fixed for submission of written comments etc.

4. That the issues involve resolved finally between the parties.

Management side

Signature

Sd/-

1. (P.K. Roy)
Dy. Personnel Manager.

Sd/-

2. (S.R.K. Rao)
Personnel Officer.

Union Side

Signature

Sd/-

1. (Ram Janam Singh)
Branch Secretary, RCMS,
Bhulanbararee Colliery

Sd/-

2. (Rama Shankar Singh)
OBR, Bhulanbararee Colliery.
Part of the Award

S.O. 55.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron & Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(i)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 17 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of M/s. Indian Iron & Steel Company Limited, P. O. Bhaga, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers.—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen.—Shri S. Bose, Secretary Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, the 4th December, 1982

AWARD

By Order No. L-20012(277)/80-D. III(A) dated the 14th April, 1981, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Dis-

Act, 1947 (hereinafter referred to as the Act), referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of S/Shri S. H. Rahman, Ajit Mishra, Birendra Singh, Sovnath Yadav, Shama Tabroji, Jafar Khan, Shrinath, K. K. Gupta, Shyamal, Haripada Tewari, Sarbajit Yadav, Akhtar Khan, Lukman Passi, Sahadeo Mishra, Raghupaty, Hari Ram Yadav, Sachida Nand, Chandrika Singh, Ramesh and Hanu Bhuiya, Heavy Tyndals of Noonodih-Jitpur Colliery, of Messrs Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Bhaga, District Dhanbad, for payment of Category-IV wages from June, 1977 is justified? If so, to what relief are the said workmen entitled?"

2. The General Secretary of the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh which has sponsored the cause of the concerned workmen, has filed written statement and rejoinder on behalf of the concerned workmen, and, similarly, the Area Manager of Noonodih-Jitpur Colliery has filed written statement and rejoinder on behalf of the management.

3. The case of the concerned workmen is that they, along with several others, are permanent employees of Noonodih-Jitpur Colliery of M/s. Indian Iron and Steel Company Limited, P. O. Bhaga, District Dhanbad since 1971 on the same or similar job equivalent to the job of Heavy Tyndals both on the surface as well as in the underground mines according to orders of the controlling authorities at the colliery level and, in accordance with the job performed by them regularly over the years they are entitled to receive Cat. IV rates of wages, whereas they are being paid different rate of wages of Cat. II or Cat. III, and thus they are being discriminated against by the management. They represented their case before the management for paying them Cat. IV rate of wages when a group of their co-workers were paid Cat. IV rate of wages with effect from June, 1977 but the concerned workmen were left out. For having failed to receive justice from the hands of the management, the workmen represented their case before Assistant Commissioner (Central), Dhanbad. But the proceedings ended in failure and this led to the present reference by the Central Government. On these grounds the workmen claim Cat. IV rate of wages with effect from June, 1977.

4. On the other hand, the case of the management is that the job description of "Tyndals" at Sl. No. 5 of Cat. IV (Skilled Junior) at page 46 of Appendix V of Vol-II of the Central Wage Board recommendations for the Coal Mining Industry, accepted by the Central Government with effect from 15-8-1967, vide Notification No. WB-16(5)/666 dated 21-7-1967 of the Government of India, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation (Deptt. of Labour & Employment), is as follows :

"Men generally employed in moving engineering stores, drums of oil and greases. Also responsible for erection, dismantling of structures and installation and withdrawal of machinery."

According to the management, the concerned workmen do not move engineering stores, drums of oil or greases and they are also not called upon for erection, dismantling of structures and installation and withdrawal of machinery. In fact, in Jitpur colliery there are 76 Tyndals in the engineering side and 32 Tyndals in the mining side which are much more than the number required in carrying on the work. So far as the concerned workmen are concerned they were deployed, if and when so required, in miscellaneous jobs. None of them has either the capacity or capability of doing job of Tyndal. At times their services are required in lowering timber/arches/girders etc. in underground. Timber lowering has always been done. Lowering of arches/girders is due to new technology. Such type of jobs which are all comparatively new developments are not covered by the job description in the Coal Awards or in the Wage Board recommendations. This is why the matter was referred to the Standardisation Committee of Joint Bipartite Committee for the Coal Industry (hereinafter referred to as JBCCI) which has been specially constituted to review and examine the reports of the different subcommittees constituted by the JBCCI on new jobs and giving appropriate categories and preparation of job descriptions for underground mines and

also for miscellaneous sections such as workshop, excavation etc. as per clause 11-7-2 of the National Coal Wage Agreement (II) (hereinafter referred to as NCWA-II). So far as the JBCCI is concerned it has already standardised a number of jobs and also provided job descriptions. The type of job involved in the instant case has not so far been finalised but the management has already made a reference in this regard and the Standardisation Committee is already seized of the matter and decision is awaited soon. So far as NCWA(II) is concerned it is a settlement within the meaning of Sec. 2(p) of the Act in as much as copies of the agreement, which is tripartite one, between several companies including M/s. Indian Iron and Steel Company Limited, representing the management, and several trade unions, including INTUC, to which the sponsoring union, the Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh is affiliated, representing the workers, were duly forwarded to the appropriate authorities under Rule 58(4) of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957 (hereinafter referred to as the Rules). Since the settlement is still subsisting and has not been terminated, no industrial dispute can be raised during the pendency of the settlement. This was pointed out to the conciliation officer, but he lost sight of the matter, and, without jurisdiction, proceeded with the conciliation proceedings and submitted a failure report to the Govt. of India recommending a reference to an Industrial Tribunal. The employers as also the workmen are bound by the decision of the Standardisation Committee as approved by the JBCCI, and, therefore, in case this Tribunal proceeds with the reference and gives any findings, there may be a conflict of decision which is not warranted, apart from the fact that the employers as also the workmen have already selected their forum, and, therefore, the present reference is bad and not maintainable before the Tribunal.

5. Parties have led both oral and documentary evidence in support of their respective cases.

6. At the time of hearing there did not appear to be any difference or dispute between the parties regarding the type or work that the concerned workmen have been doing in Noonodih-Jitpur colliery. S. H. Rahman (WW-1), who is the only witness examined on behalf of the concerned workmen, has stated in his examination-in-chief that he was working in Noonodih-Jitpur colliery since 1974 and since June 1977 he was doing the work of un-loading rails from truck on which they are brought from Chasnala colliery and he carries them to the workshop of Noonodih-Jitpur colliery and other concerned workmen are also doing these jobs since 1977. He has further deposed that thereafter he and other concerned workmen get those rails cut to various sizes by the machine men of the workshop, and thereafter they carry those rail pieces of different sizes to the pit top of the colliery and thereafter some of the concerned workmen go down the mines with those rails in a cage and inside the mine those rails are again un-loaded by some of the concerned workmen and taken to a place of storage, and similarly heavy gutters are also handled by the concerned workmen. He has further deposed that he and other concerned workmen also un-load arches which are brought from Chasnala colliery and take them inside the mine in the same manner and they also carry props, ventilation pipes and wooden sleepers inside the mines on cage which are operated by electric lifts, and they also carry damaged and defective arches and pipes from inside the mine to the ground surface with the help of cages, and these are all the works which he and other concerned workmen do. His aforesaid evidence in the examination-in-chief regarding the types of work that he and other concerned workmen have been doing in Noonodih-Jitpur colliery has not been challenged by the management in his cross-examination, and, on behalf of the management, it has only been suggested in his cross-examination that the type of work about which he had deposed in his examination-in-chief are all work required to be done by general un-skilled mazdoors, which he has, of course, denied. A. K. Chatterjee (MW-1), who is an Asst. Supdt. in Jitpur colliery, has also stated in his very examination-in-chief that the concerned workmen do the work of lowering timbers, cozzing, sleepers, arches, girders and rails inside the mine from the surface level. In his cross-examination he has also admitted that heavy material such as arches, joist, rails etc. are brought from Chasnala colliery to Jitpur colliery by truck and the concerned workmen un-load those materials from truck and take them to the workshop for cutting the

rails to different required sizes and thereafter those materials are carried by the concerned workmen to the pit top and then they lower them down underground with the help of cages and they also un-load these materials from the cages and store them at the pit bottom and they also carry arches from the pit head to the underground in cages and un-load them at the pit bottom. His evidence in his examination-in-chief that the concerned workmen do not carry drums of oil or greases nor they are employed in erection or dismantling of structures or installation or withdrawal of machinery, has not been challenged on behalf of the workmen in his cross-examination.

7 From the aforesaid evidence adduced by the parties it would, thus, appear, as has already been stated above, that there is no dispute between the parties regarding the types of work that the concerned workmen have been doing at Noonodih-Jitpur colliery.

8 It is, however, the case of the management that the types of work which the concerned workmen are admittedly doing do not conform to the job description of Tyndals mentioned under item No. 5 of Cat IV at page 46 of Appendix-V of Vol II of the Central Wage Board recommendations which has already been quoted above. The case of the management on his point is that since according to their own case and evidence the concerned workmen are not employed in moving drums of oil and greases nor are they responsible for erection, dismantling of structures and installation and withdrawal of machinery, they cannot come under that category of Tyndals and their work being that of general unskilled mazdoors they have been put in Cat II or III as the case may be according to the nature of work that they are doing.

9 On the other hand it has been contended by Mr Bose appearing for the workmen that prior to the recommendations of the Central Coal Wage Board there was Mazumdar Award as confirmed by the Labour Appellate Tribunal and modified by Das Gupta Award according to which the job description of "Tyndal (Light)" for colliery under Item No. 90 at page 77 of Appendix XI of Vol-II of the Mazumdar Award was "Men generally employed in moving engineering stores, drums of oil and greases etc", the job description of "Tyndal (Heavy)" as given in Item No. 98 at page 78 was "A workman employed in moving heavy objects or in engineering erection work under the direction of Tyndal Supervisors or Jamadars", the job description of Tyndals (Heavy) for workshop under Item No. W 29 at page 85 was "See job description for Colliery Tyndals. These men handle machinery at the workshop and also work at collieries from time to time, particularly in erection and dismantling work," and the job description of "Tyndal (Ordinary)" under Item No. W 30 at the same page was "These men do general tyndals' work but are not usually employed on erection work requiring skill. They are mainly employed on the moving of stores etc and the loading and unloading of lorries", and under Appendix XII at page 88 Tyndals (Light) were placed under Cat IV and Tyndals (Heavy) were placed under Cat VI, but all types of tyndals whether in Cat IV or in Cat VI of the Mazumdar Award were put under one Cat IV under the Coal Wage Board recommendations when 10 categories of Mazumdar Award were compressed into 6 categories, and hence the concerned workmen who are atleast doing some of the jobs of Tyndals mentioned in the Mazumdar Award or jobs similar to that should be placed under Cat IV of the Wage Board recommendations as Tyndals.

10 The main contention raised by Mr T. P. Choudhury appearing for the management, however, was that since the work done by the concerned workmen do not in term conform to the job description of Tyndals mentioned under Item No. 5 of Cat IV of Wage Board recommendations and since the use of girders and arches, which also the concerned workmen lower inside the mine, are new techniques which have come into use round about the year 1972 or 1973 and consequently no reference about them are to be found in the job descriptions given either in the Mazumdar Award of the year 1956 or in the Wage Board recommendations of the year 1967 a reference was made by the management in the year 1980 by its letter dated 23.9.80 (Ext. M-4) to JBCCI as per clause 12.7.2 of NCWA(II) to which agreement the management as well as the INTUC to which the concerned workmen's Union, the Rashtriya Colliery Maz-

door Sangh, is affiliated, are parties, and since that reference is still pending for consideration by the Standardisation Committee of JBCCI, the present reference by the Central Government to this Tribunal is incompetent as the said NCWA(II) is a settlement within the meaning of Sec 2(p) of the Industrial Disputes Act inasmuch as copies of the agreement which is a Bi partite one was duly forwarded to the appropriate authorities under Rule 58(4) of the Rules by Memo No. CSC/JBCCI/458 dated 13.8.1979 (Ext. M-3) under the signature of Sri R. S. Murty (MW-2) who was formerly Director (Personnel) Central Coalfields Ltd and was a Member-Secretary of JBCCI, and who has proved the said Memo.

11 Mr Bose appearing for the union has, however, challenged the NCWA(II) being a settlement within the meaning of Sec 2(p) of the I. D. Act on the sole ground that the aforesaid forwarding memo (Ext. M-3) was signed only by the Member-Secretary, Sri R. S. Murty (MW-2) and it was not jointly signed by all the members of JBCCI although the requirement of Rule 58(4) of the Rules is that the parties to the settlement shall jointly send the copies thereof to the different authorities concerned. This was the only objection raised by Mr Bose to the aforesaid argument of Mr T. P. Choudhury.

12 It may, however, be mentioned that NCWA(II) is itself jointly signed by all the members of JBCCI and the aforesaid objection of Mr Bose is only regarding the aforesaid forwarding Memo No. CSC/JBCCI/458 dated 13-8-79 (Ext. M-3) under which copies of NCWA(II) were forwarded to the authorities concerned and which is also signed by Sri R. S. Murty, Member-Secretary, but, which according to Mr Bose, should also have been signed by all the members of JBCCI. I may, however, mention here that the requirement of Rule 58(4) of Rules is only that the settlement arrived at between the employer and his workmen otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be sent by the parties to the settlement jointly to the different authorities concerned and not that its forwarding memo shall be jointly signed by them. In the present case the forwarding memo (Ext. M-3) was signed by Sri R. S. Murty Member-Secretary of JBCCI, obviously on behalf of all the members constituting the Committee, and, consequently it could not but be said that it was sent jointly by them, and hence there was compliance of the aforesaid Rule 58(4) of the Rules and it was not necessary that the forwarding memo should also be signed by all the members constituting the committee when those members had already signed the NCWA(II).

13 Moreover, in a Division Bench decision of the Orissa High Court in the case of Kalinga Jute Products (Pvt.) Ltd. Vs Presiding Officer, Industrial Tribunal and others [1980 (I) LJ 239], it has been held that the requirement of the rule that copies of the settlement shall be jointly sent is a requirement in excess of Sec 2(p) of the Act and it cannot be held, therefore, to be mandatory. In that decision a reference has also been made to Sec 18(1) of the Act which provides that a settlement arrived at by agreement between the employer and the workmen otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be binding on the parties to the settlement and also to Sec 19(1) of the Act which provides that such settlement shall come into operation on such date as is agreed upon by the parties to the dispute and if no date is agreed upon, on the date on which the memorandum of settlement is signed by the parties to the dispute and reading both these provisions together it has been further held in that decision that it not the intendment of law that the said operation is to be kept in abeyance until after a copy has been jointly sent, and viewed from this angle also requirement of joint sending is not mandatory so as to affect the validity of the settlement or its coming into operation. The rule of joint sending has therefore been held to be only directory, and not mandatory which should not be allowed to invalidate a settlement. In support of the aforesaid view a Supreme Court decision in the case of State of Madras Vs C. P. Saithy and another [(1953) (i) LJ 174] has also been cited.

14 In view of my aforesaid finding that the sending of copies of NCWA(II) to the parties concerned under Memo No. CSC/JBCCI/458 dated 13-8-79 by Sri R. S. Murty (MW-2) Member-Secretary of JBCCI, was joint sending by the members of JBCCI and there was full compliance of

the provisions of Rule 38(4) of the Rules, the aforesaid decision of the Orissa High Court need not in the present case be pressed into service to hold that NCWA(II) is a settlement within the meaning of Sec. 2(p) of the Act. But even without my aforesaid finding, NCWA(II) would be a settlement within the meaning of Sec. 2(p) of the Act in view of the aforesaid decision of the Orissa High Court according to which the requirement of joint sending of copies of the agreement to the authorities concerned is only directory and not mandatory and non-sending of it does not affect the validity of the settlement or its coming into operation. I, therefore, hold that in either view of the matter, NCWA(II) is a settlement within the meaning of Sec. 2(p) of the Act.

15. Clause 12.1.2 of the Agreement under Chapter XII at page 21 of NCWA(II) provides that this agreement would be in operation for a period of 4 years with effect from 1-1-79. According to the terms of the agreement, therefore it is to continue till 31-12-82. Sec. 19(2) of the Act provides that a settlement shall be binding for such period as is agreed upon by the parties, and shall continue to be binding on the parties after the expiry of the period aforesaid, until the expiry of two months from the date on which a notice in writing of an intention to terminate the settlement is given by one of the parties to the other party or parties to the settlement. Therefore the settlement under NCWA(II) will continue even after 31-12-82 and also thereafter until one or the other party gives written intimation of the intention to terminate the settlement and until expiry of two months from the date of such intention [See Shukla Manseta Industries Pvt. Ltd. Vs. Workmen, 1977 (II) LLJ. 339].

16. Clause 12.7.1 of NCWA(II) provides for a Standardisation Committee and it is agreed that with a view to examine and standardise different designations, job descriptions, disparities in service conditions among different sets of employees including hours of work leaving days, categorisation of jobs or whether there is obvious and also to examine such anomalies as may be brought to the notice of the Committee, a Standardisation Committee consisting of representatives of employees and representatives of the management shall be constituted. Clause 12.7.2 of the Agreement further provides that the functions of the Standardisation Committee shall, inter-alia, be to review and examine the reports of several sub-committees including the sub-committee B constituted by JBCCI on new jobs and categorisation and preparation of job description for old jobs (where they did not exist) for underground mines, and the first function of the Standardisation Committee would be to take up the unanimous recommendations of the sub-committees mentioned above with a view to co-ordinate them, resolve anomalies, if any, that may arise and recommend action for their implementation and it will thereafter examine those reports of the sub-committees where different opinions about the category to be awarded to specific jobs or any other differences of opinion have been expressed by representatives of the workers and managements, and to resolve the same. It is also the function of the Standardisation Committee to consolidate the job descriptions of different jobs available in different documents and also to examine all cases of anomalies and disparities in regard to the job description, categorisation and principle service conditions of employees brought to its notice.

17. It was in pursuance to the aforesaid terms of the agreement of NCWA(II) that the management by its letter dated 23-9-80 (Ext. M-4) referred several cases to JBCCI for categorisation of new jobs which were created in different collieries after NCWA(I) including the following :—

“Material lowering gang.—This gang lowers materials like rails, girders, arches, timber etc. from surface to underground. They are mostly placed in Cat. II and they are demanding designation and category of tyndal. There is different jobs description of tyndal in wage board award.”

In the aforesaid letter the management requested the JBCCI to take up the matter in the next Standardisation Committee meeting as the concerned employees were very much restive and approaching the management for their proper categorisation and raising industrial disputes and creating industrial relations problems. The Standardisation

Committee of JBCCI has not as yet given its decision on the aforesaid reference made by the management but is seized of the problem and a decision is expected. The Union of the concerned workmen which is, affiliated to INTUC is bound by NCWA(II) which, as already held, is a settlement, and they having agreed that all cases of anomalies and disparities in regard to the job description, categorisation and principle service conditions of employees brought to the notice of the Standardisation Committee shall be examined and resolved by the Standardisation Committee consisting of representatives of employees and representatives of the management, cannot raise any industrial dispute on that score to be decided by the Industrial Tribunal so long that settlement is in force and effect. In the case of Shukla Manseta Industries Pvt. Ltd. vs. Workmen [1977 (II) LLJ. 339], the Supreme Court has reiterated the legal position that where a settlement has been arrived at and has not been terminated in accordance with Sec. 19(2) of the Act any reference made by the Government of a dispute during the period of settlement will be invalid. The Punjab and Haryana High Court in the case of Atlas Cycle Industries Ltd. Vs. Industrial Tribunal, Haryana and others [1973 (I) LLJ. 182] has expressed a similar view that a matter covered by settlement cannot be subject matter of a reference during the currency of such settlement. The same view has been expressed by the Orissa High Court in the case of Kalinga Iute Products (Pvt.) Ltd. Vs. Presiding Officer, Industrial Tribunal and others [1980 (I) LLJ 239].

18. Then there is another aspect of the matter. It may be argued on behalf of the workmen that NCWA (II) simply provides for constitution of a Standardisation Committee consisting of representatives of the employees and representatives of the management to examine and resolve all cases of anomalies and disparities in regard to the job description, categorisation and principle service conditions of employees brought to the notice of the Standardisation Committee, but it does not per se settle the present dispute of the concerned workmen which has been referred to this Tribunal for adjudication and hence NCWA (II), even if it is held to be a settlement, does not debar this Tribunal from adjudicating the dispute in question. Though this argument was not advanced before me by Mr. Bose appearing for the workmen, I have considered it necessary to take care of that aspect of the matter also as it may be a possible argument on behalf of the workmen.

19. A similar question had been raised before the Punjab and Haryana High Court in the aforesaid case of Atlas Cycle Industries Ltd., Vs. Industrial Tribunal, Haryana and others [1973 (I) LLJ. 182]. In that case a general settlement had been made between the management and the workmen which provided that all matters in dispute arising from time to time between the management and the workmen shall be referred by either party to a settlement board consisting of five representatives of the workmen and five representatives of the management which will be presided over by an executive to be appointed by the management, and the settlement board will endeavour to take decision on the disputes referred to the board, but if unanimous decision is not possible in any case, the matter would be referred to the executive director/works director for his decision is not in case the decision of the executive works director is not acceptable to the workmen, it would be open to them to seek any remedy which may be available under any law in force. The point involved in that case was whether during the currency of such settlement the question whether the dismissal of a workman was proper or otherwise can be referred to the Industrial Tribunal at the instance of a workman without first exhausting the remedies provided under the settlement. The argument of the management was that the settlement makes it obligatory for the aggrieved workman to take advantage of the procedure and the machinery set up for amicable settlement of the dispute before resorting to legal remedies available to him under the Act. The Industrial Tribunal was, however, of the view that the power of the Government to make reference cannot be curtailed simply on the ground that the workman concerned did not take recourse to the procedure laid down in the settlement. It was ruled by the Industrial Tribunal that, under subsection (1) of Section (10) of the Act, the Government had statutory power to refer a dispute and all that is necessary is that an industrial dispute should exist or should be apprehended and, secondly, the Government should consider

to expedient to make a reference. It was, therefore, held by the Industrial Tribunal on that the validity of the reference cannot be challenged. It was against that decision of the Industrial Tribunal that the management had filed a Writ petition in the High Court. In that case the main argument in the High Court advanced on behalf of the workmen was that the settlement was not a settlement qua-demand raising an industrial dispute and that the dispute was not covered by the settlement. The whole basis of this argument was that settlement must be with regard to an existing dispute. The argument was, however, negated by the High Court on the ground that there can legitimately be a settlement between the parties providing for a reasonable and quick procedure saving the workmen as well as the management from unnecessary litigation which takes a very long time for the dispute to be finally settled in case the matter is referred to an Industrial Tribunal. Thus, the settlement with regard to the procedure cannot be said to be outside the purview of the "settlement" as defined in the Act on the ground that the same did not relate to an existing industrial dispute. So far as the argument advanced on behalf of the workmen that the dispute was not covered by the settlement is concerned, it was held by the High Court to have no force for the simple reason that the matter how the grievances of the workmen are to be settled in first instance, was specifically provided in the settlement. In that case the grievance of the workmen was that he was wrongly dismissed. That was certainly a matter which could be referred to a settlement board and if the workman did not find satisfaction with the decision either by the Settlement Board or the Works Director, as provided, it was open to him to proceed under the Act. For these reasons it was held that before exhausting the remedies as provided in the settlement, the workman could not approach the conciliation officer and the conciliation officer had no jurisdiction to go into the matter before the procedure laid down in the settlement had been followed, and, for the same reason, the matter could not be referred to the Industrial Tribunal either. In the circumstance the writ application filed by the management was upheld and the decision of the Industrial Tribunal was quashed.

20. Relving on the aforesaid decision of the Punjab and Harvana High Court I, therefore, also negative the aforesaid possible argument referred in para 18 above which, though not advanced before me by Mr. Bose appealing for the workmen, could possibly be an argument on their behalf.

21. Finally, therefore, I hold that so long the NCWA(M), which has been held to be a settlement, is in force and effect which has provided for a Standardisation Committee consisting of representatives of employees and representatives of the management to examine and resolve all cases of anomalies and disparities in regard to job description, categorisation and principle service conditions of employees brought to its notice, to which the management has already referred the dispute for decision and which is seized of the matter and the decision whereof is awaited, the present dispute cannot be referred to the Industrial Tribunal for adjudication, and hence the reference is held to be invalid. In that view of the matter I need not express any opinion on the merit of the dispute. In the circumstance of the case, however, there will be no order for cost.

Sd/-

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.
[No. I 20012(277)/80-D. III (A)]

S.O. 56.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Co. Limited Post Office Chasnalla, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No 18 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of M/s. Indian Iron and Steel Company Limited, Post Office Chasnalla, District Dhanbad

AND

Their Workmen

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Pre-siding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri T. P. Choudhury, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar.

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad the 2nd December, 1982

AWARD

The present reference arises out of Order No. L-20012-(125)/80D.III(A) dated 24-9-1980 passed by the Central Government in respect of an industrial dispute between the parties mentioned above. The subject matter of the dispute has been specified in the schedule to the said order and the said schedule runs as follows :—

"Whether the demand of the workmen of Noonodih-Jitpur Colliery of Messrs Indian Iron and Steel Company Ltd, Post Office Bhaga, District Dhanbad that Sarvashri K. C. Nagpal, S. N. Tiwari and G. P. Singh should be promoted as Grade-I Clerk from the date their juniors were promoted is justified? If so, to what relief are the said workmen entitled?"

2 The dispute has been settled out of Court. A memorandum of settlement dated 2-12-1982 has been filed in Court. I have gone through the terms of settlement and I find them quite fair and reasonable. There is no reason why an award should not be made on the terms and conditions laid down in the Memorandum of Settlement. I accept it and make an award accordingly. The memorandum of settlement shall form part of the award.

3. Let a copy of this award be sent to the Ministry as required under Section 15 of the Industrial Disputes Act, 1947

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer.
[No. L-20012(125)/80-D.III(A)]

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

Reference No. 18 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Noonodih-Jitpur Colliery of M/s IISCO Ltd.,

AND

Their Workmen.

PETITION OF COMPROMISE

In the matter of adjudication above dispute both the parties have agreed to settle their differences amicably and after a number of discussions it has been agreed as follows :—

1. That the concerned workmen S/Shri K. C. Nagpal, S. N. Tiwary and G. P. Singh will be placed in clerical Grade I by the employers from the date of this compromise petition in terms of which an Award is to be given.
2. That the above named workmen shall be given notional seniority from the date the other persons namely S/Shri K. Prasad, K. P. Tiwary and others were placed in clerical Grade I i.e. from 1-4-79.
3. That the concerned workmen shall not be paid nor entitled to any back wages or arrears or any other financial benefits for the period from 1-4-79 till the date of Award.
4. That the concerned workmen shall be given fitment from 1-11-82 and annual increment in the new grade with effect from 1-3-83 as per provisions of NCWAI like those who were promoted earlier.
5. That both the parties agree that no claim/dispute and/or new interpretation will be made or given by either party in the context of above terms of the compromise petition, at any time in future.

That since the above terms of settlement forming the petition of compromise are fair and reasonable both the parties have jointly agreed and accepted the same, the compromise petition is filed before the Hon'ble Tribunal.

That both the parties, therefore, pray that the Hon'ble Tribunal will be pleased to record this compromise petition and give its Award in terms thereof and a copy of this compromise petition may be made a part of the Award

For & on behalf of the
Employers.
Sd/-

For & on behalf of the Workmen/
Union
Concerned Workmen.
1. K. C. Nagpal
2. S. N. Tewari
3. G. P. Singh

Part of the Award.

ORDER

S.O. 57.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jealgora Central Hospital, Bhowra Area of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office, Jealgora District Dhanbad and their workmen which was received by the Central Government on the 9th December 1982.

BEFORE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, NO. 3, DHANBAD

Reference No. 81/82

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jealgora Central Hospital, Bhowra Area of M/s. Bharat Coking Coal Ltd, P.O. Jealgora, Dist. Dhanbad

AND

Their workman.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri R. S. Murthy, Advocate.

For the Workman—Shri S. Bose, Secretary R.C.M.S.

INDUSTRY : Coal.

STATE : Bihar.

Dated the 2nd December, 1982

AWARD

The Govt. of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No L-20012-(101)/82-D.III(A) dated the 9th August, 1982.

SCHEDULE

"Whether the demand of the workman of Jealgora Central Hospital, Bhowra Area of M/s. Bharat Coking Coal Ltd., P.O. Jealgora, Dist. Dhanbad, that Shrimati Mithila Kamin should be regularised on the post of Aya and paid wages as per the National Coal Wage Agreement is justified? If so, to what relief is the said worker entitled?"

2. On 29-11-1982 both the parties have filed a joint petition of compromise duly signed on their behalf and they pray that an award be passed in terms of the settlement.

3. I have gone through the settlement which is beneficial for the workman.

4. In the circumstances the award is passed in terms of the settlement which shall form part of the award.
Enc : Settlement.

Sd/-

J. N. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012/101/82-D.III(A)]

"MEMORANDUM OF SETTLEMENT"

Representing Management

Representing Workman.

1. Shri J.M. Gupta,
Agent, Jealgora Colliery.

1. Sri G.D. Pandey Secy.
RCMS.

2. Sri N.K.P. Sinha,
P.M. Bhowra Area.

2. Smt. Mithila Devi.

SHORT RACITAL

An Industrial dispute was raised by RCMS over alleged denial of grade of Aya to Smt. Mithila Devi, PR worker of Jealgora Hospital. Smt. Mithila Devi was originally designated as wagon loader and placed in group III. Subsequently she was transferred to work at Jealgora hospital as unskilled mazdoor in Group I there she deployed as Aya since there was no job of PR unskilled mazdoor. The matter was discussed at length and mutually agreed by both the parties on the following terms of settlement:—

1. Smt. Mithila Devi shall be designated as Aya and placed in grade II under Coal Mines Wage Board Recommendations. Her basic wages will be fixed under NEW Gr. II.

2. The dispute is finally decided and she shall not claim any back wages whatsoever.

3. The above agreement shall be effective from the date it is signed by both the parties.

4. A copy of agreement shall be sent to the concerned authority under Sub-Section 4 of Section 58 of Industrial Disputes Central Rules, 1957 for registration.

Representing Management

Representing Workman.

1. Sri J.M. Gupta,
Agent, Jealgora Colliery

1. Sri G. B. Pandey, Secy.
RCMS.

2. Sri N.K.P. Sinha,
Personnel Manager,
Bhowra Area.

2. Smt. Mithila Devi.

Witnesses:

1.

2.

New Delhi, the 17th December, 1982

S.O. 58.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bagdigi Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Lodna, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 1 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Bagdigi Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Lodna, Dist. Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice Manoranjan Prasad (Retd.) Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary, Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh.

STATE : Bihar

INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, dated the 17th December, 1982

AWARD

By Order No. L-20012/160/80.D.III(A) dated the 24th December, 1980, the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the demand of the workmen of Bagdigi Colliery of Messrs, Bharat Coking Coal Limited, Post Office Lodna, District Dhanbad that Shri Giasuddin, Clerk Grade-II should be placed in Clerical Grade-I is justified? If so, to what relief is the said workman entitled?"

2. The case of the concerned workman, Giasuddin, is that he joined service at Bagdigi Colliery in June, 1963, and since 1973 he was placed as provident fund incharge and was being paid Clerical Grade-II wages. In 1976 and 1977 the management upgraded workman according to the nature of duties performed by each of them after taking their seniority into consideration. As section incharge of the provident fund he should have been placed in Clerical Grade-I from 1973, but the management deprived him from his legitimate claim and kept him in Clerical Grade-II. Thereupon he made representation to the management for considering his case and upgrading him from Clerical Grade-II to Grade-I, but to no effect. Thereafter the Union of the concerned workmen took up the matter with the management but when that also proved to be of no avail, the Union placed the dispute before the Asstt. Labour Commissioner (C), Dhanbad for conciliation which also ended in failure, and the Asstt. Labour Commissioner (C) submitted a failure report to the Central Government whereupon this reference has been made to this Tribunal for adjudication. On these grounds the claim of the concerned workmen is that he should be placed in Clerical Grade-I from 1973 with proper seniority and he should be paid the difference of wages.

3. The case of the management, on the other hand, is that the concerned workman joined at Bagdigi Colliery on 2-11-76 after being transferred from North Tisra Colliery where he worked from 20-7-76 to 1-11-76 as clerk and at the time of his transfer he was a provident fund clerk in

Grade-II. The Bagdigi colliery has man power strength of 2000 approximately and to deal with matters connected with provident fund, the management has engaged four provident fund clerks including the concerned workman, and the duties have been distributed amongst the four clerks. The concerned workman does clerical works mainly connected with and incidental to forms A, M, H and W as prescribed under the Coal Mines Provident Fund Scheme. He handles the correspondence files pertaining to the provident fund matters. The other three clerks carry on duties connected with other forms, cards and returns and registers. All the four provident fund clerks have been placed in clerical Grade II according to Coal Wage Board recommendations and National Coal Wage Agreements. According to Coal Wage Board Scheme certain clerks like cashiers, store keepers, head clerks etc. are placed in Grade-II as well as in Grade-I, but rest of the clerks are placed in Grade-III and Grade-II. The maximum grade provided for a provident fund clerk is Grade-II. The head clerk (senior) is the controlling clerk of the office under whom provident fund clerks, bonus clerks, bill clerks, time keepers etc. work. When the head clerk (senior) is placed in Grade-I, it is absurd to place a provident fund clerk in the same grade. There was no post of provident fund incharge nor the concerned workman ever worked as section-incharge and there is also no rule for granting Grade-I to section-incharge. The management, however, considers the cases of all Grade-II clerks in the establishment for promotion to Grade-I to fill up the vacancies in Grade-I, and Departmental Promotion Committee has been constituted for the purpose, and the usual norms for promotion are seniority-cum-suitability. The Departmental Promotion Committee constituted in the year 1977 considered the case of the concerned workman for promotion to Grade-I along with others but did not recommend his case for promotion. On these grounds the contention of the management is that the concerned workman is not entitled to any relief.

4. It is, however, worthwhile to note that during the pendency of the present reference, the concerned workman has been, by management's Office Order No. GM:LA:PER:EST DPC-M.S.82/6513 dated 17-8-1982 (Ext. W-1), promoted from Grade-II to Grade-I with effect from 29-7-82 on the recommendation of Departmental Promotion Committee, and, therefore, the case of the concerned workman in the present reference is now confined to his claim for promotion from Grade-II to Grade-I from 1973 to 28-7-1982 on the sole ground that during that period he worked as provident fund incharge.

5. It is the admitted case of the parties that the concerned workman is working in the provident fund section of Bagdigi colliery. The case of the management, however, is that he is working there simply as provident fund clerk along with three other provident clerks and he has been rightly placed in Grade-II which is the grade provided for provident fund clerks under the heading "Clerical Staff Grading and Nomenclature" in Appendix VI at page 54 of Vol-II of the Coal Wage Board recommendations which has been approved by the Government of India, Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Deptt. of Labour & Employment) by Resolution No. WB-16(5)/666 dated 21-7-1967 with effect from 15-8-1967 and that there is no post of provident fund incharge in the said colliery nor the concerned workman ever worked as provident fund incharge nor any post of provident fund incharge has been placed in Grade-I in the aforesaid Appendix VI. On the other hand, it is the case of the concerned workman that he was placed as provident fund incharge since 1973 and hence he should be placed in clerical Grade-I from 1973. The concerned workman Giasuddin, who has examined himself as WW-1, has stated in his very examination-in-chief that once a written order was given by the management allotting duties to different clerks of the provident fund section including himself in the year 1977. In his cross-examination he has further stated that in the office order which was issued in the year 1977 it was mentioned that his duty will be to supervise the work of other clerks of the provident fund section but it was not mentioned therein that he would be incharge of the section and that office order might be in the file in his office and he might be able to show it to this Tribunal later on; but no such office order has ever been shown or filed. In his cross-examination he has further admitted that there is no order of the company appointing him as incharge of provident fund section nor any circular has been issued by the management to the effect that in every section there would be a section incharge who would be placed in Grade-I. At the end of his cross-examination he has again stated that the management never declared him in writing as section incharge of provident

fund section, but he has added that the management took from him the supervision work of the section which pertains to the duties of a section-incharge. No paper has, however, been filed to show that he did any supervisory duty in that section. In fact, his statement in his cross-examination is that he has been regularly filling up forms A, M, H and W under the Coal Mines Provident Fund Scheme and the other three clerks in the provident fund section similarly fill up other forms, returns and registers under Coal Mines Provident Fund Scheme. The position, therefore, is that there is neither any order of the management creating any post of provident fund incharge in the provident fund section, nor there is any order appointing the concerned workman as provident fund incharge nor there is any evidence to show that the concerned workman supervised the work of other clerks of provident fund section, and, on the other hand, from the own evidence of the concerned workman it appears that he is working only as a clerk in the provident fund section as any other clerk in that section.

6. The only paper on which the concerned workman banks is a letter dated 9-12-1978 (Ext. W-2) written by the Superintendent, Bagdigi Colliery, to the Regional Commissioner Zone 'C', Coal Mines Provident Fund, Dhanbad, in which it has been stated "For verification of the declaration form 'A' we are sending our P.F. Sec. Incharge Md. Giyasuddin who will verify the age/date of birth of 8 workers said in previous letter and one Sri Hiram Mahato a/c. No. C/222432." According to the concerned workman, Giyasuddin (WW-1), he was sent with this letter by the Superintendent, Bagdigi Colliery, to the office of the Regional Commissioner Zone 'C', Coal Mines Provident Fund, Dhanbad, for verification of declaration Form A which he did. He relies on that part of the letter in which he has been described as "P.F. Sec. Incharge". In that letter he might have been described as provident fund section incharge as, according to his own evidence, he was incharge of filling up Form A which was required to be verified in the office of the Regional Commissioner Zone 'C', and, in any case, simply because in the said letter he was described as provident fund section incharge he cannot become provident fund section incharge when there was neither any such post nor there was any order of the management appointing him as provident fund section incharge.

7. It is also worthwhile to mention that in the aforesaid "Clerical Staff Grading and Nomenclature" in Appendix VI at page 54 of Vol-II of Coal Wage Board recommendations there is no post of provident fund section incharge in Grade-I in which only some senior posts appear.

8. On the evidence on record, as discussed above, I, therefore hold that the concerned workman, Giyasuddin, never worked as section incharge of provident fund section nor he ever supervised the work of that section and in no view of the matter he is entitled to be placed in Grade-I from 1973 to 28-7-82 and to be paid difference of any back wages for that period i.e. prior to his getting the promotion from Grade-II to Grade-I in due course with effect from 29-7-82 on the recommendations of the Departmental Promotion Committee under management's letter dated 17-8-82 (Ext. W-1). The award is made accordingly. In the circumstance of the case there will be no order as to cost.

MANORANJAN PRASAD, Presiding Officer

[No. L-20012/160/80-D.III(A)]

S.O. 59.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 3, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Badjna Colliery of Messrs Eastern Coalfields Limited, Post Office Nirshachatti, District Dhanbad, and their workmen, which was received by the Central Government on the 13th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 3, DHANBAD

Reference No. 30/81

PRESENT :

Shri J. N. Singh, Presiding Officer.

PARTIES :

Employers in relation to the management of Badjna Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Nirshachatti, Dist, Dhanbad

AND

Their workman

APPEARANCES :

For the Employers—None.

For the Workman—None

INDUSTRY : Coal.

STATE : Bihar

Dated, the 3rd December, 1982

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them U/s 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 14 of 1947 has referred the dispute to this Tribunal for adjudication under Order No. L-20012(64)/81-D.III(A) dated the 23rd June, 1981.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Badjna Colliery of M/s. Eastern Coalfields Ltd., P.O. Nirshachatti, Dist. Dhanbad in not placing Shri Chandradeo Mishra in Clerical Grade-I as Loading Supervisor in Incharge with effect from the 1st May, 1973 is justified? If not, to what relief is the said workman entitled?"

2. The present reference was registered by this Tribunal on 1-7-1981 and notices were issued to the parties. After several notices Sri T. P. Chowdhury Advocate for the management and Sri Bose, Advocate for the union appeared and on all most all the dates fixed in the case they took time on the ground that the matter is to be settled outside Court and that settlement will be filed shortly. For filing settlement or for filing written statements several adjournments were granted by the Court, but to no effect. On the last date it was submitted by the Advocate for the management that one chance more may be given to the parties either to file settlement or to file written statements. But inspite of the last chance also neither written statement or settlement has been filed in this case.

3. From the order-sheet it appears that the parties are not taking any interest in the Reference and it appears that there is no dispute between the parties.

4. In the circumstances a 'no dispute' award is passed.

J. N. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-20012/64/81-D.III(A)]

S.O. 60.—In pursuance of section 17 of the industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2 Dhanbad in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Govindpur Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL (NO. 2), DHANBAD

Reference No. 24 of 1980

In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)(d) of the
I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Govindpur
Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited,
Post Office Sonardih, District Dhanbad and their
workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri G. Prasad, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary,
Rastriya Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.
Dhanbad, the 30th November, 1982

AWARD

This is a reference under S. 10 of the I.D. Act, 1947. The Central Government by its order No. L-26012(75)/80-D.III(A) dated 25th September, 1980 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

THE SCHEDULE

"Whether the demand of the workmen of Govindpur Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih District Dhanbad that Shri Shamsul Khan should be allowed to resume duty and regularised as car cleaner, with full wages for the period of his idleness is justified. If so, to what reliefs the said workman entitled."

2. The case of the concerned workman is that he was employed as car cleaner, Area No. III from December, 1973 and worked continuously upto 13-9-75 when he was stopped from duty. The stoppage is said to have been done by the management without any reason and without issuing any notice. The workman was paid on voucher and in ordinary course his service should have been regularised with the passage of time, but since he approached the management to regularise him in the job, he was stopped from work. This action of the management is said to be illegal, arbitrary and an unfair labour practice. His further case is that he approached the local officers of the management who were pleased to forward his case to the Headquarter (Personnel) for absorption of the workman in the employment of M/s Bharat Coking Coal Limited. Thereafter the workman and his union made several efforts to settle the matter and ultimately when the management did not do anything the union raised an industrial dispute resulting into this reference for adjudication.

3. The plea taken by the management is that Shri Shamsul Khan was never a workman and he was never a car cleaner. The relationship of employer and employee is denied. A point was raised that the area office of BCCL is not a mine and the concerned workman could not be said to be an employee of the mine so as to confer the jurisdiction of the Central Government to make this reference. The management wanted to decide the question of jurisdiction as preliminary point and after a hot contest it has been held by this Tribunal in a separate order dated 5-5-82 that the reference is maintainable. Ordinarily therefore the only question to be decided in this reference is as to whether the concerned workman Shri Shamsul Khan should be allowed to resume duty and regularised as car cleaner with full wages for the period of his idleness. On behalf of the management, however an argument has been advanced by Shri G. Prasad, Advocate that since in the evidence the concerned workman stated to be a car cleaner in Area No. 1 and the schedule of the reference says that he is a workman of Area No. III, this Tribunal cannot enlarge the scope of this reference to consider the case of the concerned workman. So the reference should be rejected on this ground alone. We have therefore to answer this reference in the light of the two points indicated above

4. I would like to first deal with the case of the management that the concerned workman could not get any relief because according to the workman he worked in Area No. I and the relief is sought against Area No. III. In the written statement of the workman the workman is said to be a car cleaner in Area No. III. Shri Shamsul Khan, WW. 1 in his evidence has said he was a khalasi doing the job of car cleaner in the office of the General Manager of the Area No. I at Sijua. He was doing this work from December, 1973 to September, 1975. His evidence further is that in 1974 he demanded to be made permanent and the Area Personnel Manager of that area prepared papers and sent the same to the headquarters for making his service permanent. He has said that in the meanwhile there was reorganisation of the areas and his area was shifted to Govindpur Area No. III. He has said that at the time of transfer of the area the management had stopped him from work. In his cross-examination he has said that Govindpur Area No. III is at a distance of 10 Kms. from Sijua and that he never worked in Govindpur Area No. III. From the evidence of WW. 1 it is clear that the concerned workman was working as a car cleaner and he was employed in Area No. I. On reorganisation the area where he was working was shifted to Area No. III, as a result of reorganisation. At the time of reorganisation he was stopped from work and so he did not work in Area No. III. An inference can be taken that had he continued to be in service his place of working would have been Govindpur Area No. III in normal course. Shri S. Bose, Advocate representing the workman has therefore argued that since the concerned workman would be still deemed to be in continuous service in spite of the action of the management in stopping him from work, the dispute could be raised only against Area No. III, and not Area No. I. He has further argued that the plea of the management is absurd in view of the fact that had the schedule of the reference mentioned that the concerned workman was a workman in Area No. I, the management would have taken a plea that since the area where the concerned workman worked is now designated as Govindpur Area No. III the reference should be rejected on this score alone. In this connection the evidence of WW. 2 may be enforced who had said that till 1975 he was employed in Area No. I, Sijua as driver. This shows that sometime in the year 1975 there was reorganisation of areas and the then area No. I was reallocated to Govindpur Area No. III. Now this is a question of fact, and except for the evidence that I have quoted above, the management has not clarified the position with any evidence whatsoever, either oral or documentary. So we have only the evidence of WW. 1 who speaks about reorganisation and explains that Area No. I which was situated at Sijua has been shifted to Govindpur Area No. III, where he would be deemed to have continued in spite of his stoppage of work. This point therefore is concluded by a finding of fact that the concerned workman could seek relief only against Govindpur Area No. III and that the dispute was rightly raised against Area No. III. Shri Bose has further argued that since the management has no case whatsoever on merits of the case the management is simply showing technical objection to the case of the concerned workman to see that he could not succeed in his case. According to him the areas have been created by the owner M/s. Bharat Coking Coal Ltd. for the sake of administrative convenience and the areas therefore could not be regarded as separate establishments. On this ground alone Shri Bose has said that the objection taken by the management is not sustainable. I agree that since the areas have been reorganised from time to time by the headquarters of the BCCL, it could not be said that the establishments of the areas are separate establishments. In fact the establishments of the areas are part and parcel of the BCCL.

5. Having dispensed with the technical objection raised on behalf of the management, let us now consider the merits of the case as put forth by the management. The management has produced monthly and pay book register of Area No. 1 Sijua from June, 1974 to September, 1975. Nobody has come to prove this document. No positive entry in this book has been sought to be proved. In fact this register is a monthly attendance register and although in the heading of this register pay book is also mentioned, there is no entry to denote payment to the workers mentioned in the attendance register. It has been filed to show that the names of the concerned workman does not find place in this register. This register will show that it includes attendance of officers also and begins with Mr. R. J. Sinha General Manager in the Area No. 1. This also includes the names of drivers, malis and others. The name of WW. 2 the driver appears in this book.

Shri S. Bose has contended that this register mentions the names of only those workers and officers who are on the permanent roll of Area No. 1. According to him the concerned workman was employed on temporary basis and payment to him was made through vouchers. So there was ample reason for the management not to include his name in this register. Apart from this register no evidence has been adduced on behalf of the management. Shri G. Prasad Advocate has argued that since the concerned workman was never a workman of Area No. 1 or of BCCL, he could not produce any paper to prove this fact that he was never a workman. Shri Bose has pointed out that he filed a petition dated 18-11-81 calling for quite a number of documents from the management. Through the petition dated 18-11-81 the following documents were demanded :

- (a) Letter No. DYM/AR-30-III/183/11602 dated 14/19-7-76 from DPM Area No. III to Shri S. D. Pandey, DPM (IR) Karmik Bhawan with details of engagement of Shri Shamsul Khan, car cleaner.
- (b) Payment vouchers from December, 1973 to September, 1975 for payments made to Shri Shamsul Khan
- (c) Petition dated 16-2-78 from Shri Shamsul Khan to the various authorities including :
 - (1) Chairman/Managing Director of BCCL.
 - (2) Director (Personnel) of BCCL.
 - (3) Director (T&P) of BCCL.
 - (4) Chief Personnel Manager, BCCL.

In this petition the workman made it clear that the aforesaid documents were necessary to prove his case. This Tribunal asked the management to produce those documents. The management replied by filing a petition dated 23-12-81 in which the management took the following pleas showing inability to produce the same.

1. The workman had not shown the relevancy of the document called for without affidavit.
2. The documents were not in the custody of the employer of Area No. III.
3. Under the Mines Act and Mines Rules the registers are not required to be maintained for more than a year.

6. It will appear that in the petition dated 18-11-81 item (a) is said to be a letter giving details of the engagement of Shri Shamsul Khan as car cleaner. The payment vouchers are relevant as shown by item (b) for the reason that the workman's case is that he was paid through vouchers. The management reply is that these documents could not be available in Area No. III, and if available they were liable to be destroyed in course of a year. The management never says that these documents were already destroyed. At least item No. (a) is in Area No. III and is a letter in a particular file. It is not the case of the management that the whole file has been destroyed. Item No. (c) of the petition dated 18-11-81 is a petition dated 16-2-78. Copies of the petition dated 16-2-78 had been sent to various authorities, but none of them has been produced. This letter could have shown that the workman demanded from the management to be put on the job he was doing in the BCCL. There does not appear to be any reason why the management should not have produced this document called for. Shri Bose has pointed out in the course of his argument that the attempt of the management is to put hurdle in the way of the concerned workman to show that he was a workman of the BCCL as car cleaner. Shri Bose has further argued that since all the documents concerning his employment in BCCL as car cleaner could be with the BCCL the workman could not be expected to produce them in order to prove his case. The workman has done his best by calling for the documents from the custody of the management giving the fullest particulars possible to trace them out. But all that the management did was to show inability to produce them on one pretext or another which could not be sustainable in a court of law. It appears to be no doubt true a serious attempt is being made by the employer in this case to obstruct the workman in proving his case through legal methods. We have therefore no option but to

fall back upon whatever the evidence has been adduced in this case. The workman has examined himself as WW. 1 and says that he worked as car cleaner from December, 1973 to September 1975. He used to attend 7 vehicles being cars and jeeps and all these vehicles belonged to BCCL. He has said that he used to be paid through vouchers and he received Rs. 150 per month. He has been supported by Shri Nakul Mahato, WW. 2 who had been in the employment in BCCL since 1971, as a car driver. Till 1975 he was employed in Area No. 1, Sijua. He has said that there were 5 vehicles belonging to BCCL in Area No. 1. He has identified Shri Shamsul Khan the concerned workman in this court as a workman employed as car cleaner for 3 years during his time. The learned Advocate for the management has said that while WW. 1 has said that there were only 5 vehicles, WW.2 has said that there were 7 vehicles in Area No. 1. He has also pointed out that the concerned workman in his evidence has said that his service was continuous, while WW.2 says that the concerned workman worked for 3 years with certain gaps. The learned Advocate for the management has said that they were vital contradiction and for this reason the evidence of WW. 1 and WW. 2 should be rejected. I must say that these contradictions cannot be said to be vital for the simple reason that after a lapse of time there bound to be such discrepancies when witnesses depose from their memory. The vital question is as to whether the concerned workman was a car cleaner for a period of 3 years in Area No. 1, Sijua. On this point both WW. 1 and WW. 2 are consistent. Their evidence has not been rebutted by any counter evidence on behalf of the management. I have therefore to hold that the concerned workman Shri Shamsul Khan worked as car cleaner from December, 1973 to September, 1975 and was paid at the rate of Rs. 150 per month through vouchers. I have also to hold that after September, 1975 the management of BCCL stopped him from work. The evidence of WW. 1 is that in 1974 he had approached the Area Officers for making him permanent and the APM of the Area office had recommended his case to the headquarters office for making him permanent. In the meantime reorganisation of the Areas came and the area of the concerned workman was shifted to Govindpur Area No. III. It was at that time that he was made to sit idle without assigning any reason. Shri Bose has said that this is an unfair labour practice inasmuch as the concerned workman after serving for a period of 3 years should not have been stopped from work in such an arbitrary manner. Since we have come to a conclusion on the strength of evidence adduced in this case that the concerned workman was a car cleaner in the Area office, he should not have been stopped from work without assigning any reason or without serving him with any notice. It is objectionable on the part of the management that a car cleaner should be appointed on voucher when this job is clearly defined in the wage board recommendation. It is in category I which is the lowest paid workman in the colliery service. I wonder how a workman having worked for 3 years in his capacity as car cleaner could not be absorbed in category I on regular basis.

7. Shri G. Prasad, Advocate on behalf of the management has argued that the claim is belated because the dispute was raised in 1979 and he was stopped from work from September 1975. The simple case of the workman is that he had been approaching the various officers of the BCCL and for quite some time his union also made attempts with the management to see that he was put in employment. It cannot therefore be said to be a belated claim.

8. Having considered all aspects of the case I hold that the demand of the workman of Govindpur Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office, Sonard District Dhanbad that Shri Shamsul Khan should be allowed to resume duty and regularised as car cleaner with full wages for the period of his idleness is justified. Consequently, Shri Shamsul Khan, the concerned workman should be deemed to be in the service of the colliery w.e.f. 14-9-75 when he was stopped from work. He is also entitled to back wages and other emoluments w.e.f. 14-9-75.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer
[No. L-20012/75/80.D.II(A)]

A. V. S. SARMA, Desk Officer

New Delhi, the 13th December, 1982

S.O. 61—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Industrial

Tribunal, Hyderabad, in the Industrial dispute between the employers in relation to the management of Singareni Collieries Co. Ltd. Bellampalli Division-I, and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th December 1982.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL)
AT HYDERABAD

Industrial Dispute No. 8 of 1982

BETWEEN

The Workmen of Singareni Collieries Company Limited
Bellampalli Division-I, Adilabad District. (A.P.).

AND

The Management of Singareni Collieries Company Limited,
Bellampalli Division-I, Adilabad District (A.P.)

APPEARANCES :

None—for the Workmen.

Sri P. Venkateswara Rao, Senior Personnel Officer,
Bellampalli Division I—for the Management.

AWARD

The Government of India by order No. 21012 (14)/81-D.IV (B) dated 16-2-1982 referred this industrial dispute existing between the employers in relation to the Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division I and their workmen for adjudication to this Industrial Tribunal:—

"Whether the management of Singareni Collieries Company Limited, Bellampalli Division I (AP) is justified in refusing to confirm Shri B. Achanna, General Mazdoor as Clerk Gr. II and to pay the difference of wages between the pay of Clerk Gr. II and the wages of Category I to Shri Achanna, General Mazdoor for the period he worked as Clerk from 4-1-75 to 30-7-78? If not to what relief is the workman is entitled?"

(the name of the worker is wrongly described in the above order as R. Archanna. Hence the correct name R. Achanna is given in this award)

2. After registering the above industrial dispute in I.D. No. 8 of 1982, notices were issued to both the parties. After receipt of notices, the parties intimated to this Tribunal that the Industrial Disputes had been settled on 15-1-1982. Thereupon the parties were directed to file the settlement into the Tribunal. Several adjournments were granted to the parties for the above purposes. Ultimately the compromise petition in M.P. No. 183/82 was filed into this Tribunal on 20-10-1982 signed by the Management's representative, namely P. Venkateswara Rao, Senior Personnel Officer, Bellampalli Division I and the President, Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli, namely, S. Nagaiah Reddy for the Workmen. A memorandum of settlement arrived at between the parties on 15-1-1982 was enclosed to the above petition.

3. The following are the terms of settlement contained in the above memorandum of settlement :—

- (1) Shri R. Achanna shall also be considered for appointment as Clerk Gr. II along with other Graduate employees subject to his passing the Written Test/interview going to be held shortly for selection of Gr. II Clerks.
- (2) The Management agree to pay special allowance to Shri R. Achanna, at the rate of Rs. 60/- per month during the period from April 1976 to September, 1977.
- (3) The amount due to Shri R. Achanna, as per the item No. 2 of the said settlement, will be paid on or before 20th March, 1982.

(4) The Union, therefore, agreed to withdraw the dispute pending before the Conciliation Machinery and Ministry of Labour, Government of India, and to treat the dispute as settled fully and finally.

(5) Both the parties agree to submit this Memorandum of Settlement to the concerned Government Authorities as required under the Industrial Disputes Act Rules.

(6) The parties shall send their implementation report on or before 30th March, 1982, failing which it will be treated that the settlement has been fully implemented.

4. As can be seen from the above memorandum of settlement, the present industrial dispute was settled between the Management and the workman on 15-1-1982 i.e. a month prior to the date of reference of the dispute to this Tribunal. Obviously for some reason or other, the above settlement was not brought to the notice of the Government of India, by the time the present reference was made to this Industrial Tribunal. As can be seen from the contents of the compromise petition, the terms of the settlement were also implemented by the Management. As per Paragraph 1 of the settlement, the workman, namely, R. Achanna had been considered, selected and appointed as Clerk, Gr. II by the Management. As per paragraphs 2 and 3 of the settlement, the Management had already paid the special allowance of Rs. 60.00 per month for the period from April, 1976 to September, 1977 before 20th March, 1982.

5. In view of the above facts, the compromise is recorded by me today. Therefore this award is passed in terms of the above settlement. Copies of the compromise petition and memorandum of settlement shall be appended to this award.

Dictated to the Stenographer, transcribed by him and corrected by me and given under my hand and the seal of this Tribunal, this the 11th day of November, 1982.

Sd/-
Industrial Tribunal.

APPENDIX OF EVIDENCE

—NIL—

Sd/-
(Illegible)
Presiding Officer.

[No. L-20012/14/81-D.IV(B)]
S. S. MEHTA, Desk Officer.

BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL (C),
HYDERABAD

I.D. No. 8 of 1982

BETWEEN

The Management of Singareni Collieries Company Limited,
Bellampalli Division-I, Adilabad District (AP)
...Management.

AND

Workmen of Singareni Collieries Company Limited,
Bellampalli Division-I, Adilabad District (AP)

..Workmen.

MEMO OF COMPROMISE

It is submitted that the parties have entered into a Memorandum of Settlement and thereby settled the dispute as follows :

1. As per para-1, of the Settlement, Shri R. Achanna, has, since been considered, selected and appointed as Clerk Gr. II.
2. As per para-2 and 3, the Management has already paid a special allowance of Rs. 60/- p.m. during the period from April, 1976 to September, 1977 before 20th March, 1982.

3. The Settlement arrived at could not be informed in time to the concerned authorities and hence, the dispute was referred for adjudication.
4. As per para-6, the implementation report on the Settlement has already been sent to the concerned authorities
5. As per para-5, both the parties hereby submit this Memo of Settlement, in seven copies.

It is prayed that an award in terms of the Memorandum of Settlement filed herewith may please be passed.

Be pleased to consider.

Sd/-
For Management,
Sr. Personnel Officer,
Bellampalli Division I.
Sd/-
for Workmen
President,
Tandur Coal Mines Labour Union,
Bellampalli.

Memorandum of Settlement arrived at under Rule 58(4) of the I.D. Act, 1947, on 15-1-1982, at Bellampalli, between the management of the S.C. Company Limited and their workmen represented by the Tandur Coal Mines Labour Union, Bellampalli, regarding alleged non-confirmation of Shri R. Achanna C.S.L., Boipalli No. 1 incline as Clerk Gr. II.

PARTIES PRESENT

Representing the Management :

Shri P. Krishnaji, Sr. Personnel Officer, the S.C. Company Limited, Bellampalli-504251.

Representing the Workmen :

Shri S. Nagaiah Reddy, President, TCML Union, Bellampalli-504251.

Short recital of the case

The President, T.C.M.L. Union, vide his letter No. 31(81) 49, dated 7-3-1981, raised an Industrial Dispute before the Asstt. Labour Commissioner (Central), Hyderabad demanding that Shri R. Achanna, C.S.L., Boipalli No. 1 Incline should be confirmed as Clerk Gr. II and the difference of wages between Category-I and Clerk Gr. II should be paid from 21-1-1975 to 31-7-1978 stating that he worked as Clerk Grade-II during that period.

The Asst. Labour Commissioner (Central), Hyderabad held conciliation proceedings on 30-9-1981. Since the Management and the Union could not come for an amicable settlement, over the dispute, the conciliation proceedings ended in failure. The Asst. Labour Commissioner (C)/Hyderabad, had submitted the failure of conciliation report to the Government of India, Ministry of Labour, New Delhi. The Desk Officer, Government of India Ministry of Labour, New Delhi, had written a letter to the Secretary, Government of Andhra Pradesh, requesting the State Government to pursue the Management for an amicable settlement of the dispute or in the alternate to agree to the reference of the dispute for adjudication.

* The Management held discussions again with the President, T.C.M.L. Union, over the entire dispute on 15-1-1982. During the discussions, it was explained that Shri R. Achanna was discharging the duties of a clerk intermittently, but not continuously for one year and three months. The Union was also informed that the Management is going to recruit some clerks shortly, and the case of Shri R. Achanna, C.S.L., Boipalli No. 1 Incline will also be considered for the post of Clerk Gr. II provided he is possessing required qualifications for the post of Clerk Gr. II and passes in the Test/Interview.

1085 GI/82—11.

After the discussions, the management and the Union have come to an agreement on the following terms :—

TERMS OF SETTLEMENT

- (1) Shri R. Achanna shall also be considered for appointment as Clerk Gr. II along with other Graduate employees subject to his passing the written Test/Interview going to be held shortly for selection of Gr. II Clerks.
- (2) The Management agree to pay special allowance to Shri R. Achanna, at the rate of Rs. 60 per month during the period from April 1976 to September, 1977.
- (3) The amount due to Shri R. Achanna, as per the item No. 2 of the said settlement, will be paid on or before 20th March, 1982.
- (4) The Union, therefore, agreed to withdraw the dispute pending before the Conciliation Machinery and Ministry of Labour, Government of India, and to treat the dispute as settled fully and finally.
- (5) Both the parties agreed to submit this Memorandum of Settlement to the concerned Government Authorities as required under the Industrial Disputes Act Rules.
- (6) The parties shall send their implementation report on or before 30th March, 1982, failing which it will be treated that the settlement has been fully implemented.

SIGNATURES

Representing the Management : Representing the Workman :

Sd/-
(P. Krishnaji)

Sd/-
(S. Nagaiah Reddy)

Witnesses :

Sd/-
(B.R.S. Naidu)
D.P.O., SC Co. Ltd., BPA

Sd/-
(T. P Muller George),
Head Clerk, Personnel Dept., BPA.

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० आ० 62:—विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकार तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (1954 का 44) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा तमिलनाडु सरकार के राजस्व विभाग में संयुक्त सचिव (पुनर्वास) तथा उपसचिव (पुनर्वास) को, जैसा भी मामला हो, उनके अपने कर्तव्य-भार के अनिश्चित, तमिलनाडु राज्य में मुद्रावजा पूल की भूमि तथा सम्पत्तियों के संबंध में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बन्दोबस्त आयुक्त को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये, बन्दोबस्त आयुक्त नियुक्त करती है।

[संख्या-1(19)/विशेष सच/82-ए०एन०एन०(क)]

महेन्द्र कुमार कंनल, अवर सचिव

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 62.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) 1954 (44 of 1954), the Central Government hereby appoints the Joint Secretary (Rehabilitation) and Deputy Sec-

etary (Rehabilitation) as the case may be, in the Revenue Department, Government of Tamilnadu, as Settlement Commissioner for the purpose of performing, in addition to his own duties, the functions assigned to a Settlement Commissioner by or under the said Act, in respect of the land and properties forming part of the Compensation Post within the State of Tamil Nadu.

[No. 1(19)Spl.Cell[82-SS.II(A)]

M. K. KANSAL, Under Secy.

S.O. 63.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL: CALCUTTA

Reference No. 31 of 1979

PARTIES:

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their workmen

PRESENT:

Mr. Justice M. P. Singh Presiding Officer.

APPEARANCES:

On behalf of Employers

Mr. D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen.

Mr. Kamal Kumar Banerjee, Asstt. Secretary of the Union.

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Port

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No. L-32012/14/D.IV(A) dated 19th May, 1979 referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in allowing Sri A. K. Mukherjee, U.D. Clerk, under the Chief Engineer to be superseded for the purpose of promotion to the post of Upper Division (Selection)? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

2. The facts are simple. Sri A. K. Mukherjee was an U.D. clerk under the Chief Engineer of the CPT (Calcutta Port Trust). There was a vacancy in the year 1977 in the UD (Selection) post. Sri Mukherjee was superseded and instead Ajoy Kumar Guha Khasnabis who was also a U.D. clerk in the same department was promoted and appointed to the UD (Selection) post. It is admitted by both sides that the person who was senior was entitled to be appointed to that post. So the simple question is whether A. K. Khasnabis was senior to A. K. Mukherjee. I think he was.

3. Admittedly Sri Khasnabis was confirmed in the post of UD clerk in the Dock unit on 1st January 1963 but Sri Mukherjee was confirmed as UD clerk in the Calcutta unit on 23rd January 1963. Thus Khasnabis was confirmed ear-

lier. The date of seniority, in my opinion, should be determined by reference to the date of confirmation and not from the date of appointment in a particular grade or rank. It may be mentioned here that there were three units under the Port Development Wing (briefly, the PD Wing) under the Chief Engineer. (i) Calcutta unit, (ii) Dock unit and (iii) Head office unit. The PD wing was a temporary establishment. The UD (S) post was to be filled by the seniormost UD clerk from a combined list of all the three units. We are not concerned with the seniority of any UD clerk in any other particular unit. For the purpose of UD (S) post all the three units were to be considered as if one unit and the seniormost of them was to be appointed to the UD(S) post. Sri Ajoy Kumar Guha Khasnabis having been confirmed earlier must, therefore, be held to be senior. Rule 2 of the seniority rules framed by the CPT runs as under:

"When however a man is confirmed in a grade, he becomes senior to all other who have not been confirmed in that grade for purpose of promotion."

In the present case when Sri Ajoy Kumar Guha Khasnabis was confirmed, Sri Mukherjee had not been confirmed on that date and therefore Ajoy Kumar became senior to him.

4. The union argues that the seniority rules do not apply to the Chief Engineer's department. I do not agree. No separate rule has yet been framed for the department of the Chief Engineer in the CPT. The union itself in another written statement filed by them in Reference No. 11 of 1982 (Ext. M-3) in paragraph stated as follows:

"4. That all promotions of the workmen of CTP are done or governed by the seniority rules passed at the meeting of the erstwhile Commissioners for the Port of Calcutta on 8-5-57 under Resolution No. 473. In this connection copy of Secretary CPC's letter No. 7354 dated 2nd June, 1958 together with a copy of the report of the Committee set up to draw up rules for determining seniority of staff are enclosed marked with Annexure 'A' and 'A-1' and since then all promotions to the workmen of CPT were given as per said seniority rules."

On a perusal of the above it is clear that the union admitted the fact that the seniority rules in question governed all promotion of the workmen of the CPT.

5. The union next relied on Rule 1 of the said seniority rules. It runs as below:

"The seniority of a man in a grade should be determined on the basis of total length of his service in that grade or in an equivalent grade."

Suffice to say that this rule does not deal with a case of confirmation and therefore it is not applicable to the present case.

6. It is next contended on behalf of the union that Sri Mukherjee had officiated in the UD(S) post from 2-12-1953 to 1st February 1954 and this period of officiation should be counted in determining the length of service. In continuation of this submission it was further pointed out that Sri Mukherjee had been appointed as LD clerk earlier than Sri Ajoy Kumar Guha Khasnabis and from that point of view also the total length of service of Sri Mukherjee was more than that of Sri Khasnabis. In my opinion, the length of service has to be determined in a particular grade or rank in which the question of seniority arises and the period of another grade or rank cannot be taken into consideration. I am further of the opinion that in a case of confirmation the period of officiation can have no weightage and that seniority must be counted from the date of confirmation.

7. The union next submits that the existing seniority rules were amended by the erstwhile Commissioners for the Port of Calcutta (now Calcutta Port Trust) in the year 1973 by Resolution No. 1472 and by that amendment the seniority by confirmation had been ruled out. Suffice to say that these rules have not yet been approved by the Central Government and so they have absolutely no force.

8. The union next urged that according Annexure "E" (Ext. W 5) which is an observation of the Financial Advisor and Chief Accounts Officer to the effect that Sri Mukherjee was senior to Sri Ajoy Kumar, it should be held that Sri Mukherjee was senior to Ajoy Kumar. This observation was made on 26th November 1977. On this observation an endorsement was made by the Secretary to the effect that the Chief Engineer should see that observation and should send the papers to his office as early as possible. In my opinion, this observation is of no value. The FA and CAO thought that Sri Mukherjee had been appointed and confirmed as LD clerk earlier than Sri A. K. Guha Khasnabis and therefore he was senior. The observation is misconceived and exhibits ignorance of the rule as to seniority. I have already said that seniority has to be determined only by reference to the date of confirmation in the particular grade or rank in which the question arises. Here the question arise in the grade of UD clerk. Therefore nothing about the period as LD clerk can be considered. I may mention here that the Chief Engineer in his letter dated 20th September 1977 observed that Sri A. K. Guha Khasnabis was senior to Sri Mukherjee. That view in my opinion is correct.

9. The union next submitted that there was no combined list of seniority of the three units of the department of Chief Engineer. I think that this becomes a minor matter in view of the positive fact that A. K. Guha Khasnabis was confirmed earlier in the grade of UDC.

10. The Union next referred to Annexure C (Ext. W3) and Annexure D (Ext. W4) of their written statement. These two exhibits, in my opinion, are of no help to the union. Annexure C shows as to when certain clerks had been appointed in the Lower Division Clerk's post or Upper Division clerks post. This in my opinion is of no consequence in view of the discussions made above. Annexure D is in respect of the two clerks concerned, namely Sri Mukherjee and Sri Khasnabis. They have been shown as LD clerks as well as UD clerks with their dates of appointment confirmation and promotion. This also is of no importance in view of the discussions held. I have already mentioned the relevant dates for the purpose of determining the seniority. The contention thus has no force.

11. In the result, I hold that the management in relation to the CPT are justified in superseding Sri A. K. Mukherjee, UD clerk under the Chief Engineer and to promote Ajoy Kumar Guha Khasnabis in the post of Upper Division (Selection) Post in the Department of the Chief Engineer. Sri A. K. Mukherjee, therefore, is not entitled to any relief.

Dated, Calcutta the 20th November, 1982.

M. P. SINHA, Presiding Officer
[No. L-32012/14/78-D-IV(A)]

New Delhi, the 17th December, 1982

S.O. 64.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA.

Reference No. 45 of 1979

PARTIES .

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta.

AND

Their Workmen.

APPEARANCES :

On behalf of Employers.—Sri D. K. Mukherjee, Industrial Relations Officer.

On behalf of Workmen—Sri Asgher Ali, Vice-President of the Union.

STATE : West Bengal INDUSTRY : Port

AWARD

By Order No. L-32012(12)/78-D. IV(A) dated 12th July, 1979 the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the management in relation to Calcutta Port Trust are justified in imposing punishment by way of reduction of pay by two stages on Shri Mohiuddin, Loco Driver, under the Chief Mechanical Engineer on the charge of negligent and rash driving in November, 1975 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?"

2. On 20th July 1976 Mohiuddin, a Loco Driver was charged with misconduct inasmuch as he negligently and rashly drove engine No. D/51 on 3/4.11.75 and made a collision with the last wagon of the train carried by Engine No. 44 at 3 K. P. line causing damage to Loco No. D/51 and the wagon. Further, that said Shri Mohiuddin while on duty from 2206 hrs. On 3/4.11.75 failed to stop the engine D/51 at fouling point, in spite of being cautioned by the Shunter Gunner on the basis of the report made by the Loco Foreman. He gave explanation on 31st July 1976 but the same was found not satisfactory. A domestic enquiry was held on 8th December 1976 by the Enquiry Officer Sri A. K. Sankar who found him guilty of the charge. On receipt of the findings of the Enquiry Officer (Ext M 5) the Chief Mechanical Engineer imposed the punishment as mentioned in the order of reference by his order dated 31st January 1977. His appeal therefrom was rejected by the Deputy Chairman.

3. According to the concerned workman (vide Ext. W1 dated 7 August 1976 and M3 dated 31st July 1976) he was asked to proceed to E J C by line No. 2 without any caution order, the level crossing was jammed up with vehicles in such a manner that it was not possible to know whether the line was clear, that the head-light of the engine became visible at the relevant time, that there was no stop signal and that the shunter gunner Jadu Tiwari who was with him for giving guidance did not ask him to stop. He denied the fact that he did not stop the engine in time. This could have properly be considered only when the person who were present with him in the engine would have been examined by the management. It appears that one shunter gunner and one member of the CISF were present at the time of accident. None was examined. The management had filed several documents including the accident report and enquiry report (Ext M 1) but these documents cannot show whether the concerned workman stopped or did not stop the engine in time or whether the headlight had become dim at the relevant time. These matters could prima facie be proved only by oral evidence of the two persons present in the engine at the time of accident. That evidence was available but the management did not bring them before the Enquiry Officer. Hence the documents are not of real assistance to the management for proving the charge against him. The whole enquiry was conducted only on one day namely 8th December 1976 simply on the basis of statement made by Mohiuddin.

4. The management contends that the departmental enquiry is valid because sufficient opportunity was given to the workman to defend himself. In my opinion that is not correct. Enquiry was held only on one day (8-12-76). Mohiuddin, the loco driver applied for adjournment to another date on the ground that his counsel was not available on that day due to his pre-engagement to some other work. No time was granted and enquiry was held in absence of the defence counsel. It may be pointed out that the management is bound to consider the representation made by the concerned

workman under the provisions of Rule 12 of the Calcutta Port Commissioners Employees' (Discipline and Appeal) Rules, 1964, briefly the 1965 Rules. The defence counsel could have placed before the enquiry officer the proper defence in an effective manner. There was, therefore, denial of reasonable and effective opportunity to the concerned workman and thus there was denial of justice too. The contention raised by the management thus has no force.

5. Mr. D. K. Mukherjee appearing for the management next contended that the holding of enquiry was not necessary for minor penalty under Rule 12 of the 1964 Rules. He pointed out that enquiry was necessary only when major penalty were imposed as contemplated in Rule 11 of 1964 Rules. Suffice to say that if the management adopts the procedure of enquiry it is not open to them to say that they are not bound by it even if the enquiry was not necessary. In the circumstances of this case the management is bound by that enquiry because it chose to adopt it. The enquiry held in this case is not based on any evidence. It is therefore perverse. If so, the order of punishment passed upon it must go.

6. Sri Sgheer Ali, appearing for the concerned workman, contended that during the departmental enquiry 10 or 11 questions were put to him and that being in the nature of cross-examining was not permissible in law. He also contended that the concerned should not have been examined prior to production of some evidence by the management. It is not necessary to go into this question because of the view expressed above.

7. In the result, my concluded award is that the management in relation to the Calcutta Port Trust were not justified in imposing punishment by way of reduction of pay by two stages on a charge of negligence and rash driving in November 1975, on Mohiuddin, the loco driver. I accordingly direct the management of the Calcutta Port Trust to pay back the amount which has been deducted to the concerned workman, namely Mohiuddin, loco driver.

Dated, Calcutta,
The 6th December, 1982.

M. P. SINGH, Presiding Officer
[N. L-32012/12/78-D. IV (A)]

S.O. 65.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 2, Bombay in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Salgaonkar Engineers Private Limited, Vasco-da-Goa and their workmen, which was received by the Central Government on the 29th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2 BOMBAY

Reference No. CGIT-2/42 of 1982

PARTIES :

Employers in Relation to the Management of M/s.
Salgaonkar Engineers Pvt Ltd., Vasco-da-Gama,
Goa.

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employers—No appearance

For the workmen—No appearance

INDUSTRY : Port and Docks STATE : Goa, Daman
and Diu

Bombay, the 8th November, 1982.

AWARD

In their letter No. L-35012(3)/82-D.IV(A) dated 1-10-1982 the Central Government have referred the following dispute

for adjudication under Section 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947 :—

"Whether the action of the management of Messrs Salgaonkar Engineers Private Limited in retrenching with effect from 9-6-1982 the 62 workmen (whose names are mentioned in the annexes) employed in transhipper "m.v. Gosalia Prospect." is justified ? If not, to what relief are the concerned workmen entitled?"

ANNEXURE

S. No.	Name
1.	Shri J. S. Fernandes
2.	" Pralhad Manirekar
3.	" Keshav Rane
4.	" Gurunath Kochrekar
5.	" Diogo Severes
6.	" Vinayak Sawant
7.	" Joaquim D'Costa
8.	" Caetano Pereira
9.	" Milagres Rodrigues
10.	" Shaikh Hassan
11.	" Kubiraab Iddelgi
12.	" Manial Saraj
13.	" Mohidinsab Gulbarga
14.	" Mathaye Chowan
15.	" Kasimsah Gulbarga
16.	" Shivlingappa Koonreddi
17.	" K. B. Mathel
18.	" Usman Khan
19.	" Dattatraya B. Shirke
20.	" Mayappa Harijan
21.	" Hanumantha Muthatl
22.	" Sabanna U. Narsonagi
23.	" Hanjmantha Gangur
24.	" Kechappa Harijan
25.	" Apanna D. Guledar
26.	" Amarappa Wallihar
27.	" Shivlingappa Sarur
28.	" Rajput Pal
29.	" Pyarelal Bindh
30.	" Claram Saroj
31.	" Parasnath Bindh
32.	" Baijanath Bindh
33.	" Rammahesh Bindh
34.	" Ramprish Chawan
35.	" Mohanlal Bindh
36.	" Gajraj Bindh
37.	" Gulraj Chowan
38.	" Dikhi Bindh
39.	" Thakur Chowan
40.	" Ramdhani Dusad
41.	" Rambachan Bindh
42.	" Brijlal Bindh
43.	" Chandeshwar Chowan
44.	" Ankush Omkhande
45.	" Madhukant Naik
46.	" Antonio Antao
47.	" Mahadeo Shet Gaonkar
48.	" P. R. L. Triudade
49.	" Mohan Kavlekar
50.	" Chandrakant Parab
51.	" Sudhakar Rane
52.	" Michal Rodrigues
53.	" Gopinath Khorjuvenkar
54.	" Philip Vaz
55.	" Babuso Amonkar
56.	" J. D. Sequira
57.	" Shantaman Marajkar
58.	" Yeshwant Naik

S. No. Name

59. Shri Manohar Kanoji
60. „ Narsinva Muckaikaar
61. „ Manual Fernandes
62. „ Shamsuddin Shah

2. As is evident the dispute relates to the alleged retrenchment of 62 workmen from the services of the Respondent Company. During the pendency of the present reference, however, the matter seems to have been mutually negotiated whereby the parties namely the Goa, Mining Labour Welfare Union who espoused the cause of these 62 workmen and the management have arrived at certain terms embodied in the terms of settlement, on the strength of which there is a request to pass an award by both the parties. I have perused the terms of the settlement whereby I find that out of 62 workmen 52 have been agreed to be reinstated with certain monetary benefits while the remaining 10 workmen who stand retrenched from 9-6-1982 are to get additional amount equivalent to 75 per cent of the total amount of retrenchment compensation and gratuity payable to them under the notice of retrenchment. These payments were to be made by 30-9-1982 in full and final settlement to the retrenchment workmen.

3. It is true that out of 62 workmen 10 workmen remained out of service but then having regard to the fact that a major portion of the workmen is agreed to be reinstated and since the Union who has espoused the cause have found the settlement fair and reasonable whereby the dispute has been brought to an end, I endorse the settlement, hold it to be fair and reasonable and the dispute therefore does not survive.

No order as to costs.

M. A. DESHPANDE, Presiding Officer.

[No. L-36012/3/82-D. IV(A)]

S.O. 66.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL : CALCUTTA

Reference No. 42 of 1980

PARTIES :

Employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. D. K. Mukherjee Industrial Relation Officer.

On behalf of Workmen—M/s. Asghar Ali, Vice-President, National Union of Waterfront Workers.

STATE : West Bengal

INDUSTRY : Port

AWARD

By Order No. L-32012/4/80-D.IV(A) dated 7th June, 1980 the Government of India, Ministry of Labour referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in not confirming Shri Sadhan Chandra Mondal, Lascar, U.R.R. Party, Falta with effect from 1st August, 1977 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled?”

2. When the case was taken up for hearing, the parties filed a petition stating that the matters have been settled amicably between the parties on the terms embodied in the said petition and prayed that an award be passed in terms of the said compromise petition. I have gone through the terms of settlement and I am satisfied that the terms are fair and reasonable. I therefore accept the same and pass an award in terms of the said compromise petition which will form part of this Award as Annexure “A”.

Dated, Calcutta,

The 4th December, 1982.

M. P. SINGH, Presiding Officer.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL CALCUTTA

In the matter of Reference No. 42 of 1980

AND

In the matter of the Government of India, Ministry of Labour Order No. L-32012/4/80-D.IV(A) dated 7-6-1980.

AND

In the matter of Notice No. Ref. 42/80/641 dated 18/19-7-1980 issued by the Secretary to the Court, Central Government Industrial Tribunal, Calcutta.

BETWEEN

The employers in relation to the management of the Calcutta Port Trust, Calcutta

AND

Their Workmen

Represented by National Union of Waterfront Workers, 15, Coal Dock Road, Calcutta-700043.

Humble petition of the applicants, employers in relation to the management of Calcutta Port Trust, Calcutta and the workmen represented by the National Union of Waterfront Workers (hereinafter referred to as the “Board” and the “Union” respectively in this matter).

Most Respectfully Sheweth :

1. That your petitioners submit that the Government of India, Ministry of Labour under Order No. L-32012/4/80-D.IV(A) dated 7-6-1980, referred to the Hon'ble Tribunal the dispute in respect of the matters specified in the Schedule below :

“THE SCHEDULE

Whether the management in relation to the Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in not confirming Shri Sadhan Chandra Mondal, Lascar, U.R.R. Party, Falta with effect from 1st August, 1977 ? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

2. That your petitioners state that the Written Statement on behalf of the “Board” was filed before the Hon'ble Tribunal on 29-8-1980 and the Written Statement on behalf of the “Union” was submitted on 30-8-1980. The case is now fixed for pre-emptory hearing on 3-12-1982.

3. That your petitioners state that meanwhile the matter has been further discussed between the parties to the dispute

and it has been voluntarily agreed that the concerned workmen in the dispute, who are named below, be confirmed with effect from the dates shown against each and be adjudged the inter-se seniority position amongst them in the cadre of Lascars under the Upper Reaches Research Station, Phalga. Chief Hydraulic Engineer's Department, in the order mentioned herein :

Order in Seniority	Name	Designation	Date of confirmation in the post of Lascar in U.R.R.S. Phalga
1	2	3	4
1.	Shri Santu Ranjan Purkait	Temporary Lascar	29-9-1980
2.	Shri Samad Ali	Temporary Lascar	30-9-1980
3.	Shri Sadhan Chandra	Temporary Lascar	1-10-1980

4. That your petitioners submit that the above reference before the Hon'ble Tribunal may kindly be disposed of in terms of the above compromise.

Under the above circumstances, your petitioners most humbly pray that your Honour would be graciously pleased to consider the matter in terms of the above settlement and give an award accordingly.

And for this, your petitioners as in duty bound shall ever pray.

Sd./- I.R.O. Calcutta Port Trust
Sd./- Vice-President National Union of Waterfront Workers

Witness : 1. Sd./-
Witness : 1. Sd./-

2. Sd./-
2. Sd./-

Calcutta,

Dated this the 3rd Day of December 1982.

M P. Singh, Presiding officer
[No. L-32012/4/80-D. IV(A)]

T. B. SITARAMAN, Desk Officer

New Delhi, the 16th December, 1982

S.O. 67.—In pursuance of the provisions of sub-section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Calcutta, in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank, Calcutta, and their workmen, which was received by the Central Government on the 7th December, 1982.

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL AT CALCUTTA

Reference No. 43 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to the management of Punjab National Bank, Calcutta,

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of Employers—Mr. Rameswar Singh, Law Officer

On behalf of Workmen—Mr. R. L. Singh, General Secretary of the Union.

STATE : West Bengal.

INDUSTRY : Banking.

AWARD

By Order No. L-12012/48/80-D.II.A dated 29th October, 1981 the Government of India, Ministry of Labour, referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Punjab National Bank in relation to its Biplabi Rash Bihari Basu Road, Calcutta Branch, in imposing the punishment of stoppage of three increments and debarring with effect from 25th March, 1978 for promotion to clerical cadre of Shri G. P. Trivedi, Peon is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The terms of reference show that two kinds of punishment were imposed on the peon G. P. Trivedi : (i) stoppage of three increments and (ii) debarring him with effect from 25th March, 1978 from promotion to clerical cadre (vide Exts. M-10 and M-11). The question is whether this action of the management is justified? The main facts of the case are admitted and are simple. G. P. Trivedi joined the service of the Punjab National Bank, Biplabi Rash Behari Bose Road, Calcutta (briefly, the bank) as a probationer peon on 20th April, 1967. At the time of joining he declared that his educational qualification was VIII class pass and he also produced certificate exhibit M-2 to that effect. In fact he was a matriculate at that time but he did not disclose this fact then. In the year 1974 he informed (vide letter Ext. W-1—exhibit M-4) the bank that he was a matriculate and he had passed the Matriculation examination in the year 1961. He produced a high school certificate, Ext. M-5. Thereafter he began to make representation requesting the bank to give him chance of officiating in the vacant post of a clerk. He made three such representations in 1974 (Exhibits W-1, W-2 and W-3) and two representations in 1975 (Exts. W-4 and W-5). The General Secretary of the Union also wrote for him to the management. On 25th October, 1976 the management issued a chargesheet to him asking him to show cause as to why disciplinary action should not be taken against him for the false declaration as to his educational qualification at the time of joining his service as a probationer peon. In the chargesheet it was mentioned, "The bank as a matter of policy does not employ over-qualified persons (i.e. those who have passed the matriculation—higher secondary examination) in subordinate cadre. Thereafter the bank held the enquiry which started on 7th January, 1977 and concluded on 21st June, 1977. The Enquiry Officer's report is exhibit M-8. The Enquiry Officer Mr. G. S. Burmah found as follows :

- (i) It is established beyond doubt that Sri Trivedi who passed matriculation examination in 1961, joined the services of the Bank in April, 1967, informed the Bank at the time of his appointment that he had passed Junior High School Examination. In this way he suppressed his higher qualification which is a material fact ;
- (ii) The above conduct on the part of Sri Trivedi although not covered in the list of gross mis-conducts under the Bipartite Settlement of 1966 is a *prima facie* gross misconduct.
- (iii) From the evidence adduced by the management representative of the Bank, it could not be established, on the basis of documentary proof, that in the year 1967 (when Sri Trivedi joined the services of the Bank) as per policy the Bank was not appointing matriculates or higher secondary passed candidates in subordinate cadre ;
- (iv) It appears that there are cases in the Bank wherein matriculates or higher secondary passed candidates have been appointed in subordinate cadre.

While above may be the correct position, in the case of Sri Trivedi what has been established beyond doubt is that he had suppressed his educational qualification which was a material fact.

This leads to a doubt that Sri Trivedi at the time of the appointment in the Bank service must have been aware of the fact that his higher qualification might come in his way in appointment in the Bank in subordinate cadre. He further declared

his qualification as Junior High School pass only although he had passed matriculation much before his joining the Bank service."

On receipt of the enquiry report the management imposed the punishment as stated above on the ground of concealment of a material fact which was considered to be gross misconduct.

3. In my opinion, though the Bank was empowered to impose the punishment of stoppage of increment, it was not justified to do so in the facts and circumstances of this case. It is true that neither in the chargesheet (Ext. W-7) nor in the enquiry report (Ext. M-8) nor in the order of proposed punishment (Ext. M-10) it was mentioned as to what administrative order of the management or what clause of the bipartite settlement of 1966 was contravened by Sri Trivedi but the central fact remains that Sri Trivedi concealed a material fact at the time of his entry into service in the year 1967. The management has pointed out that the bank had issued a circular Ext. M-9 dated 16th May, 1973 which was to the effect that a person giving false declaration about his educational qualification should be discharged from service. This circular, however, was not in existence in 1967 when Trivedi joined his service. It was argued on behalf of the workman that the Enquiry Officer has found that the bank has failed to substantiate that in the year 1967 when Trivedi joined the service of the bank its policy was that matriculates will not be appointed as a candidate in subordinate cadre. That is correct. Admittedly at the time of the chargesheet and onwards there was the circular of 1973 in existence under which such person could be discharged for making false declaration as to his qualification. So irrespective of the Bank's policy regarding non-appointment of matriculates as peons Sri Trivedi could be punished. It was argued by the Union that the bank itself had appointed several matriculates as peons and that the bank did not produce the service records of 25 clerks as demanded by Sri Trivedi which could have shown that matriculates had been appointed as peons by the bank. Even if that be so, it is no ground to exonerate him from liability for his misconduct. It was next urged by the workmen that the act of Sri Trivedi was not misconduct as per provisions of the Bipartite Settlement of 1966. Suffice to say that an act can be misconduct outside the settlement. Any way, the punishment of stoppage of increment cannot be sustained in view of the Bank's own conduct in appointing Matriculates as peons and also in view of the fact that its alleged policy of non-appointment of over qualified persons was not established.

4. So far as the second punishment of debarring him from officiating promotion is concerned, it was confined only to two years with effect from 25-3-1978 which ended on 25th March, 1980 (vide circular Ext. M-14 dated 29th January, 1977 and Ext. M-15 dated 30th August, 1978). Sri Trivedi is now admittedly eligible for officiation and promotion. It may also be noticed that officiation or promotion is primarily a management function. No employee has a right to officiate or to be promoted. Sri Trivedi can have no grievance in this behalf. He can have no right to force the management to promote him to a higher post unless any rule or agreement permits it. After all he did conceal a material fact regarding his educational qualification at the time of joining his service. That fact on his part cannot be called fair. In my opinion it amounts to misconduct.

5. After having considered the submissions of the parties and the facts and circumstances of the case I come to the conclusion that the punishment of stoppage of increment imposed upon Sri G. P. Trivedi, Peon by the management is not justified and it ought to be set aside. It is accordingly set aside. As regards the second punishment of debarring him from promotion, I am of opinion that the action of the management in this behalf is justified. Sri Trivedi is, therefore, entitled to get relief in part. The management is directed to pay all his legal dues respecting the increment as may be permissible as per rules of the management.

This is my award.

Dated, Calcutta,

M. P. SINGH, Presiding Officer

The 16th November, 1982.

[No. L-12012(48)/80-D.II(A)]

New Delhi, the 6th December, 1982

30. 68.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India Bombay, and their workman, which was received by the Central Government on the 26th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-23 of 1978

PARTIES :

Employers in relation to Union Bank of India, Bombay.

AND

Their Workman.

APPEARANCES :

For the employer—Mr. F. D. Damania, Advocate.

For the workman—Mr. M. S. Udeshi, Advocate

INDUSTRY : Banking.

STATE : Maharashtra.

Bombay, the 30th day of October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-12012/48/78-D.II.A dated 23/27th November, 1978, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of Union Bank of India, Bombay, and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Union Bank of India, Bombay, in terminating the services of Shrimati N. P. Bhisma, Special Assistant with effect from 1st October, 1976 is legal and justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

2. The workman, Mrs. N. P. Bhisma, joined the Bank on 10th June, 1957 as a Clerk. At the relevant time the workman was attached to Prabhadevi Branch of the Bank as a Special Assistant. The services of the workman were terminated by the employer-Bank on 1st October, 1976 purporting to do so under paragraph 522.1 of the Sastry Award. The workman alleged that the action of the Bank in terminating her services as above was wrongful, illegal and inoperative, for the reasons mentioned in the statement of claim. The workman, therefore, claimed reinstatement with full back wages and continuity of service.

3. The employer Bank by its written statement dated 26th July, 1979 maintained that its action of terminating the services of the workman was perfectly proper and justified.

4. It appears that the grievance of the Bank was that while the workman was working in the Bank, it was observed, that she was highly irregular in her attendance and she was in the habit of frequently remaining absent without prior permission and/or justifiable grounds or reasons causing considerable inconvenience to whichever branch she was posted. It also appears from the document produced in this reference that it was the case of the Bank that she had been advised in various memoranda to improve her attendance and in spite of that she did not improve.

5. It appears that the talks of settlement were going on between the parties and finally on 8th October, 1982 a settlement was arrived at between them. The terms of the settlement signed by both the parties have been placed on record where under by way of all amounts payable to the workman from the date of her termination till 8th October,

1982, the Bank offered to pay and the workman agreed to receive a sum of Rs. 52,586.10 less an amount of Rs. 977 being income-tax payable on the said sum. The break up of this amount has been given in the settlement. In view of this payment the workman has given up her claim for reinstatement in the service of the Bank as also her claim for back wages. As desired by the workman the employer has paid to the workman at the time of filing the present consent terms before this Tribunal a sum of Rs. 51,609.10 by pay order drawn on Union Bank of India, Bombay Main Branch in favour of the workman's Advocate on record, Mr. M. S. Udeshi.

6. The settlement was filed before this Tribunal on 23rd October, 1982. It is duly signed by the parties themselves and their Advocates. I find the settlement to be just and fair.

7. I, therefore, pass an award in terms of the settlement annexed to this award. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer

[No. L-12012(48)/78-D. II(A)]

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT No. 23 of 1978

Smt. N. P. Bhishma ... Workman

Versus

Union Bank of India ... Employer

MAY IT PLEASE THE HONOURABLE TRIBUNAL

1. The workman Smt. N. P. Bhishma and the employer, Union Bank of India, have settled their dispute referred to this Hon'ble Tribunal under the above Reference as per the terms of Settlement signed by them today.

2. Both the parties agree that the said Settlement is fair and proper. The Bank has today made payment to the Advocate for the workman of a sum of Rs. 51,609.10, which is the net amount payable after deducting a sum of Rs. 977 from the total amount of Rs. 52,586.10 payable under the terms of the Settlement. The workman admits having received the said amount.

3. In view of the aforesaid, both the parties jointly apply to this Hon'ble Tribunal to dispose of the above Reference in accordance with the terms of Settlement filed before this Hon'ble Tribunal.

Dated at Bombay this 8th day of October, 1982.

(M. S. UDESHI)

Advocate for the Workman.

(Firoze Darasha Damania)

Advocate for Union Bank of India.

N. P. BHISHMA,

Workman above named.

Sd/-

For Union Bank of India
Superintendent.

Sd/-

(Married daughter of
Mrs. N. P. Bhishma)

PRESENT:

Mr. M. S. Udeshi—Advocate for workman.

Smt. Vordene Rana, married daughter of workman—
present for workman.

Mr. S. K. Talsoma Advocate holding for Mr. F. D. Damania, Mr. Udeshi Advocate for workman says that the Bank has issued payees account pay order in the name of

Advocate for the workman in terms of column 7 of the consent terms; and as stated in the application.

Settlement appears to be fair & just. Award in terms of settlement.

23-10-1982.

Sd/-

for Central Tribunal

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT No. 23 of 1979

Smt. N. P. Bhishma ... Workman

Versus

Union Bank of India ... Employer.

TERMS OF SETTLEMENT

With a view to resolve the dispute amicably and as a gesture of goodwill, the Union Bank of India (hereinafter referred to as 'the bank') agrees to settle the case of Smt. N. P. Bhishma (hereinafter referred to as 'the workman').

2. By way of all amounts payable to the workman for the period from 1st October, 1976 till 8th October, 1982 either by way of wages/leave wages/bonus/ex-gratia payment or allowances, perquisites and privileges, the Bank agrees to pay the workman and the said workman agrees to receive a sum of Rs. 52,586.10 Less an amount of Rs. 977.00 being income tax payable on the said sum. The break-up of Rs. 52,586.10 is as under:—

(a) Encashment of 30 days privilege leave	Rs. 2,535.00
(b) Retrenchment compensation for 25 years @ 15 days salary for each year of service	Rs. 31,687.50
(c) Employer's Provident Fund Contribution from 1-10-1976 to 8-10-1982	Rs. 5,647.90
(d) Gratuity on the basis of wages as on 8-10-1982	
Entitlement to Gratuity	Rs. 18,195.00
Less : Already paid at the time of Abandonment of service	Rs. 8,565.00
Total amount of Gratuity to be paid...	Rs. 9,630.00
(e) 3 months notice pay on the basis of wages as on 8-10-1982	Rs. 7,505.00
Less : Notice pay paid at the time of terminating her services	Rs. 4,419.30
	Rs. 3,085.70
	Rs. 52,586.10

(Rupees Fifty two thousand Five hundred Eighty six and Paise Ten only)

3. The aforesaid amounts have been calculated on the basis of the salary the employee would have drawn had she been in the service of the Bank as on date and the workman agrees to the settlement arrived at in clause 2 above.

4. In view of the above, the workman hereby gives up her claim for reinstatement in the service of the Bank as also her claim for back wages from 1st October, 1976 to 8th October, 1982.

5. Income Tax to the tune of Rs. 977.00 is deducted from the full amount and therefore, the balance amount of Rs. 51,609.10 only is payable to the workman and the workman agrees to receive the amount of Rs. 51,609.10 by way of settlement.

6. The workman hereby declares that on receipt of the said sum of Rs. 51,609.10 she does not and will not have any claim whatever against the employer.

7. As desired by the workman, the employer has paid to the workman at the time of filing the present consent terms, a sum of Rs. 51,609.10 arrived at in clause 5 above, by pay order No. 043586 drawn on Union Bank of India, Bombay Main Branch, dated the 5th October, 1982 favouring the workman's advocate on record in the above matter viz. Shri M. S. Udeshi.

8. The parties agree to bear their own costs of the above reference proceedings.

Dated at Bombay this day of October, 1982.

Sd/-

(M. S. Udeshi)

Advocate for Workman

Sd/-

(Firoze Darasha Damania)

Advocate for

Union Bank of India.

Sd/-

(N. P. Bhishma)

Workman above named

Mrs. Vandana Raman

(married daughter of Mrs. N. P. Bhishma)

For Union Bank of India

Sd/-

Superintendent

SO 69—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Bombay, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India, Maharashtra, and their workman, which was received by the Central Government on the 26th November, 1982.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT BOMBAY

Reference No. CGIT-31 of 1981

PARTIES :

Employers in relation to State Bank of India

AND

Their workmen

APPEARANCES :

For the employer—Mr. G. G. Modak, Advocate.

For State Bank of India & Subsidiary Bank Employees' Association—Mr. R. Rajan Pillai, Advocate.

INDUSTRY : Banking. **STATE :** Maharashtra.

Bombay, dated the 29th day of October, 1982

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. I-12011/17/80-D.II.A dated 18th December, 1981, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute between the employers in relation to the management of State Bank of India and their workman in respect of the matters specified in the schedule mentioned below :—

1085 GI/82-12

SCHEDULE

"Whether the management of State Bank of India, Chief Regional Manager, Nagpur, is justified in denying overtime claims to S/Shri Laware, Ingle and Deshmukh, Godown Watchmen of Khamgaon Branch during the period from April, 1969 to December, 1972? If not, to what relief they are entitled to?"

2. The State Bank of India has got a branch at Khamgaon. The three workmen mentioned in the schedule set out above were working as Godown Watchmen at Khamgaon branch during the period from April, 1969 to December, 1972. It is not disputed that it is an establishment registered under the Bombay Shops and Establishments Act, 1948 (hereinafter referred to as the "Shops Act"). The provisions of the Shops Act are, therefore, applicable to Khamgaon branch of the State Bank of India.

3. The three watchmen were deputed by the employer-Bank for work as detailed below :

"(i) M. G. Laware was deputed to work as a Watchman of the Godown of M/s. Bhudas Karsandas & Co.;

(ii) D. J. Ingle was deputed to the Godown of M/s. Thunjunwala & Co.; and

(iii) S. R. Deshmukh was deputed to M/s. Thunjunwala Rolling Mills and Engineering Works."

These workmen were required to work at the godowns of the aforesaid concerns for the relevant period. It is the case of the workmen that they were required to perform 12 hours duty. According to them, they were required to work overtime for four hours a day. The workmen claimed that the total amount due to them on account of overtime wages was as follows :

"(i) Laware : Rs. 12,001.81.

(ii) S. R. Deshmukh : Rs. 12,568.58.

(iii) D. J. Ingle : Rs. 10,897.78".

However, the Bank did not make the payment to them for overtime wages. They alleged that the godowns where they were detailed to work were under the Municipal limits of Khamgaon and the provisions of the Shops Act are, therefore, applicable. They contended in their statement of claim that the factum of performance of 12 hours work per day is not disputed by the Bank. They, therefore, prayed that this Tribunal be pleased to pass an award granting them the relief in respect of the overtime wages as claimed.

4. In the written statement filed on behalf of the Bank it was admitted that the provisions of the Shops Act are applicable. It was, however, pleaded that as laid down in paragraph 195 of the Labour Appellate Tribunal's decision, a godown watchman has no fixed hours of work and is not required to sign the Attendance Register in the office of the Bank. It was, therefore, denied that the workmen are entitled to overtime wages as claimed. It was contended that these workmen are entitled to godown allowance as provided in clause 512 of Chapter-V of the award of the Labour Appellate Tribunal. They are paid an allowance of Rs. 8 each. It was, therefore, alleged that there could not be any question of these workmen having performed the duties in excess of their prescribed period and/or their being entitled to claim overtime allowance. It was denied that they had admitted the factum of performance of overtime by these workmen. It was pleaded that under item 14 of Schedule II of the Shops Act these workmen are exempted from the operation of certain sections of the Shops Act which included Section 14 of that Act. It was, therefore, submitted that no overtime wages are payable to the workmen and the reference be disposed of accordingly.

5. It is not in dispute that the Shops Act is applicable to the establishment viz., the Khamgaon branch of the State Bank of India where the workmen worked. Reliance is, however, placed upon Section 14 read with Section 4 of the Shops Act. It is pointed out for the Bank that under item No. 14 of Schedule II of the Shops Act the workmen are

excluded from the provisions of Section 14 of the Shops Act, Section 14(1) provides :—

"Subject to the provisions of this Act, no employee shall be required or allowed to work in any shop or commercial establishment for more than nine hours in any day and forty-eight hours in any week."

It is argued on the basis of this provision read with item No. 14 in Schedule II of the Shops Act that the provisions regarding hours of work as mentioned in Section 14(1) of the Shops Act are not applicable to the case of workmen. The argument is that the workmen may be made to work for more than the hours of work specified in the said section and because of the exemption they will not be entitled to claim overtime wages under Section 63 of the Shops Act.

6. Mr. Pillai, the learned counsel for the Union, submitted that exemption granted under item No. 14 of Schedule II of the Shops Act will not be available to the Bank for resisting the claim for overtime work. In support of this submission, he relied upon the decision of the Division Bench of the Bombay High Court in the case of Penambur Vishnumurti Narayan Upadhaya v. C. P. Fernandes (Vol. 58 B.L.R. 1956 p. 799). That was a case where the employee of a bakery, who was a deliveryman whose work was to deliver bread and loaves prepared by the bakery to its customers, applied under Section 63 of the Shops Act for payment of overtime wages. A contention was raised on behalf of the bakery that under Schedule II, item 8 of the Shops Act the prohibition contained in Section 14 of the Shops Act, prohibiting the employer from making the employee work beyond the limit of hours prescribed therein was removed as regards deliveryman. It was held that in spite of the above provision, if the employee established that he had worked overtime in any particular work, he was entitled to overtime wages as provided in Section 63 of the Act. Their Lordships observed :—

"It is erroneous to assume that because an establishment is exempted from the provisions of S. 14 and because there is no limit of work laid down with regard to that establishment under S. 14, therefore there is no limit of hours of work applying to that establishment as far as Section 63 is concerned. The limit of work for the purpose of S. 14 is entirely different from the limit of work laid down by the legislature for the purpose of Section 63. Whereas the limit of work for the purpose of S. 14 is laid down in order to prohibit the employer from requiring an employee to make him work beyond the limit, the limit of work laid down for the purpose of Section 63 is purely for the purpose of computing overtime wages. In our opinion, therefore, if the employee in this case establishes that he has worked overtime in any particular week he would be entitled to overtime wages as provided by Section 63."

It was further observed in this decision that the authority below was in error in taking the view that because there was no limit of work with regard to a particular establishment under Section 14, therefore, there would be no limit of work under Section 63 and the establishment could make an employee work for any length of time without paying him overtime wages. This decision is a complete answer to the argument that in view of the entry No. 14 in Schedule II of the Shops Act the employees cannot claim overtime for the overtime work under the provisions of Section 63 of the Shops Act. It must, however, be noted that item 14 in Schedule II of the Shops Act, does not say that the provisions in Section 63 also are not applicable to the employees of the establishments mentioned in item No. 14.

7. It will, therefore, have to be held that the workmen i.e. the three watchmen in this reference are entitled to overtime wages by virtue of the provisions in Section 63 of the Shops Act.

8. Mr. Modak, the learned counsel for the Bank, referred to the agreement dated 31st March, 1967, between the State Bank of India and its Workmen represented by the All India State Bank of India Staff Federation. Para 5.12 therein provides :—

GODOWN ALLOWANCE

Godown Keepers and Godown Watchmen to whom the provisions regarding hours of work and overtime do not apply and who were excluded by the Labour Appellate Tribunal in paragraphs 194 and 195 of its Decision dated 28th April 1954 shall be paid a Godown Allowance of Rs. 25 per month if he is a Godown Keeper and Rs. 15 per month if he is a Godown Watchman."

Relying upon this provision it is contended for the Bank that the Godown Watchmen are not entitled to overtime wages, but to Godown Allowance only. However, it is made clear in the said paragraph itself that the provisions regarding payment of Godown Allowance will be applicable to Godown Keepers and Godown Watchmen to whom the provisions regarding hours of work and overtime do not apply. Now, obviously under the provisions of the Shops Act, the Godown Watchmen, who are working within the Municipal limits, would be entitled to overtime wages, if their hours of work exceed the prescribed limit. This para, therefore, is of no avail to the Bank. Even though under item No. 14 of Schedule II to the Shops Act, there is exemption in the case of Godown Watchmen in respect of the provisions mentioned in column 3 of item No. 14, there is no exemption in their case in respect of the provisions in Section 63 of the Shops Act. The provisions in Section 63 of the Shops Act will be available to these Godown Watchmen for claiming wages for overtime work. Under Section 63(1) of the Shops Act they shall be entitled, in respect of the overtime work, to wages at the rate of 1-1/2 time their ordinary rate of wages.

9. A notice was given on 13th August, 1982 by the Association, who espoused the case of workmen to the Bank to produce certain documents. The Bank has now produced the documents as per that notice. One of the documents produced is a letter written by the Branch Manager, Khamgaon Branch on 26th April, 1973 to the Regional Manager, State Bank of India, Bombay. In that letter there is clear admission that the three Watchmen have put in overtime work and overtime pay as claimed by them is payable to them. In fact the Branch Manager had sought the permission of the Regional Manager to make payment for the overtime work as claimed by the three Godown Watchmen in their statement of claim.

10. I, therefore, find that the management of the State Bank of India, Chief Regional Manager, Nagpur, is not justified in denying overtime claims to the three Godown Watchmen, Laware, Ingle and Deshmukh. They are entitled to overtime wages as provided in Section 63 of the Shops Act, 1948.

11. My award accordingly. No order as to costs.

M. D. KAMBLI, Presiding Officer

[No. 1-12012(48)/78-D.II(A)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1982

का० आ० 70:—केन्द्रीय सरकार, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) की धारा 10 के अनुसरण में, वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान उक्त अधिनियम के अधीन वित्त वित्त पोषित अपने श्रिया कलापों का वृत्त देने हुए उस वर्ष के लेखा विवरण के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट प्रकाशित करती है :—

यामान्य :—चूना-पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि, चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 (1972 का 62) के अधीन गठित की गई थी, जिसमें किसी खान में उत्पादित उतने चूना

पत्थर और डालोमाइट पर, जिनका चूना पत्थर और डोलोमाइट खाना में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अनिवार्य करने के लिए —

- (1) किसी कारखाने के अधिष्ठाता का प्रत्यक्ष किया जाता है या अन्यथा व्ययन किया जाता है, या
- (2) ऐसी खान के स्वामी द्वारा मॉडल, लोहा या इस्पात के निर्माण में किसी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है।

यथास्थिति चूना पत्थर या डोलोमाइट पर एक स्था प्रति मीटरी टन में प्रत्यक्ष दर में उत्पादन शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण की व्यवस्था की गई है। इस समय उद्ग्रहण की वास्तविक दर बीस पैसे प्रति मीटरी टन है। उपर के प्रागम मुख्यतः लाभ स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था, आवास और पोषण कार्यक्रमों, आदि के लिए प्राथमिकता देने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

2 प्रशासनिक सुविधाओं के लिए, उद्योग राज्यों और मध्य भागित क्षेत्र गोंदा और दिल्ली का जिनमें देश की चूना पत्थर और डोलोमाइट खान है, पांच क्षेत्रों में बांटा गया है और इन क्षेत्रों के कल्याण आयुक्तों का इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों का लागू करने के लिए कल्याण और उपर आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया गया है। क्षेत्रों का आवंटन इस प्रकार किया गया है —

कमाक अधिकारी का मुख्यालय पदनाम	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य
1 कल्याण आयुक्त, जबलपुर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार जबलपुर।	मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और मध्यभागीत क्षेत्र गोंदा
2 कल्याण आयुक्त, भुवनेश्वर श्रम मंत्रालय, भारत सरकार भुवनेश्वर।	उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय।
3 कल्याण आयुक्त, इलाहाबाद श्रम मंत्रालय, भारत सरकार इलाहाबाद।	बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और मध्यभागीत क्षेत्र दिल्ली
4 कल्याण आयुक्त, भीलवाड़ा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, भीलवाड़ा।	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश।
5 कल्याण आयुक्त, बगलौर श्रम आयुक्त, भारत सरकार, बगलौर।	तमिलनाडु, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश

नतीजा यह था कि खानों के अधिकारियों के लिए निम्नलिखित कारण सुविधाओं की व्यवस्था की गई है

(क) स्वास्थ्य

3.1 पहली स स्वास्थ्य 12 आयुर्वेदिक और 14 एलोपैथिक औषधालयों के अलावा, आलाय्य अवधि के दौरान चार और औषधालयों जूनागढ़ (राजस्थान) चित्तौड़गढ़ (राजस्थान), मानस (हिमाचल प्रदेश) और लहेरी (राजस्थान), में एक एक का मजूरी दी गई। इन औषधालयों में 2.53 लाख से अधिक रोगी लाभ उठाते हैं।

3.2 आलोय्य वर्ग के दौरान खान प्रबंधन का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान भी मंजूर किए गए —

(क) एम्बुलेंस खर्च	2,37,000 रुपये
(ख) एक्सरे मशीन	—
(ग) अन्य व्यय	1,30,409.56 रुपये

3.3 घातक अन्न गमारा दुर्घटना यात्रा के अंतर्गत 22 व्यक्तियों को लाभ प्राप्त हुआ और 17 चिकित्सा के रोगियों का इलाज किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में चिकित्सा से पीड़ित रोगियों के लिए 41 पलक अर्पित किए गए।

शिक्षा

4 चूना-पत्थर और डालोमाइट श्रमिकों के पुत्रों और पुत्रियों का छात्रवृत्तियां देने की यात्रा के अंतर्गत 1776 छात्रों का छात्रवृत्तियों के रूप में 1,33,055 रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसमें भीलवाड़ा क्षेत्र के 336, बगलौर क्षेत्र के 17, जबलपुर क्षेत्र के 297, भुवनेश्वर क्षेत्र के 16 और इलाहाबाद क्षेत्र के 110 छात्र थे।

आवास

5 वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान टाइट-1 आवास यात्रा के अंतर्गत 646 मकानों का निर्माण करने की स्वीकृति दी गई और रिपोर्टिंग वर्ष के दौरान 132 मकानों का निर्माण किया जा चुका था और आता मकान बनाओ योजना के अंतर्गत 130 मकानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई और 1981-82 के दौरान 27 मकानों का निर्माण पूरा किया गया।

मनोरंजन

6 आलाय्य वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर 9 विनोद प्रोजेक्टरों और 8 रेडियो सेटों की व्यवस्था करने की स्वीकृति दी गई।

6.1 इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रबंधकों द्वारा चलाए जा रहे कल्याण केन्द्रों का 1629.80 रुपये की सहायता अनुदान की मजूरी दी गई और विभिन्न क्षेत्रों में टूर्नामेंटों, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 56,207.44 रुपये की राशि मंजूर की गई।

जल प्रदाय :

7. रिपोर्टधीन अवधि के दौरान, जल प्रदाय स्कीम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खानों के प्रबंधन को 14,68,026 रुपए को अन्तिम किस्त स्वीकृत की गई।

8. वर्ष 1981-82 का लेखा विवरण

	रु०
1-4-81 को अथशेष	1,80,25,796.00
1981-82 के दौरान प्राप्तियां	66,361.22
व्यय	41,33,843
31-3-1982 को अन्तशेष	2,05,52,975.00

[सं० जैड-16016/1/82-एम० वी/डब्ल्यू II]

टी० डी० सलहोत्रा, अवर सचिव

New Delhi, the 15th December, 1982

S.O. 70.—In pursuance of section 10 of the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972), the Central Government hereby publishes the following report giving an account of its activities financed under the said Act during the financial year 1981-82 together with the statement of accounts of that year :—

General.—The Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund was constituted under the Limestone and Dolomite Mines Labour Welfare Fund Act, 1972 (62 of 1972) which provides for the levy and collection of cess at a rate not exceeding one rupee per metric tonne on so much of Limestone and Dolomite produced in any mine,

- (i) as is sold or otherwise disposed to the occupier of any factory, or
- (ii) as is used by the owner of such mine for any purpose in connection with the manufacture of cement, iron or steel,

to promote the welfare of the persons employed in limestone and dolomite mines. The actual rate of levy presently is twenty paise per metric tonne. The proceeds of the cess are being utilised mainly for the improvement of public health and sanitation, provision of medical facilities, subsidy on housing and programmes of nutrition etc.

2. For administrative convenience, the nineteen States and Union Territories of Goa and of Delhi which have Limestone and dolomite mines in the country, have been grouped into five regions, and the Welfare Commissioners of the areas have been appointed as Welfare and Cess Commissioners for the enforcement of the Act and Rules framed thereunder.

The allocation of the region is as under:—

Sl. No.	Designation of the Officer	Headquarters	Name of the States and their jurisdiction
1.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Jabalpur.	Jabalpur	Madhya Pradesh, Maharashtra and Union Territory of Goa.
2.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India Bhubaneswar.	Bhubaneswar	Orissa, West Bengal Assam and Meghalaya
3.	Welfare Commissioner, Government of India, Ministry of Labour, Allahabad.	Allahabad	Bihar, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir and Union Territory of Delhi
4.	Welfare Commissioner, Ministry of Labour, Government of India, Bhillwara.	Bhillwara	Rajasthan, Gujarat, Haryana, Punjab and Himachal Pradesh.

5. Welfare Commissioner, Bangalore
Ministry of Labour
Government of India
Bangalore

Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh.

The following welfare facilities have been provided to Limestone and Dolomite Mines workers:—

A. HEALTH Besides 12 Ayurvedic and 14 Allopathic dispensaries established earlier, four more dispensaries one each at Junagarh (Rajasthan), Chittorgarh (Rajasthan), Manal (H.P. and Lahori (Rajasthan) were sanctioned during the year under report. These dispensaries serve more than 2.53 lakhs patients.

3.2 Grant in aid for the following purposes were also sanctioned to the mine managements during the year under report:—

(a) Ambulance	R. 2,37,000
(b) Chest Screening Machine	...
(c) Other Hospital Equipments	R. 1,30,409.56

3.3. 22 persons were provided benefits under Fatal benefit and serious accident Scheme and 17 patients were treated for Tuberculosis 41 beds were reserved for T.B. patients in different regions.

EDUCATION:—

Under the scheme of award of scholarships to sons and daughters of limestone and dolomite workers, an amount of Rs. 1,33,055 lakhs was paid as scholarships to 1776 students. Out of these 336 were in Bhilwara, 17 in Bangalore, 297 in Jabalpur and 16 in Bhubaneswar and 110 in Allahabad.

HOUSING:

5. During financial year 1981-1982, 646 houses were sanctioned under Type I Housing Scheme, 132 houses were constructed during the year under report and 130 houses were sanctioned under Build Your Own House Scheme and 27 houses have been completed during 1981-1982.

RECREATION:

During the year under review 9 cinema projectors and 8 Radio Sets were sanctioned for providing at different places.

6.1 In addition, grants-in-aid amounting to Rs. 1629-80 was sanctioned to the Welfare Centres maintained by the different managements and an amount of Rs. 56,207.44 was sanctioned for tournaments, social and cultural activities in different regions.

WATER SUPPLY:

7. During the period under report for water supply scheme a final instalment amounting to Rs. 14,68,026 was sanctioned to the management of different quarries in different regions.

8. Statement of account for year 1981-1982

Opening Balance as on 1-4-1981	Rs. 1,80,25,796.00
Receipts during 1981-1982	Rs. 66,361.22
Expenditure	Rs. 41,33,843
Closing balance as on 31-3-1982	Rs. 2,05,53,975.00

[F.No. Z-16016/1/82-M.V.W.II]
T.D.SALHOTRA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1983

का. आ. 71.—नियमित (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मैसर्स पेस्ट मोरटम (इंडिया) प्रा लि 53-1-16, मकावरी सेट, जगन्नाथपुर, काकीनाड-2, को निम्नलिखित मदों के भरीकरण के लिए अभिकरण के रूप में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देती है —

- 1 तेल रहित चावल की भूसी और
- 2 हड्डी का चूरा, सूर और सींग ।

[स 5(3)/82-ई आई एण्ड ई पी]

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st January, 1982

S.O. 71.—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises for a period of one year M/s. Pest-Mortem (India) Pvt Ltd, 53-1-16, Mekavari St., Jagannapukur, Kakimada 2, as an agency for the fumigation of following items —

- 1 De oiled Rice Bran, and
- 2 Crushed Bones, Hooves and Horns

[No 5(3)/82-EI&EP]

आदेश

का० आ० 72 — भारत के निर्यात व्यापारिक विकास के लिए प्रेशर कुकरों का निर्यात में पूर्व क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अधीन लाने के लिए कनिष्ठ प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षाानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 2287 तारीख 26 जून, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड-3, उप-खंड (ii) तारीख 26 जून 1982 में प्रकाशित किए गए थे,

और उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशित हान के पैंतालीस दिन के भीतर उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी,

और उक्त राजपत्र की प्रतिया जनता का 12 जुलाई, 1982 को उलब्ध करा दी गई थी,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्राप्ति प्रस्ताव पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, निर्यात निरीक्षण परिपद्ध से परामर्श करने के पश्चात अपना यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापारिक विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण

और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए —

- (1) अधिसूचित कंपनी है कि प्रेशर कुकर निर्यात में पूर्व निरीक्षण के अधीन होंगे,
- (2) प्रेशर कुकर निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1963 के अनुसार निरीक्षण के प्रकार का निरीक्षण के ऐसे प्रकार के रूप में निर्दिष्ट कंपनी है जो निर्यात में पूर्व ऐसे प्रेशर कुकरों का निर्यात
- (3) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा निर्यात निरीक्षण परिपद्ध द्वारा मान्यता प्राप्त और नियमों के मानकों का प्रेशर कुकरों के निर्यात मानक निर्दिष्टों के रूप में मान्यता देती है तथा
- (4) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दौरान प्रेशर कुकरों के निर्यात को तब तक प्रतिषेध करती है जब तक कि उनके साथ निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7 के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त अभिकरणों में से किसी एक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण-पत्र न हो कि प्रेशर कुकरों का परीक्षण इसके निरीक्षण से संचालित शर्तों का पूरा करना है तथा निर्यात योग्य है।

2 इस आदेश की कोई भी बात भू-भाग, समुद्री मार्ग या वायु मार्ग द्वारा किये गये प्रेशर कुकर के वास्तविक नमूना के निर्यात पर लागू नहीं होगी।

3 इस आदेश, में, 'प्रेशर कुकर' से 4 लीटर से लेकर 22 लीटर तक की धारिता वाला ऐसा कोई दाब-पाक पात्र अभिप्रेत है जिसका प्रयोग बाहरी उष्मा में होता है जिसमें 10 किलोग्राम एफ/सेटी मीटर 2 का कार्यकरण दाब बनाये रखने की क्षमता होती है।

4 यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

[स० 6(9)/81-ई० आई० एण्ड ई० पी०)]

ORDER

S.O. 72 —Whereas for the development of the export trade of India certain proposals for subjecting Pressure Cookers to quality control and inspection prior to export were published as required by sub rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part II—Section 3—Sub-section (ii) dated the 26th June, 1982, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No S.O. 2287 dated 26th June, 1982,

And whereas the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby within 45 days of the publication of the said Order in the Official Gazette, And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th July, 1982,

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft proposal have been considered by the Central Government;

Now, therefore, the Central Government, after consulting the Export Inspection Council, being of opinion that it is necessary and expedient so to do for the development of export trade of India, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), hereby—

- (1) notifies that the Pressure Cookers shall be subject to inspection prior to export;
 - (2) specifies the type of inspection in accordance with the export of Pressure Cookers (Inspection) Rules, 1983 as the type of inspection which would be applied to such Pressure Cookers prior to export;
 - (3) recognises National and International Standards, and standards of other Bodies recognised by Export Inspection Council as the standard specifications for the Pressure Cookers; and
 - (4) prohibits the export in the course of International Trade of Pressure Cookers unless the same is accompanied by a certificate issued by any one of the Agencies recognised or established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) to the effect that the consignment of Pressure Cookers satisfies the conditions relating to its inspection and is exportworthy.
2. Nothing in this Order shall apply to the export by land, sea or air of bonafide samples of the Pressure Cookers.
3. In this Order, "Pressure Cookers" means any pressure cooking vessel of capacity from 4 litres upto and including 22 litres for use with external heat sources capable of maintaining working steam pressure of 1.0 kgf/cm².
4. This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[No. 6(9)/81-EI&FP]

का० अ० 73.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रेशर कुकर निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1983 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो; —

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "अभिकरण" से अधिनियम की धारा 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित अभिकरणों में से या मान्यता प्राप्त कोई संगठन अभिकरण अभिप्रेत है।

(ग) "प्रेशर कुकर" से 4 लीटर से लेकर 22 लीटर तक की धारिता वाला ऐसा कोई दाब-पाक पात्र अभिप्रेत है जिसका प्रयोग बाहरी उष्मा से होता है जिसमें 1.0 किलोग्राम एफ/सेंटीमीटर का

कार्यकरण दाब बनाये रखने की क्षमता होती है।

3. निरीक्षण का आधार तथा प्रक्रिया—(1) निर्यात के लिये आगबित प्रेशर कुकर का निरीक्षण यह देखने के विचार में किया जायेगा कि वे अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निविर्देशों के अनुरूप हैं अर्थात् राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय मानक तथा निर्यात निरोधक परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य निकायों के मानक, प्रेशर कुकरों के लिये मानक विनिर्देशों के रूप में।

या तो

(क) यह सुनिश्चित करके कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान नियम 3 के उप-नियम 2 (क) के मधीन उपाबंध-1 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण ट्रिगर्स का प्रयोग किया गया है,

(ख) नियम 3 के उप-नियम 2 (ख) के अनुसार लिये गये निरीक्षण के आधार पर,

या

(ग) दोनों के द्वारा।

(2) प्रेशर कुकरों के निरीक्षण के लिये निरीक्षण की निम्नलिखित स्कीमों में से कोई एक स्कीम या दोनों स्कीमों अपनाई जायेंगी, अर्थात्:—

(क) प्रक्रिया क्वालिटी नियंत्रण:—

(i) कोई भी विनिर्माण एकक जिसके पास उपाबंध-1 के अनुसार प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है, अभिकरण के निकटतम कार्यालय को आवेदन करेगा।

(ii) निर्यात निरीक्षण अभिकरण विनिर्माण एकक में जाने का प्रबंध करेगा तथा यह निर्धारित करेगा कि उत्पादन के दौरान क्वालिटी नियंत्रण पद्धति सन्तोषजनक रूप के कार्य कर रही है।

(ख) परेक्षणानुसार निरीक्षण:—

कोई भी विनिर्माण एकक खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो वह अपने निर्यात किये जाने वाले परेक्षणों का किसी भी अभिकरण को निरीक्षण के लिये देगा जो यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि उसके द्वारा विनिर्मित उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

(3) निम्नलिखित प्रक्रिया प्रेशर कुकरों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिये अपनाई जायेंगी, अर्थात्:—

(i) प्रेशर कुकरों के निर्यात करने का इच्छुक कोई निर्यातकर्ता अपने ऐसा करने के आशय की सूचना

निश्चित रूप से देगा और उसी सूचना के साथ ऐसा निर्धारण में सम्बन्धित निर्धारण सविदा में दी गयी सभी तकनीकी विशेषताओं का विवरण देने हुए विनिर्देशों का धारणा पत्र तैयार भी अभिकरण का देगा जिससे कि यह उप-नियम (2) के खंड (क) या खंड (ख) या दोनों खंडों के अनुसार निरीक्षण कर सके।

- (ii) वह उसी समय सूचना की एक प्रति निरीक्षण के लिये परिषद के कार्यालय का देगा।
- (iii) उप-नियम (2) के खंड (क) के अनुमोदित एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों के निर्माण के लिये निर्धारित ऐसी सूचना के साथ यह भी धारणा करेगा कि निर्धारण के लिये आशयित प्रेशर कुकरों का विनिर्माण उपावध-1 में अधिकतम नमालिटी नियंत्रण का प्रयोग करके किया गया है और परेक्षण इस प्रयोजन के लिये अधिनियम की धारा 6 के अधीन मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।
- (iv) खंड (iii) के अधीन प्रत्येक सूचना तथा ओवरला विनिर्माता के परिषद में परेक्षण के भेजे जाने से कम से कम 3 दिन पहले परिषद तथा अभिकरण के कार्यालय में पहुंच जानी चाहिये।
- (v) निर्यातकर्ता अभिकरण का परेक्षण पर लगाये जाने वाले पहचान चिन्ह भी देगा।
- (vi) खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन सूचना तथा धारणा प्राप्त होने पर अभिकरण—

(क) उप-नियम (2) के खंड (क) के अधीन अनुमोदित एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों का निर्धारण करने वाले निर्यातकर्ता की दशा में करना यह समाधान कर लेने पर कि विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान एकक न उपावध-1 के अधीन दिये गये पर्याप्त नमालिटी नियंत्रणों का प्रयोग किया है और इस संबंध में परिषद द्वारा जारी किये गये निर्देशों, यदि कोई हों, का पालन किया है तो यह तीन दिन के भीतर यह धारणा करने हुए प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि प्रेशर कुकरों का परेक्षण निर्यात योग्य है। तथापि अभिकरण कालिक निरीक्षणों द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि विनिर्माण परिषदों पर पर्याप्त नियंत्रणों का प्रयोग किया गया है तथा उत्पाद मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है, और

(ख) उप-नियम (2) के खंड (ख) के अंतर्गत आने वाले एककों द्वारा विनिर्मित उत्पादों

का निर्धारण करने वाले निर्यातकर्ता की दशा में प्रेशर कुकरों का निरीक्षण यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से करेगा कि उत्पाद इस प्रमाणन के लिये मान्यता प्राप्त विनिर्देशों के अनुरूप है।

- (vii) (1) जब कभी अभिकरण द्वारा परीक्षा की जाये कि निर्धारित निर्धारण परेक्षण में न प्रेशर कुकरों के नमूने निरीक्षण और परीक्षण के लिये निर्यात देगा। तथापि, ऐसे नमूने निरीक्षण करने के पश्चात् अभिकरण द्वारा धारणा कर दिये जायेंगे।
- (2) निरीक्षण की समाप्ति के पश्चात् अभिकरण परेक्षण में परीक्षा की इस रीति में पुनः परीक्षा करेगा कि यह सुनिश्चित हो जाये कि मुहरबंद परेक्षा में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।
- (3) परेक्षण अस्वीकृत हो जाने की दशा में, यदि निर्यातकर्ता ऐसा चाहे तो अभिकरण परेक्षण को मुहरबंद नहीं करेगा।
- (4) ऐसे मामले में, तथापि, निर्यातकर्ता अस्वीकृत के विरुद्ध अपील करने का हकदार नहीं होगा।
- (viii) यदि अभिकरण का समाधान हो जाता है कि प्रेशर कुकरों का परेक्षण इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं का पूरा करता है तो वह निरीक्षण की समाप्ति के सात दिनों के भीतर निर्यातकर्ता को यह धारणा करने हुए, प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि परेक्षण निर्यात योग्य है।

परन्तु जहां अभिकरण का समाधान नहीं हो पाता है वहां वह उक्त सात दिनों के अन्तर्गत उसके लिये कारण देने हुए अस्वीकृत-पत्र जारी करेगा।

1. मान्यताप्राप्त चिन्ह का चिपकाना और उसकी प्रक्रिया—

भारतीय मानक सस्था (प्रमाणन चिन्ह) अधिनियम, 1952 (1952 का 36) भारतीय मानक सस्था (प्रमाणन चिन्ह) नियम, 1955 तथा भारतीय मानक सस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के उपावध प्रेशर कुकरों पर निर्धारण से पूर्व मान्यता प्राप्त चिन्ह या मुहर लगाने की प्रक्रिया के संबंध में यथा सभव लागू होंगे तथा इस प्रकार चिन्हित प्रेशर कुकरों का नियम 3 के अधीन कोई भी निरीक्षण नहीं किया जायेगा। 5 निरीक्षण का स्थान—इन नियमों के अधीन निरीक्षण विनिर्माता के या अन्य परिषदों पर किया जायेगा जहां परीक्षण और निरीक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

6. निरीक्षण शुल्क निर्यातकर्ता, अधिकरण को निरीक्षण फीस निम्न प्रकार देगा :

प्रति परेक्षण न्यूनतम 20 रुपये (बीस रुपये) के अर्धान रहने हए

- (1) अनुमोदिन प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण एकाई द्वारा निर्यात के लिए विनिर्मित और आशयित तथा नियम 3 के उप-नियम (1) (2) और (4) के आधार पर निरीक्षण करने के लिए वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.2% की दर से।
- (2) अनुमोदिन प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण एकाई द्वारा विनिर्मित और व्यापारी निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात के लिए आशयित तथा नियम 3 के उप-नियम (4) के आधार निरीक्षण के लिए विनिर्मित वस्तुओं के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.3% की दर से।
- (3) व्यापारी निर्यातकर्ताओं द्वारा निर्यात के लिए आशयित तथा नियम 3 के उप-नियम (3) के आधार पर निरीक्षण के लिए विनिर्मित वस्तुओं के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.4% की दर से।
- (4) राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की संबंधित सरकारों के पास लघु उद्योग विनिर्माण एकाई के रूप में रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं द्वारा निर्यात के लिए आशयित वस्तुओं और नियम 3 के उप-नियम (1), (2) तथा (3) के आधार पर निरीक्षण करने के लिए आशयित वस्तुओं के पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.18% तथा 0.36% की दर से।

7. अपील :

- (1) नियम 3 के अर्धान अधिकरण द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के इन्कार से व्यथित व्यक्ति उसके द्वारा ऐसे इन्कार की सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर कम से कम तीन व्यक्तियों के विशेषज्ञ पैनल को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किया जा सकेगा, अपील कर सकेगा।
- (2) विशेषज्ञ पैनल की कुल सदस्यता संख्या में से कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।
- (3) पैनल की गणपूर्ति तीन से होगी।
- (4) अपील, प्राप्त होने के पन्द्रह दिनों के भीतर निपटा दी जाएगी।

उपाबंध-1

प्रक्रियागत क्वालिटी नियंत्रण :

निर्यात के लिए आशयित प्रेशर कुत्तरो की क्वालिटी विनिर्माता द्वारा, उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट नियंत्रण के स्तरों

पर, विनिर्माण के विभिन्न प्रक्रमों पर निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके निश्चित की जाएगी।

- 1 क्रय की गयी सामग्री तथा संघटकों का नियंत्रण :
 - (क) विनिर्माता प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री या संघटकों की विशेषताओं तथा सहायताओं सहित विशुद्ध विमाओं को समाविष्ट करने हए, क्रय विनिर्देश अधिकथित करेगा।
 - (ख) स्वीकृत परेक्षणों के साथ या तो क्रय विनिर्देशों की अपेक्षाओं की संपुष्टि करने हए, उत्पादक का परीक्षण प्रमाणपत्र होगा या ऐसे परीक्षण प्रमाणपत्र के न होने पर, क्रय विनिर्देशों से इसकी अनुसरण की जांच करने के लिए प्रत्येक परेक्षण में से नमूनों की नियमित जांच की जाएगी। उत्पादक के परीक्षण प्रमाणपत्र की शुद्धता स्थापित करने के लिए पांच परेक्षणों में से कम से कम एक पुनः जांच की जाएगी।
 - (ग) आने वाले परेक्षणों का निरीक्षण और परीक्षण, माध्यिकी नमूना योजना के अनुसार क्रय विनिर्देशों से अनुसरण सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा।
 - (घ) निरीक्षण या परीक्षण किए जाने के पश्चात् स्वीकृत और अस्वीकृत माल या संघटकों के पृथक्करण के लिए तथा अस्वीकृत माल या संघटकों के निपटान के लिए व्यवस्थित पद्धतियां अपनाई जाएंगी।
 - (ङ) उपरोक्त नियंत्रण के संवद्र में पर्याप्त अभिलेख व्यवस्थित रूप में रखा जाएगा।

प्रक्रिया नियंत्रण :

- (क) विनिर्माता विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए व्योरेवार प्रक्रिया विनिर्देश अधिकथित करेगा।
- (ख) प्रक्रिया विनिर्देश में अधिकथित प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए उपस्कर या उपकरणों की पर्याप्त सुविधाएं होंगी।
- (ग) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयुक्त नियंत्रणों का स्थापन करने के लिए पर्याप्त अभिलेख रखा जाएगा।

3. उत्पाद नियंत्रण :

- (क) मानक विनिर्देशों के अनुसार उत्पाद का परीक्षण करने के लिए विनिर्माता के पास या ता अपनी परीक्षण सुविधाएं होंगी या उसकी पहुंच वहां तक होगी जहां ऐसी सुविधाएं विद्यमान है। इसके लिए पर्याप्त अभिलेख रखा जाएगा।
- (ख) परीक्षण के लिए नमूना (जहां कहीं भी अपेक्षित हो) अभिलेखित अन्वेषण पर आधारित होगा।

(ग) प्रत्येक समुच्चय को जांच अधिकथित निरीक्षण जांच सूची के अनुसार की जाएगी।

4. माप-पद्धति नियंत्रण :

उत्पादन और निरीक्षण में प्रयुक्त गेजों तथा उपकरणों की कालिक जांच या उनका अनुमंशोधन किया जाएगा तथा अभिलेख, दृत्त कार्ड के रूप में रखे जाएंगे।

5. ररिरक्षण नियंत्रण :

(क) उत्पाद को मौसमी परिस्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए विनिर्माता द्वारा ब्यौरेवार विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे।

(ख) उत्पाद भंडारकरण और अभिवहन दोनों के दौरान अच्छी प्रकार से ररिरक्षित रखा जाएगा।

6. पैकिंग नियंत्रण :

उपयुक्त उत्पाद की पैकिंग के लिए विनिर्देश अधिकथित किया जाएगा।

उपाबंध 2

नियंत्रण के स्तर

क्रम संख्यांक	निरीक्षण/परीक्षण की विशेषताएं	अपेक्षाएं	नमूना आकार	सॉट आकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	कय की गयी सामग्री और संघटक			
	(क) चाक्षुष निरीक्षण (कारीगरी और फिनिश सहित)	प्रयोजन के लिए मान्यता - प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	---
	(ख) सह्यताओं सहित विमाणं			
	(1) सबसे मुख्य	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषणों के आधार पर निश्चित किया जाएगा	प्रत्येक सॉट
	(2) अन्य	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	यथोक्त	प्रत्येक सॉट
	(ग) अन्य कोई अपेक्षा	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	यथोक्त	प्रत्येक सॉट
2.	विनिर्मित संघटक तथा उप समुच्चय			
	(क) चाक्षुष निरीक्षण (कारीगरी और फिनिश सहित)	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	---
	(ख) सह्यताओं सहित विमाणं			
	(1) सबसे मुख्य	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा।	प्रत्येक सॉट
	(2) अन्य	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	अभिलेखित अन्वेषण के आधार पर निश्चित किया जाएगा।	यथोक्त
3.	समुच्चय			
	(क) कारीगरी और फिनिश	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	---
	(ख) परीक्षण			
	(1) क्षमता परीक्षण	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	ढले हुए कुकरो के लिए 50 कुकरो में से एक और पिटवा लोहे के कुकरो या इसके भाग के लिए प्रति 500 कुकरो में से एक	
	(2) वायु दाब परीक्षण	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रत्येक	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(3) प्रूफ दाब परीक्षण				
(क) ढले हुए कुकुरों के लिए	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त	(1) प्रति माह 2000 नगों तक के उत्पादन के लिए	कुल उत्पादन का 4%	
(ख) कुकुरों के लिए पिटवा लोहे के	मानक विनिर्देशों के अनुसार	(2) प्रति माह 2001 से 10,000 नगों तक के उत्पादन के लिए	कुल उत्पादन का 2%	
		(3) प्रति माह 10,000 नगों से अधिक उत्पादन के लिए	कुल उत्पादन का 1%	
(4) दाब नियंत्रण युक्ति के लिए प्रचालन परीक्षण				
	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	(क) प्रति माह 2000 नगों तक के उत्पादन के लिए	कुल उत्पादन का 10%	
		(ख) प्रति माह 2001 से 10,000 नगों तक के उत्पादन के लिए	कुल उत्पादन का 5%	
		(ग) प्रति माह 10,000 नगों से अधिक उत्पादन के लिए	कुल उत्पादन का 2%	
(5) सुरक्षा दाब विभाजन यंत्र के लिए परीक्षण				
	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार		कुल उत्पादन का 1%	
(6) बिस्फोट दाब परीक्षण				
(क) ढले हुए कुकुरों के लिए प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त	प्रति 100 कुकुरों में से एक			
(ख) कुकुरों के लिए मानक विनिर्देशों के अनुसार		(1) प्रति माह 2000 नगों तक के उत्पादन के लिए	प्रत्येक 500 कुकुरों में से एक	
पिटवा लोहे के		(2) प्रति माह 2001 नगों और 10,000 नगों तक के उत्पादन के लिए	प्रत्येक 700 कुकुरों में से एक	
		(3) प्रति माह 10,000 नगों से अधिक उत्पादन के लिए	प्रत्येक 1000 कुकुरों में से एक	
(7) दाब के अधीन (जहाँ कहीं लागू हो) ढक्कन को हटाने के लिए परीक्षण				
	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रति 500 कुकुरों में से एक	—	
(8) स्प्रिंग भारित संरचना के लिए परीक्षण (जहाँ कहीं लागू हो)				
	प्रयोजन के लिए मान्यताप्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुसार	प्रति 100 कुकुरों में से एक	—	

S.O. 73.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. (i) Short title and commencement.—These rules may be called the Export of Pressure Cookers (Inspection) Rules, 1983.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963, (22 of 1963);

(b) "Agency" means any of the agencies established at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras or any other organisation recognised by the Central Government under section 7 of the Act;

(c) "Pressure Cooker" means any pressure cooking vessel of capacity from 4 litres upto and including 22 litres for use with external heat sources capable of maintaining working steam pressure of 1.0 kgf/cm².

3. Basis and procedure of inspection.—(1) Inspection of Pressure Cookers intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the specifications recognised by the Central Government under section 6 of the Act i.e. National and International Standards and standards of other bodies recognised by Export Inspection Council, as the standard specifications for the Pressure Cookers.

either

(a) by ensuring that during the process of manufacture the inprocess quality control drills as specified in Annexure-I, under sub-rule 2(a) of rule 3 have been exercised;

or

(b) on the basis of inspection carried out in accordance with sub-rule 2(b) of rule 3;

or

(c) by both.

(2) Any one or both of the following schemes of inspection shall be adopted for pressure cookers, namely:—

(a) Inprocess Quality Control:—

(i) Any manufacturing unit having adequate in process quality control as per Annexure I shall apply to the nearest office of the Agency.

(ii) Export Inspection Agency shall then arrange a visit to the manufacturing unit and assess as to whether an effective inprocess quality control system is operating satisfactorily.

(b) Consignment-wise inspection.—Any manufacturing unit not satisfying the requirements specified in clause (a) shall offer to any agency their export consignments for inspection which shall be done to ensure that the products manufactured by it conforms to the specifications recognised by Central Government under section 6 of the Act.

(3) The following procedure shall be followed for inspection and certification of pressure cookers, namely:—

(i) Any exporter intending to export pressure cookers shall give intimation in writing of his intention so to do and submit alongwith such intimation a declaration of the specifications giving details of all technical characteristics as stipulated in the Export contract relating to such export to any of the Agencies to enable it to carry out inspection in

accordance with clause (a) or clause (b) or both the clauses of sub-rule (2).

(ii) He shall at the same time endorse a copy of such intimation for inspection to the office of the Council.

(iii) For export of products manufactured by units approved under clause (a) of sub-rule (2) the exporter shall also submit alongwith such intimation a declaration that the pressure cookers intended for export has been manufactured by exercising quality control as laid down in Annexure I and the consignment conforms to the requirements of the specifications recognised under section 6 of the Act for this purpose.

(iv) Every intimation and declaration under clause (iii) shall reach the office for the Agency and the Council not less than 3 days prior to the despatch of the consignment from the manufacturer's premises.

(v) The exporter shall also furnish to the Agency the identification marks applied on the consignment.

(vi) On receipt of the intimation and declaration under clause (ii) or clause (iii), the Agency—

(a) in the case of an exporter exporting products manufactured by units approved under clause (a) of sub-rule (2) on satisfying itself that during the process of manufacture the unit has exercised adequate quality control as provided under Annexure I and followed the instructions, if any, issued by the Council in this regard, shall within three days issue a certificate declaring the consignment of pressure cookers as exportworthy. However, the Agency shall ensure through periodic inspections that adequate controls are exercised at the manufacturing premises, and products conform to the recognised specification; and

(b) in case of exporter exporting products manufactured by units falling under clause (b) sub-rule (2) shall carry out inspection of pressure cookers with a view to ensuring that the product conforms to the specifications recognised for the purpose.

(vii) (a) The exporter shall supply free of charge for inspection and testing samples of pressure cookers from export consignment as and when required by the Agency. Such samples, however, shall be returned by the Agency after the inspection is done.

(b) After completion of inspection the Agency shall immediately seal packages in the consignment in a manner so as to ensure that the sealed packages cannot be tampered with.

(c) In case of rejection of a consignment, if the exporter so desires, the consignment may not be sealed by the Agency.

(d) In such cases, however, the exporter shall not be entitled to prefer any appeal against the rejection.

(viii) If the Agency is satisfied that the consignment of pressure cookers complies with the requirement under these rules it shall within seven days of completion of inspection issue a certificate to the exporter declaring that the consignment is exportworthy;

Provided that where the Agency is not so satisfied, it shall within the said period of seven days issue rejection letter communicating the reasons therefor.

4. Affixation of recognised mark and procedure thereof.—The provisions of the Indian Standard Institution (Certification Marks) Act, 1952 (36 of 1952), the Indian Standard Institution (Certification Marks) Rules, 1955 and the Indian Standard Institution (Certification Marks) Regulation, 1955,

shall, so far as may, apply in relation to the procedure of affixation of the recognised marks or seal on pressure cookers prior to export and pressure cookers so marked, shall not be subjected to any inspection under rule 3.

5. Place of Inspection.—Inspection under these rules shall be carried out at the manufacturer or other premises where adequate testing and inspection facilities are available.

6. Inspection fee.—Inspection fee shall be paid by the exporter to the Agency as under : subject to a minimum of Rs. 20 (Rupees Twenty only) per consignment :

- (i) at the rate of 0.2 per cent of fob value of goods manufactured and intended for export by approved in-process quality control units and for inspection on the basis of sub-rules (i), (ii) and (iv) respectively of rule 3 ;
- (ii) at the rate of 0.3 per cent of fob value of the goods manufactured by approved in-process quality control units and intended for export by merchant exporters and for inspection on the basis of sub-rule (iv) of rule 3;
- (iii) at the rate of 0.4 per cent of fob value of the goods intended for export by merchant exporters and for inspection on the basis of sub-rule (iii) of rule 3.
- (iv) at the rate of 0.18 per cent and 0.36 per cent of f.o.b. value of the goods manufactured and intended for export by manufacturers registered as small scale manufacturing units with the concerned government of States or Union Territories and for inspection on the basis of sub-rules (i), (ii) and (iii) respectively of rule 3.

7. Appeal.—(1) Any person aggrieved by the refusal of the Agency to issue a certificate under rule 3 may within ten days of the receipt of the communication of such refusal by him prefer an appeal to a panel of Experts consisting of not less than three persons that may be constituted by the Central Government.

(2) The panel shall consist of at least two-thirds of non-official of the total membership of the panel of Experts.

(3) The quorum for the panel shall be three.

(4) The appeal shall be disposed of within fifteen days of its receipt.

ANNEXURE I

Inprocess Quality Control :

The quality of the pressure cookers intended for export shall be ensured by the manufacturer by effecting the following controls at different stages of manufacture, at the levels of control specified in Annexure-II.

1. Bought out materials and components control :

- (a) Purchase specifications shall be laid down by the manufacturer incorporating the properties of materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

materials or components to be used and the detailed dimensions thereof with tolerances.

- (b) The accepted consignments shall be either accompanied by a producer's test certificate corroborating the requirements of the purchase specifications or in the absence of such test certificates, a samples from each consignment shall be regularly tested to check up its conformity to the purchase specifications. The producer's test certificate shall be counter-checked at least once in five consignments to verify the correctness.

- (c) The incoming consignments shall be inspected and tested for ensuring conformity to purchase specifications against statistical sampling plans.

- (d) After the inspection or test is carried out, systematic methods shall be adopted in segregating the accepted and rejected materials or components and for disposal of rejected materials or components.

- (e) Adequate records in respect of the above mentioned control shall be systematically maintained.

2. Process Control :

- (a) Detailed process specifications shall be laid down by the manufacturers for various processes of manufacture.

- (b) Equipment or instruments facilities shall be adequate to control the processes as laid down in the process/specifications.

- (c) Adequate records shall be maintained to enable the verification of the controls exercised during the process of manufacture.

3. Product Control :

- (a) The manufacturer shall either have his own testing facilities or shall have access to such testing facilities existing elsewhere to test the product as per the standard specifications. Adequate records thereof shall be maintained.

- (b) Sampling (wherever required) for testing shall be based on a recorded investigation.

- (c) Each and every assembly shall be checked against laid down inspection check list.

4. Metrological Control.—Gauges and instruments used in the production and inspection shall be periodically checked or calibrated and records shall be maintained in the form of history cards.

5. Preservation Control :

- (a) A detailed specification shall be laid down by manufacturer to safeguard the product from adverse effects of weather conditions.

- (b) The product shall be well preserved both during storage and during transit.

6. Packing Control.—A specification shall be laid down for packing the aforesaid products.

ANNEXURE II LEVELS OF CONTROL

Sl. No.	Particulars of Inspection/Test	Requirement	Sample Size	Lot size
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. (a)	Bought out materials and components	As per standard specification	Each.	—
	Visual inspection (including workmanship and finish)	recognised for the purpose.		
(b)	Dimensions with tolerances			
	(i) Critical	As per standard specification	To be fixed on the basis of recorded investigation.	Each lot.
		recognised for the purpose.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ii) Others	As per standard specification recognised for the purpose.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	Each lot.
	(c) Any other requirement	As per standard specification recognised for the purpose.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	Each lot.
2. Manufactured components and sub-assembly				
	(a) Visual inspection (including workmanship and finish)	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
	(b) Dimensions with tolerances			
	(i) Critical	As per standard specification recognised for the purpose.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	Each lot.
	(ii) Others	As per standard specification recognised for the purpose.	To be fixed on the basis of recorded investigation.	—
3. Assembly				
	(a) Workmanship and finish	As per standard specification recognised for the purpose.	Each.	—
	(b) Tests			
	(i) Capacity test	As per standard specification recognised for the purpose.	One in every 50 cookers for cast cookers and one in every 500 and part thereof for wrought cookers.	—
	(ii) Air Pressure Test	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
	(iii) Proof Pressure Test			
	(a) for cast cookers	As per standard specification recognised for the purpose.	Each	—
	(b) for wrought cookers	As per standard specification recognised for the purpose.	(1) for production upto 2000 pcs. per month. (2) For production between 2001 and 10000 pcs. per month. (3) For production above 10000 pcs. per month.	4 % of the total production. 2 % of the total production. 1 % of the total production.
	(iv) Operating test for pressure regulating device.	As per standard specification recognised for the purpose.	(a) For production upto 2000 pcs. per month. (b) For production between 2001 and 10000 pcs' per month. (c) For production above 10000 pcs. per month.	10% of the total production. 5% of the total production. 2% of the total production.
	(v) Test for safety pressure relief device.	As per standard specification recognised for the purpose.	1% of the total production.	—
	(vi) Bursting pressure test			
	(a) for cast cookers.	As per standard specification recognised for the purpose.	One in every 100 Cookers. *(1) For production upto 2000 pcs. per month.	— One in every 500 cookers.
	(b) for wrought cookers.	*As per standard specification recognised for the purpose.	(2) For production between 2001 pcs. and 10000 pcs. (3) For production above 10000 pcs. per month.	One in every 700 cookers. One in every 1000 cookers.
	(vii) Test for removal of lid under pressure (wherever applicable)	As per standard specification recognised for the purpose.	One in every 500 cookers	—
	(viii) Test for spring loaded mechanism (wherever applicable).	As per standard specification recognised for the purpose.	One in every 100 cookers.	—

का० आ० 74.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम 1964 के नियम 3 के साथ पठित निर्यात क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, 1 जनवरी, 1983 से एक वर्ष की अवधि के लिए श्री एस० अबिद हुसैन, आई० ए० एस० वाणिज्य सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), को निर्यात निरीक्षण परिषद् के अध्यक्ष के रूप में तथा निम्नलिखित को सदस्यों के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है :—

1. निदेशक, निरीक्षण तथा क्वालिटी नियंत्रण निर्यात निरीक्षण परिषद्, नई दिल्ली—सदस्य सचिव।
2. महानिदेशक, भारतीय मानक संस्थान, नई दिल्ली।
3. भारत सरकार के कृषि विभाग सलाहकार।
4. महानिदेशक, वाणिज्यक जातदारों तथा प्रकसंकेतन, कलकत्ता।
5. सचिव (तकनीकी विकास) उद्योग मंत्रालय।
6. कु० रोना मजूमदार, अवर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।
7. अध्यक्ष, लघु उद्योग संघ फेडरेशन।
8. अध्यक्ष, सुदुरी खाद्य निर्यात संघ, कोचीन।
9. अध्यक्ष, चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद् मद्रास।
10. अध्यक्ष, इंडियन जूट मिक्स एमोसिएशन।
11. विकास आयुक्त, लघु उद्योग।
12. कार्यकारी निदेशक, इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद्।
13. माइक्रोडेंट प्रा० लि० बंगलोर. (मद्रास, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम्)।
14. मैसर्स डा० रमन सी० अमीन के डा० रमन सी० अमीन, बम्बई।
15. महानिदेशक, नेशनल टेस्ट हाउस, कलकत्ता।

[फा० नं० 3/94/75-ई० आई० एण्ड ई० पी०]

सी. बी. कुक्रेती, निदेशक

S.O. 74.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with Rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby appoints Shri S. Abid Hussain, IAS Commerce Secretary, Ministry of Commerce (Department of Commerce) as Chairman and nominates the following as Members of the Export Inspection Council for a period of one year with effect from 1st January, 1983.

1. Director of Inspection and Quality Control, Export Inspection Council, New Delhi—Member Secretary.
2. Director General of Indian Standards Institution, New Delhi.
3. Agricultural Marketing Advisor of the Government of India.

4. Director General of Commercial Intelligence and Statistics, Calcutta.
5. Secretary (Technical Development) Ministry of Industry, New Delhi.
6. Km. Roma Mazumdar, Additional Secretary, Ministry of Commerce, New Delhi.
7. President, Federation of Association of Small Industries.
8. President, Seafood Exporters Association, Cochin.
9. Chairman, Leather Export Promotion Council, Madras.
10. Chairman, Indian Jute Mills Association.
11. Development Commissioner, Small Scale Industries.
12. Executive Director, Engineering Export Promotion Council.
13. Mysodet Pvt. Ltd., Bangalore, (Madras, Vijayawada, Visakhapatnam).
14. Dr. Raman C. Amin of M/s Dr. Raman C. Amin Bombay.
15. Director General, National Test House, Calcutta.

[F. No. 3(94)/75 EI&EP]
C. B. KUKRETI, Jt. Director

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1982

का०आ० 75.—चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री एन० रामादुराई को, जो हाल में नियंत्रक, लाइसेंसिंग के पद पर थे, 1 जून 1982 के पूर्वान्ह से नियमित आधार पर सचिव, चाय बोर्ड, के पद पर नियुक्त करती है।

[सं० के० 12013(1)/82-प्लांट (ए)]

पी०एस० रंधावा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th November, 1982

S.O. 75.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of Sub-section (1) of Section 9 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) the Central Government hereby appoints Shri N. Ramadurai, lately Controller of Licensing as Secretary, Tea Board on regular basis with effect from the forenoon of the 1st June, 1982.

[No. K-12013(1)/82-Plant. A]

P. S. RANDHAWA, Under Secy.

(टैक्सटाइल विभाग)

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

का०आ० 76.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य श्री शिरोमणि शर्मा, विकास आयुक्त, हथकारवा को और आदेश होने तक केन्द्रीय रेशम बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

[फा० सं० 25012/11/82-रेशम]

(Department of Textiles)

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 76.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 6 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby appoints Shri Shiromani Sharma, Development Commissioner for Hand-loom as a member of the Central Silk Board as Vice-Chairman of the Central Silk Board until further orders.

[F. No. 25012/11/82-Silk]

का०आ० 77.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय (टैक्सटाइल विभाग) की अधिमूचना सं० का०आ० 2234, तारीख 24 अप्रैल, 1982 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिनियम में,—

(1) मद 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

“1. श्री शिरोमणि शर्मा, अधिनियम की धारा विकास आयुक्त (हथकरघा), 4 (3) (ख) के अधीन टैक्सटाइल विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय, भारत नामनिर्देशित।”

(2) मद 16 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

“16. रेशम उत्पादन और रेशम बुनाई निदेशक, पश्चिमी बंगाल सरकार, 45, गणेश चन्द्र ऐवेन्यू, कलकत्ता। अधिनियम की धारा 4 (3) (च) के अधीन पश्चिमोत्तर बंगाल सरकार द्वारा नामनिर्देशित।”

16क. श्री डी० सी० जोगद्वार, भूतपूर्व संसद सदस्य, डा० मालदा-732101 जिला मालदा, (पश्चिमी बंगाल)

(3) मद 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्:—

“30. कु० कल्याणी चौधरी, अधिनियम की धारा 4 उप-सचिव, (3) (अ) के अधीन टैक्सटाइल विभाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार। नामनिर्देशित।”

[फा०सं० 25012/11/82-रेशम]

के० चौधरी, उप-सचिव

S.O. 77.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 4 of the Central Silk Board Act, 1948 (61 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce (Department of Textiles) No. S. O. 2234, dated the 24th April, 1982, namely:—

In the said notification,—

(i) for item 1 and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“1. Shri Shiromani Sharma, Nominated by the Development Commissioner Central Government (Handlooms), Department of Textiles, Ministry of Commerce, Government of India.”

(ii) for item 16 and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“16. Director of Sericulture and Silk Weaving, Government of West Bengal, 45, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta. 16A. Shri D.C. Jodari, Ex-M.P., P.O. Malda-732101, District Malda, (West Bengal).”

Nominated by the Government of West Bengal under section 4(3)(f) of the Act.”

(iii) for item 30 and entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

“30. Km. Kalyani Chaudhuri, Nominated by the Deputy Secretary, Central Government Department of Textiles, Ministry of Commerce, Government of India, under section 4(1)(j) of the Act.”

[F. No. 25012/11/82-Silk]

K. CHAUDHURY, Dy. Secy.

(मुख्य-नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1982

का०आ० 73-जर्बरी आर० एस० राडीड, 15 कुमायुं हन्दीर, मार्फत 56 ए पी प्रो को बिलाया के निये विशेष उपकरण युक्त एक मातफू डीजल कार 1588 सी०सी० के आयात क लिये 65000 रुपये मूल्य का एक आयात लाइसेंस सं० पी०/एफ०/2028719, दिनांक 5-9-81 प्रदान किया गया था।

2. आवेदक ने उपर्युक्त लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति जारी करने के लिये इस आधार पर आवेदन किया है कि मूल प्रति उनसे खो गई है। आगे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति किसी भी सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास पंजीकृत नहीं कराई गई थी अतः आयात लाइसेंस के मूल्य का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हुआ है।

3. अपने तर्कों के समर्थन में, लाइसेंसधारी ने शपथ आयुक्त, दिल्ली के सामने विधिवत् शपथ लेकर एक शपथ-पत्र दाखिल किया है। तदनुसार, मैं संतुष्ट हूँ कि आयात

लाइसेंस सं० पी०/एफ/2028719, दिनांक 5-9-81 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति आवेदक से खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है। समय-समय पर यथासंशोधित आयात नियंत्रण आदेश, 1955 दिनांक 7-12-1955 की उपधारा 9(सी०सी०) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री आर० एम० राठी के नाम में जारी किये गये उपर्युक्त लाइसेंस सं० पी०/एफ०/2028719 दिनांक 5-9-81 की मूल मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति एतद्वारा रद्द की जाती है।

4. आयात लाइसेंस की मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रति की अनुलिपि प्रति श्री आर०/एस० राठी को अलग से जारी की जा रही है।

[मि० सं० एफ०-48/81-82/बी०एल०एस०]
जे० पी० सिंघल, उप मुख्य-नियंत्रक,
आयात-निर्यात

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports)

New Delhi, the 14th December, 1982

S.O. 78.—Mr. R. S. Rathore, 15 Kumaon, Indore, C/o 56 APO was granted an Import Licence No. P/F/2028719 dated 5th September, 1981 for Rs. 65,000 only for the import of one Golf Diesel Car 1588 CC fitted with Special Equipment for disabled.

2. The applicant has applied for issue of a Duplicate copy of Exchange Control Copy of the above mentioned Import Licence on the ground that the original Exchange Control Copy of the Licence has been lost. It has further been stated that the original Exchange control copy of the Licence was not registered with any Customs Authority and as such the value of the Import Licence has not been utilised at all.

3. In support of his contention, the licensee has filed an affidavit, duly sworn before the Oath Commissioner, Delhi. I am accordingly satisfied that the original Exchange Control Copy of the Import Licence No. P/F/2028719 dated 5th September, 1981 has been lost or misplaced by the applicant. In exercise of powers conferred under Sub-Clause 9(cc) of the Import Control Order 1955 dated 7th December, 1955, as amended from time to time, the said original Exchange Control copy of Licence No. P/F/2028719 dated 5th September 1981 issued to Mr. R. S. Rathore is hereby cancelled.

4. A duplicate copy of the Exchange Control Copy of the Import Licence is being issued to Mr. R. S. Rathore separately.

[F. No. F-48/81-82/BLS]

J. P. SINGHAL, Dy. Chief Controller,
Imports & Exports.

(संयुक्त मुख्य नियंत्रक आयात तथा

निर्यात का कार्यालय)

मद्रास, 21 अगस्त, 1982

का० प्रा० 79 :—सर्वश्री नवरत्न जेनरल प्राडक्ट्स, नम्बर-139, एन० एस० सी० बोस रोड, मद्रास-600 001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936064-सी-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने

का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नवरत्न जेनरल प्राडक्ट्स, नम्बर 139, एन० एस० सी० बोस रोड, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-एजट-1936064-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1203-एम-82-एयु-3]

(Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports.)

ORDER

Madras, the 21st August, 1982

S.O. 79.—M/s. Navarathan General Products, No. 139, N.S.C. Bose Road, Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1936064/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936064/C/XX/82/M/81, dated 6-3-1982 issued to M/s. Navarathan General Products, No. 139, N.S.C. Bose Road, Madras-1 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1203/AM. 82/AU. III]

का० प्रा० 80 :—सर्वश्री संगवी स्टोर्स, नम्बर 14 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936061-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982

को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री संगवी स्टोर्स, नम्बर 14, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936061-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1195-एम-82-एयू 3]

S.O. 80.—M/s. Sangvi Stores, No. 14, Narayana Mudali Street, Madras-600001 were granted a licence No. PZ/1936061/C/XX/82/M/81, dated 6-3-1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. PZ/1936061/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 issued to M/s. Sangvi Stores, No. 14, Narayana Mudali Street, Madras-1 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1195/AM.82/AU.III]

का० आ० 81.—सर्वश्री राकेश एन्टरप्राइजस नम्बर 136, एन० एस० सी० बोस रोड, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936091-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त

किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राकेश एन्टरप्राइजस नम्बर 136, एन० एस० सी० बोस रोड, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च, 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936091 सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1245-एम/82-एयू 3]

S.O. 81.—M/s. Rakesh Enterprises, No. 136, N.S.C Bose Road, Madras-600001 were granted a licence No. PZ/1936091/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. PZ/1936091/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82, issued to M/s. Rakesh Enterprises, No. 136, N.S.C. Bose Road, Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1245/AM.82/AU.III]

का० आ० 82.—सर्वश्री वीनस कारपोरेशन, नम्बर 64, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936002-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वीनस कारपोरेशन नम्बर 64 नारायण मुदली

स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936002-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1106-एम-82-एयू 3]

S.O. 82.—M/s Venus Corporation No. 64 Narayana Mudali Street Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1936002/C/XX/82/M/81, dated 3-3-1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936002/C/XX/82/M/81, dt. 3-3-1982 issued to M/s. Venus Corporation 64 Narayana Mudali Street Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. FP. 1106/AM. 82/AU.III]

का. आ. 83.—सर्वश्री राजेश कारपोरेशन, संख्या 57, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935855-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राजेश कारपोरेशन, संख्या 57, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935855-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-884-एम 82-एयू 3]

S.O. 83.—M/s. Rajesh Corporation, No. 57, Narayana Mudali Street, Madras-600001, were granted a Licence No P/Z/1935855/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935/855/C/XX/82/M/81 dt. 19-2-81 issued to M/s. Rajesh Corporation, No. 57, Narayana Mudali Street, Madras-600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. DF/884/AM. 82/AU. III]

मद्रास, 2 सितम्बर, 1982

का० आ० 84.—सर्वश्री गौतम ट्रेडर्स 77, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को रुपये 10,001 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935857-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री गौतम ट्रेडर्स, 77, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को अप्रैल-मार्च, 1982 अवधि के लिये रुपये 10,000 तक जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935857-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-883-एम-82-एयू-3]

Madras, 2nd September, 1982

S.O. 84.—M/s. Goutham Traders, 77, Narayana Mudali St., Madras-600001 were granted a licence No. PZ/1935857/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935857/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Goutham Traders, 77 Narayana Mudali St., Madras-600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/883/AM. 82/AU. III]

का० आ० 85—सर्वश्री महेश्वरी एजन्सीज, 135, एन० एस० सी० बीस रोड, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों के आयात करने के लिये आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936007-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र ने भ्रष्टाचारविक्रता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। आने वाले मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिये पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री महेश्वरी एजन्सीज, 135, एन० एस० सी० बीस रोड, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिये जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936007-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1103-एम-82-एयू 3]

S.O. 85.—M/s. Maheswari Agencies 135, M.S.C. Bose Road, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936007/C/XX/82/M/81, dated 3-2-82, for import of Dry fruits of Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Imports Licence No. P/Z/1936007/C/XX/82/M/81 dated 3-2-82 issued to M/s. Maheswari Agencies, 135, N.S.C. Bose Road Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1103/AM. 82/AU. III]

का० आ० 86—सर्वश्री वी०जी० प्राविजन्स, संख्या-11, तनिकाचल मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936003-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के भ्रष्टाचारविक्रता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वी०जी० प्राविजन्स, संख्या-11, तनिकाचल मुदली स्ट्रीट, मद्रास-21 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936003-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1107-एम 82-एयू-3]

S.O. 86.—M/s. V. G. Provisions, No. 11, Thanigachala Mudali Street, Madras-600021 were granted a licence No. P/Z/1936003/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936003/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 issued to M/s. V. G. Provisions, No. 11 Thanigachala Mudali Street, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1107/AM. 82/AU. III]

आदेश

का० आ० 87.—सर्वश्री शान्ति एजेंसी, 5/17, जेनरल कालन्स रोड, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या इजट-1935996-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री शान्ति एजेंसी, 5/17, जेनरल कालन्स रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या / पी-इजट-1935996-सी-एक्सएक्स-82 एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1076-एम-82-एयू 3]

S.O. 87.—M/s. Santhi Agency, 5/17, General Collensroad, Madras-600012, were granted a Licence No. P/Z/1935996/C/XX/82/M/81 dated 2-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Import (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935996/C/XX/82/M/81 dated 2-3-82 issued to M/s. Santhi Agency, 5/17, General Collens Road, Madras-600012, for import Dry Fruit for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. DF/1076/AM. 82/AU. III]

का०आ० 88.—सर्वश्री वर्मा ट्रेडर्स, 92, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-

1936059-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाये। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वर्मा ट्रेडर्स, 92, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936059-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1181-एम-82-एयू 3]

S.O. 88.—M/s. Varma Tradeis, 92 Narayana Mudali Street, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936059/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936059/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 issued to M/s. Varma Traders, 92 Narayana Mudali Street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1181/AM. 82/AU. III]

का०आ० 89.—सर्वश्री रामदेव जेनरल स्टोर्स, 21, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी इजट-1936065-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया

है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षी निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री रामदेव जेनरल स्टोर्स, 21 नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इन्कस 1936065-सी-एक्सएक्स 82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1204-एम-82-एयू 3]

S.O. 89.—M/s. Ramadev General Stores, 21, Narayana Mudali Street, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936065/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Import (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936065/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Ramadev General Stores, 21, Narayana Mudali Street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1204/AM. 82/AU. III]

कां.आ. 90.—सर्वश्री नवीना जेनरल स्टोर्स, 49 पेरियार रोड, पाडी, मद्रास-50 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी इन्कस-1936067-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी

न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री नवीना जेनरल स्टोर्स, 49, पेरियार रोड, पाडी मद्रास-50 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रु० 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी इन्कस 1936067-सी-एक्सएक्स 82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1202-एम 82-एयू 3]

S.O. 90.—M/s. Naveen General Stores, 49, Periar Road, Padi, Madras-50 were granted a Licence No. P/Z/1936067/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licensing holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936067/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Naveen General Stores, 49, Periar Road, Padi, Madras-50 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[P. No. DF/1202/AM. 82/AU. III]

कां.आ. 91.—सर्वश्री मोहदी न स्टोर्स, 39 मेडक्स स्ट्रीट, बेंपेरी, मद्रास-600007 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी इन्कस-1935913-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

में, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मोइदीन स्टोर्स, 39, मेड्डक्स स्ट्रीट, वेपरी, मद्रास-7 को, अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी-इजिट-1935913-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-951-एम-82-एयु 3]

S.O. 91.—M/s. Moideen Stores, 39, Maddax Street, Vepery, Madras-600007 were granted a Licence No. P/Z/1935913/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence *ex-parte*.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935913/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 issued to M/s. Moideen Stores, 39, Maddax Street, Vepery, Madras-7 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/951/AM82/AU-III]

का० प्रा० 92.—सर्वश्री लक्की स्टोर्स, 12, सुब्रह्म चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास -12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी- इजिट-1936096-सी- एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने को एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री लक्की स्टोर्स 12 सुब्रह्म चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी

किये गये लाईसेंस संख्या पी इजिट-1936096-सी- एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ-1263-एम-82-एयु 3]

S.O. 92.—M/s. Lucky Stores, 12 Subbaraya Chetty St., Madras-12 were granted a Licence No. P/Z/1936096/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence *ex-parte*.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936096/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Lucky Stores, 12 Subbaraya Chetty Street, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1263/AM. 82/AU. III]

का० प्रा० 93.—सर्वश्री धनलक्ष्मी स्टोर्स, 49, नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी- इजिट-1936097-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने को एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 का धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री धनलक्ष्मी स्टोर्स 49 नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी- इजिट-1936087-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1246-एम-82-एयु-3]

S.O. 93.—M/s. Dhannalakshmi Stores, 49, Narayanan Mudali Street, Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936097/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936087/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Dhannalakshmi Stores, 49, Narayana Mudali St., Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1246/AM. 82/AU. III]

का० आ० 94—सर्वश्री महेश कुमार प्राविजन स्टोर्स, 47, नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-600001 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी-एजट 1936009-सी-एक्सएक्स-82 एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपयुक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मोहन कुमार प्राविजन स्टोर्स, 47, नारायण मुदली स्ट्रीट मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी-इजट-1936009-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1100-एम-82-एयु-3]

S.O. 94.—M/s. Mahesh Kumar Provision Stores, 47, Narayana Mudaly St. Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1936009/C/XX/82/81 dated 3-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not

genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936009/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 issued to M/s. Mahesh Kumar Provision Stores, 47, Narayana Mudaly St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1100/AM. 82/AU. III]

का० आ० 95—सर्वश्री कृष्णा ट्रेडर्स, 18 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाईसेंस संख्या पी-इजट-1936063-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को जारी किया गया था।

उपयुक्त लाईसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाईसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाईसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाईसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा, 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कृष्णा ट्रेडर्स, 18 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाईसेंस संख्या पी-इजट 1936063-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1196-एम-82-एयु-3]

S.O. 95.—M/s. Krishna Traders, 18, Narayana Mudali St., Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1936063/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied

that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1930603/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Krishna Traders, 18, Narayana Mudali St., Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1196/AM. 82/AU. III]

क्र० आ० 96.—सर्वश्री महिपाल एन्टरप्राइजेस, 22, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 का रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट 193608-सी-एक्सएक्स-82 एन-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने का पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेना हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री महिपाल एन्टरप्राइजेस, 22, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट 1936068-सी एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1202 (ए)-एम-82-एयू 3]

S.O. 96.—M/s. Mahipal Enterprises, 22, Narayana Mudali Street, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1936068/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As, there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936068/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82, issued to M/s. Mahipal Enterprises, 22, Narayana Mudali, Street, Madras-1, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. DF/1202(a)/AM. 82/AU. III]

क्र० आ० 97.—सर्वश्री मूर्ति प्राविजन स्टोर्स, संख्या 1, पोन्नप्पन स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट -1936110-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मूर्ति प्राविजन स्टोर्स, संख्या-1, पोन्नप्पन स्ट्रीट मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट 1936110-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1260-एम-82-एयू 3]

S.O. 97.—M/s. Moorthy Provision Stores, No. 1, Ponnappan Street Madras-12 were granted a licence No. P/Z/1936110/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936110/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Moorthy Provision Stores No. 1 Ponnappan Street Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. PF/1260/AM. 82/AU. III]

क्र० आ० 98.—सर्वश्री मदन ट्रेडर्स, 8, एडपालयम स्ट्रीट, मद्रास-600003 को रुपये 10000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936037-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मदन ट्रेडर्स, 8, एडपालयम स्ट्रीट, मद्रास-600003 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936037-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ- 1174-ए एम 82-एयू 3]

S.O. 98.—M/s. Madan Traders, 8, Edapalayam Street, Madras-600003 were granted a licence No. P/Z/1936037/C/XX/82/M/81 dated 4-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936037/C/XX/82/M/81 dated 4-3-82 issued to M/s. Madan Traders, 8, Edapalayam Street, Madras-600003 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1174/AM. 82/AU. III]

का० आ० 99.—सर्वश्री पोनमणी स्टोर्स, 43 टांक बांड रोड, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935881-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने

का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री पोनमणी स्टोर्स, 43, टांक बांड रोड, मद्रास-600012 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिये रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935881-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी-एफ-912-एएम 82-एयू 3]

S.O. 99.—M/s. Ponmani Stores, No. 43, Tank Band Road, Madras-600002 were granted a Licence No. P/Z/1935881/C/XX/82/M/81, dt. 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935881/C/XX/82/M/81, dt. 22-2-82 issued to M/s. Ponmani Stores, No. 43, Tank Band Road, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/912/AM.82/AU.III]

का० आ० 100.—सर्वश्री जयमधुमी स्टोर्स 12, तुलसी नाथवकन स्ट्रीट, मद्रास-600012 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935904-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी

किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जयलक्ष्मी स्टोर्स, 12, तुलसी नाथकन स्ट्रीट मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935904-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-935-एम-82-एयू 3]

S.O. 100.—M/s. Jayalakshmi Stores, 12, Thulasi Naicken Street, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/193-5904/C/XX/82/M/81, dated 24-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935904/C/XX/82/M/81 dated 24-2-82 issued to M/s. Jayalakshmi Stores, 12, Thulasi Naicken Street, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/935/AM.82/AU-III]

का० आ० 101:—सर्वश्री बेंकटरमण प्राविजन स्टोर्स, 52, संजीवरायन कोयिल स्ट्रीट, मद्रास-21 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935912-सी-एक्सएक्स-82-एम 81 दिनांक 25-2-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री बेंकटरमण प्राविजन स्टोर्स, 52, संजीवरायन कोयिल स्ट्रीट, मद्रास-21 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935912-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-949-एम-82-एयू 3]

S.O. 101.—M/s. Sri Venkataramana Provision Stores, 52, Sanjevarayan Koil Street, Madras-21 were granted a Licence No. P/Z/1935912/C/XX/82/M/81, dated 25-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935912/C/XX/82/M/81, dated 25-2-82 issued to M/s. Sri Venkataramana Provision Stores, 52, Sanjevarayan Koil Street, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/949/AM 82/AU.III]

का० आ० 102.—सर्वश्री रमेश एण्ड प्राविजन स्टोर्स, 38, नारायण मुद्दली स्ट्रीट, मद्रास को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936058-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रमेश एण्ड प्राविजन स्टोर्स, 38, नारायण मुद्दली स्ट्रीट, मद्रास को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए

जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936058-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1180-एम-82-एयू 3]

S.O. 102.—M/s Ramesh and Provision Stores, 38, Narayana Mudali Street Madras were granted a Licence No. P/Z/1936058/C/XX/82/M/81, dt. 5-3-1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936058/C/XX/82/M/81, dt. 5-3-1982 issued to M/s Ramesh and Provision Stores 38, Narayana Mudali Street Madras for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No DF/1180/AM.82/AU III]

क्रा० आ० 103.—पर्वशी लक्ष्मी प्राविजन स्टोर्स, 24, सेल्वपेरुमाल कोट्टल स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936112-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 का व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955, की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री लक्ष्मी प्राविजन स्टोर्स, 24, सेल्वपेरुमाल कोट्टल स्ट्रीट, मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936112-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1265-एम-82-एयू 3]

S.O. 103.—M/s Lakshmi Provision Stores, 24, Solva Perumal Koil Street, Madras, 12 were granted a Licence No. P/Z/1936112/C/XX/82/M/81, dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936112/C/XX/82/M/81, dated 6-3-82 issued to M/s Lakshmi Provision Stores, 24, Solva Perumal Koil Street, Madras, 12, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1265/AM.82/AU.III]

क्रा० आ० 104.—पर्वशी तगम स्टोर, 20, न्यू स्ट्रीट, ओट्टेरी, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936119-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री तगम स्टोर, 20, न्यू स्ट्रीट, ओट्टेरी, मद्रास-600012 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936119-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1267-एम-82-एयू 3]

S.O. 104.—Thangam Store, 20, New Street, Otteri, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1936119/C/XX/82/M/81, dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken

to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 25-6-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936119/C/XX/82/M/81, dated 6-3-82 issued to M/s. Thangam Stores, 20, New Street, Ottori, Madras-600 012, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/1267/AM.82/AU.III]

का० धा० 105.—सर्वश्री महालक्ष्मी एन्टरप्राइजेस, 51, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1836006-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 25-6-1982 का व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री महालक्ष्मी एन्टरप्राइजेस, 51 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1936006-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1105-एम 82-एयू 3]

S.O. 105.—M/s. Mahalakshmi Enterprises, 51, Narayana Mudali Street, Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1936006/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 25-6-1982. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936006/C/XX/82/

M/81 date 3-3-82 issued to M/s. Mahalakshmi Enterprises, 51, Narayana Mudali Street, Madras-600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/1105/AM. 82/AU. III]

मद्रास, 15 अक्टूबर, 1982

का० धा० 106.—सर्वश्री स्वामी एन्टरप्राइजेस, 184, सैडनामस रोड, मद्रास-600112 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935917-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री स्वामी एन्टरप्राइजेस, 184, सैडनामस रोड, मद्रास-600112 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी जेड-1935917-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-955-एम 82-एयू 3]

Madras, 15th October, 1982

S.O. 106.—M/s. Swamy Enterprises, 184, Sydenhams Road, Madras-600 112 were granted a Licence No. P/Z/1935917/C/XX/M/81 dated 25-2-82 for import of Dry Fruits for Rs 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above Import Licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935917/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 issued to M/s. Swamy Enterprises, 184, Sydenhams Road, Madras-600 112 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/955/AM. 82/AU. III]

का० प्रा० 107.—सर्वश्री बालाजी प्राविजन स्टोर्स, संख्या 38, डीमेल्लोस रोड, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935934-सी एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 29-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बालाजी प्राविजन स्टोर्स, संख्या 38, डीमेल्लोस रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935934-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 29-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-982-ए एम 82-ए यू 3]

S.O. 107.—M/s. Balaji Provision Stores, No. 38, Demellows Road, Madras-12 were granted a Licence No P/Z/1935934/C/XX/M/81 dated 29-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1935934/C/XX/M/81 dated 29-2-82 issued to M/s. Balaji Provision Stores, No. 38, Demellows Road, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1983 period.

[F. No. DF/982/AM. 82/AU. III]

का० प्रा० 108.—सर्वश्री अशोक ट्रेडर्स, 3, केशव ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600003 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1936053-सी एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात में संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री अशोक ट्रेडर्स, 3, केशव ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600003 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1936053-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1178-ए एम 82-ए यू 3]

S.O. 108.—M/s. Ashok Traders, 3, Kesava Iyer Street, Madras-600 003 were granted a Licence No. P/Z/1936053/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936053/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 issued to M/s. Ashok Traders, 3 Kesava Iyer Street, Madras-600 003, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/1178/AM. 82/AU. III]

का० प्रा० 109.—सर्वश्री श्रीनीवास स्टोर्स, संख्या 32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935895-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी

किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्रीनीवामा स्टार्स, संख्या 32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 का अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935895-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डीएफ/859/एएम 82/एयू 3]

S.O. 109.—M/s. Srinivasa Stores, No. 32, Kasi Chetty Street, Madras-600 001 were granted a licence No. P/Z/1935895/C/XX/82/M/81 dated 23-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by production a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935895/C/XX/82/M/81 dated 23-2-82 issued to M/s. Srinivasa Stores, No. 32, Kasi Chetty Street, Madras-600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[No. DF/859/AM. 82/AU. III]

कां०आ० 110.—सर्वश्री नरेन्द्रा कारपोरेशन, 14, तोलमिंगम स्ट्रीट, मद्रास-600 001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935864-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 23-9-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नरेन्द्रा कारपोरेशन, 14, तोलमिंगम स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935864-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 23-9-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डीएफ-894-एमएम 82-एयू 3]

S.O. 110.—M/s. Narendra Corporation, 14-Tholasingam Street, Madras-600 001, were granted a Licence No. P/Z/1935864/C/XX/82-M/81 dated 23-9-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935864/C/XX/82/M/81 dated 23-9-82 issued to M/s. Narendra Corporation, 14, Tholasingam Street, Madras-600 001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March 1982 period.

[F. No. DF/894/AM. 82/AU. III]

कां०आ० 111—सर्वश्री प्रकाशमल भारन कुमार, 73, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935867-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए,

सर्वश्री प्रकाशमल भारत कुमार, 73, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास 600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935867 सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करना है।

[सं० डीएफ 895 एमएम 82 एयु 3]

S.O. 111.—Prakashmal Kharat Kumar, 73, Narayana Mudali Street, Madras-600 001 were granted a Licence No. P/Z/1935867/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above Import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935867/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Prakashmal Bharat Kumar, 73 Narayana Mudali Street, Madras-600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March 1982 period.

[No. DF/895/AM. 82/AU. III]

का०आ०-112—सर्वश्री बांवे ट्रेडर्स 6 कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास 1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1936056 सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-1982 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-6-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारा किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक उचित निर्णय लेना है।

मैं, आयात (नियंत्रण) अधिनियम 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बांवे ट्रेडर्स, 6, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-655551 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,055 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1636056-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-3-1982 को एतद्वारा रद्द करना है।

[सं० डीएफ-1177-एम-82-एयु 3]

S.O. 112.—M/s. Bombay Traders, 6, Kasi Chetty Street, Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1936056/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936056/C/XX/82/M/81 dated 5-3-82 issued to M/s. Bombay Traders, 6, Kasi Chetty Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[No. DF/1177/AM. 82/AU. III]

का०आ० 113—सर्वश्री सुरेन्द्र एन्टरप्राइजस, 58, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935856-सी-एक्सएक्स 82 एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 का व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारा किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक उचित निर्णय लेना है।

मैं, आयात (नियंत्रण) अधिनियम 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सुरेन्द्र एन्टरप्राइजस, 67, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935856-सी-एक्सएक्स-82 एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करना है।

[सं० डी एफ-891-एम 82-एयु]

S.O. 113.—M/s. Surendia Enterprises, 87, Narayana Mudali Street Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935856/C/XX/82/M/81 dt. 19-2-82 for import of dry fruits for Rs. 10000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to

cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the Party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955 hereby cancel the import licence no. P/Z/1935856/C/XX/82/M/81 dt. 19-2-82 issued to M/s. Suresh Enterprises 87 Narayana Mudali Street-Madras 600 001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/891/AM. 82/AU. III]

मद्रास, 3 नवम्बर, 1982

का०प्रा० 1140—सर्वश्री मंजू सेल्स कारपोरेशन, संख्या-11, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935875-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मंजू सेल्स कारपोरेशन, संख्या-11, कासी चेट्टी लेन, मद्रास 600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935875-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डी एफ-913-एम 82-एयू 3]

Madras, the 3rd November, 1982

S.O. 114.—M/s. Manju Sales Corporation, No. 11, Kasi Chetty Lane, Madras. 1 were granted a licence No. P/Z/1935875/C/XX/M/81 dt. 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935875/C/XX/82/M/81 dt. 22-2-82 issued to M/s. Manju Sales Corporation, No. 11, Kasi Chetty Lane, Madras-600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/913/AM. 82/AU. III.]

का०प्रा० 1150—सर्वश्री युनैटेड सेल्स कारपोरेशन, 32, स्ट्रॉटन मुथुला मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935910-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री युनैटेड सेल्स कारपोरेशन, संख्या-32, स्ट्रॉटन मुथुला मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,005 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935910-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डीएफ/934/एम/82 एयू 3]

S.O. 115.—M/s. United Sales Corporation, 32, Strotten Muthia Mudaly St., Madras—1 were granted a licence No. P/Z/1935910/C/XX/82/M/81 dated 24-2-82 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935910/C/XX/82/M/81 dt. 24-2-82 issued to M/s. United Sales Corporation No. 32, Strotten Muthia Mudali St., Madras—1 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/934/AM. 82/AU. III.]

का.आ. 116;—सर्वश्री यमुना ट्रेडिंग कम्पनी 32 स्ट्राटन मुथिया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935890-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पृष्ठते हुए एक कारण बतायी नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गता सदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ग) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री यमुना ट्रेडिंग कम्पनी 32, स्ट्राटन मुथिया मुदली स्ट्रीट मद्रास 600001 को अक्टूबर-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस पी-इजट-1935890-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[सं डीएफ-9 27-एम-82-एयू 3]

S.O. 116.—M/s. Yamuna Trading Co., 32, Strotten Muthia Mudali St., Madras-600001 were granted a licence No. PZ/1935890/C/XX/82/M/81 dated 23-2-82 for import of Dry fruits for Rs 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. PZ/1935890/C/XX/82/M/81 dt. 23-2-82 issued to M/s. Yamuna Trading Co., 32, Strotten Muthia Mudali St., Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 82 period.

[No. DF/927/AM. 82/AU. III]

का.आ. 117;—सर्वश्री अजन्ता ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या 24, रेड्डी रामन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935935-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 27-2-1982 जारी किया गया था।

1085 GI/82—16.

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पृष्ठते हुए एक कारण बतायी नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गता सदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री अजन्ता ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-34, रेड्डी रामन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अक्टूबर-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस सं. पी इजट-1935935-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 27-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[सं डीएफ-930-एम-82-एयू 3]

S.O. 117.—M/s. Ajantha Trading Co. No. 34, Reddy Raman St. Madras-600001, were granted a licence No. PZ/1935935/C/XX/82/M/81 dated 27-2-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import licence has been obtained by fraudulent means, and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. PZ/1935935/C/XX/82/M/81 dated 27-2-82 issued to M/s. Ajantha Trading Co., No. 34 Reddy Raman St., Madras. 600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 Period.

[No. DF/980/AM. 82/AU. III]

का.आ. 118—सर्वश्री जाली ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-4, लक्ष्मी नाइकन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935876-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पृष्ठते हुए एक कारण बतायी नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले

को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जोती ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-4, तम्बु नाइकेन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-एचट-1935876-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-914-एम 82-एयू 3]

S.O. 118.—M/s. Jothi Trading Co., No. 4, Thambu Naicken Street, Madras-600 001, were granted a Licence No. P/Z/1935876/C/XX/82/M/81 dt. 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935876/C/XX/82/M/81-dt. 22-2-82 issued to M/s. Jothi Trading Co., No. 4, Thambu Naicken Street, Madras-600 001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/914/AM. 82/AU. III.]

का०प्रा० 119—सर्वश्री सरस्वती एम्पोरियम, 5, अयलूर मुत्तैया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-एचट-1935686-सी-एक्सएक्स-81-एम-81 दिनांक 17-12-81 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सरस्वती एम्पोरियम, 5, अयलूर मुत्तैया मुदली

स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-एचट-1935686-सी-एक्सएक्स-81-एम-81 दिनांक 17-12-81 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-668-एम/82-एयू 3]

S.O. 119.—M/s. Saraswathi Emporium, 5, Ayalur Muthiah Mudali Street, Madras—600 001 were granted a Licence No. P/Z/1935686/C/XX/81/M/81 dated 17-12-81 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As, the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935686/C/XX/81/M/81 dated 17-12-81 issued to M/s. Saraswathi Emporium, 5, Ayalur Muthiah Mudali Street, Madras—600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/668/AM/82/AU. III]

का०प्रा० 120—सर्वश्री लालबाणी प्रोविजन ट्रेडर्स, 26, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी-एचट-1935833-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री लालबाणी प्रोविजन ट्रेडर्स, 26, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-एचट-1935833-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-846-एम 82-एयू 3]

S.O. 120.—M/s. Lalwani Provision Traders, 26-Narayana Mudali Street, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935833/C/XX/82/M/81 dt. 16-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import Licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935833/C/XX/82/M/81-dt. 16-2-82 issued to M/s. Lalwani Provision Traders, 26, Narayana Mudali Street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/846/AM. 82/AU. III.]

का०आ० 121.—सर्वश्री पारमार प्राविजन स्टोर, 89, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935835-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारणवताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री पारमार प्राविजन स्टोर, 89, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935835-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-849-एम 82-एयू 3]

S.O. 121.—M/s. Parmar Provision Store, 89, Naryana Mudali St. Madras-1. were granted a licence No. P/Z/1935835/C/XX/82/M/81 dated 16-2-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the Party did not turn up for a personal Hearing

to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935835/C/XX/82/M/81 dated 16-2-82 issued to M/s. Parmar Provision Store 89, Narayana Mudali Street, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 Period.

[No. DF/849/AM. 82/AU. III.]

का०आ० 122.—सर्वश्री यूनिवर्सल ट्रेडर्स, 20 कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935838-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारणवताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री यूनिवर्सल ट्रेडर्स, 20, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल—मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935838-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-853-एम-82-एयू 3]

S.O. 122.—M/s. Universal Traders, 20, Kasi Chetty St., Madras; 600001 were granted a Licence No. P/Z/1935838/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935838/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Universal Traders, 20, Kasi Chetty St., Madras. 1. for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/853/AM. 82/AU. III]

का० आ० 123.—सर्वश्री रवी ट्रेडर्स, 383, कोन्नूर हाई रोड, मद्रास-600012 को रूपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी० इजट०-1935826-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 12-2-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रवी ट्रेडर्स, 383, कोन्नूर हाई रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए, रूपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935826-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 12-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ ।

[संख्या : डी एफ०-834-ए एम 82-ए यू 3]

S.O. 123.—M/s. Ravi Traders, 383, Konnur High Road, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935826/C/XX/82/M/81 dated 12-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935826/C/XX/82/M/81 dated 12-2-82 issued to M/s. Ravi Traders 383, Konnur High Road, Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[No. DF/834/AM. 82/AU. III]

का० आ० 124.—सर्वश्री मंजू ट्रेडिंग कम्पनी, 25, आदियप्प नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रूपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट०-1935687-सी-एक्स एक्स० 82-एम०-81 दिनांक 17-12-81 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है । उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए । अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने के एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मंजू ट्रेडिंग कम्पनी, 25, आदियप्प नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रूपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी० इजट०-1935687-सी-एक्स एक्स० 82-एम-81 दिनांक 17-12-81 को एतद्वारा रद्द करता हूँ ।

[संख्या : डी एफ० 667-ए एम 82-ए यू 3]

S.O. 124.—M/s. Manju Trading Company 25, Audiappa Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935826/C/Z/1935687/C/XX/82/M/81 dated 17-12-81 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935687/C/XX/82/M/81 dated 17-12-81 issued to M/s. Manju Trading Co., 25, Audiappa Naicken St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 periods.

[No. DF/667/AM. 82/AU. III]

का० आ० 125.—सर्वश्री लक्ष्मी ट्रेडर्स, 25, वेस्ट क्लबसंघम रोड, रायपुरम, मद्रास-600013 को रूपए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट०-1935789-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 4-2-82 जारी किया गया था ।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री लक्ष्मी ट्रेडर्स, 25, वेस्ट कलामंडपम रोड, रायपुरम, मद्रास 13 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935789 सी० एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ० 798-ए एम 82-ए यू 3]

S.O. 125.—M/s. Shri Lakshmi Traders, 25, West Kalamandapam Road, Royapuram, Madras-600013, were granted a Licence No. P/Z/935789/C/XX/82/M/81 dt. 4-2-1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/935789/C/XX/82/M/81 dt. 4-2-82 issued to M/s. Shri Lakshmi Traders, 25, West Kalamandapam, Road, Rayapuram, Madras-600013 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/798/AM.82/AU.III]

का० आ० 126.—सर्वश्री रेनुका एण्ड कम्पनी, 12, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को को रुए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935668-सी० एक्सएक्स-82-एम० 81 दिनांक 7-12-81 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए।

अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रेनुका एण्ड कम्पनी, 12, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935668-सी० एक्स० एक्स० 82-एम० 81 दिनांक 7-12-81 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ० 658-ए एम 82-ए यू 3]

S.O. 126.—M/s. Renuka & Co., 12, Kosi Chetty Street Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935668/C/XX/81/M/81 dated 7-12-81 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means for April—March, 1982 period.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935668/C/XX/81/M/81 dated 7-12-81 issued to M/s. Renuka & Co., 12, Kasi Chetty Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 Period.

[No. DF/658/AM.82/AU.III]

आ० का० 127.—सर्वश्री श्री जयलक्ष्मी स्टोर्स, संख्या-9 कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुए 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट० 1935891-सी० एक्स० एक्स० 82-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री जयलक्ष्मी स्टोर्स, संख्या-9, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी०इजट० 1935891-सी० एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 23-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या: डी एफ-926-ए एम 82- एयू 3]

S.O. 127—M/s. Sree Jayalakshmi Stores, No. 9, Krishna Iyer St., Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1935891/C/XX/82/M/81, dated 23-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1935891/C/XX/82/M/81 dated 23-2-82 issue to M/s. Sree Jayalakshmi Stores No. 9, Krishna Iyer St., Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/926/AM.82/AU.III.]

का०आ० 128.—सर्वश्री गोल्डन ट्रेडर्स, 32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०इजट०-1935840-सी० एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री गोल्डन ट्रेडर्स, 32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस

संख्या पी०इजट० 1935840-सी०एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ- 862-ए एम 82- एयू 3]

S.O. 128.—M/s. Golden Traders, 322, Kasi Chetty Street, Madras-600001, were granted a licence No. P/Z/1935840/C/XX/82/M/81 dt. 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the Licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935840/C/XX/82/M/81 dt. 17-2-82 issued to M/s. Golden Traders, 32, Kasi Chetty Street, Madras-600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/862/AM.82/AU.III]

का० आ० 129.—सर्वश्री विजया ट्रेडर्स, 37, एम० एस० कोहल स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०इजट०-1935788-सी०एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 4-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री विजया ट्रेडर्स, 37, एम० एस० कोहल स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०इजट० 193778-सी०एक्स-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 4-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी० एफ०-802-ए० एम० 82-ए०यू० 3]

S.O. 129.—M/s. Vijaya Traders, 37, M. S. Koil Street, Royapuram, Madras-13 were granted a licence No. P/Z/1935788[C]XX/82[m]81 dt. 4-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports Control, Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935788[C]XX/82[m]81 dt. 4-2-82 issued to M/s. Vijaya Traders, No. 37, M. S. Koil Street, Madras-13 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/802/AM.82/AU.III]

का० आ० 130.—सर्वश्री मनोज एन्टरप्राइजस्, संख्या-7, तम्बू नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.ई.जट०-1935909-सी.एक्स.एक्स. 82-एम. 81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मनोज एन्टरप्राइजस्, संख्या-7, तम्बू नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी.ए.जट. 1935909-सी. एक्स.एक्स. 82-एम. 81 दिनांक 24-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०. 936-ए० एम० 82-ए० यू०-3]

S.O. 130.—M/s. Manoj Enterprises, No 7 Thambu Naicken St., Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935909[C]XX/82/M/81 dated 24-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a

Personal Hearing on 15-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935909[C]XX/82/M/81 dated 24-2-82 issued to M/s. Manoj Enterprises, No. 7, Thambu Naicken St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April/March, 1982 period.

[No. DF/936/AM.82/AU.III]

का० आ० 131.—सर्वश्री डाइमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-7, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.ई.जट०-1935936-सी०.एक्स.एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 27-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री डाइमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-7, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी.ई.जट०. 1935936-सी०.एक्स.एक्स०. 82-एम०. 81 दिनांक 27-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-986-ए० एम० 82-ए० यू०-3]

S.O. 131.—M/s. Diamond Trading Co., No. 7, Kasi Chetty Lane, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935936[C]XX/82/m/81 dated 27-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935936[C]XX/82/m/81 dated 27-2-82 issued to M/s. Diamond Trading Co., No. 7, Kasi Chetty Lane, Madras for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. PF/986/AM.82/AU.III]

का० प्रा० 132.—सर्वश्री गुडविल एन्टरप्राइजेज, 9, कृष्ण एथर स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1935854-सी.एक्स.एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 15-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री गुडविल एन्टरप्राइजेज, 9, कृष्ण एथर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1935854-सी.एक्स.एक्स-82.एम.81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी० एफ०-889-ए० एम०-82-ए० यू०-3]

S.O. 132.—M/s. Goodwill Enterprises, 9, Krishna Iyer Street, Madras-1, were granted a Licence No. P/Z/1935854/C/XX/82/M/81, dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past import which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 15-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935854/C/XX/82/M/81, dated 19-2-82 issued M/s. Goodwill Enterprises, Madras-600001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/889/AM.82/AU.III]

का० प्रा० 133.—सर्वश्री सैयमा मालिगै संख्या-12, डी मैल्लोस रोड, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1936098-सी.एक्स.एक्स-82-एम.81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री सैयमा मालिगै, संख्या-12, डी मैल्लोस रोड, मद्रास-600012 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1936098-सी.एक्स.एक्स-82.एम.81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1248/ए० एम० 82-ए० यू०-3]

S.O. 133.—M/s. Syama Maligai, No. 12, Demellows Road, Madras-600012, were granted a Licence No. P/Z/1936098/C/XX/82/M/81, dt. 6-3-82 for Import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936098/C/XX/82/M/81 dt. 6-3-82 issued to M/s. Syama Maligai, No. 12, Demellows Road, Madras-12, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982, period.

[F. No. DF/1248/AM.82/AU.III]

मद्रास, 9 नवम्बर, 1982

का० प्रा० 134.—सर्वश्री रायोर एजेन्सीस, संख्या 3/14, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी.इ.जट. 1935800-सी.एक्स.एक्स-82.एम.81 दिनांक 5-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का

कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ग) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राधोर एजेंसीस, संख्या 3/14, कसी चट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1 को अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935809-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 5-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी.एफ.-805-एम-82-एयु-3]

ORDER

Madras, the 9th November, 1982

S.O. 134. —M/s. Rathore Agencies, No. 3/14, Kasi Chetty St. Madras-1 were granted a Licence No. P/Z/1935809/C/XX/82/M/81, dated 5-2-82, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935809/C/XX/82/M/81 dated 5-2-82 issued to M/s. Rathore Agencies, No. 3/14, Kasi Chetty St., Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/805/AM.82/AU.III]

कां०आ० 135—सर्वश्री बालाजी स्टोर, संख्या-2, रामनाइकन स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935836-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में मैं विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछी हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ग) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बालाजी स्टोर, संख्या-2 रामनाइकन स्ट्रीट रायपुरम, मद्रास-13 को अप्रैल - मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935836-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 16-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ। [संख्या : डी.एफ.-850-एम-82-एयु-3]

S.O. 135—M/s. Balaji Store, No. 2, Ramanaicken Street, Royapuram, Madras-600013 were granted a Licence No. P/Z/1935836/C/XX/82/M/81 dated 16-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935836/C/XX/82/M/81 dt. 16-2-82 issued to M/s. Balaji store, No. 2, Ramanaicken street, Madras-13, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[F. No. DF/850/AM.82/AU.III]

कां०आ० 136:—सर्वश्री बालमुहगन मालिगै स्टोर्स, संख्या-5, के० हेब० रोड, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-जेड-1935884-पी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में मैं विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मै, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बालमुरुगन मलिगै स्टोर्स, मद्रास-5, के. एच. रोड, मद्रास-600012 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935884-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 का एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-897-एम-82-एम्यु3]

S.O. 136.—M/s. Balamurugan Maligai Stores, No. 5, K.H. Road, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935884/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935884/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Balamurugan Maligai Store, No. 5, K. H. Road, Madras-600012 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[F No DF/897/AM 82/AU III]

का० आ० 137—सर्वश्री राजेश्वरी प्राविजन्स स्टोर्स, संख्या-44, डी-मेल्लोस रोड, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-एजिट-1935883-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस का रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मै, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राजेश्वरी प्राविजन्स स्टोर्स, 44, डेमेल्लोस रोड, मद्रास-600012 को, अप्रैल-मार्च, 1982 का अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए

जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935883-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-898-एम 82-एम्यु 3]

S.O. 137.—M/s. Rajeswari Provisions Stores, No. 44, Demellows Road, Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935883/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing No. 29-10-82. As the party did not turn up for Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935883/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Rajeswari Provisions Stores, 44 Demellows Road, Madras-600012 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No DF/898/AM-82/AU. III]

का० आ० 138 -- सर्वश्री बाणी प्राविजन्स 7 जी० ए० रोड, मद्रास 600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935879-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मै, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बाणी प्राविजन्स, 7, जी० ए० रोड, मद्रास-600021 को, अप्रैल-मार्च, 1982 का अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935879-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-905-एम 82-एम्यु 3]

S.O. 138.—M/s. Vani Provisions, 7 G.A. Road, Madras 600021 were granted a Licence No. P/Z/1935879/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935879/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Vani Provisions, 7, G.A. Road, Madras-600021 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/905/AM-82/AU. III]

का० आ० 139:—सर्वश्री तिरुमुगन प्राविजन स्टोर्स, 21, मन्तीयप्पा मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को रु. 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935880-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मन्दी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के प्रामाण्यता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी में यह पृष्ठे हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्या न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मन्दी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री तिरुमुगन प्राविजन स्टोर्स, 21, मन्तीयप्पा मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935880-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 का एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-911-एम० 82-एयू 3]

S.O. 139.—M/s. Thirumugan Provision Stores, 21, Sengthiappa Mudali St., Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1935880/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was

not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935880/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Thirumugan Provision Stores, 21, Sunthappa Mudali Street, Madras-600012 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April-March, 1982 period.

[No. DF/911/AM 82/AU. III]

का० आ० 140:—सर्वश्री रूप ट्रेडिंग कम्पनी, 51, कुटुथाम्-विरान स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936106-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मन्दी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के प्रामाण्यता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी में यह पृष्ठे हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्या न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने, व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मन्दी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रूप ट्रेडिंग कम्पनी, 51, कुटुथाम्-विरान स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936106-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1259-एम० 82-एयू 3]

S.O. 140.—M/s. Roop Trading Company, 51, Kututham-biran St., Madras-600012 were granted a Licence No. P/Z/1936106/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936106/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Roop Trading Company, 51, Kuttithambian St., Madras for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March 1982 period

[No DF/1259/AM. 82/AU. III]

क्र० आ० 141.—सर्वश्री श्री कनगदुर्गा जेनरल स्टोर्स 16, नमसिवायम चेट्टी लेन, मद्रास-600021 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935877-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मन्दी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी ने यह पृष्ठते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मन्दी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री कनगदुर्गा जेनरल स्टोर्स 16 नमसिवायम चेट्टी लेन, मद्रास-21 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935877-सी०-एक्स-एक्स-82-एम०-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-910-एम 82-एम 3]

S.O. 141.—M/s. Sri Kanagadurga General Stores, 16, Namasivayam Chetty Lane, Madras-600021 were granted a Licence No. P/Z/1935877/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935877/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Sri Kanagadurga General Stores, 16, Namasivayam Chetty Lane, Madras 21 for import of dry fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/910/AM. 82/AU. III]

क्र० आ० 142.—सर्वश्री निर्मल ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या 27, स्ट्राटन मुथया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 का रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935878-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मन्दी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी ने यह पृष्ठते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मन्दी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करता हूँ, सर्वश्री निर्मल ट्रेडिंग कम्पनी संख्या-27, स्ट्राटन मुथया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935878-सी-एक्स-एक्स-82-एम०-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-909-एम 82/एम 3]

S.O. 142.—M/s. Nirmal Trading Co. No. 27, Shortten Muthia Mudali Street, Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935878/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I was satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1)(a) of the Imports (Control) Order 1955 hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935878/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Nirmal Trading Co. No. 27, Shortten Muthia Mudali Street, Madras 600001 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No DF/909/AM 82/AU. III]

क्र० आ० 143.—सर्वश्री श्री उमा जेनरल स्टोर्स, संख्या-68, जी० ए० रोड मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935885-सी-एक्स-एक्स-82-एम०-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

आर्थिक तदर्थें सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनकी जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री उमा जेनरल स्टोर्स, संख्या-68, जी० ए० रोड, मद्रास-600021 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935885-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-899/एम/82-एयू 3]

S.O. 143.—M/s. Sri Uma General Stores, No. 68, G.A. Road, Madras-600 021 were granted a Licence No P/Z/1935885/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935885/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Sri Uma General Stores, No. 68, G.A. Road Madras-600 021 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/899/AM. 82/AU. III]

का०आ० 144.—सर्वश्री मेर्कुरी ट्रेडर्स, संख्या-32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजिट-1936102-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनकी जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के

किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मेर्कुरी ट्रेडर्स, संख्या-32, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1936102-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ/1269/एम 82/एयू 3]

S.O. 144.—M/s. Mercury Traders, No. 32, Kasi Chetty St., Madras-600 001 were granted a Licence No. P/Z/1936102/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936102/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Mercury Traders, No. 32, Kasi Chetty St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1269/AM. 82/AU. III]

का०आ० 145.—सर्वश्री गायत्री एम्पोरियम, संख्या-41, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजिट-1935779-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उम प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने में, पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनकी जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के

कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री गायत्री एम्पोरियम, मध्य-41, कासी चेट्टी लेन, मद्रास-1 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935779-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-788-एम-82-एयू 3]

"S.O. 145.—M/s. Gayatri Emporium, No. 41, Kasi Chetty Lane, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935779/C/XX/82/M/81. dt. 1-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past import; which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 29-10-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935779/C/XX/82/M/81 dt. 1-2-82, issued to M/s. Gayatri Emporium, No. 41, Kasi chetty lane, Madras. 1, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982-period.

[F. No. DF/788/AM. 82/AU.III.]

का०आ० 145.—सर्वश्री बालाजी केमिकल्स, संख्या-6, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935805-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए,

सर्वश्री बालाजी केमिकल्स, मध्या-6, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935805-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 5-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-806-एम 82-एयू 3]

S.O. 146—M/s. Balaji Chemicals, No. 6, Kasi Chetty St. Madras. 600001 were granted a Licence No. P/Z/1935805/C/XX/82/M/81 dated 5-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82 As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935805/C/XX/82/M/81 dated. 5-2-82 issued to M/s. Balaji Chemicals No. 6, Kasi Chetty St., Madras. 600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No : DF/806/AM. 82/AU. III.]

का० आ० 147.—सर्वश्री श्री रामू ट्रेडर्स, 15, नर्ममिवाय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935882-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस मनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उन प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 29-10-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत मनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री रामू ट्रेडर्स, 15 नर्ममिवाय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600021 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए, रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस मध्या पी-इजट-1935882-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 22-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ-900-एम 82-एयू 3]

S.O. 147.—M/s. Sri Rama Traders 15, Namasivaya Chetty St Madras, 600021 were granted a Licence No. P/Z/1935882/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-10-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the Powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935882/C/XX/82/M/81 dated 22-2-82 issued to M/s. Sri Rama Traders 15, Namasivaya Chetty St., Madras, 600021 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/900/AM. 82/AU. III.]

मद्रास, 15 अक्टूबर, 1982

कां०प्रा० 148.—सर्वश्री स्वस्तीक ट्रेडिंग कम्पनी संख्या 32 स्ट्राट्टन मुथिया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10 000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935839-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस, सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी मे यह पूछने हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से सतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री स्वस्तीक ट्रेडिंग कम्पनी, संख्या-32, स्ट्राट्टन मुथिया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल—मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935839-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डीएफ-855-एम 82-एयु-3]

Madras, the 15th November, 1982

S.O. 148.—M/s. Swastik Trading Co., No. 32, Strotten Muthia Mudali Street, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935839/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was

not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935839/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Swastik Trading Co, 32, Strotten Muthia Mudali Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/855/AM. 82/AU. III.]

कां०प्रा० .—149 सर्वश्री वर्दमान ट्रेडर्स, 37, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास 600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस पी-इजट-1935852-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखायी देने से, पार्टी मे यह पूछने हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वर्दमान ट्रेडर्स, 37, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास 600001 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935852-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डीएफ-874-एम 82-एयु 3]

S.O. 149.—M/s. Vardhman Traders, 37, Narayana Mudali Street, Madras, 600091 were granted a license No. P/Z/1935852/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby

cancel the import licence No. P/Z/1935852/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 issued to M/s. Vardhman Traders, 37, Narayana Mudali Street, Madras. 600 001, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/874/AM. 82/AU. III.]

कां० 150.—सर्वश्री सुरेश ट्रेडर्स, 11, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास 600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936046-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सुरेश ट्रेडर्स, 11, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936046-सी एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[सं० डी एफ-1173-एम 82-एयु 3]

S.O. 150.—M/s. Suresh Traders, 11 Kasi Chetty St., Madras-600 001 were granted a Licence No. P/Z/1936046/C/XX/82/M/81 dated 4-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 29-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1982, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936046/C/XX/82/M/81 dated 4-3-82 issued to M/s. Suresh Traders, 11 Kasi Chetty Street, Madras—600 001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1173/AM. 82/AU. III]

कां० 151.—सर्वश्री नागेश्वरा प्राविजनस, संख्या-29, तुलसी नाइकेन स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936044-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी ने यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नागेश्वरा प्राविजनस, संख्या-29, तुलसी नाइकेन स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936044-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-1170-एम 82-एयु 3]

S.O. 151.—M/s. Nageshwara Provisions, No. 29, Thulasi Naicken Street, Madras-12, were granted a Licence No. P/Z/1936044/C/XX/82/M/81 dated 4th March, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936044/C/XX/82/M/81, dated 4th March, 1982 issued to M/s. Nageshwara Provisions, No. 29-Thulasi Naicken Street, Madras-12, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/1170/AM. 82/AU.III]

कां० 152.—सर्वश्री गंमरी ट्रेडर्स, 19, थाना स्ट्रीट जेपेरी, मद्रास-7 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935900-सी एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 21-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रोसरी ट्रेडर्स 19, थाना स्ट्रीट, वेपेरी, मद्रास-7 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935900-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 21-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-944-एम 82-एयू 3]

S.O. 152.—M/s. Rosary Traders, 19, Thana Street, Vepery, Madras-7, were granted a Licence No. P/Z/1935900/C/XX/82/M/81 dated 21st February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the Licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935900/C/XX/82/M/81 dated 21st February, 1982 issued to M/s. Rosary Traders, No. 19, Thana Street, Vepery, Madras-7 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/944/AM. 82/AU.III]

का०आ० 153.—सर्वश्री कमलेश ट्रेडर्स, संख्या-4, तोलसिंगम स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935868-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक

कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कमलेश ट्रेडर्स, संख्या-4, तोलसिंगम स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935868-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-896-एम 82-एयू 3]

S.O. 153.—M/s. Kamlesh Traders No. 4, Tholasingam street, Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935868/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 23rd September, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935868/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 issued to M/s. Kamlesh Traders No. 4, Tholasingam Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/896/AM. 82/AU. III]

का०आ० 154.—सर्वश्री कोटी स्टोर्स 34/2, डी मेल्लोस रोड, मद्रास-12 को - रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935902-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बनाओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार

पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कोटी स्टोर्स, 34/2, डी डेल्लोस रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935902-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-945-एम 82-एयू 3]

S.O. 154.—M/s. Koti Stores, 34/2, Demellows Road, Madras-12 were granted a licence No P/Z/1935902/C/XX/82/M/81 dated 24th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935902/C/XX/82/M/81 dated 24th February, 1982 issued to M/s. Koti Stores, 34/2, Demellows Road Madras-12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/945/AM. 82/AU.III]

का०आ० 155.—सर्वश्री नाडार मालीगै, 25, पेरिय तम्बो मुदली स्ट्रीट, मद्रास-7 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935888-सी-एक्सएम-82-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नाडार मालीगै, 25, पेरिय तम्बो मुदली स्ट्रीट, मद्रास-7 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये

10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1934888-सी एक्स-एक्स 82-एम-81 दिनांक 22-7-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी एफ-922-एम 82-एयू 3]

S.O. 155.—M/s. Nadar Maligai, 25, Peria Thambi Mudali St., Madras-7, were granted a Licence No. P/Z/1935888/C/XX/82/M/81 dated 23rd February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935888/C/XX/82/M/81 dated 22nd July, 1982 issued to M/s. Nadar Maligai, 25, Peria Thambi Mudali St., Madras-7 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/922/AM. 82/AU.III]

का० आ० 156.—सर्वश्री मुथा जेनरल ट्रेडर्स, संख्या 3, तम्बू नाडक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी० इजट-1935837-पी०-एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मुथा जेनरल ट्रेडर्स, संख्या-3, तम्बू नाडक्कन स्ट्रीट, मद्रास 600001 को अप्रैल, मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1935837-सी०-एक्स० एक्स०-82 एम०-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-854-एम० 82-एयू० 3]

S.O. 156.—M/s. Mutha General Traders, No. 3, Thambu Naicken Street, Madras-60001 were granted a Licence No. P/Z/1935837/C/XX/82/M/81, dated 17th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24th September, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935837/C/XX/82/M/81 dated 17th February, 1982 issued to M/s. Mutha General Traders No. 3, Thambu Naicken Street, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. 854/AM. 82/AU.III]

का० प्रा० 157.—सर्वश्री अरुणा ट्रेडर्स, 18 सुब्बराय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936054-सी०-एक्स०एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री अरुणा ट्रेडर्स, 18, सुब्बराय चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600012 को, अप्रैल-मार्च, 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936054-सी०-एक्स०-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 5-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1176-ए० एम०-82-एयु० 3]

S.O. 157.—M/s. Aruna Traders 18, Subbaraya Chetty St., Madras-600012, were granted a licence No. P/Z/1936054/C/XX/82/M/81 dated 5th March 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant

Certificate certifying their past imports which was not genuine. A show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20th September, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936054/C/XX/82/M/81, dated 5th March, 1982 issued to M/s. Aruna Traders, 18, Subbaraya Chetty St., Madras-600012 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1176/AM. 82/AU.III]

का० प्रा० 158.—सर्वश्री जया मुरुगन स्टोर्स, 46, एम० एस० कोइल स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936048 सी०-एक्स०एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 5-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने को एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को धारा 9 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जया मुरुगन स्टोर्स, 46, एम० एस० कोइल स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च, 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936048-सी०-एक्स०-एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 5-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1183-ए० एम० 82-एयु० 3]

S.O. 158.—M/s. Jaya Murugan Stores, 46, M.S. Koil St., Royapuram, Madras-13, were granted a Licence No. P/Z/1936048/C/XX/82/M/81, dated 5th March, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936048/C/XX/82/M/81 dated 5th March, 1982 issued to M/s. Jaya Murugan Stores, 46, M. S. Koil St., Royapuram, Madras-13, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1183/AM. 82/AU.III]

का० आ० 159.—सर्वश्री तामस स्टोर, 2, न्यू स्ट्रीट, ओट्टेरी, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936072-सी०-एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री तामस स्टोर, 2, न्यू स्ट्रीट, मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट 1936072-सी०-एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1196-ए० एम० 82-एयु० 3]

S.O. 159.—M/s. Thomas Stores 2, New Street, Otteri, Madras-600012, were granted a licence No. P/Z/1936072/C/XX/82/M/81, dated 5th March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20th September, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of clause 9(1)(a) of the imports (control) order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936072/C/XX/82/M/81, dated 6th March, 1982 issued to M/s. Thomas Store, 2, New Street, Madras-12, for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1196/AM. 82/AU. III]

का० आ० 160.—सर्वश्री मोडी ट्रेडर्स, संख्या-11, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936070-सी०-एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मोडी ट्रेडर्स, संख्या-11, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936070-सी०-एक्स० एक्स०-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1191-ए० एम० 82-एयु० 3]

S.O. 160.—M/s. Modi Traders No. 11, Kasi Chetty Street, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1936070/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936070/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Modi Traders No. 11, Kasi Chetty Street Madras-600001 for import of dry fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/1191/AM '82/AU. III]

का० आ० 161.—सर्वश्री राजा राजेश्वरी जनरल मर्चेंट्स, 39/1, डीमेल्लोम रोड, मद्रास-600112 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936121-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एड् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री राजा राजेश्वरी जनरल मर्चेंट्स, 39/1, डीमेल्लोम रोड, मद्रास-600112 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936121-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1241-ए० एम० 82-ए० यु० 3]

S.O. 161.—M/s. Raja Rajeswari General Merchant, 39/1 Demellows Road, Madras-600112 were granted a Licence No. P/Z/1936121/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the Party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936121/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Raja Rajeswari General Merchants 39/1 Demellows Road, Madras-600112 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1241/AM. 82/AU. III]

का० आ० 162.—सर्वश्री नाडार एण्ड कम्पनी, 74, रामस्वामी स्ट्रीट, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936111-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री नाडार एण्ड कम्पनी, 74, रामस्वामी स्ट्रीट, मद्रास-600012 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936 111-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी० एफ०-1249-ए० एम०-82/ए० यु० 3]

S.O. 162.—M/s. Nadar & Co., 74, Ramaswamy Street, Madras-600012 were granted a licence No. P/Z/1936111/C/XX/82/M/81, dated 6-3-1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import licence No. P/Z/1936111/C/XX/82/M/81, dated 6-3-82 issued to M/s. Nadar & Co., 74, Ramaswamy St., Madras-600012 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1249/AM. 82/AU. III]

का० आ० 163.—सर्वश्री मूनस्टार एन्टरप्राइजस, 11, तिरुवेंगडस्वामी स्ट्रीट, पुलियांतोप, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936108-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछने हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनका जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट

करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मूनस्टार एंटरप्राइजेस, 11, तिरुवेंगाडस्वामी स्ट्रीट, पुलियन्तोप, मद्रास-600 012 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी० इजट-1936108 सी०-एक्स-एक्स-82एम-81 दिनांक 6-3-1982 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1252-एम 82-एयू 3]

S.O. 163.—M/s. Moonstar Enterprises, 11 Thiruvengadaswamy Street Pulianthope, Madras-600012 were granted a licence No. P/Z/1936108/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered account and certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936108/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Moonstar Enterprises, 11, Thiruvengadaswamy Street Pulianthope Madras-600012 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1252/AM. 82/AU. III]

का० आ० 164:—सर्वश्री ऐयप्पा स्टोर्स, संख्या-26, न्यू स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी०-इजट-1936-073 सी-एक्सएक्स-82-एम०-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाण-पत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने के एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री ऐयप्पा

स्टोर्स, संख्या 26, न्यू स्ट्रीट, मद्रास-600 012 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गये लाइसेंस पी० इजट-1936073 सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-1186-एम 82-एयू 3]

S.O. 164.—M/s. Sri Iyappa Stores, No. 26, New Street, Madras-600012 were granted a licence No. P/Z/1936073/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered account certificate certifying their past imports which has not genuine a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936073/C/XX/82/M/81 dated 6-3-82 issued to M/s. Iyappa Stores, 26 New Street, Madras-600012 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1186/AM '82/AU. III]

का. आ. 165 :—सर्वश्री विनोद सेल्स सेन्टर, संख्या-9, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935841 सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री विनोद सेल्स सेन्टर, संख्या-9, कृष्ण ऐयर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935841 सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डी० एफ०-858-एम 82-एयू 3]

S.O. 165.—M/s. Vinod Sales Centre, No. 9, Krishna Iyer Street, Madras-600001 were granted a licence No. P/Z/1935841/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Account

tant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955 hereby Cancel the Import licence No. P/Z/1935841/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Vinod Sales Centre, No. 9 Krishna Iyer Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/856/AM. 82/AU. III]

का. आ. 163 :—सर्वश्री वीनस ट्रेडर्स, संख्या-4, तम्बु नाइकेन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935842-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 जारी किया गया था।

उपयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वीनस ट्रेडर्स, संख्या-4, तम्बु नाइकेन स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935842-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 17-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-857-एएम 82-एयू 3]

S.O. 166.—M/s Venus Traders, No. 4, Thambu Naicken Street, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935842/C/XX/82/M/81, dated 17-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No P/Z/1935842/C/XX/82/M/81 dated 17-2-82 issued to M/s. Venus Traders, 4, Thambu Naicken street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/857/AM 82/AU. III]

का. आ. 167 :—सर्वश्री पापूलर ट्रेडर्स, संख्या-7, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों

का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935860-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री पापूलर ट्रेडर्स, संख्या-7, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935860-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-857-एएम 82-एयू 3]

S.O. 167.—M/s. Popular Traders, No. 7, Kasi Chetty Lane, Madras-600001, were granted a Licence No. P/Z/1935860/C/XX/82/M/81, dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate Certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 24-9-82. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935860/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Popular Traders, No. 7, Kasi Chetty Lane Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March, 1982 period.

[No. DF/857/AM.82/AU.III]

का. आ. 168 :—सर्वश्री महेन्द्रा एजेन्सीज, 27, नारायण मन्दीर स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935851-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 जारी किया गया था।

उपयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल

प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री महेन्द्रा एजेन्सीज, 27, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935851-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 18-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-867-एम 82-एयू 3]

S.O. 168.—M/s. Mahendra Agencies, 27-Narayana Mudali street, Madras-600001, were granted a licence No. P/Z/193585/C/XX/82/M/81 dated 18-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935851/C/XX/82/M/81 dt. 18-2-82 issued to M/s. Mahendra Agencies, 27-Narayana Mudali street, Madras-1 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April-March 1982 period.

[F. No. DF/867/AM. 82/AU. III.]

का. जा. 169 :—सर्वश्री ए. के. एस. प्रोविजन्स, संख्या 1, जमालिया ग्राउन्ड, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936010-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री ए. के. एस. प्रोविजन्स, संख्या-1, जमालिया ग्राउन्ड, मद्रास-12 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936010-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-115-एम 82-एयू 3]

जी. सी. फरनन्डज, उप-मुख्य नियंत्रक,
आयात तथा निर्यात

S.O. 169.—M/s. A K S Provisions, No. 1, Jamalia ground, Madras 12 were granted a Licence No. P/Z/1936010/C/XX/82/M/81, dt 3-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above Import Licence has been obtained by Producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936010/C/XX/82/M/81, dt. 3-3-82 issued to M/s. A. K. S. Provisions, No. 1 Jamalia ground, Madras 12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[F. No. DF/115/AM. 82/AU. III]

C. G. FERNANDEZ, Dy. Chief Controller,
Imports and Exports

का० जा० 170.—सर्वश्री प्रभु जेनरल मर्चन्ट्स, 32/2, टी० के० मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600007 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936092-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं उस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री प्रभु जेनरल मर्चन्ट्स, 32/2, टी० के० मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600007 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936092-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1244-एम 82-एयू 3]

S.O. 170.—M/s. Prabhu General Merchants 32/2, T.K. Mudali Street Madras-600007 were granted a licence No. P/Z/1936092/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-8-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Import (Control) Order, 1955 hereby cancel the import licence No. P/Z/1936092/C/XX/82/M/81 dated 6-3-1982 issued to M/s. Prabhu General Merchants, 32/2 T. K. Mudali Street, Madras-600007 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1244/AM/82/AU. III]

का० आ० 171 :—सर्वश्री वी० एम० स्टोर, 27, वेस्ट कलमण्डपम रोड, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936101-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री वी० एम० स्टोर, 27, वेस्ट कलमण्डपम रोड, रायपुरम, मद्रास-13 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936101-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-1982 का एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ / 1264/एम 82-एयू-3]

S.O. 171.—M/s. V. M. Store, 27, West Kalmandapam Road, Royapuram, Madras-13 were granted a licence No. P/Z/1936101/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20th August, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936101/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. V. M. Store, 27, West Kalmandapam Road, Royapuram, Madras-13 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1264/AM. 82/AU. III]

1085 GI/82—19.

का० आ० 172.—सर्वश्री अमर सेल्स कारपोरेशन, संख्या-7, तम्बू, नाइकेन स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट—1935893-सी-एक्सएक्स-82 एम-81 दिनांक 23-2-83 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 को धारा 9 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री अमर सेल्स कारपोरेशन, संख्या 7, तम्बू नाइकेन स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935893-सी-एक्सएक्स 82-एम- 81 दिनांक 23-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-925 - एएम - 82-एयू-3]

S.O. 172.—M/s. Amar Sales Corporation, No 7, Thambu Naicken Street, Madras-1 were granted a licence No. P/Z/1935893/C/XX/82/M/81, dated 23rd February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935893/C/XX/82/M/81 dated 23-2-1982, issued to M/s. Amar Sales Corporation No. 7, Thambu Naicken Street, Madras-1 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/925/AM. 82/AU.III]

का० आ० 173 :—सर्वश्री सोलंकी एन्टरप्राइजस, 82, नारायण सुंदरा स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935858-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सोलंकी एन्टरप्राइजस, 82, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935858-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या: डीएफ-892-एम 82-एयू 3]

S.O. 173.—M/s. Solanki Enterprises, 82, Narayana Mudali St., Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935858/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 23-9-82. As the Party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decided to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935858/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Solanki Enterprises, 82, Narayana Mudali St., Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/892/AM. 82/AU. III]

का० आ० 174.—सर्वश्री रिशबदेव एन्टरप्राइजस, 29, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935865-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 23-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रिशबदेव एन्टरप्राइजस, 29, नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को, अप्रैल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935865-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद् द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या: डीएफ-893-एम 82-एयू 3]

S.O. 174.—M/s. Rishabdev Enterprises, 29, Narayana Mudali St., Madras-600001 were granted a Licence No. P/Z/1935865/G/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 23-9-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935865/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 issued to M/s. Rishabdev Enterprises 29-Narayana Mudali St. Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/893/A.M. 82/AU. III]

का० आ० 175.—सर्वश्री गणपति एन्टरप्राइजस, संख्या 32, स्ट्राट्टन मुथिया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935861-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द किया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत

सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री गणपति एन्टरप्राइजेस, संख्या-32, स्ट्रोटेन मुथिया मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600001 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935861-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-886-एम-82-एयू 3]

S.O. 175.—M/s. Ganapati Enterprises, No. 32, Strotten Muthia Mudali St., Madras-600 001 were granted a licence No. P/Z/1935861/C/XX/82/M/81, dated 19-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 24-9-1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935861/C/XX/82/M/81 dated 19-2-82 issued to M/s. Ganapati Enterprises, No. 32, Strotten Muthia Mudali Street, Madras-600001 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March 1982 period.

[No. DF/886/AM. 82/AU. III]

का. आ. 176 :—सर्वश्री कासीमारी एजेंसीस्, 92, पोलू स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936109-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री कासीमारी एजेंसीस्, 92, पोलू स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936109-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1247-एम 82-एयू 3]

S.O. 176.—M/s. Kasimari Agencies, 92, Jolu Street, Madras 12, were granted a Licence No. P/Z/1936109/C/XX/82/M/81 dt. 6-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import Licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine. A Show Cause Notice was issued calling upon the licence holder to Show Cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-8-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in items of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936109/C/XX/82/M/81 dt. 6-3-82 issued to M/s. Kasimari Agencies 92, Jolu street, Madras 12 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[F No. DF/1247/AM 82/AU. III]

का. आ. 177 :—सर्वश्री शक्ति प्रोविजन स्टोर, 15, रामनाइक्कल स्ट्रीट, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936099-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपयुक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 24-9-1982 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री शक्ति प्रोविजन स्टोर, 15, रामनाइक्कल स्ट्रीट, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936099-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1261-एम 82-एयू 3]

S.O. 177.—Sakthi Provision Store, 15, Ramanaicken St., Madras-13 were granted a licence No. P/Z/1936099/C/XX/82/M/81 dt. 6-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 20-8-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex parte.

I in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936099/C/XX/82/M/81 dt. 6.3.82 issued to M/s. Sakthi Provision Store, 15, Ramanaicken St., Madras-13 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1261/A.M 82/AU. III]

का. आ. 178 :—सर्वश्री श्रीनीवासा किराना एण्ड जेनरल मर्चेन्ट्स, 79, सोलैपन स्ट्रीट, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935977-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सर्वश्री लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-1982 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्रीनीवासा किराना एण्ड जेनरल मर्चेन्ट्स, 79, सोलैपन स्ट्रीट, मद्रास-21 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935977-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1071-एम 82-एयू 3]

S.O. 178.—M/s. Srinivasa Kirana & General Merchants 79, Solappam Street, Madras-600021 were granted Licence No. P/Z/1935977/C/XX/82/M/81 dated 1-3-82 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal Hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935977/C/XX/82/M/81 dated 1-3-82 issued to M/s. Srinivasa Kirana & General Merchants, 79, Salaipam Street, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1071/AM 82/AU. III]

का. आ. 179 :—सर्वश्री बाबू प्रोविजन स्टोर्स, संख्या-15, पोन्नपचट्टी स्ट्रीट, मद्रास-3 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935997-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-1982 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं

इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बाबू प्रोविजन स्टोर्स, संख्या-15, पोन्नपचट्टी स्ट्रीट, मद्रास-3 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किया गया लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935997-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ-1028-एम 82-एयू 3]

S.O. 179.—M/s. Babu Provision Stores, No. 15, Ponnappachetty Street, Madras-3 were granted a Licence No. P/Z/1935997/C/XX/82 M/81 dated 2-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, A Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to Show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935997/C/XX/82/M/81 dated 2-3-82 issued to M/s. Babu Provision Stores, No. 15, Ponnappachetty Street, Madras-3 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1082/AM. 82/AU. III]

का. आ. 180 :—सर्वश्री तंगम स्टोर्स, 53/1, सायन्न नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600007 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935914-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एकपक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री तंगम स्टोर्स, 53/1, सायन्न नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-600007 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000

तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935914-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ/952/एम 82-एयू 3]

S.O. 180.—M/s. Thangam Stores, 53/1-Sathanna Naicken St., Madras—600007 were granted a Licence No. P/Z/1935914/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the Licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935914/C/XX/82/M/81 dated 25-2-82 issued to M/s. Thangam Stores, 53/1-Sathanna Naicken St., Madras-600 007 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/952/AM. 82/AU. III.]

कां० 181.—सर्वश्री दास जनरल स्टोर्स, 64, अंगलम्मन कोडल स्ट्रीट, मद्रास-600012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1925984-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक-2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री दास जनरल स्टोर्स, 64, अंगलम्मन कोडल स्ट्रीट, मद्रास 600112 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935984-सी-एक्सएक्स-82-एम 81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ/1077/एम/82/एयू 3]

S.O. 181.—M/s. Dass General Stores, 64, Angalamma koli Street, Madras, 600 012 were granted a Licence No. P/Z/1935984/C/XX/82/M/81 dt. 2-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by production a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, I show cause notice was issued calling upon the Licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9 (1) (a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935984/C/XX/82,M,81, dt. 2-3-82 issued to M/s. Dass General Store, 64, Angalamman koll Street, Madras-600112 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[F. No. DF/1077/AM. 82/AU. III.]

कां० 182.—सर्वश्री अब्दुल सलाम, संख्या 5, तिरुपुर कुमरन स्ट्रीट, पम्मल, मद्रास-75 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935956-सी-एक्सएक्स 82-एम-81 दिनांक 1-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न, रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री अब्दुल सलाम, संख्या-5, तिरुपुर कुमरन स्ट्रीट, पम्मल, मद्रास-75 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935956-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ/1015-एम 82/एयू 3]

S.O.182.—M/s. Abdul Salam No. 5, Tirupur Kumaran St., Pammal, Madras, 75 were granted a Licence No. P/Z/1935956/C/XX/82/M/81 dated 1-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 43,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon

the Licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935956[C/XX/82/M/81 dated 1-3-82 issued to M/s. Abdul Salam No. 5 Tirupur Kumaran Street, Pammal Madras-75 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1015/AM. 82/AU III]

का०आ० 183.—सर्वश्री माया मर्चेंट्स, 75/2-टी-के मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600007 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935901-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस का रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री माया मर्चेंट्स, 75/2-टी-के-मुदली स्ट्रीट, मद्रास-600007 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935901-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 24-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ/940/एम 82/एयू 3]

S.O. 183.—M/s. Maya Merchants, 75/2, T.K. Mudali Street, Madras-600007 were granted a Licence No. P/Z/1935901[C/XX/82/M/81 dated 26-2-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22-7-82. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby

cancel the Import Licence No. P/Z/1935901[C/XX/82/M/81 dated 24-2-82 issued to M/s. Maya Merchants, 75/2-T. K. Mudali St., Madras-600007 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/940/AM. 82/AU. III]

का० आ० 184.—सर्वश्री जैन एन्टरप्राइजस, 38, एकाम्बरेस्वरर अग्रहारम, मद्रास-3 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936114-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने का एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री जैन एन्टरप्राइजस, 38, एकाम्बरेस्वरर अग्रहारम, मद्रास-3 का, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936114-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ/1254-एम/82-एयू 3]

S.O. 184.—M/s. Jain Enterprises, 18, Ekambareswarar Agraharam, Madras-3, were granted a Licence No. P/Z/1936114/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 20th August, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936114[C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Jain Enterprises, 38, Ekambareswarar Agraharam Street, Madras-3 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1254/AM. 82/AU. III]

कां०आ० 185 :--सर्वश्री बाबुलाल एण्ड कम्पनी, संख्या 6, कासी स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936047-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त गलत लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बाबुलाल एण्ड कम्पनी, संख्या-6, कासी चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-1 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936047-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 4-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ/1172/एम 82-एयू 3]

S.O. 185.—M/s. Babulal & Co., No. 6, Kasi Chetty Street Madras-1, were granted a licence No. P/Z/1936047/C/XX/82/M/81 dated 4th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936047/C/XX/82/M/81 dated 4th March, 1982 issued to M/s. Babulal & Co., No. 6, Kasi Chetty St., Madras-1 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1172/AM. 82/AU. III]

कां०आ० 186 :--सर्वश्री गुरुनाथ प्राविजन स्टोर्स, 48, एम०पी० कोइल स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936005-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री गुरुनाथ प्राविजन स्टोर्स, 48, एम०पी० कोइल स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936005-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ/1112-एम 82-एयू 3]

S.O. 186.—M/s. Gurnath Provision Stores, 48, S. P. Koil Street, Madras-12, were granted a licence No. P/Z/1936005/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936005/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Gurnath Provision Stores, 48, S. P. Koil Street, Madras-12 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1112/AM. 82/AU. III]

कां०आ० 187 :--सर्वश्री रमेश ट्रेडर्स, संख्या-14, पिल्लैयार कोइल स्ट्रीट, मद्रास-3 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935993-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-83 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी में यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी

किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रमेश ट्रेडर्स, संख्या-14 पिल्लैयार कोइल स्ट्रीट, मद्रास-3 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935993-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

(संख्या डीएफ-1079-एम 82-एयू 3)

S.O. 187.—M/s. Ramesh Traders, No. 14, Pillar Koil Street, Madras-3, were granted a licence No. P/Z/1935993/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal Hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import licence No. P/Z/1935993/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 issued to M/s. Ramesh Traders, No. 14, Pillar Koil St., Madras-3 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1079/AM. 82/AU. III]

कां.प्रा. 188 :—सर्वश्री एम०बी०एम० एन्टरप्राइजस, 42, वेस्ट कलमण्डम रोड, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936120-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी ने आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बी०एम० एन्टरप्राइजस, 42, वेस्ट कलमण्डम रोड, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936120-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1266एम-82-एयू 3]

S.O. 188.—M/s. S. B. M. Enterprises, 42, West Kalmandapam Road, Madras-13, were granted a Licence No. P/Z/1936120/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 20th August, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936120/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. S. B. M. Enterprises, 42, West Kalmandapam Road, Madras 13 for import of Dry fruits for Rs 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/1266/AM. 82/AU. III]

कां.प्रा. 189 :—सर्वश्री माकनचन्द नेमीचन्द, 23 नारायण मुदली स्ट्रीट, मद्रास-1 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935866-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत मुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत मुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री शा माकनचन्द नेमीचन्द, 23 नारायण मुदली स्ट्रीट

मद्रास-1 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935866-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 19-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-882-एम 82-एम 3]

S.O. 189.—M/s. Sha Makanchand Nemichand, 23, Narayana Mudali Street, Madras-1, were granted a licence No. P/Z/1935866/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935866/C/XX/82/M/81 dated 19th February, 1982 issued to M/s. Sha Makanchand Nemichand Madras-1 for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/882/AM. 82/AU. III]

कां० 199 :—सर्वश्री रामा प्रोविजन स्टोर, 9, रामा नाइक्कन स्ट्रीट, रायपुरम मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936100-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनवी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 20-8-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनवी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रामा प्रोविजन स्टोर, 9 रामा नाइक्कन स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936100-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1262-एम 82-एम 3]

1085 GI/82.—20.

S.O. 190.—M/s. Rama Provision Store, 9, Rama Naicken Street, Royapuram, Madras-13, were granted a Licence No. P/Z/1936100/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 20th August, 1982. As the party did not turn up for a Personal Hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936100/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Rama Provision Store, 9, Rama Naicken Street, Royapuram, Madras-13 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1262/AM. 82/AU. III]

कां० 191 :—सर्वश्री ए० करीम प्रोविजन स्टोर्स, 24 तुलसी नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935892-सी-एक्सएक्स-एम-81 दिनांक 23-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनवी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से सन्तुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनवी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री ए० करीम प्रोविजन स्टोर्स, 24, तुलसी नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1935892-सी-एक्सएक्स-एम-81 दिनांक 23-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-924-एम 82-एम 3]

S.O. 191.—M/s. A. Kareem Provision Stores, 24-Thulasi Naicken Street, Madras-12, were granted a Licence No. P/Z/1935892/C/XX/M/81 dated 23rd February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon

the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a Personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a Personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935978/C/XX[M]81 dated 23rd February, 1982 issued to M/s. A. Kareem Provision Stores, 24-Thulasi Nairken Street, Madras-12, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/924/AM. 82/AU. III]

का० घा० 192—सर्वश्री श्री सायबाबा स्टोर्स, संख्या-4, श्री रंगम्माल लेन, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935978-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री श्री सायबाबा स्टोर्स, संख्या-4, श्री रंगम्माल लेन, मद्रास-21 को, अप्रैल—मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935978-सी/एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 1-3-82 का एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1074-एम-82-एयू 3]

S.O. 192.—M/s. Sri Saibaba Stores, No. 4, Sri Rangammal Lane, Madras-600021, were granted a licence No. P/Z/1935978/C/XX[M]81 dated 1st March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935978/C/XX[M]81 dated 1st March, 1982 issued to M/s. Sri Saibaba Stores, No. 4, Sri Rangammal Lane, Madras-21 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1074/AM. 82/AU. III]

का० घा० 193—सर्वश्री गजलक्ष्मी स्टोर्स, 48, श्री रंगम्माल स्ट्रीट, वाशरमेनपेट, मद्रास-21 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935979-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री गजलक्ष्मी स्टोर्स 48 श्री रंगम्माल स्ट्रीट, वाशरमेनपेट, मद्रास-21 को, अप्रैल—मार्च, 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935979-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1087-एम 82/एयू-3]

S.O. 193.—M/s. Gajalakshmi Stores, 48, Srirangammal Street, Washermenpet, Madras-21 were granted a Licence No. P/Z/1935979/C/XX[M]81 dated 2nd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935979/C/XX[M]81 dated 2nd March, 1982 issued to M/s. Gajalakshmi Stores, 48, Sri Rangammal Street, Washermanpet, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[F. No. DF/1087/AM. 82/AU. III]

का० धा० 194.—सर्वश्री सेल्वम स्टोर्स, 5/3 तुलसी नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936011-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल के प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सेल्वम स्टोर्स, 5/3, तुलसी नाइक्कन स्ट्रीट, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936011-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1113/एएस-82/एयू 3]

S.O. 194.—M/s. Selvam Stores, 5/3 Tulasi Naicken Street, Madras-12, were granted a licence No. P/Z/1936011/C/XX/82/M-81 dated 3rd March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1936011/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Selvam Stores, 5/3 Tulasi Naicken Street, Madras-12, for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1113/AM 82/AU. III]

का० धा० —सर्वश्री मुरली एन्टरप्राइजस, 16, सोमू चेट्टी स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936071-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मुरली एन्टरप्राइजस, 16, सोमू चेट्टी स्ट्रीट, रायपुरम, मद्रास-13 को अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1973071-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 6-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ-1189-एएम 82-एयू 3]

S.O. 195.—M/s: Murali Enterprises, 16 Somuchetty Street, Royapuram, Madras-13, were granted a licence No. P/Z/1936071/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 for import of dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/193071/C/XX/82/M/81 dated 6th March, 1982 issued to M/s. Murali Enterprises, 16 Somuchetty Street, Royapuram, Madras-13, for import of dry fruits for Rs. 10,000 for April—March 1982 period.

[No. DF/1189/AM 82/AU. III]

का० धा० 196 सर्वश्री ए०जी० एस० स्टोर्स, 73, पेक्कूरु हाई रोड, मद्रास-600 012 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936001-सी-एक्स-एक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के वास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण

बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सर्वश्री एं.जी.एस. स्टोर्स, 73, पेरम्बूर हाई रोड, मद्रास-600 012 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस संख्या पी-इजट 1936001-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ/1116-एएम 82-ए यू 3]

S.O. 196.—M/s. A.G.S. Stores, 73, Perambur High Road, Madras-600012, were granted a Licence No. P/Z/1936001/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936001/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. A.G.S. Stores, 73, Perambur High Road, Madras-600012, for import of Dry Fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1116/AM. 82/AU. III]

का० प्र० 197.—सर्वश्री रत्ना स्टोर्स, 2, जी०ए० रोड, मद्रास-21 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1036015-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर

प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री रत्ना स्टोर्स, 2, जी०ए० रोड, मद्रास-21 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936015-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1108-एएम 82-ए यू 3]

S.O. 197.—Rathna Stores, 2-G.A. Road, Madras-21 were granted a Licence No. P/Z/1936015/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936015/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Rathna Stores, No. 2, G.A. Road, Madras-21 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1108/AM. 82/AU. III]

का० प्र० 198.—सर्वश्री मोहन प्राविजनल स्टोर्स, 50, पेरम्बूर हाई रोड, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजट-1936000-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री मोहन प्राविजनल स्टोर्स, 50, पेरम्बूर हाई रोड, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च, 1982 की अवधि के लिए

रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1936000-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या डीएफ-1104-एम 82-एयू 3]

S.O. 198.—M/s. Mohan Provisional Stores, 50, Perambur High Road, Madras-12, were granted a Licence No. P/Z/1936000/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1936000/C/XX/82/M/81 dated 3rd March, 1982 issued to M/s. Mohan Provisional Stores, 50, Perambur High Road, Madras-12, for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1104/AM. 82/AU. III]

का० आ० 199:—सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स, 84, अप्पाराव गार्डन, मद्रास-12 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935915-सी-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाण पत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 22-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री बालाजी ट्रेडर्स, 84, अप्पाराव गार्डन, मद्रास-12 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गए लाइसेंस संख्या पी-इजिट 1935915-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 25-2-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ/953-एम-82-एयू 3]

S.O. 199.—M/s. Balaji Traders, 84, Apparao Garden Madras-12 were granted a Licence No. P/Z/1935915/C/XX/82/M/81 dated 25th February, 1982 for import of Dry fruits for Rs. 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 22nd July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence ex-parte.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the import licence No. P/Z/1935915/C/XX/82/M/81, dated 25th February, 1982 issued to M/s. Balaji Traders, 84, Apparao Garden, Madras-600112 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

To

[No. DF/953/AM. 82/AU. III]

का० आ० 200:—सर्वश्री एस०एम० स्टोर, संख्या 39, पोन्नप्प चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-3 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस संख्या पी-इजिट 1935998-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपर्युक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उनको जारी किया गया लाइसेंस क्यों न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपर्युक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाण-पत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1)(ए) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री एस०एम० स्टोर, संख्या 39, पोन्नप्प चेट्टी स्ट्रीट, मद्रास-3 को, अप्रैल-मार्च 1982 की अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस संख्या पी-इजिट-1935998-सी-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 को एतद्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डी एफ/1030-एम-82-एयू 3]

S.O. 200.—M/s. S. M. Stores, No. 39, Ponnappachetty Steel, Madras-3, were granted a Licence No. P/Z/1935998/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 for import of Dry fruits for Rs 10,000.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a chartered accountant certificate certifying their past imports which was not genuine, a show cause notice was issued calling upon the

licence holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30th July, 1982. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above import licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence *ex parte*.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935998/C/XX/82/M/81 dated 2nd March, 1982 issued to M/s. S. M. Stores, No. 39, Ponnappachetty Street, Madras-3 for import of Dry fruits for Rs. 10,000 for April—March, 1982 period.

[No. DF/1030/AM. 82/AU. III]

का० घा० 201.—सर्वश्री सेल्वराज प्राविजन्स, 90, वी० ए० रोड, मद्रास-600021 को रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए आयात लाइसेंस सख्या पी-इजट-1935995-सी०-एक्स एक्स-82-एम-81 दिनांक 2-3-82 जारी किया गया था।

उपरोक्त लाइसेंस सनदी लेखापाल द्वारा भूतपूर्व आयात के प्रमाणपत्र जारी करने के आधार पर प्राप्त किया गया है। उस प्रमाणपत्र के अवास्तविकता के बारे में विश्वास करने का कारण दिखाई देने से, पार्टी से यह पूछते हुए एक कारण बताया नोटिस जारी किया गया था कि 30-7-82 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उनको जारी किया गया लाइसेंस क्या न रद्द कर दिया जाए। अपने मामले को स्पष्ट करने व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पार्टी न आने के कारण, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि उपरोक्त लाइसेंस गलत सनदी लेखापाल प्रमाणपत्र के आधार पर प्राप्त किया गया है और एतद् द्वारा लाइसेंस को रद्द करने की एक-पक्षीय निर्णय लेता हूँ।

मैं, आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 की धारा 9(1) (ए) के अन्तर्गत प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, सर्वश्री सेल्वराज प्राविजन्स, 90, जो० ए० रोड, मद्रास-21 को, अप्रैल-मार्च 1982 को अवधि के लिए रुपये 10,000 तक सूखे फलों का आयात करने के लिए जारी किये गये लाइसेंस सख्या पी-इजट-1935995-सी०-एक्सएक्स-82-एम-81 दिनांक 3-3-82 को एतद्द्वारा रद्द करता हूँ।

[संख्या : डीएफ/1078-एम/82-एयू 3]

आर० सेल्वराज, उप मुख्य नियंत्रक आयात तथा निर्यात

S.O. 201.—M/s. Selvaraj Provisions, 90, G.A. Road, Madras-600021 were granted a Licence No P/Z/1935995/C/XX/82/M.81 dated 2-3-82 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/-.

As there was a reason to believe that the above import licence has been obtained by producing a Chartered Accountant Certificate certifying their past imports which was not genuine, a Show Cause Notice was issued calling upon the Licence Holder to show cause why action should not be taken to cancel the licence giving an opportunity for a personal hearing on 30-7-82. As the party did not turn up for a personal hearing to explain his case, I am satisfied that the above Import Licence has been obtained by fraudulent means and hereby decide to cancel the licence *ex parte*.

I, in exercise of the powers vested on me in terms of Clause 9(1)(a) of the Imports (Control) Order, 1955, hereby cancel the Import Licence No. P/Z/1935995/C/XX/82/M/81 dated 3-3-82 issued to M/s. Selvaraj Provisions Stores, G.A. Road, Madras-21 for import of Dry Fruits for Rs. 10,000/- for April—March, 1982 period.

[No. DF/1078/AM. 82/AU. III]
R. SELVARAJ, Dy. Chief Controller,
Imports & Exports.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास मंत्रालय)

आदेश

नई दिल्ली, 1982

का०घा० 202.—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का०घा० 797 (अ), तारीख 12 नवम्बर, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—
उक्त आदेश में :—

- (1) पैरा 12 में राजपत्रित पंक्ति शब्दों के स्थान पर सहायक निदेशक या समतुल्य पंक्ति का अधिकारी शब्द रखे जाएंगे,
- (2) अनुसूची में क्रम संख्यांक 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात् :—

“क्रम संख्यांक 11 सा०मा० 4250-1980”।

टिप्पण :— हिन्दी पाठ में क्रम संख्यांक 7 और 33 की प्रविष्टियाँ ठीक हैं। इसलिए उनका अनुवाद किया जाना आवश्यक नहीं है।

[का०सं० एस० एस० I(I)-24(62)/81]

एस०के० चक्रवर्ती, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDER

New Delhi, the 10th December, 1982

S.O. 202.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry No. S.O. 797(E) dated the 12th November, 1981, namely :—
In the said Order—

- (i) in paragraph 12, for the words “Gazetted ranks”, the words “Assistant Director or Officer of equivalent rank” shall be substituted;
- (ii) in the Schedule for S. Nos. 7, 11, and 33 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries thereof shall respectively be substituted, namely :—
“S. No. 7 IS : 1596—1977”;
“S. No. 11 IS : 4250—1980”; and
“S. No. 33 IS : 6446—1972”.

[No. SSI(D)-24(62)/81].

S. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1982

का०प्रा० 203—अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड I अधिकारी श्री बी० नन्जुन्दैया को 6 दिसम्बर, 1982 के पूर्वान्हन से वायदा बाजार आयोग, बम्बई के अध्यक्ष के रूप में आगे और आदेश होने तक के लिये, नियुक्त करते हैं।

[मिसिल संख्या ए-12011/17/82 प्रशा० 2]

बी०डी० गोपाला, अव्वर सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 8th December, 1982

S.O. 203.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby appoints Sh. B. Nanjundaiya, a Grade I Officer of the I.E.S., as Chairman, Forward Markets Commission, Bombay, with effect from the forenoon of 6th December, 1982 until further orders.

[File No. A. 12011/17/82-Estt. II]

B. D. GOPALA, Under Secy.

नयी दिल्ली, 14 दिसम्बर, 1982

का०प्रा० 204—नागरिक पूर्ति मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, डा० पी०एल० कौल ने 6 दिसम्बर, 1982 के दोपहर के पहले से वायदा बाजार आयोग, बम्बई के सदस्य तथा साथ ही अध्यक्ष के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

नागरिक पूर्ति विभाग

(भारतीय मानक संस्था)

नई दिल्ली, 1982-11-24

का०प्रा० 205—समय समय पर संशोधित भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) विनियम, 1955 के विनियम 4 के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियम (3) के उपविनियम (1) के अनुसार प्राप्त अधिकारों के अधीन एहां अनुसूची में दिये भारतीय मानकों के संशोधन जारी किये गये हैं।

अनुसूची

क्रम सं०	संशोधित भारतीय मानक की मदसंख्या और शीर्षक	जिस राजपत्र अधिसूचना में भारतीय मानक के तैयार होने की सूचना छपी थी उसकी संख्या और तिथि	संशोधित मानक की संख्या और तिथि	संशोधन का संक्षिप्त विवरण	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IS : 178—1965 सूती टिबल की विशिष्ट (पुनरीक्षित)	एस ओ 1992 दिनांक 1966-07-02	सं० 2 जन० 1980	खंड 2.2.1 के पश्चात् एक नयी टिप्पणी जोड़ी गई है।	1980-01-31
2.	IS : 180—1965 सूती कमीज के कपड़ों की विशिष्ट (पुनरीक्षित)		सं० 2 जन० 1980	खंड 2.2.1 के पश्चात् एक टिप्पणी जोड़ी गई है।	1980-01-31

2. केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-I अधिकारी, श्री नन्जुन्दैया को 6 दिसम्बर, 1982 के दोपहर के पहले से आगे और आदेश होने तक के लिये वायदा बाजार आयोग, बम्बई के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और साथ ही उन्हें आयोग का अध्यक्ष भी नामित करती है।

3. इसे नागरिक पूर्ति मंत्रालय की 8 दिसम्बर, 1982 की इसी संख्या की अधिसूचना को रद्द करते हुए जारी किया गया है।

[मिसिल संख्या ए-12011/17/82-प्रशा०-2]

गुरनाम सिंह, अव्वर सचिव

New Delhi, the 14th December, 1982

S.O. 204.—Dr. P. N. Kaul, Economic Advisor in the Ministry of Civil Supplies relinquished charge of the post of Member as well as Chairman of the Forward Markets Commission, Bombay, on the forenoon of the 6th December, 1982.

2. In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 3 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby appoints Shri B. Nanjundaiya, a Grade I Officer of the I.E.S., as a Member of the Forward Markets Commission, Bombay and also nominates him to be the Chairman of the Commission with effect from the forenoon of the 6th December, 1982 until further orders.

3. This has been issued in supersession of the Ministry of Civil Supplies notification of even number dated the 8th December, 1982.

[File No. A-12011/17/82-Estt. II]

GURNAM SINGH, Under Secy.

1	2	3	4	5	6	7
3. IS : 178—1965 स्थायी रिफाई के लिये नीली-कासी तरल स्थाही की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस प्रो 1992 दिनांक 19 66-07-02	सं० 1 दि० 19 80	IS : 8642—1977 “जल-प्राधारित लिखने की स्थाही की विशिष्टि” के प्रकाशन से जिस में इंक-ब्ल्यू रंजक की अपेक्षा की गई है IS : 224-7-1962 “स्थाही उद्योग के लिये इंक-ब्ल्यू रंजक की विशिष्टि” को वापस लिया गया है। अतः यह संशोधन जारी किया गया है।	1980-02-31		
4. IS : 453—1973 ग्ररणी के तेल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस प्रो 469 0 दिनांक 19 75-11-01	सं० 1 दि० 19 79	(1) खंड 4. 2 के स्थान पर एक नया खंड दिया गया है। (2) पृष्ठ 4 और 5 खंड 4. 2. 1 इन्हें काटिए। (3) परिशिष्ट ए के शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक दिया गया है।	1980-01-31		
5. IS : 69 4—19 77 1100 बो० तक की कार्यकारी बोल्टता के पी० बी सी रोधित केबल की विशिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	—	सं० 1 जन० 19 80	(1) पृष्ठ 3 पर क्रमांक संख्या 11 और 12 के सामने विशेष धातु को संशोधित किया गया है। (2) खण्ड 0. 3 के पश्चात् एक नया खण्ड 0. 4 जोड़ा गया है और तत्पश्चात् खण्डों की क्रमांक संख्या को तदनुसार ठीक किया गया है। (3) खण्ड 1. 1, 1. 2, 9. 4, 10. 1, 11, 11. 1, 12, 12. 1, 12. 3. 1 और ए०-1 को संशोधित किया गया है। (4) खण्ड 2. 4, 11. 4, 12. 2, 12. 3, ए-2 से ए-3. 1 और बी० 1. 1 के स्थान पर नये खण्ड लाये गये हैं। (5) खण्ड 8. 1 के नीचे वर्तमान टिप्पणी को “टिप्पणी 1” संख्या दी गई है और एक नयी “टिप्पणी 2” जोड़ी गयी है। (6) खण्ड 9. 4 के पश्चात् एक नया खण्ड 9. 5 जोड़ा गया है और तत्पश्चात् खण्डों का नम्बर तदनुसार बदला गया है। (7) खण्ड 13. 2 के पश्चात् एक टिप्पणी जोड़ी गयी है।	1680-12-31		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(8) शब्द 'पी' के पश्चात् नया "क्यू" जोड़ा गया है।	
				(9) (पृष्ठ 15, खंड बी 1.1, टिप्पणी)--- इसे काटिए।	
				(10) (पृष्ठ 16, खण्ड बी 2.3 अनौपचारिक सारणी, पहला खाना, दूसरी प्रविष्टि)--- शब्द "50" और उतने तक काटिए।	
6.	IS: 732--1963 विद्युत पावरिंग संस्थापना (वर्गीकृत बोल्डना 650 वो० तक) की रीतिसंहिता (पुनरीक्षण)	एस ओ 1147 दिनांक 1963-04-20 जन० 1930	सं० 6 जन० 1930	खण्ड 5.8.1 (इ) के स्थान पर एक नया खण्ड रखा गया है।	1980-01-31
7.	IS: 750--1976 हथकरघे पर बनी सूती लुगी की विधिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	-- --	सं० 2 1980	सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1980-01-31
8.	IS: 774--1971 अंग्रेजी टट्टी और मूखानयों के लिये प्ला की टंकियों (बालर रहित सादकन आधारित किस्म वाले) की विधिष्टि (तीसरा पुनरीक्षण)	एस ओ 231 दिनांक 1974-01-26 जन० 1980	सं० 5* जन० 1980	(1) खण्ड 4.3, 4.4, 4.8 और 4.8.1 के स्थान पर नये खण्ड रखे गए हैं। (2) खण्ड 2.2 और 3.2 के उपरान्त क्रमशः नये खण्ड 2.3 और 3.2.1 जोड़े गये हैं।	1980-01-31
9.	IS: 902--1974 शक्तिगत उपयोग के लिये चूषण हाथ कपलिंग की विधिष्टि (दूसरा पुनरीक्षण)	एस ओ 1596 दिनांक 1976-05-08 विप० 1979	सं० 3 विप० 1979	सारणियों 1ए, 1बी, 2ए और 2बी का संशोधन किया गया है।	1979-12-31
10.	IS: 1169--1967 विद्युत के रेडिस्टल वाले पंखे और रेन्यूनेटर की विधिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 1720 दिनांक 1968-05-18 जन० 1980	सं० 4 जन० 1980	खण्ड 16.2.1 और 16.2.12 के नोबे दी गयी टिप्पणियों के स्थान पर नयी टिप्पणी दी गई है।	1980-01-31
11.	IS: 1235--1958 एर्सर्टिक अजल की विधिष्टि	एस ओ 1949 दिनांक 1958-09-27 दिम० 1979	सं० 1 दिम० 1979	खण्ड बी-2.3.2.1 का संशोधन किया गया है।	1979-12-31
12.	IS: 1266--1938 हथकरघे पर बनी सर्ज का विधिष्टि	एस० ओ० 1654 दिनांक 2958-12-27 दिम० 1979	सं० 1 दिम० 1979	यह संशोधन संसदकीय हेर फेर करने और विभिन्न अपेक्षाओं की परीक्षण विधियों के भारतीय मानकों के नवीनतम संस्करणों का उल्लेख करने के लिये जारी किया गया है।	1979-12-31

* एस० ओ० संस्था प्रमाणन योजना के लिए यह संशोधन 1980-03-01 से लागू होगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. IS : 1288—1973 खनिज एस ओ 4690 सं० 2 जिपसम और जिपसम पदार्थों दिनांक 1975-11-01 जन० 1980 की परीक्षण पद्धतियों (पहला पुनरीक्षण)				(1) खण्ड 10.2.2 और 11.2.1.3 को संशोधित किया गया है। (2) (पृष्ठ 12, खण्ड 10.2.3 सूत्र)—“140.2” की जगह “280.4” करिए। (3) (पृष्ठ 14, खण्ड 11.2.3 सूत्र “100.8” की जगह “201.6” करिए।	1980-01-31
14. IS : 1423—1973 सूती गैज-ईर्जन की विशिष्टि एस ओ 2558 सं० 1 (पहला पुनरीक्षण) दिनांक 1975-08-09 जन० 1980				सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1980-01-31
15. IS : 1445—1977 1000 बो एस ओ सं० 1 तक की नाभिक बोल्टना तक की दिस० 1979 शिरोपरि विद्युत्प्ररोधकों की (दूसरा पुनरीक्षण)				(पृष्ठ 11, खंड 7 और 7.1 इनको काटिए तत्पश्चात् खंडों का नम्बर बढ़ा लिए।	1979-12-31
16. SI : 1492—1970 मोटरी सर्वेक्षण जंजीर की विशिष्टि एस ओ 1635 सं० 2 (पहला पुनरीक्षण) दिनांक 1972-07-08 दिस० 1979				खंड 5.1 का संशोधन किया गया है।	1979-12-31
17. IS : 1776—1961 बिन सेप वाले मुड़वां डिब्बा बनाने के गसे एस ओ 2534 सं० 3 की विशिष्टि दिनांक 1961-10-28 दिस० 1979				सारणी 1 और 2 का संशोधन किया गया है।	1979-12-31
18. IS : 1886—1967 ट्रांसफार्मर संस्थापन और देख रेख की रीति एस ओ 2789 सं० 4 संहिता दिनांक 1967-08-19 जन० 1980				(पृष्ठ 11, चित्र 1, टिप्पणी 1, लाइन 1)—शब्द “लगभग 500 किलो ए क्षमता के” काटिए।	1980-01-31
19. IS : 2037—1962 अनुरेखण कण्डे की विशिष्टि एस ओ 2562 सं० 3 दिनांक 1962-08-11 दिस० 1979				(1) दूसरे पुनर्मुद्रण में खंड सी-2.1 और तीसरे पुनर्मुद्रण में खंड सी-1.2 के स्थान पर नये खंड दिए गए हैं। (2) पहले पुनर्मुद्रण में पृष्ठ 10 पर खंड सी-2.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1979-12-31
20. IS : 2081 (भाग 1)—1976 एस ओ 3882 सं० 1 बाहन गाड़ियों की बैटरी के गाव-हुम सिरों के केबल संयोजक की विशिष्टि भाग 1 पीतल वाले संयोजक (पहला पुनरीक्षण) दिनांक 1979-11-24 जन० 1980				(1) सारणी 1 का संशोधन किया गया है। (2) रेखाचित्र 1 की जगह एक नया रेखाचित्र दिया गया है। (3) खंड 3.1 के नीचे एक नयी टिप्पणी जोड़ी गयी है।	1980-01-31
21. IS : 2361—1970 बुलडाग चिमटियों की विशिष्टि एस ओ 1277 सं० 3 (पहला पुनरीक्षण) दिनांक 1972-05-27 दिस० 1979				खंड 2.1.2 के स्थान पर एक नया खंड दिया गया है।	1979-12-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. IS: 2413—1978 सूती सुतली की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	सं० 1 जन० 1980	खंड 6.5 की अनौपचारिक सारणी का संशोधन किया गया है।	1980-01-31	
23. IS: 2453—1978 केवल बल वाले सूती रस्से की विशिष्टि (पहला पुनरीक्षण)	—	सं० 1 जन० 1980	खंड 0.2, 0.4 और सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1980-01-31	
24. IS: 2490 (भाग 1)—1974 भीतरी प्रदेश की सतह जलराशि में विमुक्त औद्योगिक निस्स्राव के लिये सहनशीलता सीमाएं भाग 1 सामान्य सीमाएं (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 182 दिनांक 1976-01-10	सं० 1 दिस० 1979	(पृष्ठ 7, सारणी 1, क्रम संख्या (24)—इसकी काटिए।	1979-12-31	
25. IS: 2582 (भाग 2)—1972 खराद स्पिंडल नोज और फेस प्लेट के परिमाण, भाग 2 स्पिंडल नोज-कैमलॉक किस्म के (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 2081 दिनांक 1975-07-25	सं० 1 दिस० 1979	रेखाचित्र 1 और सारणी 1 के स्थान पर नए खंड दिए गए हैं।	1979-12-31	
26. IS: 3775—1966 विरंजित सूती खादी हकबैक तौलिए कपड़े की विशिष्टि	एस ओ 913 दिनांक 1967-03-18	सं० 2 जन० 1980	सारणी 1 के नीचे टिप्पणी 4 के स्थान पर नयी टिप्पणी दी गई है।	1980-01-31	
27. IS: 4651—(भाग 4)—1969 जहाज गोदी और बंदरगाह संरचनाओं के लिए डिजाइन करने और निर्माण की रीति संहिता भाग 4 शीट पाइल की स्तम्भन बीमारें।	एस ओ 436 दिनांक 1970-02-07	सं० 1 जन० 1980	(IS: 465 (1 भाग 1)—1974 और IS: 4651 (भाग 3) 1974 के प्रकाशन उपरांत और IS: 7314—1974 बंदरगाह और पतन इंजीनियरिंग से संबंधित शब्दावली के प्रकाशन के बाद आवश्यक था कि IS: 4651 (भाग 4)—1969 का संशोधन किया जाए।	1980-01-31	
28. IS: 4890—1968 खुले जल-भागों में निलम्बित तलछट मापने की विधियां	एस ओ 3929 दिनांक 1969-09-27	सं० 1 दिस० 1979	खंड 4.5.3 के पश्चात् एक नया खंड 4.5.3.1 जोड़ा गया है।	1979-12-31	
29. IS: 5204—1969 अनुसंधान सूक्ष्मदर्शी की विशिष्टि	एस ओ 4848 दिनांक 1969-12-06	सं० 1 दिस० 1979	(1) खंड 4.6 के स्थान पर एक नया खंड दिया गया है। (2) (पृष्ठ 7, खंड 4-9-1-1, पंक्ति 2) —“0.001 मिमी” के स्थान पर “0.01 मिमी” पढ़िए।	1979-12-31	
30. IS: 5920—1970 प्रकाशिक अवयवों और प्रणालियों के रेखाचित्र तैयार करने की सिफारिशें	एस ओ 1555 दिनांक 1972-06-24	सं० 1 जन० 1980	(पृष्ठ 7, सारणी 1, तीसरा कॉलम “श्रेणी किस्म”—इसे काटिए	1980-01-31	
31. IS: 6234—1971 जल वाले (स्थायी वायु दबाव वाले) लुबाहा अभिनशामक की विशिष्टि।	एस ओ 1549 दिनांक 1973-06-02	सं० 4 जन० 1980	(1) खंड 4.1 के नीचे टिप्पणी के स्थान पर नयी टिप्पणी दी गई है। (2) खंड 4.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है।	1980-01-31	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(3) (पृष्ठ 5, खंड 4-4-3)--- इसे काटिए	
				(4) खंड 9.1, 9.3 और 9.3.1 .1 को संशोधित किया गया है।	
				(5) पृष्ठ 12 पर “+” और “\$” चिह्न वाली पादटिप्पणी का संशोधन किया गया है।	
				(6) खण्ड 7.2.11 के पश्चात् एक नयी टिप्पणी दी गई है।	
32. IS : 6425—1971 डाइप्टो- मीटर (लेंसमापी) की विशिष्टि	एस ओ 751 दिनांक 1974-03-16	सं० 1 जन० 1980		खंड 4.2 का संशोधन किया गया है।	1980-01-31
33. IS : 6488—1975 व्यक्ति- बैब साजसमान के लिये सूती बेबिंग की विशिष्टि। (पहला पुनरीक्षण)	एस ओ 2240 दिनांक 1978-08-06	सं० 1 जन० 1980		(1) सारणी 1 और 3 का संशो- धन किया गया है। (2) (पृष्ठ 7 खंड 7.1 7.1.1 7.1.2 और 7.2)—वर्तमान खंडों के स्थान पर निम्नलिखित रखिए—“7.1 प्रतिबन्धन योजना परीक्षण नमूनों की संख्या और अनुरूपता की कमीटी वही होगी जैसी IS : 7777—1975* के खंड 7 और 8 में दी गयी है। (3) “*” और “+” चिह्न वाली पादटिप्पणी के स्थान पर नयी टिप्पणियां दी गई हैं।	1980-01-31
34. IS : 6638—1972 टैंकर पर जनाए स्प्रिंग-लोडेड कल्टीवैटर की विशिष्टि	एस ओ 770 दिनांक 1975-03-08	सं० दिस० 1976		खण्ड 5.1 को संशोधित किया गया है।	1979-12-31
35. IS : 7056—1973 सूती हक्का बैक सीलिंग की विशिष्टि	एस ओ 2939 दिनांक 1975-09-06	सं० 2 दिस० 1979		सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1979-12-31
36. IS : 7777—1975 मुड़े किनारों वाली सूती निबाड़ की विशिष्टि	एस ओ 3351 दिनांक 1978-11-25	सं० 2 दिस० 1979		सारणी 1 और 2 का संशोधन किया गया है।	1979-12-31
37. IS : 8081—1976 खांचेदार खंडों की विशिष्टि	एस ओ 3820 दिनांक 1979-11-24	सं० 2 1979-11-24		(1) खंड 2.1 के स्थान पर नया खंड दिया गया है। (2) (पृष्ठ 5, खंड 5.4 पंक्ति 3)—“समस्त परिष्कृति में दिया जायेगा” शब्द काटिए। (3) (पृष्ठ 9, खंड 6.6.2.1 पंक्ति 1)—“अवश्य होगा” में बदलिए।	1979-12-31
38. IS : 8130—1976 रोधित विद्युत् केबल और लचीली डोरियो के लिये चालकों की विशिष्टि	एस ओ 99 दिनांक 1980-01-12	सं० 1 जन० 1980		सारणी 8 और 9 का संशोधन किया गया है।	1980-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
39. IS : 8308—1976 रोधित नेबलों के एल्यूमिनियम चालकों के लिये संपीड़ित किस्म के नलाकार इन्लाइन संयोजनों की वि-सिष्टि	एम् आ 419 दिनांक 1980-02-23	सं० 1 पार० 1980	(1) खंड 1 और 3 का संशोधन किया गया है। (2) (पृष्ठ 1 खंड 4.1)—इसे काटिए और बाद वाले खंडों की संख्या को तदनुसार बदलिए। (3) (पृष्ठ 3 सारणी 2) इसे काटिए। (4) खंड 5 और 6 का संशोधन किया गया है। (5) सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1980-02-29	
40. IS : 8438—1977 1100 वोल्ट की बोल्टों वाले केबल के लिये डबले रेजिन पर आधारित सीधे आर पार जोड़ों के सांचों की वि-सिष्टि	एम् आ 618 दिनांक 1980 03 15	सं० 1 दिस० 1979	(पृष्ठ 6 सारणी 1 टिप्पणी)—इसे काटिए	1979-12-31	
41. IS : 8810—1978 रोलेट नमूने की अश्रु भेली रजिन की वि-सिष्टि	—	सं० 1 जन० 1980	(पृष्ठ 1, खंड 1, पंक्ति 1) "स्वच्छमंडल" के स्थान पर "अश्रु" पढ़िए।	1980-01-31	
42. IS : 8914—1978 कोचांस इनेमल उद्योग के लिये जल गुणता संबंधी छूटें।	—	सं० 1 दिस० 1979	सारणी 1 का संशोधन किया गया है।	1979-12-31	

[संख्या सो०एम०डी०/13:5]

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

New Delhi, the 24th November, 1982

S. O. 205.—In pursuance of regulation 4 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian Standards Institution hereby notifies that amendment(s) to the Indian Standard (s) given in the schedule hereto annexed have been issued under the powers conferred by the sub-regulation (1) of Regulation 3 of the said Regulations.

THE SCHEDULE

Sl. No. and title of the Indian Standard amended	No. and Date of Gazette Notification in which the establishment of the Indian Standard was notified	No. and Date of the Amendment	Brief particulars of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. IS : 178-1965 Specification for cotton twills (Revised)	S.O. 1982 dated 196(-07-02)	No. 2 Jan 1980	A new note has been added after clause 2.2.1	1980-01-31
2. IS : 180-1965 Specification for cotton sheetings (Revised)	-do-	No. 2 Jan 1980	A note has been added after clause 2.2.1.	1980-01-31

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. IS : 221-1977 Specification for ink, fluid blue black, for permanent records (Second Revision)	—	No. 1 Dec 1979	In view of the publication of IS : 8642-1977 'Specification for dyes for water-based writing inks' in which the requirements of dye, ink blue, have been covered, IS : 2247-1962 'Specification for dye, ink blue for ink industry' has been withdrawn. Hence this amendment is being issued.	1979-12-31	
4. IS : 435-1973 Specification for castor oil (Second Revision)	S.O. 4690 dated 1975-11-01	No. 1 Dec 1979	(i) Clause 4.2 has been substituted by a new one (ii) (Pages 4 and 5 clauses 4.2.1 and 4.2.2 Delete (iii) Title of Appendix A has been substituted by a new	1979-12-31	
5. IS : 694-1977 Specification for PVC insulated cables for working voltages up to and including 1100 volts (Second Revision)	—	No. 1 Jan 1980	(i) Contents at page 3 against Sl. No. 11 and 12 have been amended. (ii) New clause 0.4 has been added after clause 0.3 and the subsequent clauses have been re-numbered accordingly. (iii) Clauses 1.1, 1.2, 9.4, 10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 12.3.1 and A-1 have been amended. (iv) Clause 2.4, 11.4, 12.2, 12.3, A-2 to A-3.1 and B-1.1 have been substituted by new ones. (v) Existing note has been redesignated as 'Note 1' and a new 'Note 2' has been added under clause 8.1 (vi) New clause 9.5 has been added after clause 9.4 and the subsequent clauses have been re-numbered accordingly. (vii) A note has been added after clause 13.2 (viii) A new item (q) has been added after item (P) (ix) (Page 15, clause B-1.1, Note)—Delete (x) (Page 16, clause B-2.3, informal table, first column, second entry)—Delete the words 'and up to and including 50'.	1980-01-31	
6. IS : 732-1963 Code of practice for electrical wiring installations (system voltage not exceeding 650 volts) (Revised)	S.O. 1147 dated 1963-04-20	No. 6 Jan. 1980	Clause 5.8.1 (e) has been substituted by a new one	1980-01-31	
7. IS : 750-1976 Specification for handloom cotton lungies (First Revision)	—	No. 2 Jan 1980	Table 1 has been amended	1980-01-31	
8. IS : 774-1971 Specification for flushing cisterns for water closets and urinals (valveless siphonic type) (Third Revision)	S.O. 231 dated 1974-01-26	*No. 5 Jan 1980	(i) Clauses 4.3, 4.4, 4.8 and 4.8.1. have been substituted by new ones (ii) New clauses 2.3 and 3.2.1 have been added after clauses 2.2 and 3.2 respectively	1980-01-31	
9. IS : 902-1974 Specification for suction hose couplings for fire fighting purposes (Second Revision)	S.O. 1596 dated 1976-05-08	No. 3 Dec 1979	Tables 1A, 1 B, 2A, 2B have been amended	1979-12-31	
10. IS : 1169-1967 Specification for electric pedestal type fans and regulators (First Revision)	S.O. 1720 dated 1968-05-18	No. 4 Jan 1980	Existing Notes under clauses 16.2.1 and 16.2.1.2 have been substituted by new ones	1980-01-31	
11. IS : 1235-1958 Specification for acetic anhydride	S.O. 1949 dated 1958-09-27	No. 1 Dec 1979	Clause B-2.3.2.1 has been amended	1979-12-31	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. IS: 1266-1968 Specification for handloom serge	S.O. 2654 dated 1958-12-27	No. 1 Dec 1979	This amendment is being issued to incorporate editorial changes and for referring the latest version of Indian Standards on methods of tests for different characteristics.	1979-12-31	
13. IS : 1288-1973 Methods of test for mineral gypsum and gypsum products (First Revision)	S.O. 4690 dated 1975-11-01	No. 2 Jan 1980	(i) Clauses 10.2.2 and 11.2.1.3 have been amended. (ii) (Page 12, clause 10.2.3, formula)—Substitute '280.4' for '140.2'. (iii) (Page 14, clause 11.2.3, formula)—Substitute '201.6' for '100.8'.	1980-01-31	
14. IS : 1423-1973 Specification for cotton gaberdine (First Revision)	S.O. 2558 dated 1975-08-09	No. 1 Jan 1980	Table 1 has been amended	1980-01-31	
15. IS : 1445-1977 Specification for porcelain insulators for overhead power lines with a nominal voltage up to and including 1 000 V (Second Revision)	—	No. 1 Dec 1979	(Page 11 clauses 7 and 7.1)—Delete and renumber the subsequent clauses accordingly.	1979-12-31	
16. IS : 1492—1970 Specification for metric surveying chains (First Revision)	S.O. 1635 dated 1972-07-08	No. 2 Dec. 1979	Clause 5.1 has been amended	1979-12-31	
17. IS : 1776—1961 Specification for folding box board, uncoated	S.O. 2534 dated 1961-10-28	No. 3 Dec 1979	Tables I and II have been amended	1979-12-31	
18. IS : 1886—1967 Code of practice for installation and maintenance of transformers (First Revision)	S.O. 2789 dated 1967-08-19	No. 4 Jan 1980	(Page 11, Fig. 1, Note 1, Line 1)—Delete the words 'of about 500 kVA rating'.	1980-01-31	
19. IS : 2037—1962 Specification for tracing cloth	S.O. 2562 dated 1962-08-11	No. 3 Dec 1979	(i) Clause C-2.1 of second reprint and clause C-1.2 of third reprint have been substituted by new ones. (ii) Clause C-2.1 (Page 10 of first reprint) has been substituted by a new one.	1979-12-31	
20. IS : 2081 (Pt I)—1976 Specification for taper terminal cable connectors for automobile batteries Part I brass type connectors (First Revision)	S.O. 3822 dated 1979-11-24	No. 1 Jan 1980	(i) Table 1 has been amended (ii) Fig. 1 has been substituted by a new one. (iii) A new note has been added after clause 3.1	1980-01-31	
21. IS : 2361—1970 Specification for bulldog grips (First Revision)	S.O. 1277 dated 1972-05-27	No. 3 Dec 1979	Clause 2.1.2 has been substituted by a new one.	1979-12-31	
22. IS : 2413—1978 Specification for cotton twine (First Revision)	—	No. 1 Jan 1980	Informal table of clause 6.5 has been amended.	1980-01-31	
23. IS : 2453—1978 Specification for cable-laid cotton rope (First Revision)	—	No. 1 Jan 1980	Clause 0.2, 0.4 and Table 1 have been amended	1980-01-31	
24. IS : 2490 (Pt I)—1974 Tolerance limits for industrial effluents discharged into inland surface waters Part I General limits (First Revision)	S.O. 182 dated 1976-01-10	No. 1 Dec 1979	[Page 7, Table 1, Sl. No. (xxiv)—Delete.]	1979-12-31	
25. IS : 2582 (Pt II)—1972 Dimensions for lathe spindle noses and face plates Part II spindle noses—camlock type (First Revision)	S.O. 2081 dated 1975-07-05	No. 1 Dec 1979	Fig. 1 and table 1 have been substituted by a new one.	1979-12-31	
26. IS : 3775—1966 Specification for huckaback towels, cotton khadi, bleached	S.O. 913 dated 1967-03-18	No. 2 Jan 1980	Note 4 under table 1 has been substituted by a new one	1980-01-31	
27. IS : 4651 (Pt IV)—1969 Code of practice for design and construction of dock and harbour structures Part IV sheet pile retaining walls	S.O. 436 dated 1970-02-07	No. 1 Jan 1980	[Consequent to the revision of IS : 4651 (Part I)—1974 and IS : 4651 (Part III)—1974 and also publishing a standard on Glossary, namely, IS : 7314—1974 Glossary of terms relating to port and harbour engineering, it became necessary to issue an Amendment to IS : 4651 (Part IV)—1969]	1980-01-31	

* For purposes of 'ISI Certification Marks Scheme; this amendment shall come into force with effect from 1980-03-01

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. IS : 4890—1968 Methods for measurement of suspended sediment in open channels	S.O. 3929 dated 1969-09-27	No. 1 Dec 1979	A new clause 4.5.3.1. has been added after clause 4.5.3		1979-12-31
29. IS : 5204—1969 Specification for research microscope	S.O. 4848 dated 1969-12-06	No. 1 Dec 1979	(i) Clause 4.6 has been substituted by a new one. (ii) (Page 7, clause 4.9.1.1, line 2)—Substitute '0.01 mm' for '0.001 mm'. (Page 7, Table 1, third column 'Glass Type')—Delete.		1979-12-31
30. IS : 5920—1970 Recommendations for the preparation of drawings for optical elements and systems	S.O. 1555 dated 1974-06-24	No. 1 Jan 1980	(i) Note under clause 4.1 has been substituted by a new one. (ii) Clause 4.1 has been substituted by a new one. (iii) (Page 5, clause 4.4.3)—Delete. (iv) Clause 9.1, 9.3 and 9.3.1.1 have been amended. (v) Foot notes with '†' and '§' marks at page 12 have been substituted by new ones. (vi) A new note has been added after clause 7.2.11.		1980-01-31
31. IS : 6234—1971 Specification for portable fire extinguishers, water type (constant air pressure)	S.O. 1549 dated 1973-06-02	No. 4 Jan 1980	Clause 4.2 has been amended		1980-01-31
32. IS : 6425—1971 Specification for dioptrimeter (lensometer)	S.O. 751 dated 1974-03-16	No. 1 Jan 1980	(i) Table 1 and 3 have been amended (ii) (Page 7, clauses 7.1, 7.1.1, 7.1.2 and 7.2)—Substitute the following for the existing clauses : "7.1 The sampling plan, number of test specimens and criteria for conformity shall be as given 7 and 8 of IS : 7777—1975" (iii) Foot notes with '†', '+' and '§' marks have been substituted by a new one.		1980-01-31
33. IS : 6488—1975 Specification for cotton webbing for personal web equipment (First Revision)	S.O. 2240 dated 1978-08-05	No. 1 Jan 1980	Clause 5.1 has been amended		1979-12-31
34. IS : 6638—1972 Specification for tractor-mounted spring-loaded cultivators	S.O. 770 dated 1975-03-08	No. 3 Dec 1979	Table 1 has been substituted by a new one		1979-12-31
35. IS : 7056—1973 Specification for cotton huckaback towels	S.O. 2939 dated 1975-09-06	No. 2 Dec 1969	Table 1 and 2 have been amended		1979-12-31
36. IS : 7777—1975 Specification for Cotton webbing, rolled, edges	S.O. 3351 dated 1978-11-25	No. 2 Dec 1979	(i) Clause 2.1 has been substituted by a new one (ii) (Page 5, clause 5.4, line 3)—Delete the words shall be given as even finish'. (iii) (Page 9, clause 6.6.2.1, line 1)—Substitute 'shall' for 'will'.		1979-12-31
37. IS : 8081—1976 Specification for slotted sections	S.O. 3820 dated 1979-11-24	No. 1 Dec 1979	Tables 8 and 9 have been amended.		1980-01-31
38. IS : 8130—1976 Specification for conductors for insulated electric cables and flexible cords	S.O. 99 dated 1980-01-12	No. 1 Jan 1980	(i) Clauses 1 and 3 have been substituted by new ones (ii) (Page 1, Clause 4.1)—Delete and renumber subsequent clauses accordingly. (iii) (Page 3, table 2)—Delete. (iv) Clauses 5 and 6 have been amended. (v) Table 1 has been amended (Page 6, table 1, note)—Delete.		1980-02-29
39. IS : 8308—1976 Specification for compression Type tubular in-line connectors for aluminium conductors for insulated cables	S.O. 419 dated 1980-02-23	No. 1 Feb 1980	(Page 1, clause 1, line 1)—Substitute 'ac-rimal' for 'corneal'.		1980-01-31
40. IS : 8438—1977 Specification for moulds for cast resin based at eight through joints for cables for voltages up to and including 1100 volts	S.O. 618 dated 1980-03-15	No. 1 Dec 1979	Table 1 has been amended		1979-12-31
41. IS : 8810—1978 Specification for rouging for lacrimal SAC. Collet's pattern	—	No. 1 Jan 1980			
42. IS : 8914—1978 Quality tolerances for water for vitreous enamel industry	—	No. 1 Dec 1979			

Copies of these amendments are available with the Indian Standards Institution, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and also from its branch offices at Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Hyderabad, Jaipur, Kathpur, Madras, Patna and Tiruvandur.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1982

का० आ० 206.—भारतीय मानक संस्था की ओर से एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि स्त० 2 और 3 में दी गई विभिन्न उत्पादों से संबंधी मुहर लगाने का शर्त स्त० 4 और 5 में उल्लेख के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है। मुहर लगाने का पुनरीक्षित मूलक दिनांक 1982-02-01 से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम सं०	उत्पाद	भारतीय मानक संख्या	इकाई	प्रति इकाई मुहर लगाने की कीमत	भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड 3 डाकू (2) में 2 का संदर्भ		
					अधिकृत एन ओ संख्या	सांख्यिक संशोधन एन ओ संख्या	जारी होने का तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बीएचसी (एचसीएच) धूलन चूर्ण	IS 561-1978	एक मीटर टन	रु० 3.00	--	1231 1973-04-30	1975-04-19
2.	बीएचसी (एचसीएच) जल विमर्जनीय सान्द्र चूर्ण	IS 562-1978	एक मीटर टन	रु० 10.00	--	--	--
3.	डीटीटी धूलन चूर्ण	IS 564-1975	एक मीटर टन	रु० 3.00	2326 1963-07-17	--	1962-07-28
4.	डीटीटी जल विमर्जनीय सान्द्र चूर्ण	IS 565-1975	एक मीटर टन	रु० 10.00	117 1963-02-01	--	1963-02-09
5.	गामा बीएचसी (लिटेन) पायसनीय सान्द्र	IS 632-1978	100 लिटर	रु० 20.00	--	1231 1975-04-03	1975-04-19
6.	डीटीटी पायसनीय सान्द्र	IS 633-1975	100 लिटर	रु० 15.00	1232 1975-04-03	--	1975-04-19
7.	इथाइलिन डाइक्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड मिश्रण	IS 634-1965	100 लिटर	रु० 15.00	--	831 1977-02-24	1977-03-19
8.	फोटाफ्लोराणी तरल पदार्थ	IS 1061-1978	एक किलो लिटर	रु० 10.00	1232 1975-04-03	--	--
9.	एल्ट्रिन पायसनीय सान्द्र	IS 1307-1973	100 लिटर	रु० 15.00	--	1231 1975-04-03	1975-04-19
10.	एल्ट्रिन धूलन, चूर्ण	IS 1308-1974	एक मीटर टन	रु० 5.00	--	--	--
11.	साम्रा आक्सीक्लोराइड धूलन चूर्ण	IS 1506-1977	एक मीटर टन	रु० 5.00	685 1976-01-21	--	1976-02-14
12.	साम्रा आक्सीक्लोराइड जल विमर्जनीय पायसनीय सान्द्र	IS 1507-1977	एक मीटर टन	रु० 10.00	30 1960-12-26	--	1976-01-17
13.	स्थिरकृत मेथाक्सी इथाइल पाराक्लोराइड सान्द्र से बने यौगिक पदार्थ	IS 2358-1963	100 किलोग्राम	रु० 5.00	--	1231 1975-04-03	1975-04-19
14.	मालथियोन पायसनीय सान्द्र	IS 2567-1978	100 लिटर	रु० 15.00	1232 1975-04-03	--	--
15.	मालथियोन धूलन चूर्ण	IS 2568-1978	एक मीटर टन	रु० 15.00	--	--	--
16.	मालथियोन जल विमर्जनीय सान्द्र चूर्ण	IS 2569-1978	एक मीटर टन	(1) रु० 15.00 पहली 1000 इकाइयों के लिए (2) रु० 10.00 अगली 1001 वीं 2000 तक की इकाइयों के लिए (3) रु० 2.00 शेष 2001 वीं से आगे की इकाइयों के लिए	3267 1967-09-01	--	1967-09-16
17.	क्लोरोडिन पायसनीय सान्द्र	IS 2682-1968	100 लिटर	रु० 15.00	1232 1975-04-30	--	1975-04-19

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18. कार्बाजिनान पायसनीय सान्द्र	IS : 2861-1980	100 लिटर	रु० 15.00	---	1231	1975-04-19	
					1975-04-30		
19. कार्बोमेडेट धूलन पूर्ण	IS : 2864-1973	एक मीटर टन	रु० 15.00 पहली	1232	---	---	
				1975-04-03			
20. मिथाइल पैराथियान, पायसनीय सान्द्र	IS : 2865-1978	100 लिटर	(1) रु० 15.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 10.00 अगली 501वीं से 1500 तक की इकाइयों के लिए (3) रु० 2.00 शेष 1501वीं और इसमें आने वाली इकाइयों के लिए	592	---	1979-04-17	
				1979-09-31			
21. बीजों में लगाने का शुष्क पारा यौगिक	IS : 3284-1965	100 किलोग्राम	रु० 3.00	1232	---	1975-04-19	
				1975-04-03			
22. डिनेत्र, जल विघर्षीय पूर्ण	IS : 3898-1966	एक मीटर टन	रु० 10.00	1713	---	1968-05-18	
				1968-05-01			
23. जोथाम, जल विघर्षीय पूर्ण	IS : 3901-1975	एक मीटर टन	रु० 10.00	---	1231	1975-04-19	
					1975-04-03		
24. डाइमिथोफेट, पायसनीय सान्द्र	IS : 3903-1975	100 लिटर	रु० 10.00	---	---	---	
25. थायमेटोन, पायसनीय सान्द्र	IS : 3905-1966	100 लिटर	रु० 15.00	4701	---	1975-11-01	
				1975-09-23			
26. एंडोसल्फेन, धूलन पूर्ण	IS : 4322-1967	एक मीटर टन	रु० 5.00	---	1231	1975-04-19	
					1975-04-03		
27. एंडोसल्फेन पायसनीय सान्द्र	IS : 4323-1980	100 लिटर	(1) रु० 15.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 10.00 अगली 1500 इकाइयों के लिए (3) रु० 2.00 शेष इकाइयों के लिए	1389	---	1979-04-21	
				1979-04-09			
28. धिराम जल विघर्षीय पूर्ण	IS : 4766-1968	एक मीटर टन	रु० 10.00	1232	---	1975-04-19	
				1975-05-03			
29. बीजों में लगाने का धिराम यौगिक पदार्थ	IS : 4783-1968	100 किलोग्राम	रु० 10.00	---	---	---	
30. पायरेथ्रस पायसनीय सान्द्र	IS : 4808-1968	100 लिटर	रु० 15.00	---	4502	1976-11-27	
					1976-11-05		
31. डायक्लोरोबोस, पायसनीय सान्द्र	IS : 5277-1978	100 लिटर	(1) रु० 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 5.00 अगली 1500 इकाइयों के लिए (3) रु० 2.00 शेष इकाइयों के लिए	2136	---	1974-09-31	
				1974-08-30			
32. डायक्लोबोस, पायसनीय सान्द्र	IS : 5279-1969	100 लिटर	रु० 15.00	---	4503	1976-11-27	
					1976-11-05		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33. फ़ैनीट्रायिवाल, पायसनीय सांद्र	IS : 5281--1974	100 लिटर	(1) रु० 15.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 10.00 अगली 1500 इकाइयों के लिए, (3) रु० 2.00 शेष इकाइयों के लिए	592 1979-01-31	--	1079-02-17	
34. पायरेथ्र से बना पायसनीय लाबिसाइडल सेल	IS : 6014--1978	100 लिटर	रु० 10.00	-- 1980-02-25	616	1980-04-15	
35. कास्कोमिडन जल धुलनशील सांद्र	IS : 6177--1981	100 लीटर	(1) रु० 15.00 पहली 100 इकाइयों के, लिए, (2) रु० 10.00 अगली 600 इकाइयों के लिए	1659 1981-05-14	--	1981-06-16	
36. हैप्टाक्लोर, धूलन चूर्ण	IS : 6429--1972	एक मीटरी टन	रु० 15.00	1691 1975-09-19	--	1975-11-01	
37. एलुमिनियम कास्केट में बनी टीकिया	IS : 6438--1980	एक मीटरी टन	रु० 15.00	-- 1975-04-03	12.31	1975-04-19	
38. हैप्टाक्लोर, पायसनीय सांद्र	IS : 6439--1978	100 लीटर	रु० 20.00	953 1975-03-18	--	1975-04-29	
39. कार्बाराइल जल विसर्जनीय सांद्र चूर्ण	IS : 7121--1973	एक मीटरी टन	(1) रु० 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, (2) रु० 5.00 अगली 1000 इकाइयों के लिए, (3) रु० 2.00 शेष इकाइयों के लिए	2929 1974-10-21	--	1974-11-09	
40. कार्बाराइल, धूलन चूर्ण	IS : 7122--1973	एक मीटरी टन	(1) रु० 2.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 1.00 अगली 1000 इकाइयों के लिए, (3) रु० 0.50 शेष इकाइयों के लिए	2929 1974-10-21	--	1974-11-09	
41. टाक्साफीन, पायसनीय सांद्र	IS : 7946--1976	100 लीटर	रु० 15.00	-- 1977-12-27	16	1978-01-14	
42. टाक्साफेन, धूलन चूर्ण	IS : 7947--1976	एक मीटर टन	रु० 10.00	2880 1978-09-14	--	1978-09-30	
43. क्वीनोसफोम, पायसनीय सांद्र	IS : 8029--1976	100 लीटर	(1) रु० 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, (2) रु० 5.00 अगली 1500 इकाइयों के लिए, और (3) रु० 2.00 शेष इकाइयों के लिए	-- 1977-08-02	2610	1977-08-20	

44. मोनो कंट्रोफास जल धूलनशील सांद्र	IS : 8074—1976	100 लीटर	(1) रु० 20.00 पहली 100 इकाइयों के लिए, (2) रु० 10.00 अगली 600 इकाइयों के लिए और (3) रु० 2.00 शेष इकाइयों के लिए	—	1977 1980-07-09	1980-07-26
45. ब्राक्मीडिमेटोन, मिथाइल, पायसनीय सांद्र	IS : 8259—1976	100 लीटर	रु० 20.00	1523 1979-04-27	—	1979-05-12
46. फेथोएट, पायसनीय सांद्र	IS : 8291—1976	100 लीटर	(1) रु० 15.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, और (2) रु० 5.00 शेष इकाइयों के लिए	—	313 1978-01-13	1978-02-04
47. कार्बेन्डिजिम, जल विघर्नीय सांद्र चूर्ण	IS : 8446—1977	100 किलो ग्राम	(1) रु० 20.00 पहली 250 इकाइयों के लिए, (2) रु० 10.00 अगली 500 इकाइयों के लिए और (3) रु० 3.00 शेष इकाइयों के लिए	—	3415 1980-11-21	1980-12-13
48. फोसालोन, पायसनीय सांद्र	IS : 8487—1977	100 लीटर	(1) रु० 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, (2) रु० 5.00 अगली 1500 इकाइयों के लिए, और (3) रु० 2.00 शेष इकाइयों के लिए	3056 1978-09-29	—	1978-10-21
49. फोसालोन, धूलन चूर्ण	IS : 8489—1977	एक मोटरी	(1) रु० 10.00 पहली 500 इकाइयों के लिए, (2) रु० 3.00 शेष इकाइयों के लिए	2352 1978-07-31	—	1978-08-19
50. पेराक्वेट डाइमोरोडाइड सांद्र घोल	IS : 8497—1977	100 लिटर	(1) रु० 15.00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 10.00 अगली 1500 इकाइयों के लिए, और (3) रु० 2.00 शेष इकाइयों के लिए	—	621 1981-01-27	1981-02-21
51. क्लोरापायरीफोस पायसनीय सांद्र	IS : 8944—1978	100 लिटर	रु० 20.00	1391 1979-04-11	—	1979-04-28
52. एडिफेनफास, पायसनीय सांद्र	IS : 8955—1978	100 लीटर	रु० 20.00	—	—	—
53. क्लूक्लोरासिन, पायसनीय सांद्र	IS : 8959—1978	100 लीटर	रु० 15.00	—	3415 1980-11-21	1980-12-13
54. मिथाइल पैराथियोन धूलन चूर्ण	IS : 8960—1978	एक मोटरी टन	रु० 3.00	—	2461 1981-03-19	1981-03-19
55. थूटाक्लोरा, पायसनीय सांद्र	IS : 9356—1980	100 लीटर	रु० 15.00	—	—	—

New Delhi, the 15 December, 1982

S.O. 206.—The Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 2 and 3 of the following Schedule have been revised as mentioned in Col. 4 and 5 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from 1982-02-01 :

SCHEDULE

Sl. No.	Product	IS : No.	Unit	Marking Fee per Unit	Reference to Govt. of India Gazette Notification Part-II, Sub-section (ii)		
					Superseded S.O. No.	Partially Modified S.O. No.	Date of Issue
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	BHC (HCH) dusting powders.	IS : 561—1978	One Tonne	Rs. 3.00	—	1231 1975-04-03	1975-04-19
2.	BHC (HCH) water dispersible powder concentrates.	IS : 562—1978	One Tonne	Rs. 10.00	—	1231 1975-04-03	1975-04-19
3.	DDT dusting powders	IS : 564—1975	One Tonne	Rs. 3.00	2326 1962-07-17	—	1962-07-28
4.	DDT water dispersible powder concentrates.	IS : 565—1975	One Tonne	Rs. 10.00	417 1963-02-01	—	1963-02-09
5.	Gamma BHC (indane) EC.	IS : 632—1978	100 Litres	Rs. 20.00	—	1231 1975-04-03	1975-04-19
6.	DDT emulsifiable concentrates	IS : 633—1975	100 Litres	Rs. 15.00	1232 1975-04-03	—	1975-04-19
7.	Ethylene dichloride-carbon tetrachloride mixture.	IS : 634—1965	100 Litres	Rs. 15.00	—	831 1977-02-24	1977-03-19
8.	Disinfectant fluids	IS : 1061—1975	One Kilo-litre	Rs. 10.00	1232 1975-04-03	—	1975-04-19
9.	Aldrin EC	IS : 1307—1973	100 Litres	Rs. 15.00	—	1231 1975-04-03	1975-04-19
10.	Aldrin, DP	IS : 1308—1974	One Tonne	Rs. 5.00	—	-do-	-do-
11.	Copper oxychloride, DP	IS : 1506—1977	One Tonne	Rs. 5.00	685 1976-01-21	—	1976-02-14
12.	Copper oxychloride, WDPC	IS : 1507—1977	One Tonne	Rs. 10.00	30 1960-12-26	—	1961-01-07
13.	Formulation based on stabilized methoxy ethyl-mercury chloride concentrates.	IS : 2358—1963	100 kg	Rs. 5.00	—	1231 1975-04-03	1975-04-19
14.	Malathion, EC	IS : 2567—1978	100 Litre	Rs. 15.00	1232 1975-04-03	—	-do-
15.	Malathion, DP	IS : 2568—1978	One Tonne	Rs. 15.00	-do-	—	-do-
16.	Malathion, WDPC	IS : 2569—1978	One Tonne	(i) Rs. 15.00 per unit for the first 1000 units (ii) Rs. 10.00 per unit for the 1001st to 2000 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 2001st unit and above.	3267 1967-09-01	—	1967-09-16
17.	Chloradane, EC	IS : 2682—1966	100 Litres	Rs. 15.00	1232 1975-04-03	—	1975-04-19
18.	Diazinon, EC	IS : 2861—1980	100 Litres	Rs. 15.00	—	1231 1975-04-03	-do-
19.	Chloradane, DP	IS : 2864—1973	One Tonne	Rs. 15.00	1232 1975-04-03	—	-do-
20.	Methyl parathion, EC	IS : 2965—1978	100 Litres	(i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units; (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above.	592 1979-01-31	—	1979-02-17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21. Organo mercurial dry seed-dressing formulations.	IS : 3284—1965	100 kg	Rs. 3 00		1232 1975-04-03	—	1975-04-19
22. Zinc water dispersible powder.	IS : 3899—1966	One tonne	Rs 10.00		1718 1968-05-01	—	1968-05-18
23. Ziram, water dispersible powder.	IS : 3901—1975	One Tonne	Rs. 10.00		—	1231 1975-04-03	1975-04-19
24. Dimethoate, EC	IS : 3903—1975	100 Litres	Rs. 10.00		—	-do-	-do-
25. Thiometon, EC	IS : 3905—1966	100 Litres	Rs. 15 00		4702 1975-09-03	—	1975-11-01
26. Endosulfan, DP	IS : 4322—1967	One tonne	Rs. 5 00		—	1231 1975-04-03	1975-04-19
27. Endosulfan, EC	IS : 4323—1980	100 Litres	(i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above.		1389 1979-04-09	—	1979-04-21
28. Thiram water dispersible powder.	IS : 4766—1968	One Tonne	Rs. 10.00		1232 1975-04-03	—	1975-04-19
29. Thiram seed dressing formulations.	IS : 4783—1968	100 kg	Rs. 10.00		-do-	—	-do-
30. Pyrethrum, EC	IS : 4808—1968	100 Litres	Rs. 15.00		—	4502 1976-11-05	1976-11-27
31. Dichlorovos, EC	IS : 5277—1978	100 Litres	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above.		2436 1975-08-30	—	1974-09-21
32. Dicofol, EC	IS : 5279—1969	100 Litres	Rs. 15.00		—	4503 1976-11-05	1976-11-27
33. Fenitrothion, EC	IS : 5281—1979	100 Litres	(i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above.		592 1979-01-31	—	1979-02-17
34. Emulsifiable larvicidal oil, pyrethrum based.	IS : 6014—1978	100 Litres	Rs. 10.00		—	616 1980-02-25	1980-03-15
35. Phosphamidon water soluble concentrates.	IS : 6177—1981	100 Litres	(i) Rs. 15.00 per unit for the first 100 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 101st unit to 600 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 601st unit and above.		1659 1981-05-14	—	1981-06-06
36. Heptachlor, DP	IS : 6429—1972	One Tonne	Rs. 15.00		4694 1975-09-19	—	1975-11-01
37. Aluminium phosphate tablet formulation.	IS : 6438—1980	One Tonne	Rs. 15.00		—	1231 1975-04-03	1975-04-19
38. Heptachlor, EC	IS : 6439—1978	100 Litre	Rs. 20.00		953 1975-03-18	—	1975-03-29
39. Carbaryl, WDPC	IS : 7121—1973	One Tonne	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1000 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1001st unit and above.		2929 1974-10-21	—	1974-11-09
40. Carbaryl, DP	IS : 122—1973	One Tonne	(i) Rs. 2.00 per unit for the first 5000 units; (ii) Rs. 1.00 per unit for the 5001st to 10000 units; and (iii) Rs. 50 Paise per unit for the 10001st unit and above		2929 1974-10-21	—	1974-11-09

1	2	3	4	5	6	7	8
41. Toxaphene, EC	IS : 7945—1976	100 Litres	Rs. 15.00	—	76	1977-12-27	1978-01-14
42. Toxaphene, DP	IS : 7947—1976	One Tonne	Rs. 10.00	2880 1978-09-14	—	—	1978-09-30
43. Quinalphos, EC	IS : 8018—1976	100 Litres	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above	—	2610	1977-08-02	1987-08-20
44. Monocrotophos water soluble concentrates	IS : 8074—1976	100 Litres	(i) Rs. 20.00 per unit for the first 100 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 101st to 600 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 601st unit and above	—	1997 1980-07-09	—	1980-07-26
45. Oxydemeton-methyl, EC	IS : 8259—1976	100 Litres	Rs. 20.00	1523 1979-04-27	—	—	1979-05-12
46. Phenthoate, EC	IS : 8291—1976	100 Litres	(i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; and (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st unit and above	—	313 1978-01-13	—	1978-02-04
47. Carbandazim, WDPC	IS : 8446—1977	100 kg	(i) Rs. 20.00 per unit for the first 250 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 251st unit to 500 units; and (iii) Rs. 3.00 per unit for the 501st unit and above	—	3421.5 1980-11-21	—	1980-12-13
48. Phosalone, EC	IS : 8487—1977	100 Litres	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 5.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above	3056 1978-09-29	—	—	1978-10-21
49. Phosalone DP	IS : 8489—1977	One Tonne	(i) Rs. 10.00 per unit for the first 500 units; and (ii) Rs. 3.00 per unit for the 501st unit and above	2352 1978-07-31	—	—	1978-08-19
50. Paraquat dichloride salt aqueous solution	IS : 8497—1977	100 Litres	(i) Rs. 15.00 per unit for the first 500 units; (ii) Rs. 10.00 per unit for the 501st to 1500 units; and (iii) Rs. 2.00 per unit for the 1501st unit and above	—	621 1981-01-27	—	1981-02-21
51. Chlorpyrifos, EC	IS : 8944—1978	100 Litres	Rs. 20.00	1391 1979-04-11	—	—	1979-04-27
52. Edifenphos, EC	IS : 8955—1978	100 Litres	Rs. 20.00	—	—	—	—
53. Fluchloralin, EC	IS : 8959—1978	100 Litres	Rs. 15.00	—	3415 1980-11-21	—	1980-12-13
54. Methyl parathion, DP	IS : 8960—1978	One Tonne	Rs. 3.00	—	461 1981-08-19	—	1981-09-19
55. Biotachlor, EC	IS : 9356—1980	100 Litres	Rs. 15.00	—	—	—	—

[No. CMD/13 : 10]

प्रतिबद्धता

कॉ० जा० 202--भारतीय मानक समिति के प्रारंभ से पूर्व द्वारा अधिपुष्टि किया जाता है कि स्तम्भ 2 और 3 में दी गई विविध उत्पादों से सम्बन्धी सुहर लगाने का शुल्क स्तम्भ 4 और 5 में उत्पादों के अनुसार पुनर्निश्चित किया गया है। सुहर लगाने का पुनर्निश्चित शुल्क प्रत्येक के आगे दी गई दिशियों से लागू होगा।

अनुसूची

क्रम संख्या	उत्पाद	प्रत्येक मातक का की संख्या	इकाई	प्रति इकाई मूल्य लगाने का फार्म	एक व राजपत्र मा. 2 खंड 3 उपखंड (11) म म 2 का सदस्य	अधिकृत एम० या संख्या	आंशिक सशोधित जारी होने की एम० आ० तिथि संख्या	लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ए०सी०एम० घास के लिए इस्पात का कोर वाले तार	IS 398 (भा. 2) 1976	एक मीटर की टन	रु० 4 00 सभी टन	--	1125 1978-04-04	1979-04-22	1981-10-16
2	बूझ का पाउडर	IS 1165-1975	एक मीटर की टन	(1) रु० 12 00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 8 00 अगला 500 इकाइयों के लिए (3) रु० 5 00 शेष इकाइयों के लिए	312 1983-01-21	--	1963-02-02	1981-11-01
3	सघनित बूझ	IS 1166-1973	एक मीटर की टन	(1) 12 00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 8 00 अगला 500 इकाइयों के लिए (3) रु० 5 00 शेष इकाइयों के लिए	2724 1963-09-12	--	1963-09-21	1981-11-01
4	मिश्र के लिए दुग्ध अहार	IS 1547-1969	एक मीटर की टन	(1) रु० 12 00 पहली 500 इकाइयों के लिए (2) रु० 8 00 अगला 500 इकाइ- यों के लिए (3) रु० 5 00 शेष इकाइयों के लिए	311 1963-01-21	--	1963-02-02	1981-11-01
5	टेड्रजेंट, खाद्य खाद्य ग्रेड	IS 1693-1974	एक किलोग्राम	रु० 0 40 सभी	2573 1974-09-23	--	1974-10-25	1981-10-16
6	सूर्यास्त पीला एफ० सी एफ० खाद्य ग्रेड	IS 1695-1974	एक किलो ग्राम	रु० 0 10 सभी	--वही--	--	वही	वही
7	असंशोधित खाद्य	IS 1696-1974	एक किलोग्राम	रु० 0 10 सभी	वही	--	वही	वही
8	असंशोधित, खाद्य ग्रेड	IS 1697-1974	एक किलोग्राम	रु० 0 10 सभी	2584 1974-09-23	--	वही	वही

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9. इंडियो कार्माइन IS: 1698-1974] खाद्य ग्रेड	एक किलोग्राम	रु० 0.40 सभी	बही		--	बही	बही	
10 पांसें 4 आर० IS: 2558-1974 खाद्यग्रेड	एक किलोग्राम	रु० 0.40 सभी	बही		--	बही	बही	
11. ग्राइसकीम IS: 2802-1964	100 मिटर	(1) रु० 5.00 पहली 1000 इकाइयों के लिए (2) रु० 2.00 अगली 1000 इकाइयों के लिए (3) रु० 1.50 शेष इकाइयों के के लिए	122 1968-12-27		--	1969-01-11	1981-11-01	
12. काममोसाइन IS: 2923-1974 खाद्य ग्रेड	एक किलोग्राम	रु० 0.40 सभी	2583 1974-09-23		--	1974-10-05	1981-10-16	
13. पकना पाल ई IS: 2924-1974 खाद्य ग्रेड	एक मीटरी टन	रु० 0.40 सभी	--बही		--	बही	बही	
14. केबलो पर IS: 3975-1978 कवच बढ़ाने के लिए मृदु इस्पात के तार पट्टियां और टैप	एक मीटरी एक	रु० 2.50 सभी	-- 2241 1978-07-19		--	1978-08-05	1981-01-16	
15. चमकदार नीला IS: 8408-1977 एफ०सी०एफ० खाद्य ग्रेड	एक किलोग्राम	रु० 0.40 सभी	-- 3168 1980-10-24		--	1980-11-16	1981-10-16	
16. चुहगम और IS: 8747-1981 बबलगम	एक किलोग्राम	(1) रु० 0.10 50000 इकाइयों के लिए (2) रु० 0.75 150000 इकाइयों के लिए (3) रु० 0.50 शेष इकाइयों के लिए	-- 4391 1976-10-27		--	1976-11-20	1981-10-01	
17. छोटे साइज के IS: 7347-1974 चिपारी मल्ट : वाहीइजन की कार्यकारिता का निष्पादन	एक इंच	(1) 1.00 पहली 10000 इकाइयों के लिए (2) रु० 0.50 शेष इकाइयो के लिए	2452 1975-07-07		--	1975-08-02	1981-11-16	

[सं० सी० एम० डी०/13:10]

ए० पी० बनर्जी अपर महानिदेशक

S.O. 207.—The Indian Standards Institution, hereby, notifies that the marking fees pertaining to various products referred to in Col. 2 and 3 of the following Schedule have been revised as mentioned in Col 4 and 5 thereof. The revised rate of marking fees shall come into force with effect from the dates shown against each :
1085 GI/82—23.

SCHEDULE

Sl. No.	Product	IS : No.	Unit	Marking Fee per Unit	Reference to Govt. of India Gazette Notification-Part-II, Section-3, Sub-Section (ii)			Date of Effect
					Superseded S.O. No.	Partially modified S.O. No.	Date of Issue	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Steel core wire for ACSR	IS : 398 (Part II)—1976	One Tonne	Rs. 4.00 All	—	1125 1978-04-04	1978-04-22	1981-10-16
2.	Milk powder	IS : 1165—1975	One Tonne	(i) Rs. 12.00 First 500 (ii) Rs. 8.00 Next 500 (iii) Rs. 5.00 Remaining	312 1963-01-21	—	1963-02-02	1981-11-01
3.	Condensed milk	IS : 1166—1973	One Tonne	(i) Rs. 12.00 First 500 (ii) Rs. 8.00 Next 500 (iii) Rs. 5.00 Remaining	2724 1963-09-12	—	1963-09-21	1981-11-01
4.	Infant milk foods	IS : 1547—1968	One Tonne	(i) Rs. 12.00 First 500 (ii) Rs. 8.00 Next 500 (iii) Rs. 5.00 Remaining	311 1963-01-21	—	1963-02-02	1981-11-01
5.	Tartazine, food grade	IS : 1694—1974	One kg	Rs. 0.40 All	2579 1974-09-23	—	1974-10-25	1981-10-16
6.	Sunset yellow, FCF, food grade	IS : 1695—1974	One kg	Rs. 0.40 All	-do-	—	1974-10-25	1981-10-16
7.	Amaranth, food grade	IS : 1696—1974	One kg	Rs. 0.40 All	-do-	—	1974-10-25	1981-10-16
8.	Erythrosine, food grade	IS : 1697—1974	One kg	Rs. 0.40 All	2583 1974-09-23	—	1974-10-25	1981-10-16
9.	Indigo carmine, food grade	IS : 1698—1974	One kg	Rs. 0.40 All	-do-	—	1974-10-25	1981-10-16
10.	Ponceau 4 R, food grade	IS : 2558—1974	One kg.	Rs. 0.40 All	-do-	—	1974-10-25	1981-10-16
11.	Ice-cream	IS : 2802—1964	100 Litres	(i) Rs. 5.00 First 1000 (ii) Rs. 2.00 Next 1000 (iii) Rs. 1.50 Remaining	1224 1968-12-27	—	1969-01-11	1981-11-01
12.	Carmoisine, food grade	IS : 2923—1974	One kg	Rs. 0.40 All	2583 1974-09-23	—	1974-10-05	1981-10-16
13.	Fast red E, food grade	IS : 2924—1974	One kg	Rs. 0.40 All	-do-	—	1974-10-05	1981-10-16
14.	Mild steel wires, strips and tapes for armouring of cables	IS : 3975—1979	One Tonne	Rs. 2.50 All	—	2241 1978-07-19	1978-08-05	1981-10-16
15.	Brilliant blue, FCF, food grade	IS : 6406—1977	One kg	Rs. 0.40 All	—	3168 1980-10-24	1980-11-15	1981-10-16
16.	Chewing gum and bubble gum	IS : 6747—1981	One kg.	(i) Rs. 0.10 First 50000 (ii) Rs. 0.75 next 150000 (iii) Rs. 0.05 Remaining	—	4391 1976-10-27	1976-11-01	1981-10-01
17.	Performance of small size spark	IS : 7347—1974	One Engine	(i) Rs. 1.00 First 10000 (ii) Rs. 0.50 Remaining	2452 1925-07-07	—	1975-08-02	1981-11-01

[No. CMD/13 : 10]

A.P. BANERJEE, Additional Director General

ऊर्जा मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1982

का० प्रा० 208.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सी टी एफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्राबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

बतर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करना कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विरमगाम से सी टी एफ कलोल तक पाईपलाइन बिछाने के लिए
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	ए आर ह	सेंटी- अर
वलवादी	कार्टट्रैक	0	00	75
	211	0	35	85
	209	0	27	75
	248	0	11	70
	कार्टट्रैक	0	04	20
	219		14	25
	222	0	09	60
	220	0	29	55
	221	0	13	20
	कार्टट्रैक	0	00	60

[सं० ओ-12016/62/82-प्र०]

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 6th December, 1982

S.O. 208.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra, (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol
State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec- tare	Arc Centiare
Valavadi	Cart Track	0	00 75
	211	0	35 85
	209	0	27 75
	248	0	11 70
	Cart Track	0	04 20
	219	0	14 25
	222	0	09 60
	220	0	29 55
	221	0	13 20
	Cart Track	0	00 60

[INo. O-12016/62/82-Prod.]

का० प्रा० 209.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सी टी एफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्प्राबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है;

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाईप लाईन बिछाने के लिए

राज्य-गुजरात जिला-मेहसाणा तालुका-कड़ी

गांव	सर्वे न०	हेक्टर	आर	सेंटीयर
इश्वरपुरा	41	0	28	20

[सं० 0-12016/63/82-प्रो०]

S.O. 209.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority. Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodra (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec- tare	Ar a	Centi- square
Ishwarpura	41	0	28	20

[No. O-12016/63/82-Prod.]

का० आ० 210.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सी टी एफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्त कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाईप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाणा	तालुका-कड़ी
गांव	सर्वे न०	हेक्टर आर सेन्टीयर
बिनामकपुरा	46	0 07 80
	47	0 01 80
	45	0 24 90
	42	0 10 95
	41	0 07 80
	40	0 07 50
	38	0 09 00
	39	0 00 60
	25	0 04 05
	27	0 24 75
	32	0 02 00
	28	0 04 00
	29	0 08 25
	30	0 20 25
	19	0 09 45

[सं० 0-12016/59/82-प्रो०]

S.O. 210.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kadi

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centi- tiare
Vinayakpura	46	0	07	80
	47	0	01	80
	45	0	24	90
	42	0	10	95
	41	0	07	80
	40	0	07	50
	38	0	09	00
	39	0	00	60
	25	0	04	05
	27	0	24	75
	32	0	02	00
	28	0	04	00
	29	0	08	25
	30	0	20	25
	19	0	09	45

[No. 0-12016/59/82-Prod.]

का० प्रा० 211 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एन०के०ए०एम० से जी०जी०एस० कम सी०टी०एफ० कड़ी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी साईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

अतः कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग,

मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

एन० के०ए०एम० से जी०जी०एस० कम सी०टी०एफ० कड़ी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य: गुजरात जिला: अहमदाबाद तालुका: विरमगाम

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीअर
बालसासन	280/1	0	05	40
	280/2	0	10	20
	264/1	0	18	60
	264/2	0	13	80
	265	0	09	60
	269	0	05	04
	268/3	0	06	84
	288/1	0	05	28
	249	0	20	28
	250/1	0	17	40

[सं० 0-12016/64/82-प्रोड०]

S.O. 211.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from NKAM to GGS Cum CTF Kadi in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline D.S. NKAM to GGS-Cum-CTF Kadi

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Survey No.	Hec- tare	Are	Centi- tiare
Balsasan	280/1	0	05	40
	280/2	0	10	20
	264/1	0	18	60
	264/2	0	13	80
	265	0	09	60
	269	0	05	04
	268/3	0	06	84
	268/1	0	05	28
	249	0	20	28
	250/1	0	17	40

[No. 0-12016/64/82-Prod.]

कां० 212 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सीटीएफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

वशत कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विरमगाम से सी०टी०एफ० कलोल तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : मेहसाना	तालुका : कडी		
गांव	सर्वे न०	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
कल्याणपुरा	233/2	0	21	65
	233/1	0	14	00
	234	0	03	20
	280	0	00	80
	279/2	0	31	80
	279/1	0	07	35
	277	0	15	75
कार्ट ट्रैक		0	02	25
	243	0	27	30
	273	0	22	20
	272	0	37	80
	261	0	06	75
	260	0	05	25
	259	0	02	25
	253/2	0	06	75
	254	0	04	50
	256	0	12	30

[सं० O-12016/60/82-प्रोड०]

S.O. 212.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL is Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009);

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viramgam to CTF Kalol

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Kalyanpura	233/2	0	21	65
	233/1	0	14	00
	234	0	03	20
	280	0	00	80
	279/2	0	31	80
	279/1	0	07	35
	277	0	15	75
	Cart Track	0	02	25
	243	0	27	30
	273	0	22	20
	272	0	37	80
	261	0	06	75
	260	0	05	25
	259	0	02	25
	253/2	0	06	75
	254	0	04	50
	256	0	12	30

[No. O-12016/60/82-Prod.]

कां० 213 :—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में विरमगाम से सीटीएफ कलोल तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख-भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

विरमगाम से सी०टी०एफ० कलोल तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : कडी

गांव	सर्वे नं०	हेक्टेयर	एंगरार्ड	सेन्टीअर
जेसंगपुरा	100	0	16	20
	99	0	13	60
	115	0	01	40
	103/2	0	07	35
	113	0	17	40
	112	0	08	10
	109	0	25	50
	107	0	36	30
	कार्ट ट्रैक	0	01	65
	187	0	01	20
	191	0	30	00
	190	0	00	15
	192	0	15	75
	193	0	12	00

[सं० 0-12016/61/82-प्रोड०]

S.O. 213.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Viramgam to CTF KALOL in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provident that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Viram-gam to CTF Kalol

State : Gujarat Distt. : Mehsana Taluka : Kadi

Village	Survey No.	Hec-tare	Are	Centiare
Jesangpura	100	0	16	20
	99	0	13	60
	115	0	01	40
	103/2	0	07	35
	113	0	17	40
	112	0	08	10
	109	0	25	50
	107	0	36	30
	Cart Track	0	01	65
	187	0	01	20
	191	0	30	00
	190	0	00	15
	192	0	15	75
	193	0	12	00

[No. 0-12016/61/82-Prod.]

का० आ० 214:—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित किया है।

वशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देख-भाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टता यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाइप लाइन
बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
मोटो कुमाद	158	0	05	85
	157	0	07	20

[सं० O-12016/56/82-प्रोड-I]

S.O. 214.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from C.T.F. KALOL to Viramgam in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from CTF Kalol to Viramgam

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Block No.	Hec-tare	Are	Centiare
Moti Kumad	158	0	05	85
	157	0	07	20

[No. O-12016/56/82-Prod. I]

का०आ० 215.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वाचक अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बसते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिश्चिततः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

सी०टी०एफ० कलोल से विरमगाम तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला : अहमदाबाद तालुका : विरमगाम

गांव	ब्लाक नं०	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
1	2	3	4	5
मानी कुमाद	105	0	51	15
	106	0	00	10
	107	0	15	30
	111	0	28	50
	112	0	04	35
काटें टूक		0	04	05
	100	0	25	20
	101	0	07	20
	99	0	25	65
	98	0	11	25
	81	0	16	65
	82	0	00	15
	83	0	00	75
	88	0	14	25
	90	0	31	95
	57	0	25	20
	58	0	36	45
	59	0	17	25
	52	0	09	30
	9	0	00	15
	51	0	10	35
	49	0	00	25
	50	0	11	45
	46	0	10	05
	47	0	10	35
	43	0	12	00
	42	0	10	80
	39	0	17	05
	38	0	05	80

1	2	3	4	5
	37	0	00	20
	36	0	03	00
	35	0	07	50
	34	0	08	40
	33	0	17	85
	32	0	08	40
	31	0	07	50
	30	0	07	50
	29	0	08	10
	28	0	02	55

[सं० O-12016/56/82-प्रोड]

S.O. 215.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from C.T.F. KALOL to Viramgam in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from CTF Kalol to Viramgam

State : Gujarat District : Ahmedabad Taluka : Viramgam

Village	Block No.	Hec- tars	Acre	Centi- tars
1	2	3	4	5
Nani Kumad	105	0	51	15
	106	0	00	10
	107	0	15	30
	111	0	28	50
	112	0	04	35
	Cart Track	0	04	05
	100	0	25	20
	101	0	07	20
	99	0	25	65
	98	0	11	25
	81	0	16	65
	82	0	00	15
	83	0	00	75
	88	0	14	25
	90	0	31	95
	57	0	25	20
	58	0	36	35
	49	0	17	25
	52	0	09	30

1	2	3	4	5
	9	0	00	15
	51	0	10	35
	49	0	00	25
	50	0	11	45
	46	0	10	05
	47	0	10	35
	43	0	12	00
	42	0	10	80
	39	0	17	05
	38	0	05	80
	37	0	00	20
	36	0	03	00
	35	0	07	50
	34	0	08	40
	33	0	17	85
	32	0	08	40
	31	0	07	50
	30	0	07	50
	29	0	08	10
	28	0	02	55

[No. O-12016/56/82-Prod.]

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1982

का०अ० 216.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में एस०एन०रोड से एस०एन०ए०ए०ए० तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन०एन०एन०एन०एन० में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाईन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बड़ोवरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एस०एन० जेड से एम०एन०ए०एच० तक पाइपलाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात जिला व तालुका : मेहसाणा

गांव	सं नं	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
संथाल	612/1	0	06	98
	605	0	15	72
	564	0	05	16
	565	0	13	08
	566	0	14	04
	437	0	05	16

[सं० O-12016/54/82-प्रोड०]

New Delhi, the 18th November, 1982

S.O. 216.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SNZ to SNAH in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara (390 009.)

And every person making such an objection shall also State specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from SNZ to SNAH

State : Gujarat District & Taluka : Mehsana.

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
Santhal	612/1	0	06	98
	605	0	15	72
	564	0	05	16
	565	0	13	08
	566	0	14	04
	437	0	05	16

[No. O-12016/54/82-Prod.]

का०प्रा० 217.—यन. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में ज एन एम से जे एन ए तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये

पाइपलाइन, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयाग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एन०एन०ए०एच० अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एन०एन०ए०एच० घोषित किया है ।

वर्तते कि उक्त भूमि में हितवांछ कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सूक्ष्म प्राधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयाग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकारपुरा रोड, वडादरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत

अनुसूची

जे०एन०एम० से जे०एन०ए० तक पाइपलाइन बिछाने के लिये राज्य : गुजरात जिला और तालुका : मेहसाणा

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	एअरई	सेन्टीयर
मिडोसना	125	0	14	40
	114	0	06	60
	112	0	04	80
	111	0	12	60
	108	0	00	50
	109	0	14	75
	102	0	10	80
	100	0	09	60

[सं० O-12016/53/82-प्रोड०]

S.O. 217.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from JNM to JNA in Gujarat State pipeline should be laid by the Oil and Natural Gas Commission ;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Oil and Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Makarpura Road Vadodara (390009.)

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from D.S. No. JNA to JNM

State : Gujarat

District & Taluka : Mehsana

Village	Block No	Hec- tare	Are	Centi- naire
Sidosan	125	0	14	40
	111	0	06	60
	112	0	04	80
	111	0	12	60
	103	0	00	50
	109	0	14	75
	102	0	10	80
	100	0	09	60

[No. O-12016/53/82-Prod.]

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 1982

क्रा० आ० 218.—ग० भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा जैसा कि तत्प्राप्त प्राप्ति में निर्दिष्ट किया गया है और पेट्रोलियम और गैसों अधिनियम (भूमि में उपयोग के अधिकार का अंजन) अधिनियम, 1962 के खण्ड 6 के उपखण्ड (i) के अन्तर्गत प्रमाणित किया गया है, गुजरात राज्य के रामोला तेल क्षेत्र में उक्त निर्दिष्ट भूमि में अधिनियम सं० ए० एच० एन० से अहमदाबाद-18 तक पेट्रोलियम परिवहन के लिए भूमि अधिनियम के अधिकार अंजन किये गये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस अधिनियम द्वारा उपर्युक्त नियम के खण्ड 7 के उपखण्ड (i) को प्रा० (1) के निर्दिष्ट कार्य दिनांक 28-2-82 से समाप्त कर दिया गया है।

अतः अब पेट्रोलियम अधिनियम (भूमि में उपयोग के अधिकार का अंजन) अधिनियम, 1963 के नियम-4 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारों, पेट्रोलियम उक्त निधि को कार्य समाप्त की निम्न अधिसूचना कर रहे हैं।

अनुसूची

ए० एच० एन० से अहमदाबाद 18 तक पाइप लाइन कार्य समाप्त

मंत्रालय का नाम	आव क्र०/आ०/नं०	भारत के राज पात्र में प्राप्ति की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
पेट्रोलियम			
स्वास्थ्य और हथौड़ा उर्वरक मंत्रालय	300	30-1-82	28-2-82

[सं० 12016/37/82-प्रोड]

एन० एन० गैस, निदेशक

New Delhi, the 23rd November, 1982

S.O. 218.—Whereas by the notification of Government of India as shown in the schedule appended hereto and issued under sub section (1) of section 6 of the Petroleum & Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in land) Act, 1962 the right of user has been acquired in the lands specified in the schedule appended thereto for the transport of petroleum from D.S. AHN to AHMEDABAD-18 in Ramol oil field in Gujarat State.

And whereas the Oil & Natural Gas Commission has terminated the operations referred to in clause (i) of sub section (1) of section 7 of the said Act on 28-2-82.

Now therefore under Rule 4 of the Petroleum Pipelines (Acquisition of right of user in land) Rules 1963, the Competent Authority hereby notifies the said date as the date of termination of operation to above.

SCHEDULE

TERMINATION OF OPERATION OF PIPELINE FORM D. S. AHN to AHMEDABAD-18

Name of Ministry	Villages	S.O. No.	Date of publication in the Gazette of India	Date of termination of operation
Petroleum, Chemicals & Fertilizer	Harbajan	300	30-1-82	28-2-82

[No. 12016/37/82-Prod.]

L. M. GOYAL, Director

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 1982

क्रा० आ० 219.—प्रौढि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 6 अक्टूबर 1977 की पवित्रता सं० एन० प्रो० 3363, का अधिकरण करने हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियुक्तियों

1. डा० एम० एन० मक्केना, निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौला, और
2. डा० (श्रीमती) ए० प्राहुजा, उपनिदेशक (चिकित्सा) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौला।

संपूर्ण भारत के लिए तैयार किए गए औषधि वर्गों के लिए सरकारी वित्तपोषण के रूप में करती है :—

1. सींग
2. इन्जेक्शन के प्रयोजनार्थ सोरस प्रोटीन्स का घोल
3. डीकैनि
4. टोक्सोन्स
5. एण्टोजेन्स

6. एण्टी टोकसीन्स
7. विसंक्रमित सर्जिकल लिगेचर और विसंक्रमित सर्जिकल स्क्रुचर
8. बैक्टीरिओफेजिज

[सं० एक्स० 11014/2/82-डी० एम० एस० एण्ड पी०
एफ० ए०]

जी० पंचापकेसन, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 16th December, 1982

S.O. 219.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S.O. 3363, dated the 6th October, 1977, the Central Government hereby appoints—

1. Dr. S. N. Saxena, Director, Central Research Institute, Kasauli; and
2. Dr. (Mrs.) S. Abuja, Deputy Director (Medical) Central Research Institute, Kasauli,

to be Government Analysts for the whole of India in respect of the following classes of drugs, namely :—

1. Sera
2. Solution of Serum proteins intended for injection.
3. Vaccines.
4. Toxins.
5. Antigens.
6. Antitoxins
7. Sterilized Surgical ligature and sterilized surgical suture.
8. Bacteriophages.

[No. X. 11014/2/82-DMS&PFA]
G. PANCHAPAKESAN, Under Secy.

विज्ञान और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1982

का०आ० 220—यतः निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में कुछ संशोधन, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दिल्ली की बृहद योजना में प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 10-7-1982 के नोटिस सं० एफ 20 (37)/80-एम०पी० द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उपधारा (3) में अपेक्षित आपत्ति/सुझाव इस नोटिस का तारीख से 30 दिन की अवधि के अन्तर्गत आमंत्रित किए गए थे।

और यतः उक्त संशोधनों के बारे में कोई आपत्ति और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली की बृहद योजना में संशोधन करने का निर्णय किया गया है।

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 11 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दिल्ली की बृहद योजना में निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः— संशोधन

1. "लगभग 210.43 हैक्टर (52 एकड़) भूमि जो नरेला टाउन के समीप स्थित है और ग्रामाला जाने वाली रेलवे लाइन के पश्चिम में पड़ती है, का भूमि उपयोग 'कृषि हरित पट्टी' से बदल कर व्यवसायिक (गोदाम एवं भण्डारण डिपो) किया जाता है।"
2. "लगभग 21.043 हैक्टर (52 एकड़) भूमि, जो घेवरा गांव के समीप स्थित है और रोहताक जाने वाली रेलवे लाइन के उत्तर में पड़ती है, का भूमि उपयोग 'कृषि हरित पट्टी' से बदल कर व्यवसायिक (गोदाम एवं भण्डारण डिपो) किया जाता है।"

[सं० के० 13011/4/81-डी०डी०-II ए]
वी०वी० रामनाथन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 8th December, 1982

S.O. 220.—Whereas certain modifications, which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi regarding the areas mentioned hereunder, were published with Notice No. F. 20(37)/80-MP dated the 10th July, 1982 in accordance with the provisions of section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions, as required by sub-section (3) of section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice ;

And whereas no objections and suggestions have been received with regard to the said modifications, the Central Government have decided to modify the Master Plan for Delhi ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this modification in the Gazette of India, namely :—

MODIFICATION :

- (i) "The land use of an area measuring about 21.043 hectares. (52 acres) located near Narela Town and situated on the west of Railway line to Ambala is changed from 'Agricultural Green Belt' to 'Commercial (Warehousing and storage depots).'"
- (ii) "The land use of an area measuring about 21.043 hectares. (52 acres) located near Village Ghevra and situated on the North of Railway line to Rohiak is changed from 'Agricultural Green Belt' to 'Commercial (Warehousing and storage depots).'"

[No. K-13011/4/81-DDIIA]
V. V. RAMANATHAN, Desk Officer

संपदा निवेशालय

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 1982

का०आ० 221—केन्द्रीय सरकार, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय तथा निर्माण, आवास और शहरी विकास मंत्रालय (निर्माण आवास और शहरी विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 3911 तारीख 17 दिसम्बर, 1969 का निम्नलिखित संशोधन करना है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में संलग्न मारगों के स्तंभ (1) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी

“उपनिदेशक (प्रशासन)

स्वातन्त्रता आयुर्विज्ञान

शिक्षा और अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़।”

[फा० सं० 12013(6)/78 वल्यूम II]

आर०एस० सूद, उपनिदेशक

(Directorate of Estate)

New Delhi, the 27th November, 1982

S.O. 221.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 (No. 40 of 1971), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development (Department of Works and Housing and Urban Development) No. S.O. 3911 dated the 17th September 1969, namely :—

In the Table appended to the said Notification for the entry in column (I) the following entry shall be substituted “Deputy Director (Administration) Postgraduates Institute of Medical Education and Research, Chandigarh.”

[F. No. 12013(6)/78-Vol. II]

R. S. SOOD, Dy. Secy. Estates

दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी 1983

का०आ० 222.—बंगला साहिब राड क्षेत्र के पुनर्विकास प्रारूप को प्रकाशित कराने एवं तैयार किये जाने हेतु दिल्ली विकास अधिनियम 1957 (1957 की संख्या 61) की धारा-10(1) जिसे दिल्ली विकास नियम, 1959 (मुख्य योजना तथा क्षेत्रीय विभाग योजना) के नियम 5 तथा 15 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत नोटिस।

1. (ए) बंगला साहिब राड क्षेत्र के पुनर्विकास का एक प्रारूप तैयार किया गया है तथा

(बी) उक्त प्रारूप की एक प्रति नीचे लिखे कार्यालयों में शनिवार को छोड़कर सभी कार्यशील दिनों में 11.00 बजे (पूर्वा०) से 3.00 बजे (अपरान्ह) तक और नीचे पैरा-3 में दी गई तिथि तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगी।

- (1) दिल्ली विकास प्राधिकरण कार्यालय-विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली।
- (2) नई दिल्ली नगर पालिका कार्यालय, टाउन हाल, नई दिल्ली।
- (3) दिल्ली नगर निगम कार्यालय, टाउन हाल, नई दिल्ली।
- (4) कार्यकारी अधिकारी कार्यालय, दिल्ली केन्ट बोर्ड, दिल्ली केन्ट-10

2. बंगला साहिब राड क्षेत्र के पुनर्विकास प्रारूप के संबंध में एतद्वारा आपत्ति या सुझाव आमन्त्रित किये जाते हैं।

3. आपत्ति या सुझाव दिनांक 30-1-1983 तक सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली विकास मीनार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली के पास लिखित रूप में भेजे जायें।

4. जो व्यक्ति अपनी आपत्ति या सुझाव दे, वह अपना नाम एवं पता लिखें।

[स० एक 16(46)/80-एम०पी०]

नाथूराम, सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 1st January, 1983

S.O. 222 —Notice under Section 10(1) of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with rules 5 and 15 of the Delhi Development (Master Plan and Zonal Development Plan) Rules, 1959, of the preparation and publication of the draft Redevelopment of Bangla Sahib Road Area.

1. (a) a draft of the Redevelopment of Bangla Sahib Road Area has been prepared; and

(b) a copy thereof will be available for inspection at the following offices between the hours of 11.00 a.m. and 3 p.m. on all working days except Saturdays, till the date mentioned in para 3 hereafter.

(i) Office of the Delhi Development Authority Delhi Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi.

(ii) Office of the N.D.M.C., Town Hall, New Delhi

(iii) Office of the M.C.D. Town Hall, Delhi.

(iv) Office of the Executive Officer, Delhi Cantt Board, Delhi Cantt-10.

2. Objections and suggestions are hereby invited with respect to the draft Redevelopment of Bangla Sahib Road Area.

3. The objection or suggestion may be sent in writing to the Secretary, Delhi Development Authority, Delhi Vikas Minar, I. P. Estate, New Delhi by the 30th January, 1983.

4. Any person making the objection or suggestion should also give his name and address.

[No. F. 16(46)/80-MP]
NATHU RAM, Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 1982

का०आ० 223.—चूंकि भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का०आ० 2482 दिनांक 10 जुलाई, 1982 के तहत श्री आर०सी० बैनर्जी विदेशी नौवहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये थे,

और चूंकि विशाखापत्तनम स्टीमशिप एजेंट्स एसोसिएशन श्री के० रामकृष्णराव को विदेशी नौवहन कम्पनियों का प्रतिनिधि नियुक्त किया है,

और चूंकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि श्री आर० सी० बैनर्जी, गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (5) के खंड (1) के तहत अब सदस्य नहीं रहे हैं,

और चूंकि उक्त डाक लेबर बोर्ड में एक स्थान रिक्त हो गया है,

अतः अब गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के तहत केन्द्रीय सरकार उक्त खाली पद को अधिसूचित करती है।

[फा०सं० एल०डी०वी०/6/82-यूएस (एल)]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 10th December, 1982

S.O. 223.—Whereas Shri R. C. Banerjee was appointed as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board being a representative of the Overseas Shipping Interests by notification of the Government of India, Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2482, dated the 10th July, 1982;

And whereas the Visakhapatnam Steamship Agents' Association has nominated Shri K. Ramakrishna Rao as the representative of the Overseas Shipping Interests;

And whereas the Central Government is of the opinion that Shri R. C. Banerjee is deemed to have vacated his office under clause (vi) of sub-rule (5) of rule 4 of Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962;

And whereas a vacancy has occurred in the said Dock Labour Board;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby notifies the said vacancy.

[File No. LDV/6/82-US(L)]

का०आ० 224.—गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1962 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा

(1) के दूसरे परन्तुक के साथ पठित गोदी कर्मकार (रोजगार का विनियमन) 1948 की धारा 5-क की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार श्री आर०सी० बैनर्जी के जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, स्थान पर श्री के० रामकृष्ण राव को विशाखापत्तनम डाक लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और उप प्रयोजन के लिए भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का०आ० 2432 दिनांक 10 जुलाई, 1982 में संशोधन करती है जो इस प्रकार है—

उक्त अधिसूचना में गोदी कर्मचारियों और नौवहन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शोर्बक के अन्तर्गत मद संख्या 4 में "श्री आर०सी० बैनर्जी" के स्थान पर "श्री के० रामकृष्णराव" लिखा जाय।

[फा०सं० एल०डी०वी०/6/82-यूएस (एल)]

थामस मैथ्यू, अवकाश सचिव

S.O. 224.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5-A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri K. Ramakrishna Rao as a member of the Visakhapatnam Dock Labour Board vice Shri R. C. Banerjee, who has vacated his office and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2482, dated the 10th July, 1982, as follows:—

In the said notification, under the heading "Members representing the employers of dock workers and Shipping Companies", against item No. 4, for the entry "Shri R. C. Banerjee", the entry "Shri K. Ramakrishna Rao" shall be substituted.

[File No. LDV/6/82-US(L)]
THOMAS MATHEW, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 1982

का०आ० 225.—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (रोजगार का विनियोजन) अधिनियम, 1948 की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासनिक अधिकारी, बम्बई डाक लेबर बोर्ड को उक्त अधिनियम के उद्देश्य के लिए निरीक्षक नियुक्त करती है।

[फा०सं० एल०डी०वी०/32/82 एस-4]

New Delhi, the 15th December, 1982

S.O. 225.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby appoints the Administrative Officer, Bombay Dock Labour Board to be Inspector for the purpose of the said Act.

[F. No. LDV/32/82-LIV]

अमर खण्ड

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

का०आ० 226.—कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 का संशोधन करने के लिए एक

पाठ्य अधीन, उक्त कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के नौबहन और परिष्कृत संस्करण (परिवर्तन पद) की अधिसूचना संख्यांक का० ए० 2172 तारीख 22 मई, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2 खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 12 जून, 1982 पृष्ठ पर प्रकाशित की गयी थी, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि को समाप्त तक उन सभी व्यक्तियों ने आक्षेप और सुझाव मांगे हुए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र 27 जनवरी, 1982 को जनता को उपलब्ध नोड दिया गया था,

और भारत सरकार को जनता से उक्त प्राच्य स्कीम की तावत को आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है. अर्थात् :—

1. सज्जित नाम और प्रारंभ :—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) (संशोधन) स्कीम, 1982 है।

2. कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 में—

(1) खण्ड 6 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6. अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की सेवा के निबन्धन और शर्तें और उनकी नियुक्ति—

(1) बाई, अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के बारे में सेवा के निबन्धन और शर्तें जिनके अंतर्गत वेतन तथा भत्तों के निबन्धन और शर्तें भी हैं जो वह ठीक समझे, विहित कर सकेगा :

परन्तु बाई, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उस पदों पर नियुक्ति नहीं करेगा जिसका अधिकतम वेतन, भत्तों का छोड़कर, सौबह से पचास रुपये प्रतिमास और उससे अधिक हो।

(2) अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति स्कीम में उनके लिए अन्यत्र अथवा उल्लिखित के निवाय प्रत्यक्ष द्वारा की जाएगी ;

परन्तु अध्यक्ष, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उन पदों पर नियुक्ति नहीं करेगा जिसका अधिकतम वेतन, भत्तों का छोड़कर, सौबह से पचास रुपये प्रतिमास और उससे अधिक हो :

परन्तु यह और कि एक मास से अनधिक की अवधि के लिए छुट्टी के कारण हुई किसी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।” :

(2) खण्ड 8 में,—

(क) उपखण्ड (1), (ख), (ग), और (ड) का लोप किया जाएगा।

(ख) उपखण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ठ) खण्ड 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पदों के सृजन की मंजूरी दे सकेगा।” ;

(3) खण्ड 10 के उप खण्ड (1) में,—

(क) मद (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मदे रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(क) रजिस्ट्रों और पूर्वानुमानित अपेक्षाओं के कालिक पुनरीक्षण के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विभिन्न प्रवर्गों के अधीन कर्मकारों की संख्या नियत करना और किसी प्रवर्ग की रजिस्टर में दी गई कर्मकारों की संख्या को, समय समय पर यथा आवश्यक बढ़ाना या घटाना ;

(ख) किसी प्रवर्ग में कर्मकारों की किसी विनिर्दिष्ट संख्या के, किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी देना;”

(4) खण्ड 17 के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“17क : अदला-बदली—(क) अध्यक्ष को यह शक्ति होगी कि वह किसी प्रवर्ग के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस प्रवर्ग में जिसमें कर्मकारों की कमी है और कांडला अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1969 के अंतर्गत आने वाले कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में, अभिनियोजित करे किन्तु ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अभिनियोजन से पिछली सेवा की मजदूरी में कमी या प्रभुविधाओं में हानि नहीं होगी ;

टिप्पण : यदि स्कीम के उस प्रवर्ग में जिसमें कमी है, मजदूरी या प्रभुविधा कम है तो स्थानान्तरण जखण्डता के आधार पर किया जाएगा अर्थात् कनिष्ठतम व्यक्ति को स्थानान्तरित किया जाएगा और उसके द्वारा उपभोग की जा रही मजदूरी और प्रभुविधाओं को उसके लिए वैयक्तिक समझ कर संरक्षित किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष को यह भी शक्ति होगी कि वह कांडला पत्तन न्यास के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस प्रवर्ग में अभिनियोजित करे जिसमें कर्मकारों की कमी है किन्तु ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अभिनियोजन

से पिछली सेवा की मजदूरी में कमी या प्रमुविधा में हानि नहीं होगी।” ;

(5) खण्ड 18 में,—

(i) “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, जहाँ कहीं वह आता है, “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा।

(ii) उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(क) अध्यक्ष, प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित कर्मचारियों की संख्या का कालिवात: पुनर्विलोकन करेगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उस संख्या का समायोजन करने के लिए उपयुक्त कार्यवाई करेगा।” ;

(6) खण्ड 19 में,—

(i) उपखण्ड (3) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा :

(ii) उपखण्ड (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(4) ऐसे किसी भी प्रवर्ग में, जिसमें डाक कर्मकार को पहले ही स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका हो, कोई भी नई भर्ती चाहे वह अस्थायी तौर पर हो या स्थायी तौर पर, स्थानीय रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों में से ही की जाएगी। किन्तु यदि कांडला पत्तन न्यास द्वारा नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में अधिशिष्ट कर्मकार हैं तो ऐसे अधिशिष्ट कर्मकारों को इस स्कीम के अधीन स्थानान्तरित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। स्थानान्तरण के पश्चात् यदि अध्यापक किए जाने के दिन रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हो तो रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों को ले लेने के पश्चात् सीधी भर्ती की जा सकेगी।” ;

(7) खण्ड 45 में उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) श्रम अधिकारी, उपखण्ड (1) या (2) के अधीन किसी भी मामले पर विचार करेगा और यदि प्रारम्भिक अन्वेषण के पश्चात् तथा उस कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार यथापूर्वोक्त किसी विधिपूर्ण आदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश पारित करेगा कि उस रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को खण्ड 44 के अधीन उतनी अवधि के लिए संदाय नहीं किया जाएगा जितनी श्रम अधिकारी उचित समझे।” ;

(8) खण्ड 46 में,—

(i) उपखण्ड (1) की मद (ii) की उपमद (ख) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, जहाँ कहीं वह आता है “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा :

(ii) उपखण्ड (5) में मद (ग) के पश्चात् निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(गक) उसके बौतन में कटौती करेगी और या उसे निम्नतर प्रवर्ग में प्रत्यावर्तित कर देगा;” ;

(9) स्कीम की अनुसूची-1 में, मद 1 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(1क) यदि कांडला डाक श्रम बोर्ड में अधिशेष हो और पत्तन न्यास के अधीन स्थायी हस्तलान कर्मकारों के तत्समान प्रवर्गों में कमी हो तो साधारण स्थायी (अर्थात्, पुंज स्थायी से भिन्न) की तट पर उठाई-धराई अर्थात् घाट पर स्लिंगों में से स्थायी की लदाई/उतराई तथा उसे घाट से अभिवहन क्षेत्र में और, विषयवस्तु ले जाना, अभिवहन क्षेत्र में स्थायी की उठाई-धराई।”।

[फा० सं० एल डीके/19/81-एल 4]

(Labour Division)

New Delhi, the 18th December, 1982

S.O. 226.—Whereas certain draft scheme to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969 was published as required by sub-section (1) of Section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 2251—54 of the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated 12th June, 1982 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2172 dated the 22nd May, 1982 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 27th January, 1982;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said draft scheme by the Government of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969, namely :—

1. Short title and commencement.—This Scheme may be called the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1982.

2. In the Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969.

(1) For clause 6, the following clause shall be substituted, namely :—

“6. Terms and Conditions of service and appointment of Officers and other staff :—

(1) The Board may prescribe the terms and conditions of service including those of salaries and allowances, as it may deem fit, in respect of officers and other members of staff;

Provided that no post the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand six hundred and fifty and above per mensem shall be created by the Board except with the previous approval of the Central Government.

- (2) The appointment of officers and other members of staff shall be made by the Chairman except as otherwise provided for elsewhere in the Scheme:

Provided that no appointment to posts the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand six hundred and fifty and above per mensem shall be made by the Chairman except with the previous approval of the Central Government:

Provided further that the approval of the Central Government shall not be necessary to any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than one month."

- (2) in clause 8,—

(a) sub-clauses (a), (b), (c) and (k) shall be deleted.

(b) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(1) subject to the provision of clause 6, sanction to creation of posts."

- (3) in clause 10,—

in sub-clause (1),

(a) for items (a) & (b), the following items shall be substituted, namely:—

"(a) to fix the number of workers under various categories and to increase or decrease the number of workers in any category on the Register from time to time as may be necessary after a periodical review of Registers and anticipated requirements with the previous approval of the Central Government;

(b) to sanction the temporary registration of a specified number of workers in any category for a specified period."

- (4) after clause 17, the following new clause shall be inserted, namely:—

"17A : Interchangeability.—(a) The Chairman shall have power to deploy surplus workers in a category to the category wherein there is a shortage of workers, as also under any one of the categories of workers covered by the Kandla Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1968 subject to the condition that such deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from the past service;

Note.—If the category of Scheme in which there is a shortage carries lower wage or benefit, transfer will be made on the basis of seniority, junior-most person being transferred and the wages and benefit being enjoyed by them protected as personal to them.

(b) The Chairman shall also have the power to deploy any surplus worker employed under the Kandla Port Trust in a category in which there is a shortage subject to the condition that deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from past service";

- (5) in clause 18,—

(i) for the word "Board" wherever it occurs, the word "Chairman" shall be substituted.

(ii) after sub-clause (1), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(1A) The Chairman shall periodically review the number of workers required in each category and shall take suitable action to adjust the number with the approval of the Central Government."

- (6) in clause 19,—

(i) In sub-clause (3) for the word "Board" the word "Chairman" shall be substituted;

(ii) for sub-clause (4) the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(4) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis, in any category in which dock workers have already been registered under the Scheme shall be done from amongst the workers registered with the local Employment Exchange. If however, there is a surplus in any category of workers employed by the Kandla Port Trust such surplus workers may be transferred and registered under this scheme. After the transfer, if the requirement exceeds the number of suitable men available on the register of the Employment Exchange on the day of the requisition direct recruitment may be made after absorbing suitable men from the Employment Exchange register."

- (7) in clause 45, for sub-clause (3) the following shall be substituted, namely:—

"(3) The Labour Officer shall consider any matter under sub-clause (1) or (2) and if, after preliminary investigation and after giving reasonable opportunity to the worker of being heard, he is satisfied that the registered dock worker has failed to comply with a lawful order as aforesaid, pass an order that the registered dock worker shall not be paid under clause 44 for such period as Labour Officer thinks fit";

- (8) In clause 46 —

(i) in sub-clause (1) item (i) sub-item (b) for the word "Board" wherever it occurs the word "Chairman" shall be substituted;

(ii) in sub-clause (5) after item (c) the following item shall be substituted, namely:—

"(ca) effect reduction in his pay and/or revert him to the lower category";

- (9) in Schedule-I of the Scheme after item 1 the following item shall be inserted, namely:—

"(1a) Shore handling of general cargo (ie other than bulk cargo) ie loading/unloading of the cargo into/from the slings on the wharf and carrying the same from wharf to the transit area and vice versa, handling of the cargo within the transit area, in case there is surplus in the Kandla Dock Labour Board and shortage in the corresponding categories of cargo handling workers under the Port Trust"

[F. No. 1 DK/19/21 I JV]

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 1982

का० आ० 227.—मोरमगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965 का संशोधन करने के लिए एक प्रारूप स्कीम, डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षासार भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना संख्या का० आ० 2246 तारीख 29 मई, 1982 के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 19 जून, 1982 के पृष्ठ 2317—19 पर प्रकाशित की गयी थी जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मागे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी।

और उक्त राजपत्र 5 जुलाई, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था,

और भारत सरकार को जनता से उक्त प्रारूप की बाबत कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोरमुगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन), स्कीम 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बताती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मोरमुगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1982 है।

2. मोरमुगाओ डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1965 में,

(1) खण्ड 6 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:-

6 अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द की सेवा के निबन्धन और शर्तें और उनकी नियुक्ति,

(1) बोर्ड, अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द के बारे में सेवा के निबन्धन और शर्तें जिनके अन्तर्गत वेतन तथा भत्तों के निबन्धन और शर्तें भी हैं जो वह ठीक समझे, विहित कर सकेगा:

परन्तु बोर्ड केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसा कोई पद सृजित नहीं करेगा जिसका अधिकतम वेतन, भत्तों को छोड़कर सोलह सौ पचास रुपए प्रतिमास और उससे अधिक हो।

(2) अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृन्द को नियुक्ति स्कीम में उसके लिए अन्यथा उपबंधित के सिवाय अध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परन्तु अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उन पदों पर नियुक्ति नहीं करेगा जिनका अधिकतम वेतन-भत्तों को छोड़कर सोलह सौ पचास रुपए प्रतिमास और उससे अधिक हो।

परन्तु यह और कि एक मास से अनधिक की अवधि के लिए छूटों के कारण हुई किसी रिक्ति पर नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।”;

(2) खण्ड 8 में,—

(क) उपखण्ड (क), (ख), (ग) और (ड) का लोप किया जाएगा।

(ख) उपखण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ठ) खण्ड 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए

पदों के सृजन की संजूरी दे सकेगा ;”;

(3) खण्ड 10 के उप खण्ड (1) में,—

(क) मद (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(क) रजिस्ट्रारों और पूर्वानुमानित अपेक्षाओं के कालिक पुनरीक्षण के पश्चात केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विभिन्न प्रवर्गों के अधीन कर्मकारों की संख्या नियत करना और किसी प्रवर्ग का रजिस्टर में दी गई कर्मकारों की संख्या को समय समय पर यथा आवश्यक बढ़ाना या घटाना ;

(ख) किसी प्रवर्ग में कर्मकारों की किसी विनिर्दिष्ट संख्या के किसी विनिर्दिष्ट अर्वाध के लिए अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की संजूरी देना ;”;

(4) खण्ड 17 के पश्चात निम्नलिखित नया खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“17क: अबला बदली (क) अध्यक्ष को यह शक्ति होगी कि वह किसी प्रवर्ग के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस प्रवर्ग में जिसमें कर्मकारों की कमी है अभिनियोजित करे कि तुम ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अभिनियोजन से पिछली सेवा की मजदूरी में कमी या प्रमुविधाओं में हानि नहीं होगी।

टिप्पण: यदि स्कीम के उस प्रवर्ग में जिसमें कमी है मजदूरी या प्रमुविधा कम है तो स्थानान्तरण ज्येष्ठता के आधार पर किया जाएगा अर्थात् कनिष्ठतम व्यक्ति के स्थानान्तरित किया जाएगा और उसके द्वारा उपभाग की जा रही मजदूरी और प्रमुविधाओं को उसके लिए वैयक्तिक समझ कर संरक्षित किया जाएगा।

(ख) अध्यक्ष को यह भी शक्ति होगी कि वह—
मोरमुगाओ पुस्तन न्यास के अधिशिष्ट कर्मकारों को उस प्रवर्ग में अभिनियोजित करे जिसमें कर्मकारों की कमी है किन्तु ऐसा इस शर्त के अधीन रहते हुए किया जाएगा कि ऐसे अभिनियोजन से पिछली सेवा की मजदूरी में कमी या प्रमुविधा में हानि नहीं होगी”;

(5) खण्ड 18 में,—

(i) “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा।

(ii) उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(क) अध्यक्ष, प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित कर्मकारों की संख्या का कालिक : पुनर्विलोकन करेगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से उस संख्या का समायोजन करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगा।”;

(6) खण्ड 19 में,—

(i) उपखण्ड (3) में “बोर्ड” शब्द के स्थान पर “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा ;

(ii) उपखण्ड (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा अर्थात् :-

“(4) ऐसे किसी भी प्रवर्ग में जिसमें डाक कर्मकार को पहले ही स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा चुका हो कोई भी नई भर्ती चाहे वह अस्थायी तौर पर हो या स्थायी तौर पर, स्थानोप रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों में से ही की जाएगी। किन्तु यदि मॉरमुगाओ पत्तन न्यास द्वारा नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग में अधिशिष्ट कर्मकार हैं तो ऐसे अधिशिष्ट कर्मकारों को इस स्कीम के अधीन स्थानान्तरित और रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। स्थानान्तरण के पश्चात यदि अध्यक्षों को जाने के दिन रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है तो रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज उपयुक्त व्यक्तियों को ले लेने के पश्चात सीधी भर्ती की जा सकेगी।

(7) खण्ड 35 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“35 आगाम्य राशि : जब कोई आरक्षित मूलगत कर्मकार कार्य के लिए उपस्थित हो और किसी कारणवश, वह कार्य जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है आरम्भ न हो सके या आगे न चल सके तो वह पूर्ण काल दर मजदूरी का हकदार होगा, किन्तु इस शर्त के अधीन रहते हुए कि वह पूरी पारी में उपस्थित रहे और दिया जाने वाला वैकल्पिक नियोजन स्वीकार करे।” ;

(8) खण्ड 36 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“36 छुट्टियाँ—प्रत्येक कर्मकार ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए, एक वर्ष में 11 दिन के सैलानिक अवकाश का हकदार होगा, जिसमें बोर्ड द्वारा बन्द अवकाश दिनों के रूप में घोषित दिन भी होंगे जो 7 से अधिक नहीं होंगे। इस खण्ड के अधीन किया गया कोई संदाय खंड 32 के अधीन संगणित संदाय के अतिरिक्त होगा।” ;

(9) खण्ड 45 में, उपखण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3) श्रम अधिकारी, उपखण्ड (1) या (2) के अधीन किसी भी मापने पर विचार करेगा और यदि प्रारम्भिक अन्वेषण के पश्चात तथा उस कर्मकार को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर देने के पश्चात

उसका यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार यथापूर्ववत् किसी विधिपूर्ण आदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह आदेश पारित करेगा कि उस रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को खण्ड 44 के अधीन उतनी अवधि के लिए संदाय नहीं किया जाएगा जितनी श्रम अधिकारी उचित समझे।” ;

(10) खण्ड 46 में,—

(i) उपखण्ड (1) की मद (ii) की उपमद (ख) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, जहाँ कहीं वह आता है, “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा।

(ii) उपखण्ड (5) में मद (ग) के पश्चात निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(गक) उसके वेतन में कटौती करेगा और/या उसे निम्नतर प्रवर्ग में प्रत्यावर्तित कर देगा;”।

[फा० सं० एल डी जी / 38/81-एल 4]

बी० शंकरालिंगम, उप सचिव

New Delhi, the 20th December, 1982

S.O. 227.—Whereas certain draft scheme to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965 was published as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) at pages 2317—19 of the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 19th June, 1982 under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 2246 dated the 29th May, 1982 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, till the expiry of a period of 60 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 5th July, 1982;

And whereas no objections and suggestions have been received from the Public on the said draft scheme by the Government of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965; namely:—

1. Short title and commencement.—This Scheme may be called the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1982.

2. In the Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1965,

(1) for clause 6, the following clause shall be substituted, namely:—

“6. Terms and conditions of service and appointment of officers and other staff.

(1) The Board may prescribe the terms and conditions of service including those of salaries and allowances, as it may deem fit, in respect of officers and other members of staff :

Provided that no post the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand six hundred and fifty and above per mensem shall be created by the Board except with the previous approval of the Central Government.

(2) The appointment of officers and other members of staff shall be made by the Chairman except as otherwise provided for elsewhere in the Scheme :

Provided that no appointment to posts the maximum salary of which exclusive of allowances is rupees one thousand six hundred and fifty and above per mensem shall be made by the Chairman except with the previous approval of the Central Government;

Provided further that the approval of the Central Government shall not be necessary to any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than one month."

(2) in clause 8,

(a) sub-clauses (a), (b), (c) and (k) shall be deleted.

(b) for sub-clause (1), the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(1) subject to the provision of clause 6, sanction to creation of posts;"

(3) in clause 10, in sub-clause (1),

(a) for items (a) and (b) the following item shall be substituted, namely:—

"(a) to fix the number of workers under various categories and to increase or decrease the number of workers in any category on the Register from time to time as may be necessary after a periodical review of Registers and anticipated requirements with the previous approval of the Central Government;

(b) to sanction the temporary registration of a specified number of workers in any category for a specified period;"

(4) after clause 17, the following new clause shall be inserted, namely:—

17A. Interchangeability.—(a) The Chairman shall have power to deploy surplus workers in a category, to the category wherein there is a shortage of workers, subject to the condition that such deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from the past service;

Note.—If the category of Scheme in which there is a shortage carries lower wage or benefit, transfer will be made on the basis of seniority, junior-most person being transferred and the wages and benefits being enjoyed by them protected as personal to them.

(b) The Chairman shall also have the power to deploy any surplus worker employed under the Mormugao Port Trust in a category in which there is a shortage subject to the condition that deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from past service;

(5) in clause 18,

(i) for the word "Board" wherever it occurs, the word "Chairman" shall be substituted.

(ii) after sub-clause (1) the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(1A) The Chairman shall periodically review the number of workers required in each category and shall take suitable action to adjust the number with the approval of the Central Government."

(6) in clause 19,

(i) in sub-clause (3) for the word "Board", the word "Chairman" shall be substituted;

(ii) for sub-clause (4) the following sub-clause shall be substituted, namely:—

"(4) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis, in any category in which dock workers have already been registered under the scheme shall be done from amongst the

workers registered with the local Employment Exchange. If, however, there is a surplus in any category of workers employed by the Mormugao Port Trust, such surplus workers may be transferred and registered under this Scheme. After the transfer, if the requirement exceeds the number of suitable men available, on the register of the Employment Exchange on the day of the requisition, direct recruitment may be made after absorbing suitable men from the Employment Exchange register."

(7) for clause 35, the following shall be substituted, namely:—

"35. Disappointment Money.—Where a worker in the reserve pool presents himself for work and for any reason the work for which he has attended cannot commence or proceed, he shall be entitled to full time rate wages, subject to the condition that he is available throughout the shift and accepts alternative employment if provided."

(8) for clause 36, the following shall be substituted, namely:—

"36 Holidays.—Each worker shall be entitled in a year to 11 holidays with pay at such rates as may be prescribed by the Board including all such days which shall not exceed 7 in a year as are declared by the Board as closed holidays. Any payment under this clause shall be exclusive of payment calculated under clause 32.

(9) in clause 45, for sub-clause (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) The Labour Officer shall consider any matter under sub-clause (1) or (2) and if, after preliminary investigation and after giving reasonable opportunity to the worker of being heard, he is satisfied that the registered dock worker has failed to comply with a lawful order as aforesaid, pass an order that the registered dock worker shall not be paid under clause 44 for such period as Labour Officer thinks fit."

(10) In clause 46,

(i) in sub-clause (ii)(b), for the word 'Board' wherever it occurs, the word 'Chairman' shall be substituted.

(ii) in sub-clause (5), after item (c), the following shall be substituted, namely:—

"(ca) effect reduction in his pay and/or revert him to lower category."

[F. No. LDG/36/81-L.IV]

V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 1982

का० आ० 228.—केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 12 दिसम्बर, 81 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 3353 तारीख 24 नवम्बर, 1981 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में 1010.00 एकड़ (लगभग) या 408.72 हेक्टर (लगभग) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना दी थी ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त भूमि में कोयला अभिप्राप्य है ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे संलग्न अनुसूची में उल्लिखित 1010.00 एकड़ (लगभग) या 408.72 हेक्टर (लगभग) माप की उक्त भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना देती है ।

टिप्पण-1. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले रेखांक का निरीक्षण, उपायुक्त, हजारीबाग (बिहार) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता के कार्यालय में अथवा सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) दरभंगा हाउस, रांची (बिहार) के कार्यालय में किया जा सकता है ।

टिप्पण-2. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 8 के उपबन्धों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबन्धित है —

- 8(1) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना निकाली गई है, हितबद्ध है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग या ऐसी भूमि में या उस पर किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में आपत्ति कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के अर्थान्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति का नहीं करना चाहिए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा भुनवाई का अवसर देगा और ऐसा सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई है, करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में आपत्तियों पर अपना सिफारिशों और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्टें केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अर्जित कर लिए जाते ।”

टिप्पण-3. केन्द्रीय सरकार ने, कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है ।

अनुसूची

उरी मेरी ब्लाक विस्तार—1 (बलरामपुर)

(दक्षिणी करमपुरा कोयला क्षेत्र)

जिला हजारी बाग (बिहार)

ड्राइंग सं० राजस्व 36/82

तारीख 3-5-1982

(जिसमें अर्जित की जाने वाली भूमि दर्शाई गई है)

सभी अधिकार

क्रम सं०	ग्राम	थाना	थाना सं०	जिला	क्षेत्र	टिप्पणिया
1.	उरीमेरी	बरका गांव	155	हजारीबाग	610.01	भाग
2.	जरजरा	बरका गांव	156	हजारीबाग	399.99	भाग
		कुल क्षेत्र	---		1010.00	
					एकड़ (लगभग)	
		या			408.72	
					हेक्टर (लगभग)	

ग्राम उरीमेरी में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक

ग्राम जरजरा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक—
सीमा वर्णन :

क-ख रेखा ग्राम उरीमेरी में प्लॉट संख्यांक 788, 790, 789, 791 और 802 से होकर जाती है [जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित उरीमेरी की भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है] और बिंदु 'ख' पर मिलती है।

ख-ग रेखा ग्राम उरीमेरी में प्लॉट संख्यांक 802, 521, 439 से होकर प्लॉट संख्यांक 438 की उत्तरी, सीमा के साथ साथ प्लॉट संख्यांक 313 से होकर फिर प्लॉट संख्यांक 134, 146 की उत्तरी सीमा के साथ साथ प्लॉट संख्यांक 148, 162, 163, 160, 158, 181, 194, 196, 195, 281, 280, 287, 288, 272, 620, 544, 546, 551, 552, 557, 558, 563, 562, 644, 645, 643, 646, 732 और 755 से होकर जाती है [जो कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के अधीन अर्जित उरीमेरी ब्लॉक की भागत: सम्मिलित सीमा बनाती है] और बिंदु 'ग' पर मिलती है।

ग-घ रेखा ग्राम उरीमेरी में दामोदर नदी के भागत: बाएं किनारे के साथ-साथ जाती है और बिंदु 'घ' पर मिलती है।

घ-ङ रेखा ग्राम उरीमेरी और गरमुला की सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु 'ङ' पर मिलती है।

ङ-च रेखा ग्राम जरजरा और गरमुला की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु 'च' पर मिलती है।

च-छ रेखा ग्राम जरजरा के प्लॉट संख्यांक 1060, 947, 951, 1059, 1061, 1056, 1059, 972, 1081, 1048, 1031, 1050, 1031, 200, 199, 88, 199 और 200 से होकर प्लॉट संख्यांक 339 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु 'छ' पर मिलती है।

छ-ज-फ रेखाएं ग्राम जरजरा में प्लॉट संख्यांक 339, 196, 198, 89, 64, 65, 71, 78, 77, 78, 71 और 70 से होकर जाती है और बिंदु 'झ' पर मिलती है।

झ-झ रेखा ग्राम जरजरा और पोटांगा की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और बिंदु 'झ' पर मिलती है।

ज-क रेखा ग्राम उरीमेरी और पोटांगा की भागत: सम्मिलित सीमा के साथ-साथ जाती है और आरम्भिक बिंदु 'क' पर मिलती है।

[फा० सं० 19/53/82-सी० एल०]

स्वर्ण सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

New Delhi, the 26th October, 1982

S.O. 228.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 3353 dated the 24th November, 1981, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii) dated the 12th December, 1981, under sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government gave notice of its intention to prospect for coal in 1010.00 acres (approximately) or 408.72 hectares (approximately) of the lands in the locality specified in the schedule appended to that notification;

And whereas the Central Government is satisfied that coal is obtainable in the said lands;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to acquire the said lands measuring 1010.00 acres (approximately) or 408.72 hectares (approximately) described in the Schedule appended hereto;

Note 1.—The plan of the area covered by this notification may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Hazaribagh (Bihar) or in the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta-1 or in the Office of the Central Coalfields Limited (Revenue Section), Darbhanga House, Ranchi (Bihar).

Note 2.—Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957, (20 of 1957), which provides as follows;

8(1) Any person interested in any land in respect of which a notification under section 7 has been issued may, within thirty days of the issue of the Notification, object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any right in or over such land.

Explanation.—It shall not be an objection within the meaning of this section for any person to say that he himself desires to undertake mining operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the Central Government or by any other person.

(2) Every objection under sub-section (1) shall be made to the competent authority in writing, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner and shall, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as he thinks necessary, either make a report in respect of the land which has been notified under sub-section (1) of section 7 or of rights in or over such land, or make different reports in respect of different parcels of such land or of rights in or over such land, to the Central Government, containing his recommendations on the objections, together with the record of the proceedings held by him, for the decision of that Government.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an interest in compensation if the land or any rights in or over such land were acquired under this Act.

Note 3.—The Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta, has been appointed by the Central Government as the competent authority under the Act.

SCHEDULE

Drg. No. Rev/36/82 dated 3-5-1982
(showing lands to be acquired).Urimari Block Extension-I (Balrampur)
(South Karanpura Coalfield).
Dist. Hazaribagh (Bihar)

All Rights

Serial No.	Village	Thank	Thana No.	District	Area	Remarks
1.	Urimari	Barkagan	155	Hazaribagh	610.01	Part
2.	Jarjara	Barkagan	156	"	399.99	"
Total area :				1010.00 Acres (approximately)		
or				408.72 Hectares (approximately)		

Plot numbers to be acquired in village Urimari :

1 to 133, 148 (part), 149 to 157, 158(part), 159, 160(part), 161, 162(part), 163(part), 181(part), 194(part), 195(part), 196(part), 197 to 271, 272(part), 273 to 279, 280(part), 281 (part), 287 (part), 288(part), 313 (part), 439(part), 440 to 520, 521(part), 522, 544(part), 545, 546(part), 547 to 550, 551(part), 552(part), 554 to 556; 557(part), 558(part), 561, 562(part), 563(part), 564 to 619, 620(part), 621 to 642, 643(part), 644(part), 645(part), 646(part), 732(part), 733 to 751, 753, 754, 755(part), 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 777, 778, 780, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788(part), 789(part), 790(part), 791(part), 802(part), & 803.

Plot numbers to be acquired in village Jarjara :—

64(part), 65(part), 70(part), 71(part), 72 to 76, 77(part), 78(part), 79 to 87, 88(part), 89(part), 196(part), 197, 198(part), 199, (part), 200(part), 339(part), 947(part), 951(part), 972(part), 1031(part), 1048(part), 1050 (part), 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056 (part), 1059(part), 1060 (part), 1061(part) & 1075.

Boundary Description

- A—B line passes through plot numbers 783, 770, 789, 791 & 802 in village Urimari (which forms part common boundary of the Urimari Block acquired u/s 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 and meets at point 'B'.
- B—C line passes through plot numbers 802, 521, 439, along the northern boundary of plot number 438 through plot number 313 than along the northern boundary of plot numbers 134, 146' through plot numbers 148, 162, 163, 160, 158, 181, 194, 196, 195, 281, 230' 287, 288, 272, 620, 544, 546, 551, 552, 557, 558, 563, 562, 644, 645, 643, 646, 732 & 755 village Urimari (which form part common boundary of Urimari Block acquired u/s 9(1) of the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 and meets at point 'C'.
- C—D line passes along the part left bank of Damodar River in village Urimari and meets at point 'D'.
- D—E line passes along the common boundary of villages Urimari and Garsula and meets at point 'E'.
- E—F line passes along the part common boundary of villages Jarjara & Garsula and meets at point 'F'.
- F—G line passes through plot numbers 1060, 947, 951, 1059, 1051, 1056, 1059, 972, 1031, 1048, 1031, 1050, 1031, 200, 199, 88, 199 & 200 eastern boundary of plot number 339 in village Jarjara and meets at point 'G'.
- G—H—I lines pass through plot numbers 339, 196, 198, 89, 64, 65, 71, 78, 77, 78, 71 & 70 in village Jarjara and meets at point 'I'.
- J—J line passes along the part common boundary of villages Jarjara & Potanga and meets at point 'I'.
- J—A line passes along the part common boundary of villages Urimari & Potanga and meets at starting point 'A'.

[No. 19/53/82-CL]

SWARAN SINGH, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1982

का० प्र० 229.—भारत के राजपत्र तारीख 19 जून, 1982 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 2302-2307 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की अधिसूचना का० प्र० सं० 2241 तारीख 4 जून, 1982 में :—

पृष्ठ 2303 पर

- (1) अनुसूची "क" में "रेखांक सं० डब्ल्यू सी एल/पी एल जी सी-1(ई)/III/जे आर 197-088/क"

के स्थान पर "रेखांक सं० डब्ल्यू सी एल/पी एल जी/सी-1(ई)/III/जे० आर०/197-0881 क" पढ़ें।

- (2) बीसापुर ग्राम में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में :—
(क) "259 (भाग) से 261 तक, 262/2" के स्थान पर "259 (भाग) से 261 (भाग) तक 262/1, 262/2" पढ़ें।
(ख) "277 से 291 ए बी तक" के स्थान पर "277 से 291 तक" पढ़ें।

- (3) ग्राम बल्लारपुर में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक में :—

- (क) "1X1" के स्थान पर "1/1" पढ़ें।

- (ख) "3/1, 3/3 के स्थान पर "3/1 से 3/3 तक" पढ़ें।
- (ग) "16/17 (भाग)" के स्थान पर "16/1, 17 (भाग)" पढ़ें।
- (घ) "74, 85, 76/1" के स्थान पर "74, 75, 76/1" पढ़ें।
- (4) "ग्राम कोडाली में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक" के स्थान पर "ग्राम कडोली में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक" पढ़ें।
- (5) ग्राम बाबापुर में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक में "59, 61 से 66 तक" के स्थान पर "59, 60 (भाग), 61 से 66 तक" पढ़ें।

पृष्ठ 2304 पर—

- (1) ग्राम गौरी में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक में "62 से 63 तक" के स्थान पर "62 से 73 तक" पढ़ें।
- (2) सीमा वर्णन में :—
- (क) रेखा छ-ज-अ में "बल्लारपुर" के स्थान पर "ग्राम बल्लारपुर" पढ़ें।
- (ख) रेखा "अ-ट-ट1-ठ-ड" के स्थान पर अ-ट-ट1-ठ-ड" पढ़ें।
- (ग) रेखा "त-थ-थ-द-ध" के स्थान पर "त-थ-थ1-द-ध" पढ़ें।
- (घ) रेखा "ध-ध1-क" के स्थान पर "ध-ध1-क" पढ़ें।
- (3) अनुसूची "ख" में :—
- (1) "(रेखांक सं० डब्ल्यू सी० एल०/पी० एल० जी०/सी०-1(ई)/111/जे० आर०/197-088/ख)" के स्थान पर "(रेखांक सं० डब्ल्यू सी० एल०/पी० एल० जी०/सी०-1(ई)/111/जे० आर०/197-0881 ख" पढ़ें।
- (2) क्रम सं० 2 में ग्राम का नाम स्तंभ के नीचे "बहमानी"— के स्थान पर "बाहमनी" पढ़ें और जहाँ कहीं भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है उसके स्थान पर "बाहमनी" पढ़ें।

पृष्ठ 2305 पर

- (1) कुल क्षेत्र में "2331.46 एकड़" के स्थान पर "2331.48 एकड़" पढ़ें।
- (2) बल्लारपुर ग्राम में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक में :
- (क) (199/1 जे० 199/5 तक" के स्थान पर "199/1 से 199/5 तक" पढ़ें।

(ख) "201/1 202 201/3 (भाग) के स्थान पर "201/1, 201/2 201/3 (भाग)" पढ़ें।

- (3) बाहमनी ग्राम में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक में "275ए, 274 बी 276 से 277" के स्थान पर "275 ए, 275 बी, 276 और 277" पढ़ें।
- (4) दुधली ग्राम में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक में "86 ए, 68 बी" के स्थान पर "68 ए, 68 बी" पढ़ें।
- (5) देहली ग्राम में अर्जित किए गए प्लॉट संख्यांक में :
- (क) "157 से 147 तक" के स्थान पर "137 से 147 तक" पढ़ें।

(ख) 159 ए" के स्थान पर "158 ए" पढ़ें।

(6) सीमा वर्णन में :

(क) प-फ रेखा में "करबौन नाले" के स्थान पर "काखडौन नाले" पढ़ें।

(ख) फ-ज2 रेखा में "देहली और दुधली ग्रामों के स्थान पर "देहली और दुधली ग्रामों में" पढ़ें।

(क) रेखा अ-म-प-य1-न में :—

"201/1, 201/2, 201/3" के स्थान पर "202/1 202/2, 201/3" और "201/11, 201/12, 203/1" के स्थान पर "201/11, 201/12, 203" पढ़ें।

[सं० 19/117/81-सी एल]

पी० सरकार, निदेशक

(Department of Coal)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 2nd December, 1982

S.O. 229.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 2241 dated 4th June, 1982 published at pages 2305—2307 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th June, 1982, at page 2307,—

(1) (a) in column 1, in line 13, for "36", read "37".

(b) in column 2, line 5, for "Manoi" read "Manoli".

(2) in schedule "B",

(a) against serial number 1, under the column "Govt. land", for "40.2" read "4.02".

(b) under the heading "Plot numbers acquired in village Daheli",—

(i) for "49B" read "149B".

(ii) for "171A, 172B" read "171A, 171B, 172A, 172B".

[No. 19/117/81-CL]

CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th October, 1982

S.O. 230.—In the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal), No. S.O. 3353, dated the 24th November, 1981, published in the Gazette of India, part II, section 3, sub-section (ii), dated the 12th December, 1981, at page 3824,

Under the heading boundary description, in line 7,

for "part along part"
read "along part"

[No. 19/12/81-CL]

S.O. 231.—In notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 1924 dated the 1st May, 1982, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated May 29, 1982,—

At page 2113 (i) in the first column, in line 32,

for "It shall not be"
read "It shall not be",
(ii) in the second column in line 61
for "village Muspa"
read "village Murpa".

[No. 19/30/82-CL]
P. SARKAR, Director

संचार संचालय

(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1982

का० आ० 232.—चूंकि विजयवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानी क्षेत्र में बदली किए जाने के लिए एक सर्वसाधारण सूचना, जिसका भारतीय तार नियमावली, 1951 के नियम 434 (iii) (बोबी) में अर्पित है, विजयवाड़ा के समाचार पत्रों में छिपाया गई थी और जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना थी, उनसे कहा गया था कि यदि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हों तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति/सुझाव भेज दें;

और चूंकि उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 31-7-82 के इंडियन एक्सप्रेस के विजयवाड़ा संस्करण तथा 31-7-82 के आंध्र ज्योति के विजयवाड़ा संस्करण में प्रकाशित थी;

और चूंकि उक्त सूचना के उत्तर में जनसाधारण से कई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए ;

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 434(iii) (बोबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, डाक-तार ने घोषित किया है कि तारीख 30-11-82 से विजयवाड़ा का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :

विजयवाड़ा टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

विजयवाड़ा मल्टीएक्सचेंज प्रणाली का स्थानीय संशोधित क्षेत्र यही होगा जो नए विजयवाड़ा नगरनियम के क्षेत्राधिकार 1085 GI/82--26.

में पड़ता है। किन्तु जो टेलीफोन उपभोक्ता विजयवाड़ा नगर नियम की सीमा से बाहर स्थित हैं लेकिन जिन्हें विजयवाड़ा सिटी एक्सचेंज और औद्योगिक एस्टेट एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जाती है वे जब तक अपने एक्सचेंज के 5 कि० मी० की शरीय दूरी के भीतर हैं तब तक स्थानीय शुल्क दर से अदायगी करते रहेंगे। तथापि जिन उपभोक्ताओं को औद्योगिक एस्टेट एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जा रही है उनको सीमा दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्व में बंडर रोड और कन्नूर रोड तथा दानपा रोड तक 5/5 कि० मी० तक सीमित होगी।

टिप्पणी : जो उपभोक्ता गुडाला क्षेत्र में नव-निर्धारित क्षेत्र जिसे रामवरपाडु एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जा रही है, के अंतर्गत आते हैं, वे उक्त एक्सचेंज प्रणाली द्वारा स्थानीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं के बतौर तब तक सेवा प्राप्त करते रहेंगे जब तक कि वे विजयवाड़ा टेलीफोन प्रणाली के एक्सचेंज को अंतर्गत नहीं किए जाते।

[सं० 3-2/74-पी एच० बी० (पीटी)]

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(P & T Board)

New Delhi, the 17th November, 1982

S.O. 232.—Whereas a public notice for revising the local area of Vijayawada Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Vijayawada, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas the said notice was made available to the public on Indian Express, Vijayawada Edition, dated 31-7-82 and on Andhra Jyoti Vijayawada Edition, dated 31-7-82.

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 30-11-82 the revised local area of Vijayawada shall be as under :

Vijayawada Telephone Exchange System :—

The revised local area of Vijayawada multiexchange system shall cover an area falling under the Jurisdictions of new Vijayawada Municipal Corporation boundary. Provided further that the Telephone Subscribers located outside Vijayawada City Exchange and Industrial Estate Exchange will continue to pay local tariffs as long as they are located within 5 K.M. of radial distances of their individual exchange. Moreover, subscribers who are served from Industrial Estate Exchange are subjected to further restriction of Krishna river in South to Km 5/5 on Bandar Road and Kannur Road and Danka Road in the east.

Note :—

Subscribers falling in the newly defined area in Gundala area which are now being served by Ramavarpadu Exchange shall continue to be served by that exchange system as its local area subscribers till the are transferred to the exchange in Vijayawada Telephone System.

[No. 3-2/74-PHB (P]

का० छा० 233.—चूंकि रामवरप्पाडु टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र में बदली किए जाने के लिए एक सर्वसाधारण सूचना जैसा कि भारतीय तार नियमावली 1951 के नियम 434(iii) (बीबी) में अपेक्षित है, रामवरप्पाडु के समाचारपत्रों में निकाली गयी थी और जिन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने का संभावना थी, उनमें कहा गया था कि यदि उन्हें इस संबंध में कोई आपत्ति हो या उनके कोई सुझाव हो तो वे इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति/सुझाव भेज दें;

और चूंकि उक्त सूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए 31-7-82 के इंडियन एक्सप्रेस के विजयवाड़ा संस्करण तथा 31-7-82 के आद्य ज्योति के विजयवाड़ा संस्करण प्रकाशित थी;

और चूंकि उक्त सूचना के उत्तर में जनसाधारण से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए,

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 434 (iii) (बीबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक तार महानिदेशक ने घोषित किया है कि तारीख 30-11-82 से रामवरप्पाडु का स्थानीय संशोधित क्षेत्र इस प्रकार होगा :

रामवरप्पाडु टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली :

रामवरप्पाडु का स्थानीय क्षेत्र वही होगा जो रामवरप्पाडु टेलीफोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० की शरीय दूरी के भीतर पड़ता है। किन्तु यह सीमा उत्तर में विजयवाड़ा-मुस्ताबाद, पश्चिम में विजयवाड़ा नगरपालिका की नई सीमा और दक्षिण में दागपा रोड और कन्नूर के मंगपल्ली रोड तक सीमित होगी। टिप्पणी जो उपरोक्ता गुंडाला क्षेत्र में तब-निर्धारित क्षेत्र

जिसे रामवरप्पाडु एक्सचेंज से सेवा प्रदान की जा रही है, के अंतर्गत आते हैं वे उसी एक्सचेंज प्रणाली द्वारा स्थानीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं के दायरे में

तक सेवा प्राप्त करते रहेंगे जब तक कि वे विजयवाड़ा टेलीफोन प्रणाली के एक्सचेंज को अंतर्गत नहीं किए जात।

[सं० 3-2/74-पी० एच० बी० (पी० टी०)]

एच० बी० रामामूर्ति, निदेशक, फोन(ई)

S.O. 233.—Whereas a public notice for revising the local area of Ramavarappadu Telephone Exchange System was published as required by rule 434(III)(bb) of the Indian Telegraph Rules, 1951 in the Newspapers in circulation at Ramavarappadu, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, within a period of 30 days from the date of publication of the notice in the Newspapers ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public on the said notice ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by rule 434(III)(bb) of the said Rules, the Director General Posts and Telegraphs hereby declares that with effect from 30-11-82 the revised local area of Ramavarappadu shall be as under :

Ramavarappadu Telephone Exchange System

The Local area of Ramavarappadu shall cover an area falling within 5 K.M. radial distance from the Ramavarappadu Telephone Exchange.

Provided that this limit shall be restricted to Vijayawada—Mustabad Railway line in the north, new boundary of Vijayawada Municipality in the west and Danka Road and Kannur-Kesarapalli Road in the South.

Note :—

Subscribers falling in the newly defined area in Gundala area which are now being served by Ramavarappadu Exchange shall continue to be served by that exchange system as its local area subscribers till they are transferred to the exchanges in the Vijayawada Telephone System.

[No. 3-2/74-PHB (P)]

M. B. RAMAMURTHY, Director, Phones (E)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

का० छा० 234:—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और घसीज) नियम, 1965 के नियम 34 के साथ पठित नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के संचार मंत्रालय (डाक-तार) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 620 तारीख 20 फरवरी, 1957 का निम्नलिखित और संशोधन करने हैं, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:—

(क) भाग 2, माधारण कन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' में, "डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रशिक्षण केन्द्र", शीर्षक के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

पद का वर्णन	नियुक्त प्राधिकारी	शास्ति अधिकारों को करने के लिए नक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियाँ जो वह अधिकारों कर सकता है (नियम 13 की मद सख्याओं के प्रतिनिर्देश में)	अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियाँ
डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रशिक्षण केन्द्र	प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक प्रशिक्षण)	प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक प्रशिक्षण)	सभी उपमहानिदेशक (डाक) डाक-तार निदेशालय
उच्च और निम्न चयन श्रेणियों में लिपिकवर्गीय कर्मचारिवृत्त उच्च और निम्न चयन श्रेणियों में अनुदेशक डाक घरों और रेल डाक सेवा के निरीक्षकों और सहायक अधीक्षकों के कार्डों, में अनुदेशक; तार यातायात के तार मास्टरों-या सहायक अधीक्षकों के कार्डर में तार अनुदेशक, निवासीय चिकित्सा अधिकारी, कलाकार डिजाइनर	डाक-तार निदेशालय	डाक तार निदेशालय	
		उप प्रधानाचार्य (1) से (4)	प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक प्रशिक्षण), डाक-तार निदेशालय
लिपिकीय कार्डों में सचिवीय कर्मचारीवृत्त प्रधान अनुदेशक; शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक	उपप्रधानाचार्य	उपप्रधानाचार्य लिपिकवर्गीय प्रशासनिक अधिकारी	सभी प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक प्रशिक्षण) डाक तार निदेशालय (1) से (4) उपप्रधानाचार्य
यांत्रिक; मोटर शालक, कम्पाउंडर काष्ठकार	उपप्रधानाचार्य	उपप्रधानाचार्य प्रशासनिक अधिकारी	सभी प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय (1) से (4) उपप्रधानाचार्य
प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त विभागीय अधिकारी	—	उपप्रधानाचार्य	(1) से (4) प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय
सभी अन्य पद	उपप्रधानाचार्य	उपप्रधानाचार्य प्रशासनिक अधिकारी	सभी प्रधानाचार्य/निदेशक (डाक-प्रशिक्षण) डाक-तार निदेशालय (1) से (4) उपप्रधानाचार्य

(ख) भाग 3—माधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ब" में, शीर्षक "डाक-तार प्रशिक्षण केन्द्र और डाक प्रशिक्षण केन्द्र" के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात् :-

सभी पद	प्रशासनिक अधिकारी	प्रशासनिक अधिकारी	सभी	उपप्रधानाचार्य
प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त विभागीय अधिकारी	—	प्रशासनिक अधिकारी	(1) से (4)	उपप्रधानाचार्य

[संख्या: 154/5/01-सतर्कता-3]

ग. मुख्य, सहायक महानिदेशक (सतर्कता-ख)

New Delhi, the 18th. December, 1982

S.O. 224.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of Sub-rule (2) of rule 12, and Sub-rule (1) of rule 24, read with rule 34 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Communications (Posts and Telegraphs) No. SRO 620, dated the 28th February 1957, namely :—

In the Schedule to the said notification :—

(a) In Part II—General Central Service, Group 'C' for the entries under the heading "Posts and Telegraphs Training Centre and Postal Training Centre", the following entries shall be substituted, namely :—

Description of Post	Appointing authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item numbers in Rule 13).		Appellate authority
		Authority	Penalties	
1	2	3	4	5
Posts and Telegraphs Training Centre and Postal Training Centre				
(1) Ministerial staff in Higher and Lower Selection grades; Instructors in Higher and Lower Selection grades; Instructors in the cadres of Inspectors and Assistant Superintendents of Post Offices and Railway Mail Services; Telegraph Instructors in the cadre of Telegraph Masters or Assistant Superintendent of Telegraph Traffic; Resident Medical Officer, Artist Designer.	Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate.	Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate.	All	Deputy Director General (Postal) Posts and Telegraphs Directorate.
		Vice-Principal	(i) to (iv)	Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate.
Ministerial staff in clerical cadres; Principal Instructor; Physical Training Instructor.	Vice-Principal	Vice-Principal	All	Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate.
		Administrative Officer.	(i) to (iv)	Vice-Principal.
Mechanics; Motor Driver; Compounder; Carpenter.	Vice-Principal	Vice-Principal	All	Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate.
		Administrative Officer.	(i) to (iv)	Vice-Principal.
Departmental Officials deputed for training.	—	Vice-Principal	(i) to (iv)	Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate.
All other posts.	Vice-Principal	Vice-Principal	All	Principal/Director (Postal Training), Posts and Telegraphs Directorate.
		Administrative Officer.	(i) to (iv)	Vice-Principal.

(b) In Part III—General Central Services Group 'D' for the entries under the heading "Posts and Telegraphs Training Centre and Postal Training Centre", the following entries shall be substituted, namely :—

1	2	3	4	5
All Posts	Administrative Officer	Administrative Officer	All	Vice-Principal.
Departmental Officials deputed for training.	—	Administrative Officer.	(i) to (iv)	Vice-Principal.

[No. 154/5/81-Vlg. III]

Sd/ Illegible

Assistant Director General (Vlg. B)/

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली 7 दिसम्बर, 1982

का० प्रा० 235.—राजभाषा (संब के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुपालन में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) उत्तर रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहाँ कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है:—

उत्तर रेलवे :

1. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, वाराणसी।
2. स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय, वाराणसी।
3. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, फैजाबाद।
4. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, प्रयाग।
5. मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, लालगढ़, बीकानेर।
6. मंडल यातायात अधीक्षक (अथ क्षेत्रीय अधीक्षक) का कार्यालय, दिल्ली क्वीन्स रोड।
7. मंडल सहायक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय, बीकानेर।
8. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज का कार्यालय, बीकानेर।
9. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, बीकानेर।
10. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज (परिवार नियोजन) का कार्यालय, लालगढ़।
11. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, रतनगढ़।
12. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, रतनगढ़।
13. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, चुरा।
14. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, सादुलपुर।
15. सहायक मंडल चिकित्सा इंचार्ज का कार्यालय, रेवाड़ी।
16. सहायक परिचालन अधीक्षक का कार्यालय, रेवाड़ी।
17. सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय, रेवाड़ी।
18. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, रेवाड़ी।
19. सहायक अधीक्षक का कार्यालय, दिल्ली क्वीन्स रोड।
20. सहायक यातायात अधीक्षक का कार्यालय, दिल्ली क्वीन्स रोड।
21. सहायक चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, दिल्ली सराय रोहिल्ला।
22. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, हिसार।
23. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, सिरसा।
24. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, सिरसा।
25. सहायक परिचालन अधीक्षक, निबंधन कार्यालय, मानगढ़।
26. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, हनुमानगढ़।
27. सहायक अभियन्ता-1 का कार्यालय, हनुमानगढ़।
28. सहायक अभियन्ता-2 का कार्यालय, हनुमानगढ़।
29. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी का कार्यालय, सूरतगढ़।
30. सहायक अभियन्ता का कार्यालय, लोहाड़।

[स० हिन्दी-82/रा०सा०-1/12/3]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 7th December, 1982

S.O. 235.—In pursuance of sub-rule (2) and (4) of Rule 10 of the Official Languages (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the undermentioned offices of the Northern Railway, where the staff have acquired the working knowledge of Hindi:—

Northern Railway :

1. Office of the Assistant Engineer, Varanasi.
2. Office of the Station Superintendent, Varanasi.
3. Office of the Assistant Engineer, Faizabad.
4. Office of the Assistant Engineer, Prayag.
5. Office of the Divisional Medical Officer, Lalgarh, Bikaner.
6. Office of the Divisional Traffic Superintendent, Delhi, Queens Road (Now Area Superintendent).
7. Office of the Assistant Divisional Security Officer, Bikaner.
8. Office of the Assistant Divisional Medical Officer Incharge, Bikaner.
9. Office of the Assistant Engineer, Bikaner.
10. Office of the Assistant Divisional Medical Officer Incharge (F.P.), Lalgarh.
11. Office of the Assistant Engineer, Ratangarh.
12. Office of Assistant Divisional Medical Officer, Ratangarh.
13. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Churu.
14. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Sadulpur.
15. Office of the Assistant Divisional Medical Incharge, Rewari.
16. Office of the Assistant Operating Superintendent, Rewari.
17. Office of the Assistant Traffic Superintendent, Rewari.
18. Office of the Assistant Engineer, Rewari.
19. Office of the Assistant Superintendent, Delhi Queens Road.
20. Office of the Assistant Traffic Superintendent, Delhi Queens Road.
21. Office of the Assistant Medical Officer, Delhi Sarai Rohilla.
22. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Hissar.
23. Office of the Assistant Engineer, Sirsa.
24. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Sirsa.

25. Office of the Assistant operating Superintendent, Central Office, Hanumangarh.
26. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Hanumangarh.
27. Office of the Assistant Engineer I, Hanumangarh.
28. Office of the Assistant Engineer II, Hanumangarh.
29. Office of the Assistant Divisional Medical Officer, Suratgarh.
30. Office of the Assistant Engineer, Loharu.

[No. Hindi-82/OL-1/12/3]

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1982

का०आ० 236 —सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) को धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार रेल मंत्रालय को दि० 29 नवम्बर, 1978 को अधिसूचना सा० आ० संख्या 3642, दि० 17 सितम्बर, 1980 को अधिसूचना सा० आ० संख्या 2645 तथा दि० 23 जुलाई 1981 को सा० आ० संख्या 2151 के अधिक्रम में राष्ट्रपति, उक्त अधिसूचना के अंतर्गत नियुक्त अधिकारियों के अनिवार्य, एतद्वारा नोचें दो गई तालिका के कालम 1 में उल्लिखित अधिकारियों को जो सरकार के राजस्व अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी नियुक्त करते हैं और आगे यह निदेश देते हैं कि उक्त अधिकारियों को उक्त अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों का अनुपालन उक्त तालिका के कालम (2) में तदनुसूची प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सरकारी स्थानों के संबंध में अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत करेंगे।

तालिका

अधिकारियों का पदनाम	सरकारी स्थानों को कोटियां तथा क्षेत्राधिकारों की स्थानीय सीमाएं।
---------------------	--

- | 1 | 2 |
|---|--|
| 1. मंडल रेल प्रबंधक, मध्य रेलवे, बम्बई, भुसावल, नागपुर, जयपुर, आगो और शोलापुर | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित मध्य रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर। |
| 2. मंडल इंजीनियर, पूर्व रेलवे, हावड़ा, आसनसोल धनबाद, दानापुर, सिवास-वड़ और मुंगलसराय। | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित पूर्व रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर। |

- | 1 | 2 |
|---|--|
| 3. मंडल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद, पुरोच, जोधपुर, नाबनऊ, मुशादाबाद, तां दिल्ली और धोकाने | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित उत्तर रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर। |
| 4. मंडल रेल प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर, लखनऊ बागपसा, ममस्तापुर तथा सोनपुर। | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित पूर्वोत्तर रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर। |
| 5. वरिष्ठ मंडल इंजीनियर, पूर्वोत्तर मामा रेलवे, कटिहार, अलीपुर द्वार जंक्शन और लामडिंग। | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित पूर्वोत्तर मामा रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में स्थित परिसर। |
| 6. मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण रेलवे मद्रास, मैसूर, पालघाट, मदुरै, निरुचिरा-पल्ला और त्रिवेन्द्रम। | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित दक्षिण रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में स्थित परिसर। |
| 7. मंडल रेल प्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे, मिकान्दाबाद बड़ी लाइन्स हैदराबाद (मोंटर लाइन्स) विजयवाड़ा हुबली और गुलत कन। | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित दक्षिण-मध्य रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर। |
| 8. मंडल रेल प्रबंधक, पश्चिम रेलवे, बरबई, बड़ोदरा, रतनाम, कांटा, जयपुर, अजमेर तथा नाथनगर। | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित पश्चिम रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर। |
| 9. पश्चिम रेलवे के बम्बई, बड़ोदरा जयपुर राजकोट तथा भावनगर मंडल वरिष्ठ मंडल इंजीनियर और मंडल इंजीनियर। | उनके अपने-अपने क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत स्थित पश्चिम रेलवे के प्रशासकीय नियंत्रण में परिसर। |

[फाइल नं० 82/डब्ल्यू 2/14/35]

New Delhi, the 11th December 1982

S.O. 236.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act 1971 (40 of 1971) and in supersession of Government of

India, Ministry of Railways (Railway Board) Notification S.O. No. 3642 dated 29th November, 1973, Notification No. S.O. No. 2645 dated the 17th September 1978 and Notification No. S.O. 2151 dated 23rd July, 1981, the President hereby appoints the officers mentioned in column 1 of the Table below, being Gazetted Officers of the Government to be Estate Officers for the purpose of the said Act and further directs that the said officers shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed on Estate Officers by or under the said Act with the local limits of their jurisdiction in respect of the public premises specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

TABLE

Designation of the officers	Categories of public premises and local limits of jurisdiction
1	2
1. Divisional Railway Managers Central Railway Bombay, Bhusawal, Nagpur, Jabalpur, Jhansi and Sholapur.	Premises under the administrative control of the Central Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
2. Divisional Engineers Eastern Railway, Howrah, Asansol, Dhanbad, Danapur, Sealdah and Mughalsarai.	Premises under the administrative control of the Eastern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
3. Divisional Railway Managers, Northern Railway, Allahabad, Ferozpur, Jodhpur, Lucknow, Moradabad, New Delhi & Bikaner	Premises under the administrative control of the Northern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
4. Divisional Railway Managers, North Eastern Railway, Izatnagar, Lucknow, Varanasi, Samastipur and Sonapur.	Premises under the administrative control of the North Eastern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
5. Senior Divisional Engineers, Northeast Frontier Railway, Katihar Alipurduar Junction and Lumding.	Premises under the administrative control of the Northeast Frontier Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.
6. Divisional Railway Managers, Southern Railway, Madras, Mysore, Palghat, Madurai, Tiruchchirappalli and Trivandrum.	Premises under the administrative control of the Southern Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction.

- | | |
|---|---|
| 7. Divisional Railway Managers, South Central Railway Secunderabad (B.G.), Hyderabad (M.G.), Vijayawada, Hubli and Guntakal. | Premises under the administrative control of the South Central Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 8. Divisional Railway Managers, Western Railway, Bombay, Vadodara, Ratlam, Kota, Jaipur, Ameer, and Bhavnagar. | Premises under the administrative control of the Western Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |
| 9. Senior Divisional Engineers and Divisional Engineers of Bombay, Vadodara, Jaipur, Rajkot and Bhavnagar Divisions of Western Railway. | Premises under the administrative control of the Western Railway situated within the local limits of their respective jurisdiction. |

[File No. 82/W2/14/35]

सूचि पत्र

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1982

का० भा० 237.—इस मंत्रालय की 3-11-82 की संख्या: अधिसूचना की तीसरी/चौथी लाइन से 'यांत्रिक' शब्द को निकाल दे।

[सं० हिन्दी-82/रा०भा० 1/12/3]

हिम्मत सिंह, सचिव,

रेलवे बोर्ड

एवं पदेन संयुक्त सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 18th December, 1982

S.O. 237.—The word "Mechanical" may please be deleted from 3rd/4th line of this Ministry's notification of even number dated 3rd November, 1982.

[No. Hindi-82/OL-I/12/3]

HIMMAT SINGH, Secy.
Railway Board,
& Ex. officio Jt. Secy.

